आज़ादी का अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन

2021-2022

बौद्धिक सम्पदा भारत

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प, व्यापार चिन्ह एवं भौगोलिक उपदर्शन

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन

2021-2022

बौद्धिक
सम्पदा भारत

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प,
व्यापार चिन्ह एवं भौगोलिक उपदर्शन
भारत

अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय–वस्तु	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	3
अध्याय I	बौद्धिक सम्पदा अधिकार की प्रवृत्ति–एक झलक	5
अध्याय II	जन सेवा प्रदान–दक्षता और पारदर्शिता	12
अध्याय III	पेटेंट	18
अध्याय IV	पेटेंट सहयोग संधि	42
अध्याय V	डिजाइन	47
अध्याय VI	व्यापार चिह्न	55
अध्याय VII	चिह्नों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण हेतु मेड्रिड प्रणाली	67
अध्याय VIII	भौगोलिक उपदर्शन	71
अध्याय IX	कॉपीराइट	78
अध्याय X	अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन	82
अध्याय XI	राजीव गाँधी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) एवं पेटेंट सूचना पद्धति (पीआईएस)	84
अध्याय XII	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	98
अध्याय XIII	(बौद्धिक सम्पदा अधिकार) आईपीआर में प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं बर्हि–क्रियाकलाप	101
अध्याय XIV	मानव संसाधन	104

प्राक्कथन

वर्ष 2021–22 के दौरान, कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न ने ज्ञान–आधारित बौद्धिक संपदा थाती सृजन को प्रश्रय देने के सरकार के अभियान में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है जिससे देश में नवाचार और सृजन धर्मिता का उन्नयन हुआ है। सीजीपीडीटीएम कार्यालय ने देश में आईपीआर ढांचे को सुदृढ़ करने एवं वैश्विक मानकों के अनुसार एक संतुलित और पारदर्शी आईपी पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण करने के अपने प्रयासों को अनवरत बनाए रखा है। कार्यालय ने राष्ट्रीय आईपीआर नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ–साथ आईपी सूचना तंत्र तक पहुँच सुलभ करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आईपी प्रणाली को अधिक पारदर्शी व उपयोगकर्ता समुदाय के अनुकूल बनाने हेतु विभिन्न रणनीतिक कदम उठाए गए हैं। लंबित कार्य की संख्या घटाने एवं आईपी आवेदनों पर कार्यवाही करने की समयसीमा में सुधार लाने के लिए पेटेंट और व्यापार चिह्न में तकनीकी जनशक्ति को संवर्धित किया गया है, जिसके फलस्वरूप आवेदनों का त्वरित निष्पादन संभव हो पाया है।

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान कोविड–19 महामारी ने कार्यालय की गतिविधियों के सुचारु संचालन में निरंतर चुनौतियां प्रस्तुत की। किन्तु सीजीपीडीटीएम कार्यालय ने इस चुनौती का भी डटकर मुक़ाबला किया। आईपी आवेदनों के कुशल परीक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए कार्यालय ने सफल उपाय किए एवं शीघ्र ही कार्यप्रणाली को एक आभासी मोड में परिवर्तित कर लिया। प्रक्रियात्मक समयसीमा विस्तारित करने के अलावा कुशल ऑनलाइन गतिविधियों के लिए आईपीओ कार्यों को पुनर्जीवित करने हेतु अनेक कदम उठाए गए और अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वीपीएन सुविधा के माध्यम से "घर से कार्य" लागू किया गया। इसके परिणामस्वरूप महामारी के दौरान भी ऑनलाइन परीक्षण, सुनवाई, पेटेंट अनुदान एवं आईपी आवेदनों का पंजीकरण बिना किसी व्यवधान के संभव हो पाया। आवश्यक प्रशासनिक कार्यों के संचालन और कार्यालय के सुचारू संचालन हेतु अधिकारियों को एक ऑनलाइन मॉड्यूल उपलब्ध कराया गया। पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया को अधिक सरल एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए मौजूदा डिजिटल हस्ताक्षर सुविधा के अलावा पेटेंट कार्यालय में एक नवीन ई–हस्ताक्षर सुविधा शुरू की गई।

पेटेंट नियम, 2003 में संशोधन करने के लिए 4 नवंबर 2020 को पेटेंट (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020 अधिसूचित किया गया था। इन संशोधनों द्वारा पेटेंट कार्यालय में किए जाने वाले फाइलिंग के संबंध में लिए जा रहे शुल्क अनुसूची में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। इस संशोधन के परिणामस्वरूप, आवेदकों को विशिष्टतया दो श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया गया है जो है : प्रकृत व्यक्ति या स्टार्टअप या लघु अस्तित्व एवं अन्य। इस प्रकार, लघु अस्तित्व के लिए सभी कार्यवाहियों से संबंधित आधिकारिक शुल्क काफी कम कर दिया गया। 21 सितंबर 2021 को अधिसूचित पेटेंट (संशोधन नियम) 2021 द्वारा पेटेंट दाखिल करने और कार्यवाहियों के लिए शुल्क में अस्सी प्रतिशत की कमी के लाभ का विस्तार शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी किया गया है। इन संशोधनों से लघु अस्तित्व और शैक्षणिक संस्थानों के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने की अपेक्षा है जिससे वे अपने आविष्कारों के संरक्षण के लिए अधिक पेटेंट आवेदन दाखिल करेंगे।

आईपी कार्यालय के समक्ष डिजाइन आवेदन दाखिल करने और इसके महत्व और आवश्यकता को समझते हुए सभी को अभिप्रेरित करने के उद्देश्य से 25 जनवरी 2021 को डिजाइन नियम अधिसूचित किया गया जिसका लक्ष्य त्वरित निष्पादन था और जिसने आवेदक की एक नई श्रेणी, "स्टार्टअप" का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया। ये संशोधन, स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों के सहायक हैं जो उद्यमिता को बढ़ावा देने और भारत में व्यापार करना सुलभ बनाने (ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नस) के सरकार के लक्ष्यों की दिशा में अगला कदम है। पूर्व के डिजाइन अधिनियम, 2000 में लोकार्नो वर्गीकरण के दसवें संस्करण के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण किया गया था, परंतु अब 2021 के संशोधन नियमों से, डिजाइनों को लोकार्नो वर्गीकरण (नियम 10 (1)) के नवीनतम संस्करण अर्थात 13वां संस्कारण के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। इन संशोधनों का उद्देश्य भारत में डिजाइन पंजीकरण को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाना और आवेदकों को डिजाइन पंजीकरण के लिए फाइल करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

भारतीय पेटेंट कार्यालय ने पहले ही अपने परीक्षण मॉड्यूल में वायपो डिजिटल एक्सेस सर्विसेज (डीएएस) और वायपो सेंट्रलाइज्ड एक्सेस टू सर्च एंड एग्जामिनेशन (सीएएसई) को एकीकृत कर दिया है, जिसमें अधिकारी राष्ट्रीय चरण के आवेदनों के परीक्षण के दौरान वायपो सीएएसई में उपलब्ध जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह के तंत्र से ऐसे दस्तावेज दाखिल करने के लिए आवेदकों पर बोझ कम करने में मदद मिलेगी और व्यापार करने में आसानी (ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नस) के लिए समर्थन भी

मिलेगा। भारतीय पेटेंट कार्यालय ने वायपो डीएएस सेवाएं प्रारम्भ की हैं, जो एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिससे भारत और अन्य प्रतिभागी देशों के बीच पूर्विक्ता दस्तावेजों को सुरक्षित हस्तांतरण में सहायता मिलती है।

कार्यालय ने 2021–22 के दौरान आईपी सेवाओं और आईटी–सक्षम कार्यप्रणाली का उपयोग करके प्रदर्शन को उत्प्रेरित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कार्यालय ने हितधारकों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए एक शिकायत प्रक्रिया लागू की है। आईपीओ को सुझाव देने और किसी भी कठिनाई के मामले में राहत पाने के लिए हितधारक वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रतिक्रिया तंत्र (फीडबैक मैकेनिज्म) की सुविधा का बढ़ चढ़ कर उपयोग कर रहे हैं।

आईपी प्रशासन में उत्तरोत्तर विकास, डिजिटल सुधार और आईपी प्रक्रियाओं की पुनर्रचना के परिणामस्वरूप प्रदर्शन बेहतर, लंबित मामलों में कमी तथा आईपी आवेदनों के निष्पादन की दर उच्च हुई है।

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, पेटेंट आवेदन फाइलिंग में 13.57% की वृद्धि हुई, 2020–21 से घरेलू फाइलिंग बढ़कर 2.83% हो गई। हालांकि पेटेंट अनुदत्त किए जाने में 5.95% की वृद्धि हुई लेकिन पेटेंट के निष्पादन में 31.78% की कमी आई है क्योंकि समय–सीमा की निर्धारित अवधि के विस्तार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के कारण धारा 21(1) के तहत परित्याग को स्थगित कर दिया गया था।

व्यापार चिह्न के क्षेत्र में, फाइलिंग में वृद्धि के बावजूद आवेदनों के परीक्षण में लंबितता 1 माह से भी कम रहना जारी रही। नियमों और प्रक्रिया पुनर्रचना में संशोधन द्वारा लाए गए प्रक्रियात्मक सुधारों के कारण प्रारंभिक चरण में व्यापार चिह्न आवेदनों की स्वीकृति में लगभग 50% तक की वृद्धि हुई है।

डिजाइन में, नए आवेदनों के लिए परीक्षण अवधि एक माह से भी कम रही। 2021–22 के दौरान डिजाइन आवेदन दाखिल करने, परीक्षण करने, पंजीकरण एवं डिजाइन आवेदनों के निष्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 59.38%, 59.75%, 66.85% और 68.68% का उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

कॉपीराइट कार्यालय ने भी कम्प्यूटरीकरण और प्रक्रियाओं की पुनर्रचना के कारण प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार किया है। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, नए आवेदनों का परीक्षण एक महीने के बाद किया जाना जारी रहा, जो नए आवेदनों के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि है। कॉपीराइट आवेदनों की फाइलिंग में 26.74% की वृद्धि हुई है जबकि कॉपीराइट के पंजीकरण में पिछले वर्ष की तुलना में 26.06% की वृद्धि हुई है।

भारतीय पेटेंट कार्यालय का अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण (आईएसए) और मैड्रिड प्रोटोकॉल सिस्टम के तहत व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के प्रदर्शन में आईएसआर/आईपीईआर के लिए संदर्भित लगभग सभी आवेदनों में पीसीटी समयसीमा का पालन करते हुए प्रतिवेदन वर्ष के दौरान काफी सुधार हुआ है।

भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और सुदृढ़ करने के लिए दिसंबर 2019 में पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाइवे (पीपीएच) को एक पायलट परियोजना के रूप में लागू किया गया था। भारत ने पीसीटी विनियमों के तहत न्यूनतम दस्तावेज़ीकरण के भाग के रूप में भारत की पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) को शामिल करने के लिए भी प्रस्ताव रखा है।

'आजादी का अमृत महोत्सव' के गारिमामयी अवसर पर, सीजीपीडीटीएम कार्यालय ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (निपम) नाम से एक अभियान का श्रीगणेश किया, जिसका उद्घाटन माननीय सचिव डीपीआईआईटी, श्री अनुराग जैन के कर–कमलों द्वारा 08 दिसंबर, 2021 को किया गया जिसका लक्ष्य 15 अगस्त, 2022 तक कम से कम 1 मिलियन छात्रों को आईपी जागरूकता प्रदान करना था। इस अभियान के तहत 31 मार्च, 2022 तक देश भर के 2300 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों के 6.09 लाख छात्रों और संकाय सदस्यों को बौद्धिक संपदा के बारे में जागरूक किया गया है।

वर्ष 2021–22 के दौरान की गई गतिविधियों का विवरण इस प्रतिवेदन के अगले अध्यायों में दिया गया है। अद्यतन बौद्धिक संपदा विधान, विभिन्न समारोहों के मुख्यान्श व अन्य उपयोगी सूचना हमारी आधिकारिक वेबसाइट (http://www.ipindia.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न आईपी प्रक्रियाओं के सरलीकरण, डिजिटल वातावरण के सृजन और सार्वजनिक शिकायतों का प्रभावी समाधान करने के साथ–साथ पारदर्शी और आवेदक को अनुकूल तरीके से आईपी सेवाएं प्रदान करने में समयबद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ प्रयासरत है।

(प्रो. डॉ. उन्नत पी. पण्डित)
महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न

अध्याय–I

बौद्धिक सम्पदा अधिकार की प्रवृत्ति–एक झलक

परिचय

कार्यालय महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प तथा व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों में विभिन्न बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण हेतु आवेदन दाखिल करने में विगत वर्षों के दौरान उतरोत्तर विकास देखा गया है। विभिन्न बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) हेतु दाखिल कुल आवेदनों में गत वर्ष के **(528471)** की तुलना में इस वर्ष **(568049)** वृद्धि हुई है, जो समग्र 7.5% की वृद्धि दर्शाता है। गत वर्ष की तुलना में पेटेंट, डिजाइन, व्यापार चिह्न, कॉपीराइट व भौगोलिक उपदर्शन में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गयी है।

बौद्धिक सम्पदा आवेदन दाखिल करने के संदर्भ में विगत पाँच वर्षों की प्रवृत्ति निम्नवत है:

आवेदन	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
पेटेंट	47854	50659	56267	58503	**66440**
डिजाइन	11837	12585	14290	14241	**22699**
व्यापार चिह्न	272974	323798	334805	431213	**447805**
भौगोलिक उपदर्शन	38	32	42	58	**116**
कॉपीराइट	17841	18250	21905	24451	**30988**
अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन(एससीआईएलडी)	02	शून्य	शून्य	05	**01**
कुल	**350546**	**405324**	**427309**	**528471**	**568049**

बौद्धिक सम्पदा आवेदन दाखिल करने के संदर्भ में विगत पाँच वर्षों की प्रवृत्ति

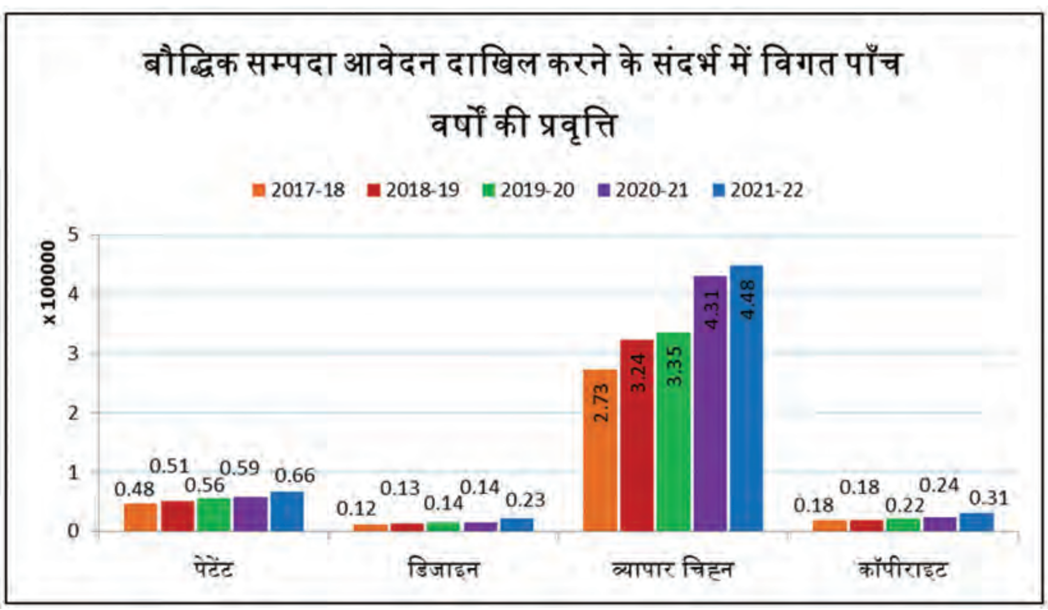

बौद्धिक सम्पदा गतिविधियों के संबंध में प्रवृत्ति :

क. पेटेंट: इस वर्ष के दौरान, कुल **66440** पेटेंट आवेदन दाखिल किए गए जो विगत वर्ष दाखिल आवेदनों की तुलना में लगभग 13.57% की वृद्धि दर्शाता है। पेटेंट आवेदनों की घरेलू फाइलिंग भी बढ़ कर **29508** हो गई है, जो 2020–2021 में कुल दाखिल आवेदन 41.58% की तुलना में 44.41% है।

दाखिल, परीक्षित, अनुदानित तथा निपटान किए गए पेटेंट आवेदनों के संदर्भ में विगत पाँच वर्षों की प्रवृत्ति निम्नवत् है। आवेदनों के निपटान में पेटेंट कार्यालय द्वारा अनुदानित व अस्वीकृत तथा आवेदकों द्वारा आहरित व परित्यक्त आवेदन शामिल हैं।

पेटेंट आवेदनों की प्रवृत्ति

वर्ष	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
दाखिल	47854	50659	56267	58503	**66440**
परीक्षित	60330	85426	80080	73165	**66571**
अनुदानित	13045	15283	24936	28385	**30073**
निपटान	47695	50884	55945	52755	**35990***

* भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सीमा अवधि के विस्तार के कारण धारा 21(1) के तहत 15991 आवेदनों का निपटान स्थगित कर दिया गया।

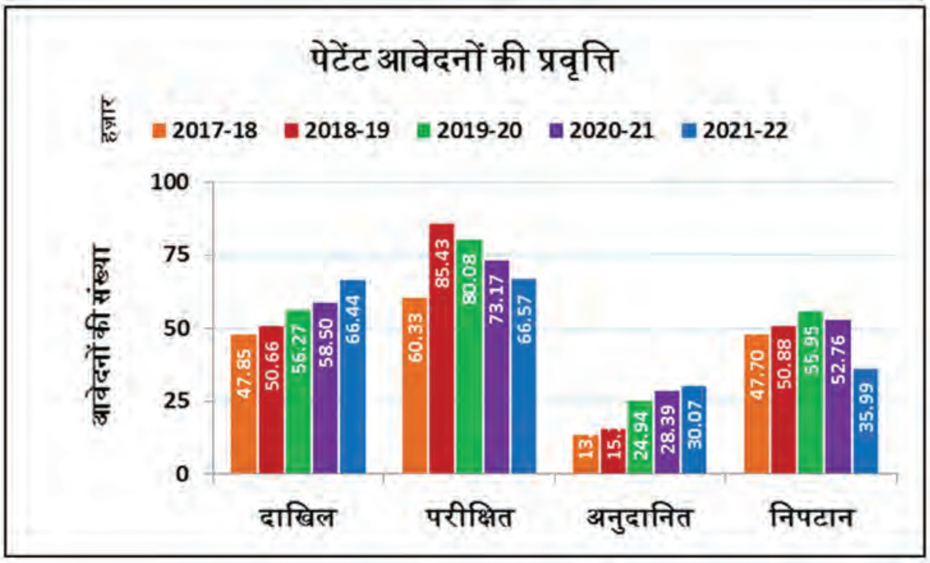

ख. डिजाइन: वर्ष के दौरान, कुल **22699** डिज़ाइन आवेदन दाखिल किए गए जो गत वर्ष की तुलना में 59.38% की वृद्धि दर्शाता है। परीक्षित आवेदनों की संख्या **22120** रही जो 59.75% की वृद्धि दर्शाता है, जबकि गत वर्ष की तुलना में, 2020–21 के दौरान, डिजाइन आवेदनों के पंजीकरण व निपटान में क्रमश: 66.85% व 68.68% की वृद्धि हुई।

डिजाइन आवेदनों की प्रवृत्ति

वर्ष	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
दाखिल	11837	12585	14290	14242	**22699**
परीक्षित	11850	12661	13642	13847	**22120**
पंजीकृत	10020	9483	12256	9147	**15262**
आवेदनों का निपटान	10788	11414	14701	9281	**15655**

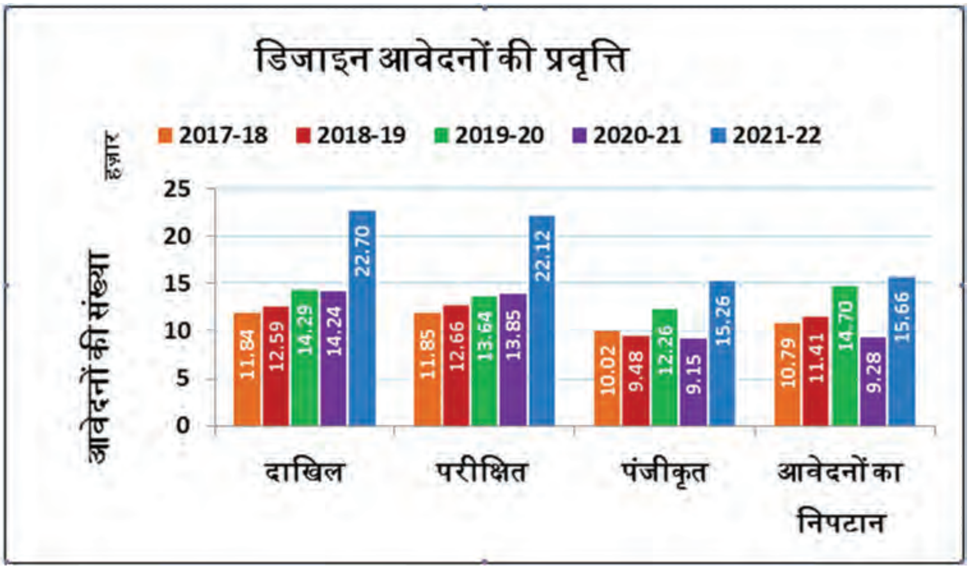

ग. व्यापार चिह्न: इस वर्ष के दौरान, व्यापार चिह्न के पंजीकरण हेतु **447805** आवेदन दाखिल किए गए और **431520** आवेदनों का परीक्षण किया गया और इस क्षेत्र में लंबितता एक माह से भी कम हो गई है। जबकि गत वर्ष की तुलना में, 2021–22 के दौरान, व्यापार चिह्न पंजीकरण और निपटान में क्रमशः 2.12% व 8.11% की वृद्धि हुई है।

व्यापार चिह्न आवेदनों की प्रवृत्ति

वर्ष	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
दाखिल	272974	323798	334805	431213	**447805**
परीक्षित	306259	337541	338551	463912	**431520**
पंजीकृत	300913	316798	294172	255976	**261408**
निपटान	555777	519185	419566	294944	**318878**

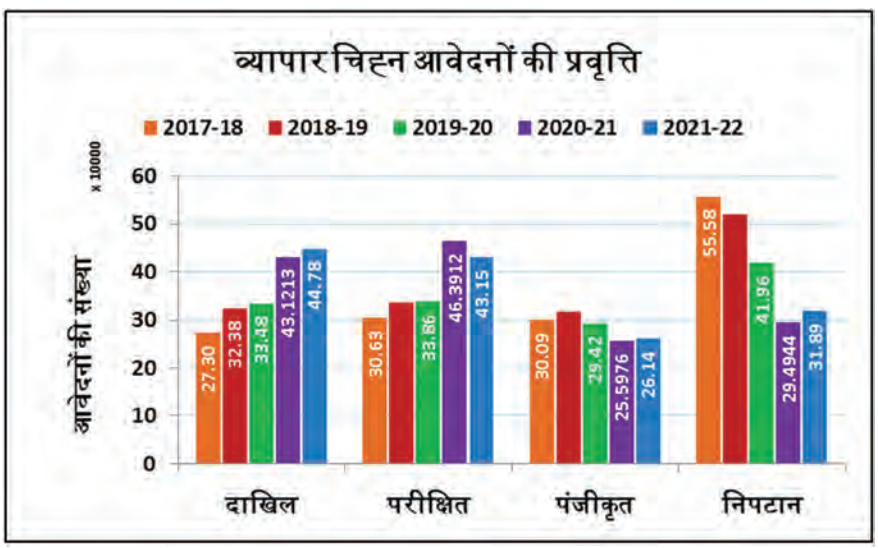

घ. भौगोलिक उपदर्शन: प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, **116** आवेदन दाखिल किए गए, **46** आवेदन परीक्षित किए गए व **50** भौगोलिक उपदर्शन पंजीकृत किए गए। विगत पाँच वर्षों के दौरान दाखिल, परीक्षित एवं पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की प्रवृत्ति निम्नवत हैं।

भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की प्रवृत्ति

वर्ष	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
दाखिल	38	32	42	58	**116**
परीक्षित	18	43	51	0	**46**
पंजीकृत	25	23	22	05	**50**

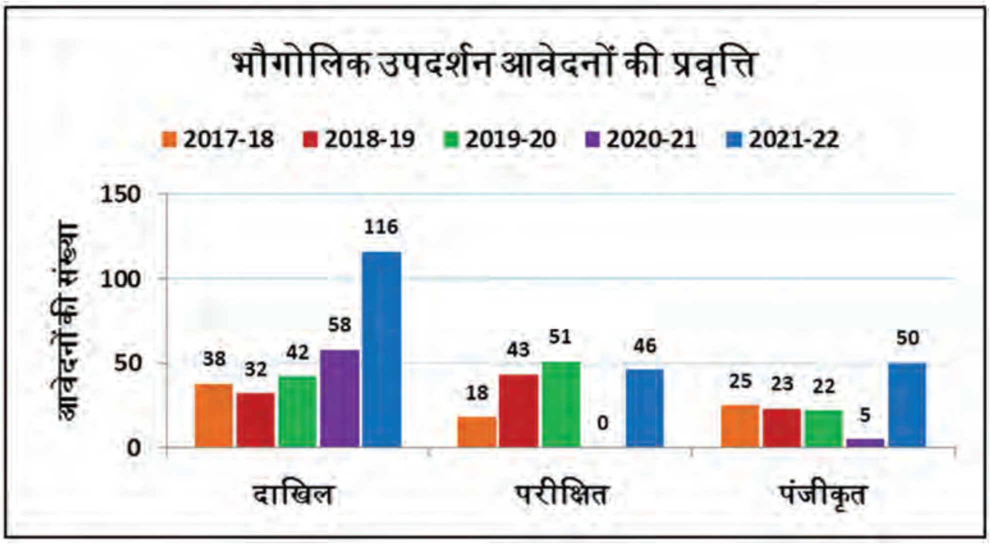

ङ. कॉपीराइटः वर्ष के दौरान कॉपीराइट के पंजीकरण हेतु कुल **30988** आवेदन प्राप्त हुए। कुल **29106** आवेदनों का परीक्षण किया गया व **20673** कॉपीराइट के पंजीकरण (आरओसी) किए गए, जबकि निपटान किए गए कुल आवेदनों की संख्या **20820** रही।

कॉपीराइट आवेदनों की प्रवृत्ति

वर्ष	कुल प्राप्त आवेदन	कुल परीक्षित आवेदन	उत्पन्न किए गए कॉपीराइट के पंजीकरण (आरओसी)	कुल निपटान
2017–18	17841	34388	19997	39799
2018–19	18250	22658	14625	25943
2019–20	21905	29670	16029	22516
2020–21	24451	21523	16399	19477
2021–22	**30988**	**29106**	**20673**	**20820**

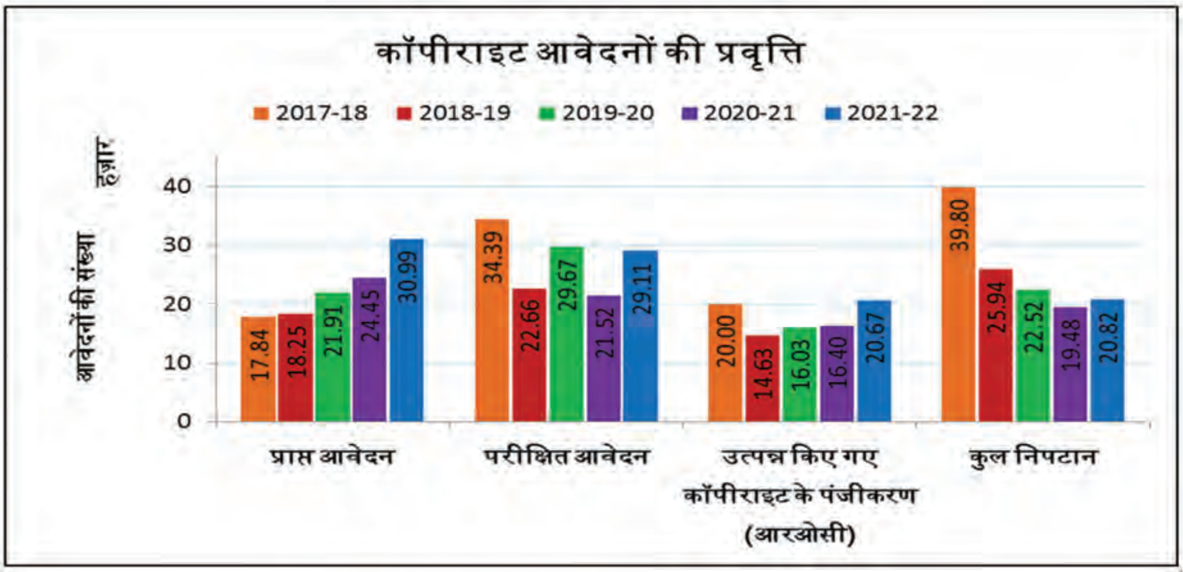

च. अनुदानित/पंजीकृत बौद्धिक सम्पदा अधिकार की प्रवृत्तिः

विगत 5 वर्षों के दौरान बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के अनुदान/पंजीकरण की तुलनात्मक प्रवृत्ति निम्नवत् है। कोष्ठक में प्रदत्त संख्या कुल निपटान प्रदर्शित करती है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार की तुलनात्मक प्रवृत्ति–अनुदानित/पंजीकृत (और निपटान किए गए)

आईपीआर/वर्ष	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
पेटेंट	13045 (47695)	15283 (50884)	24936 (55945)	28385 (52755)	**30073 (35990)**
डिज़ाइन	10020 (10788)	9483 (11332)	12256 (14701)	9147 (9281)	**15262 (15655)**
व्यापार चिह्न	300913 (555777)	316798 (519185)	294172 (419566)	255976 (294944)	**261408 (318878)**
भौगोलिक उपदर्शन	25	23	22	05	**50**
अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन (एससीआईएलडी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	**शून्य**
कॉपीराइट	19997 (39799)	14625 (25943)	16029 (22516)	16399 (19477)	**20673 (20820)**

छ. प्रकाशन एवं अनुदान–पूर्व विरोधः

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 11क के तहत **69613** पेटेंट आवेदन प्रकाशित किए गए तथा धारा 25(1) के तहत **481** अनुदान–पूर्व विरोध दाखिल हुए जो कुल प्रकाशित आवेदनों का लगभग 0.69% है। प्रकाशित तथा अनुदान–पूर्व विरोध के लिए दाखिल आवेदनों का ब्यौरा निम्नवत है:

वर्ष	प्रकाशन	अनुदान–पूर्व विरोध
2017–18	46899	260
2018–19	41776	426
2019–20	50823	800
2020–21	52764	583
2021–22	**69613**	**481**

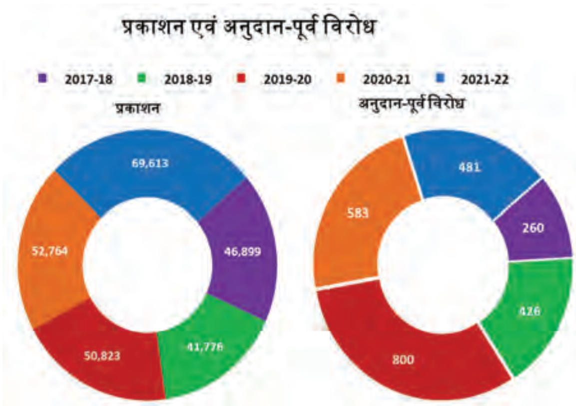

ज. राजस्व और व्यय: वर्ष 2021–22 के दौरान अर्जित कुल राजस्व **रु. 1093.24** करोड़ था, जो विगत वर्ष की तुलना में लगभग 6.42% अधिक है, जबकि कुल व्यय **रु. 204.07 करोड़** था।

पेटेंट कार्यालय द्वारा अर्जित कुल राजस्व रु. 667.49 करोड़ था (इसमें आईबी द्वारा आईएसए फीस के रूप में प्राप्त रु. 0.491 करोड़ शामिल हैं), जबकि डिजाइन कार्यालय से रु. 7.69 करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ। व्यापार चिह्न रजिस्ट्री ने रु. 417.76 करोड़ का राजस्व अर्जित किया (इसमें आईबी से मेड्रिड प्रणाली के तहत अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण हेतु फीस के रूप में प्राप्त रु. 31.35 करोड़ शामिल हैं), जबकि भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री ने रु. 0.08 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। पेटेंट सूचना पद्धति (पीआईएस) और राजीव गाँधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) ने रु. 0.2048 करोड़ का राजस्व अर्जित किया।

(i) गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2021–22 में बौद्धिक संपदा (आईपी) प्रशासन के संबंध में प्राप्त राजस्व एवं व्यय का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

वर्ष	2019–20 (लाख में रु.)	2020–21 (लाख में रु.)	2021–22 (लाख में रु.)
पेटेंट	62177.00	62384.00	**66749.31**
डिज़ाइन	690.00	655.00	**769.12**
व्यापार चिह्न	35230.95	39671.00	**41776.58**
जीआईआर	13.73	5.00	**8.35**
पीआईएस/ आरजीएनआईआईपीएम	24.15	12.35	**20.48**
कुल	**98135.83**	**102727.00**	**109323.84**

धन वापसी के प्रावधान के प्रारम्भ होने के उपरांत पिछले चार वर्षों के दौरान पेटेंट नियम के नियम 7 (4क) के तहत **परीक्षण हेतु अनुरोध की फीस वापसी का विवरण** इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
वापस की गई राशि (लाख में रु.)	472.94	434.41	145.61	**182.93**

(ii) 2019–20, 2020–21 व 2021–22 के व्यय की तुलना:

वर्ष	2019–20 (लाख में रु.)			2020–21 (लाख में रु.)	2021–22 (लाख में रु.)
कार्यालय	**योजना**	**गैर–योजना**	**कुल**	**योजना**	**कुल**
सीजीपीडीटीएम	12254.29	8484.94	20739.23	20157.68	20407.3576
पीआईएस/ आरजीएन आईआईपीएम	253.68	202.82	456.5		
जीआई रजिस्ट्री	–	63.95	63.95		
कुल	**12507.97**	**8751.71**	**21259.68**	**20157.68**	**20407.3576**

जन सेवा प्रदान–दक्षता और पारदर्शिता

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प, और व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री (सीजीपीडीटीएम) ने देश में बौद्धिक संपदा अधिकार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए है जिसमें आईपी फाइलिंग को प्रोत्साहित करने हेतु आईपी कानूनों में संशोधन, कुशल और कागजरहित सेवा वितरण प्रणाली का अंगीकरण, वर्ष 2021–2022 की अवधि के दौरान आम जनता के बीच बौद्धिक संपदा (आईपी) ज्ञान का प्रसार–प्रचार शामिल है। निम्नलिखित अनुच्छेद वर्ष के दौरान उठाए गए विभिन्न पहलों की झलकियॉ प्रस्तुत करता है।

1. पेटेंट:

1.1 पेटेंट नियमों में संशोधन:

क. पेटेंट नियमों में 2016, 2017, 2019 और 2020 में संशोधन किया गया ताकि प्रक्रियात्मक विसंगतियों को दूर करके और प्रक्रियाओं को आईटी सक्षम बनाकर आईपी प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सके, जिससे आईटी अनुदान में तेजी आए। इन नियमों में संशोधन करके देश के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आईपी फाइलिंग को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप, एमएसएमई और महिला आवेदकों सहित आवेदकों की कतिपय श्रेणियों को शुल्क में रियायत प्रदान की गई तथा शीघ्र परीक्षण का प्रावधान किया गया।

ख. वर्ष के दौरान, देश के नवाचार और आईपी पारिस्थितिकी तंत्र में शैक्षाणिक संस्थानों के महत्व को मान्यता देकर और उनकी अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु पेटेंट फाइलिंग और अभियोजन के लिए इन संस्थानों द्वारा देय आधिकारिक शुल्क में 80% की कटौती करने के लिए पेटेंट नियम 2003, में 21 सितंबर 2022 को संशोधन किया गया।

1.2 प्रक्रियात्मक सुधार :–

वर्ष के दौरान, कार्यालय ने अधिक डिजिटल पहलों को शामिल करते हुए, पारदर्शिता और उपयोगकर्ता–मित्रता में सुधार करते हुए प्रक्रियाओं की पुनर्रचना द्वारा पेटेंट कार्यालय के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के अपने मिशन को जारी रखा। वर्ष के दौरान लाए गए प्रक्रियात्मक सुधारों में शामिल हैं:

- अधिकारियों के बीच कार्यभार समान रुप से वितरित करने के लिए आवेदन आंवटन प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया।
- **घर से काम** :–कोविड–19 महामारी प्रतिबंधित अवधि के दौरान, सभी अधिकारियों को परीक्षण मॉडयूल और संबंधित संसाधनों को दूर से एक्सेस करने के लिए सुरक्षित वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) कनेक्शन दिया गया।
- पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया को अधिक सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर की मौजूदा सुविधा के अलावा पेटेंट कार्यालय में ई–हस्ताक्षर की सुविधा शुरु की गई।

1.3 आईपी जागरुकता–

क. 'आजादी का अमृत महोत्सव' के स्मारकीय अवसर पर, सीजीपीडीटीएम कार्यालय ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरुकता मिशन(नीपम) नाम से एक मिशन तैयार किया, जिसका उद्घाटन माननीय सचिव डीपीआईआईटी, श्री अनुराग जैन ने 08 दिसंबर 2021 को किया जिसका उद्देश्य 15 अगस्त 2022 तक कम से कम 10 लाख छात्रों को आईपी के बारे में जागरुकता प्रदान करना था।

ख. कार्यालय की वेबसाइट पर एक ऑनलाइन पोर्टल (https://ipindia.gov.in/) की शुरुआत की गई जिससे शैक्षणिक संस्थान आईपी कार्यालय द्वारा आईपी प्रशिक्षण / जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुरोध कर सके।

ग. कोविड 19 महामारी के कारण और अधिक पहुंच के लिए, राष्ट्रीय आईपी अकादमी के अलावा आरजीएनआईपीएम द्वारा संचालित आईपी जागरुकता / प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्चुअल मोड के माध्यम आयोजित करने का प्रावधान पूरे भारत के अन्य सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में शुरु किया गया।

1.4 उठाए गए कदमों का प्रभाव :–

कोविड 19 प्रतिबंधों के बावजूद, पिछले वर्षों की तुलना में इस अवधि के दौरान भारत में पेटेंट और जागरुकता से संबंधित गतिविधियों में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए। कुछ सुधारात्मक गतिविधियाँ इस प्रकार हैं :–

क) पेटेंट आवेदनों की फाइलिंग में 13.57% की वृद्धि हुई है, जो 2020–21 में 58503 से बढ़कर 2021–22 में 66440 हो गई है।

ख) पिछले दो दशकों में पहली बार एक तिमाही (2021–22 की चौथी तिमाही) में, भारत में राष्ट्रीय नागरिकों द्वारा पेटेंट आवेदनों की फाइलिंग विदेशी नागरिकों द्वारा किए गए पेटेंट आवेदनों की फाइलिंग से अधिक रही।

ग) पेटेंट आवेदनों के लिए प्रदान किए गए पेटेंट में 5.95% की वृद्धि हुई और यह 2020–21 के 28385 से बढ़कर 2021–22 में 30073 हो गए।

घ) प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में फाइलिंग के परीक्षण के लिए अनुरोध दाखिल करने की तारीख से पहले परीक्षण स्तर पर पेटेंट आवेदनों की औसत लंबितता को घटाकर 12 महीने से कम कर दिया गया।

ङ) कोविड –19 महामारी से संबंधित प्रतिबंधों के बावजूद, पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) के तहत, भारतीय पेटेंट कार्यालय का अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण (आईएसए) व अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण (आईपीईए) के रूप में चयन करने वाले लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों के संबंध में, उच्च गुणवत्ता वाली अंतर्राष्ट्रीय खोज और प्रारंभिक परीक्षण रिपोर्ट (आईएसआर और आईपीईआर) जारी करने के लिए निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन किया गया।

च) आईपी जागरुकता मिशन के अंतर्गत, नीपम द्वारा 31 मार्च 2022 तक देश भर के 2300 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से 6.09 लाख विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों को आईपी के बारे अवगत कराया गया।

2. व्यापार चिन्ह :

2.1 प्रक्रियात्मक सुधार :–

- व्यापार चिन्ह हेतु माल और सेवाओं के वर्गीकरण की ऑनलाइन खोज सुविधा को वर्ष के दौरान अद्यतन किया गया है ताकि खोज प्रणाली को और अधिक कारगर बनाया जा सके।
- परीक्षण के लिए आवेदनों का आवंटन उनकी दाखिल करने की तिथि के क्रम में स्वचालित रूप से किया जाता है।

2.2 पंजीकरण हेतु प्रक्रिया का स्वचालन :–

- पूर्व मानवीय प्रक्रिया द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रेषण में लंबितता से बचने के लिए व्यापार चिन्ह की पंजीकरण प्रक्रिया को स्वचालित कर दिया गया। परिणामस्वरुप, प्रकाशन के बाद निर्धारित समय पूरा होने के उपरांत, पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वचालित रुप से संसाधित होते हैं और आवेदक के निर्दिष्ट ई–मेल–आईडी पर भेज दिए जाते हैं और यह व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री (टीएमआर) द्वारा बनाए गए

इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर में भी अपलोड हो जाता है। इस परिवर्तन ने इस स्तर पर लंबित रहने की अवधि को एक महीने से कम करने में सहायता की है और आवेदकों के लिए भी काफी हद तक सहायक हुआ है।

- **नवीनीकरण की प्रक्रिया** को भी स्वचालित कर दिया गया है, जहां नवीनीकरण अनुरोध (निर्धारित समय में दाखिल) संसाधित हो जाता है और वैधता तिथि अद्यतन हो जाती है।
- आधिकारिक वेबसाइट www.ipindia.nic.in में प्रत्येक सोमवार को व्यापार चिन्ह (टीएमआर) जर्नल में पंजीकृत व्यापार चिन्ह आवेदनों के विवरण का ऑनलाइन प्रकाशन इस वर्ष के दौरान और अधिक सुव्यवस्थित किया गया।

2.3 वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कारण बताओ आवेदन की सुनवाई :–

- इस वर्ष व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री में कारण बताओ आवेदनों की सुनवाई के तरीके में भी एक आदर्श बदलाव देखा गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग द्वारा और हितधारकों की सुविधा के लिए व्यापार चिन्ह आवेदनों के प्रसंस्करण को और अधिक कारगर बनाने हेतु सभी कारण बताओ आवेदनों की सुनवाई को पूरी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड में बदल दिया गया है। इसके परिणामस्वरुप व्यापार चिन्ह आवेदनों के प्रसंस्करण में अधिक दक्षता आई है और हितधारकों को अपनी सुविधानुसार अपने कार्यालय या घर से सुनवाई में शामिल होने को अवसर भी मिला है।

3. डिजाइन :

- बेहतर कामकाज की सुविधा के लिए नए और डिजाइन आवेदनों की ई–फाइलिंग सुविधा को अद्यतन किया गया है।
- डिजाइन नियमों में अंतिम संशोधन 25 जनवरी, 2021 से लागू हुआ, जिसमें 'स्टार्टअप' के रूप में मान्यता प्राप्त एक नई श्रेणी शामिल की गई है, जो एक भारतीय इकाई के मामले में स्टार्टअप भारत पहल के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त हो एवं विदेशी आवेदक के मामले में, स्टार्टअप भारत पहल के अनुसार टर्नओवर और निगमन या पंजीकरण की अवधि के मानदंडों को पूरा करने वाली संस्था और उस आशय की घोषणा प्रस्तुत करना है।
- इसके अतिरिक्त, नियम 10 के उपनियम (1) को भी प्रतिस्थापित किया गया है तथा डिजाइन के पंजीकरण और नियमों के प्रयोजन के लिए वस्तुओं को 'विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (वायपो) द्वारा प्रकाशित औद्योगिक डिजाइन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण प्रणाली (लोकार्नो प्रणाली) के वर्तमान संस्करण के अनुसार वर्गीकृत किया जा रहा है।
- नए आवेदनों के परीक्षण में जो लंबितता थी उसे फाइलिंग तिथि से एक महीने से कम कर दिया गया है।
- वर्ष के दौरान संशोधित आवेदनों की लंबितता को काफी हद तक कम करने के उपाए किए गए है।
- कोविड–19 महामारी को ध्यान में रखते हुए वायपो–डीएएस कोड का उपयोग करते हुए प्राथमिकता दस्तावेज़ प्रस्तुत करने को प्रोत्साहित किया गया। टेलीफोन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से सुनवाई की गई।
- डिजाइनों का ई–रजिस्टर सामान्य जन के लिए उपलब्ध कराया गया।
- इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल के माध्यम से पंजीकरण के बाद की विभिन्न कार्यवाहियों का प्रसंस्करण शुरू किया गया।

4. भौगोलिक उपदर्शन :

- वर्ष के दौरान, परीक्षण और पंजीकरण में लंबितता समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। जिसके परिणामस्वरुप वर्ष के दौरान 06 जीआई आवेदनों को विज्ञापित किया गया, 46 जीआई आवेदनों का परीक्षण किया गया और 50 जीआई को पंजीकृत किया गया।

5. कॉपीराइट :

- वर्ष के दौरान, नए आवेदनों के परीक्षण की लंबित रहने की अवधि एक माह तक जारी रही, जो नए आवेदनों के लिए आपत्तियों को आंमत्रित करने के लिए अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि है।
- डिजिटलीकरण, पंजीकरण प्रक्रियाओं की पुनर्रचना और जनशक्ति के उन्नयन और बेबसाइट को अद्यतन करने के माध्यम से कॉपीराइट कार्यालय की कार्यपद्धति को सुदृढ़ बनाने के लिए कई कदम उठाए गए।
- **सार्वजनिक इंटरफ़ेस में सुधार करना और बेवसाइट को अद्यतन करना**–पारदर्शिता और हितधारकों की भागीदारी को और बढ़ाने के लिए तथा आवेदकों को उनके आवेदन की स्थिति देखने में सक्षम बनाने के लिए, कॉपीराइट कार्यालय ने एक माह के दौरान प्राप्त आवेदन और निपटान और लंबितता को कार्यालय की बेबसाइट पर प्रदर्शित करना प्रारम्भ कर दिया है। दाखिल किए गए आवेदनो की स्थिति, अनुदानित पंजीकरण और पंजीकृत कार्य की खोज प्रदान करने के लिए डैशबोर्ड तैयार किया गया है।
- कॉपीराइट कार्यालय ने कार्यों के निर्बाध पंजीकरण की सुविधा के लिए अपने ऑनलाइन पोर्टल पर साहित्यिक /नाटकीय और कलात्मक कार्यों की सॉफ्ट कॉपी अन्य संबंधित दस्तावेजों के साथ अपलोड करने का प्रावधान समाविष्ट किया है।
- कॉपीराइट कार्यालय वर्चुअल मोड द्वारा कार्यालय को जनता के लिए आसानी से सुलभ बनाने की प्रक्रिया में है। सामान्य जन को कार्यालय में आने से रोकने के लिए कॉपीराइट मामलों में वर्चुअली तरीके से सुनवाई आयोजित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
- कॉपीराइट कार्यालय सामान्य जन को कार्यालय के साथ पत्राचार को ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए भी कदम उठा रहा है। इस प्रक्रिया से जनता का समय और पैसा बचेगा और कम समय में उनकी समस्याओं का समाधान भी होगा।
- **नीपम के तत्वावधान में सामान्य जन जागरूकता कार्यक्रम** : शिक्षाविदों, छात्रों को कॉपीराइट के बारे में जागरूक करने के लिए कॉपीराइट कार्यालय ने कई संगोष्ठियों का आयोजन किया है। इन जागरूकता कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य सामान्य जन को कॉपीराइट के बारे में जागरूक करना और कॉपीराइट के पंजीकरण की प्रक्रिया और कार्यप्रणाली के बारे में उनका ज्ञानवर्धन करना है।

6. आईसीटी आधारभूत संरचना और बौद्धिक संपदा कार्यालय में महत्वपूर्ण सुधार :

6.1 ई–हस्ताक्षर एकीकरण :

- पेटेंट ई–फाइलिंग सेवा के साथ ई–हस्ताक्षर का एकीकरण किया गया है। आवेदक अब ई–हस्ताक्षर के साथ–साथ डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके अपने फाइलिंग से संबंधी दस्तावेज जमा कर सकते हैं। वर्तमान में ई–मुद्रा द्वारा ई–हस्ताक्षर की सेवाएं प्रदान की जा रही है।

6.2 व्यापार चिन्ह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाओं का उन्नयन :

- व्यापार चिन्ह की सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाओं को अद्यतन किया गया है। एक पोर्टल बनाया गया है जहां सभी निर्धारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सूची दी गई हैं। सभी सुनवाई अधिकारी को

निर्धारित सुनवाई का आयोजन करने के लिए निजी वीसी सुनवाई कक्ष दिया गया है।

6.3 नीपम :

- एक पोर्टल का शुभांरभ किया गया है जिससे नीपम संबंधी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके। यह पोर्टल आरंभिक चरण से लेकर प्रमाणपत्र के वितरण तक कार्यक्रमों की सभी सूचनाएं प्रदान करता है।

7. हितधारकों के साथ परामर्शक बैठकें :

नियमित बैठकें विभिन्न आईपी स्थानों पर आयोजित की जाती हैं ताकि आईपी नियमों में संशोधन से संबंधित प्रक्रियात्मक और तकनीकी मुद्दों को समझने और उसे हल करने, प्रक्रियाओं की पुनर्रचना, मॉडयूल–आधारित कार्य–प्रवाह, प्रणालीगत उन्नयन, हितधारकों के साथ संचार और सार्वजनिक शिकायतों का समाधान हो सके।

8. प्रतिक्रिया तंत्र :

आईपी कार्यालयों के कामकाज से संबंधित मुद्दों के संबंध में हितधारकों की बहुमूल्य प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए और हितधारकों की शिकायतों को सबसे प्रभावी ढंग से संभालने के लिए कार्यालयों में प्रतिक्रिया तंत्र को सुव्यवस्थित किया गया है।

9. बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में जागरुकता :

- आईपी कार्यालय नियमित रूप से बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी जागरूकता और सार्वजनिक आउटरीच गतिविधियों में भाग लेता है और इसके माध्यम से आईपी प्रक्रियाओं के बारे में वास्तविक और संभावित हितधारकों के लिए सूचना और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करता है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरुकता मिशन की शुरुआत 08 दिसंबर 2021 को हुई जिसका उद्देश्य 15 अगस्त 2022 से पहले विभिन्न आईपीआर के बारे में दस लाख छात्रों को जागरूक करना था।

- आईपीओ अधिकारी नियमित रुप से इन कार्यक्रमों में संसाधन व्यक्तियों के रुप में भाग लेने के साथ–साथ स्कूलों, विश्वविद्यालयों, प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के लिए आयोजित कार्यशालाओं, सेमिनारों में भी भाग लेते है।

- आरजीएनआईआईपीएम नियमित रुप से आईपीओ अधिकारियों, आईपी पेशेवरों, आईपी प्रबंधकों आदि के लिए विशेष प्रशिक्षण का आयोजन करता है और छात्रों, शिक्षकों एमएसएमई, स्टार्टअप आदि सहित सामान्य जन के लिए बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इन कार्यक्रमों का आयोजन या तो वह स्वतंत्र रुप से करता है या विधि विश्वविद्यालयों और वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन (वायपो) के सहयोग से किया जाता है।

10. आईएसआर /आईपीईए रिपोर्ट :

आईपीओ आईएसआर /आईपीईए के रुप में अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट स्थापित करने में समयबद्धता बनाए रखता है और वायपो के पेटेंट स्कोप पोर्टल पर परीक्षकों की खोज रणनीतियों को प्रकाशित करता है।

11. अंतरराष्ट्रीय समझौते–

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, कार्यालय ने अन्य आईपीओ के साथ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए है–

- सीजीपीडीटीएम और डीकेपीटीओ कार्य योजना के तहत, सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में कई बैठकें आयोजित की गईं। यात्रा प्रतिबंधों सहित कोविड–19 महामारी के कारण हुई कठिनाइयों के बावजूद, दोनों पक्ष द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति करने में सक्षम रहे।

- कार्यालय महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिन्ह और जापान बौद्धिक संपदा कार्यालय ने एक दूसरे के अंतरराष्ट्रीय खोज प्राधिकरण और अंतरराष्ट्रीय प्रारम्भिक परीक्षण प्राधिकरण को मान्यता दी (आईएसआर/ आईपीईए) और इस बात पर सहमत हुए कि दोनों कार्यालय आईएसआर/आईपीईए के रुप में 01 जुलाई 2021 से कार्य करना शुरू कर देंगे।

- दिसंबर 2021 में डीपीआईआईटी और यूएसपीटीओ के बीच आपसी समझ के अनुसार कार्य योजना लागू हुई जिस पर डीपीआईआईटी और यूएसपीटीओ ने दिसंबर 2020 में हस्ताक्षर किए थे।

- डीपीआईआईटी और बौद्धिक संपदा के लिए संघीय सेवाएँ (रोसपेटेंट) के बीच में 03 दिसंबर 2021 को बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में संधि ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए गए।

- 25 अगस्त 2021 को भारत की अध्यक्षता में 13वीं ब्रिक्स बौद्धिक संपदा कार्यालय प्रमुखों (हाइपो) की बैठक का आयोजन वर्चुअली रुप से किया गया। महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिन्ह (भारत) श्री राजेन्द्र रत्नू इस बैठक के अध्यक्ष थे। आईपी कार्यालयों के प्रमुख और उनके प्रतिनिधिमंडल ने आईपी की प्रक्रियाओं और कार्य प्रणालियों, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, जागरूकता, सूचना सेवा, आईपी रणनीतियाँ, आईपी कार्यालय के कर्मचारियों के प्रशिक्षण, डिजिटल परियोजना, भौगोलिक उपदर्शन और संबंधित न्यायालयों में सफल आईपी प्रथाओं सहित कई मुद्दों पर अपने विचारों का आदान–प्रदान किया।

12. सूचना का अधिकार–

कार्यालय महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिन्ह सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति प्रतिबद्ध रहा है। बौद्धिक संपदा कार्यालयों के क्रियाकलापों में सम्पूर्ण पारदर्शिता प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यालय की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित जानकारी आम जनता और हितधारकों के सूचनार्थ आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गयी है। साथ ही, सूचना अधिकार अधिनियम के विधायी अभिप्राय तथा अधिदेश का पूर्ण अनुकरण करते हुए अधिनियम के तहत प्राप्त सभी आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई की गयी।

पेटेंट

परिचयः

यह अध्याय पेटेंट अधिनियम, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 155 के तहत पेटेंट कार्यालयों द्वारा वर्ष 2021–22 के दौरान निष्पादित गतिविधियों के संबंध में 50वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। पेटेंट कार्यालय कोलकाता, नई दिल्ली, मुम्बई तथा चेन्नई में स्थित है, जिनका पेटेंट प्रशासन के लिए देश में विशिष्ट क्षेत्राधिकार है। हालांकि, सभी चार पेटेंट कार्यालय आभासी एकल कार्यालय के रूप में कार्य करते हैं। पेटेंट कार्यालय, महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) के अधीक्षण व प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन देश में हुए आविष्कारों के संरक्षण से संबंधित पेटेंट अधिनियम 1970 (यथा संशोधित) के प्रावधानों को लागू करता है। निम्न प्रदत्त पैराग्राफ पेटेंट विधान के तहत यथाप्रशासित पेटेंट कार्यालय की प्रमुख गतिविधियों की रूप–रेखा प्रस्तुत करते हैं।

1. पेटेंट आवेदनः

2021–22 में दाखिल पेटेंट आवेदनों की संख्या **66440** थी जो 2020–21 की फाइलिंग की संख्या 58503 में 13.57% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष के दौरान, आविष्कार के लगभग सभी क्षेत्रों में मध्यम से उच्च विकास देखा गया है विशेष रूप से कंप्यूटर विज्ञान व इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार, यान्त्रिकी व वैद्युतिक। विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित, विगत पाँच वर्षों के आवेदनों की प्रवृत्ति के विस्तृत आँकड़े परिशिष्ट–ङ और ङ1 में दर्शाए गए हैं।

(क) भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनः

कुल दाखिल **66440** आवेदनों में से, भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की संख्या **29508** रही जो गत वर्ष से लगभग **21.3%** की वृद्धि दर्शाता है, जब ऐसे आवेदनों की संख्या 24326 थी। कुल दाखिल आवेदनों में से दाखिल घरेलू आवेदन गत वर्ष के 41.58% की तुलना में 44.41% है। इस प्रकार, पिछले वर्षों की वृद्धि के अनुरूप, इस वर्ष भी, भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल किए गए आवेदनों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 2020–21 के दौरान दाखिल आवेदनों की संख्या (34177) की तुलना में वर्ष के दौरान विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की संख्या **(36932)** रही जो 8.06% की वृद्धि दर्शाता है।

(ख) भारतीय आवेदकों द्वारा राज्यवार दाखिल पेटेंट आवेदनः

2021–22 के दौरान, भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों में से, तमिलनाडु प्रथम स्थान पर रहा जबकि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश क्रमशः द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे। इस वर्ष तमिलनाडु जैसे राज्य ने गत वर्ष की तुलना में फाइलिंग में उल्लेखनीय छलांग लगाई और सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना और हरियाणा जैसे राज्यों के साथ–साथ चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर और दमन और दीव जैसे केंद्र शासित प्रदेशों ने भी अपने पिछले साल की फाइलिंग में वृद्धि की, अतः उन्होने भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल समग्र पेटेंट आवेदनों में अत्यधिक योगदान दिया।

आवेदन दाखिल करने वाले शीर्ष राज्य/केंद्र शासित प्रदेश हैं (आवेदनों की संख्या कोष्ठक में दी गयी है) तमिलनाडु (5262), महाराष्ट्र (4566), उत्तर प्रदेश (3622), कर्नाटक (3222), पंजाब (2197), तेलंगाना (1750), दिल्ली (1673), गुजरात (1067), हरियाणा (998), आंध्र प्रदेश (934), उत्तराखंड (533), मध्य प्रदेश (488), राजस्थान (465), केरल (454), पश्चिम बंगाल (453), चंडीगढ़ (348), उड़ीसा (328), हिमाचल प्रदेश (268), झारखंड (225) और असम (150)। राज्य/ केंद्र शासित क्षेत्र के अनुसार विवरण **परिशिष्ट ख** में प्रदर्शित किया गया है।

भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन (राज्यानुसार)

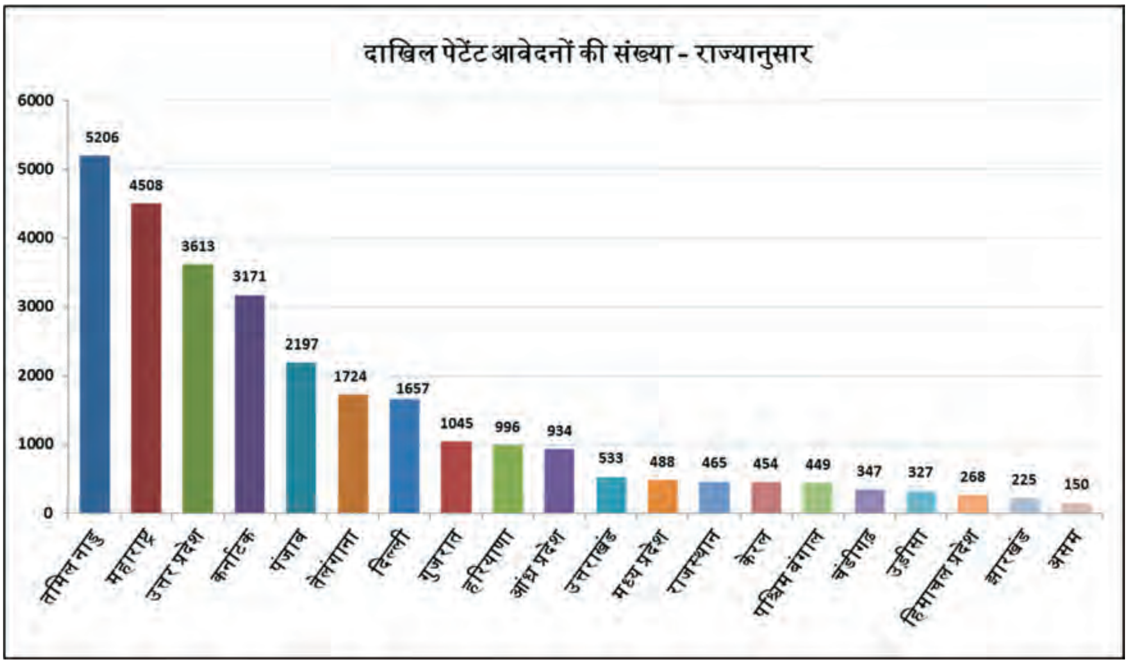

(ग) आवेदनों का श्रेणीवार वितरण:

विगत पाँच वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों जैसे प्रकृत व्यक्ति (एनपी), स्टार्टअप (एसयू), लघु अस्तित्व (एसई), शैक्षणिक संस्थान (ईआई) तथा प्रकृत व्यक्ति के सिवाय अन्य (ओएनपी) आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों का विवरण निम्नवत है। यह ध्यान दिया जाए लगभग सभी श्रेणियों में दाखिल आवेदनों में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है।

वर्ष	प्रकृत व्यक्ति (एनपी)		स्टार्टअप (एसयू)		लघु अस्तित्व (एसई)		शैक्षणिक संस्थान (ईआई)		प्रकृत व्यक्ति के सिवाय अन्य		कुल		कुल योग
	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी			
2017–18	6811	1444	511	4	491	131	0	0	7737	30725	15550	32304	**47854**
2018–19	7250	1193	801	10	607	75	0	0	8347	32376	17005	33654	**50659**
2019–20	8792	1182	1650	2	576	272	0	0	9825	34169	20843	35625	**56468**
2020–21	10844	1053	1598	13	744	53	0	0	11150	33048	24326	34177	**58503**
2021–22	**12451**	**1324**	**1482**	**19**	**985**	**384**	**7405**	**96**	**7185**	**35109**	**29508**	**36932**	**66440**

प्रकाशन एवं अनुदान-पूर्व विरोध

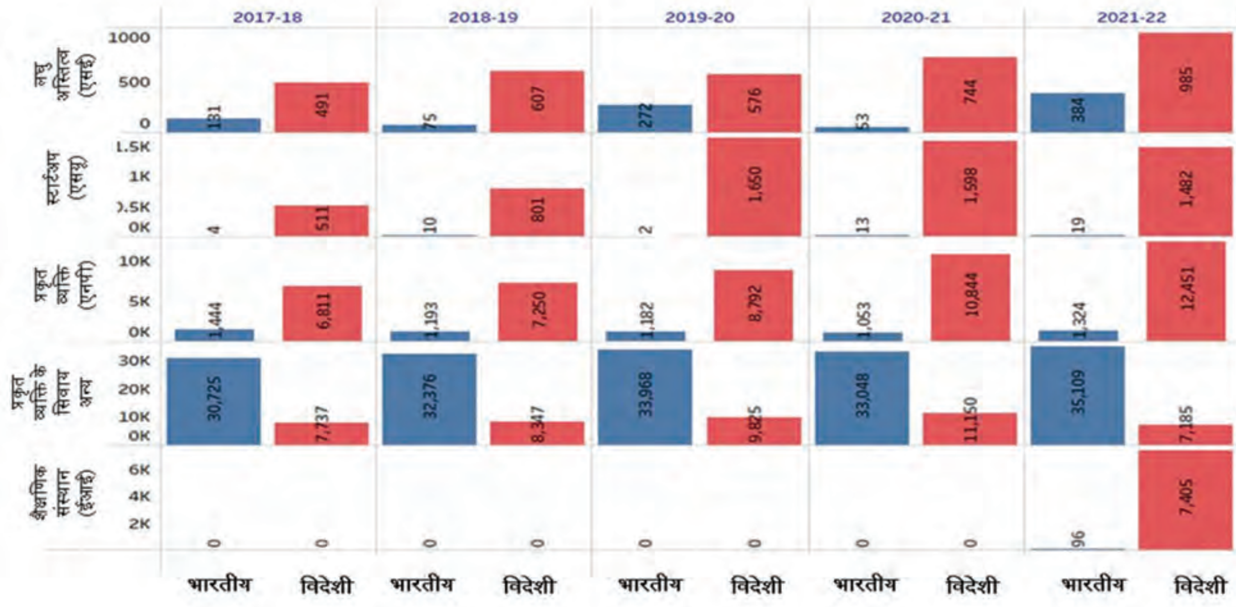

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले शीर्ष 5 भारतीय आवेदकः

क्र. सं.	कंपनी का नाम	दाखिल आवेदन
1	टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड	217
2	लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय	147
3	चंडीगढ़ विश्वविद्यालय	139
4	संस्कृति विश्वविद्यालय	115
5	जिओ (जेआईओ) प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड	110

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले शीर्ष 5 भारतीय आवेदकः

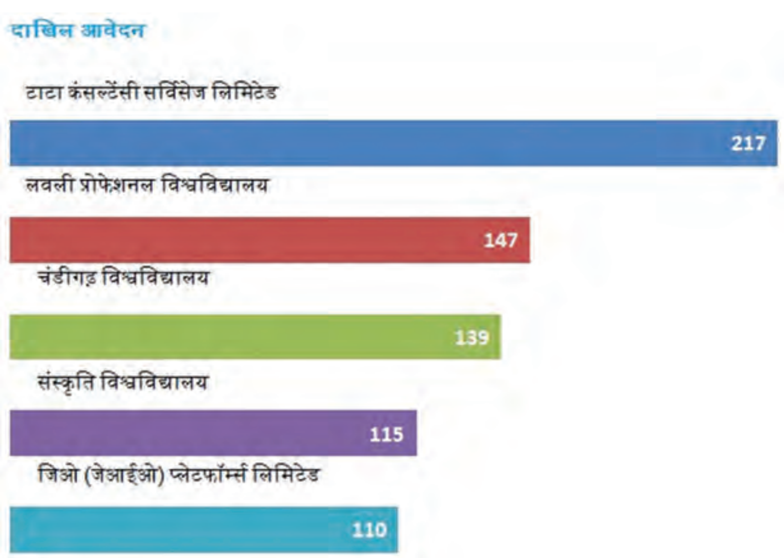

(ङ) **वैज्ञानिक अनुसंधान व विकास संस्थानों से पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले शीर्ष 10 भारतीय आवेदकः**

क्र. सं.	वैज्ञानिक अनुसंधान व विकास संस्थान का नाम	दाखिल आवेदन
1	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद	223
2	अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन	117
3	एल–टी टेक्नॉलॉजी सर्विसेज़ लिमिटेड	68
4	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	66
5	भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद	37
6	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान	36
7	सेंटर ऑफ एक्सिलेन्स इन वायरलेस टेक्नॉलॉजी	17
8	सोलारा एक्टिव फार्मा साइंसेज़ लिमिटेड	11
9	एंथम बायोसाइंसेज़ प्राइवेट लिमिटेड	10
10	जाइडस लाइफसाइंसेज़ लिमिटेड	9
10	सन फार्मा एड्वान्स्ड रिसर्च कंपनी लिमिटेड	9

वैज्ञानिक अनुसंधान व विकास संस्थानों से पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले शीर्ष 10 भारतीय आवेदकः

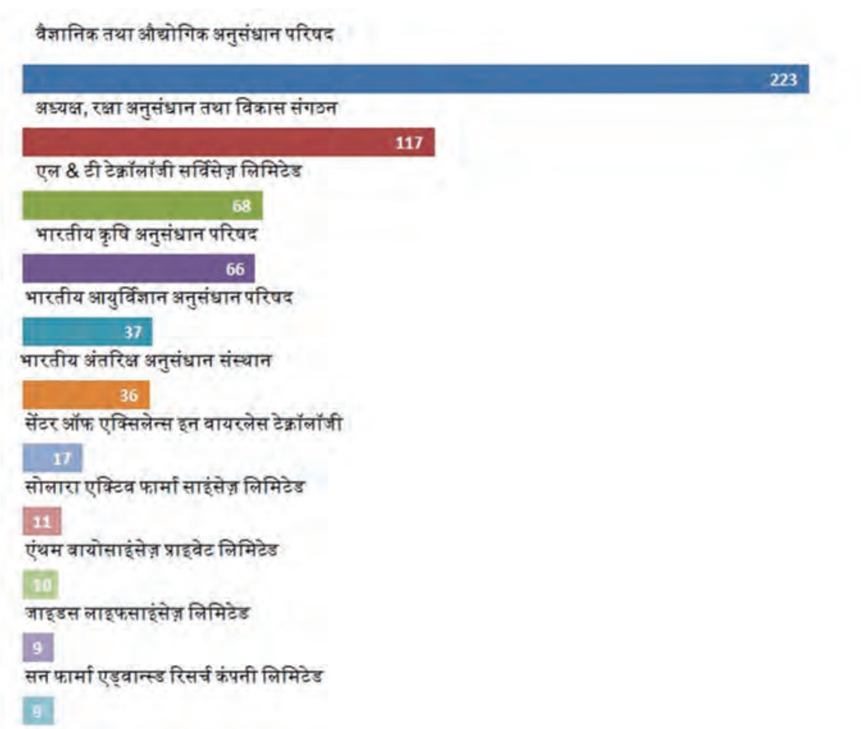

इस वर्ष वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद शीर्ष पर रहा जिसके बाद रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन का स्थान रहा। एल–टी टेक्नॉलॉजी सर्विसेज़ लिमिटेड व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद क्रमशः तीसरे व चौथे स्थान पर रहे।

(च) शैक्षिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों से पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले शीर्ष 10 भारतीय आवेदकः

क्र.सं.	संस्थानों / विश्वविद्यालयों के नाम	दाखिल आवेदन
1	संस्कृति विश्वविद्यालय	703
1	चंडीगढ़ विश्वविद्यालय	703
2	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (समेकित)	597
3	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी	529
4	चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजिस	504
5	गलगोटियास विश्वविद्यालय	417
6	तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय	404
7	शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग–टेक्नॉलॉजी (मानद विश्वविद्यालय)	224
8	अमिटी विश्वविद्यालय	203
9	शूलिनी जैव प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय	185
10	जैन (मानद विश्वविद्यालय), बैंगलौर	126
10	जीएलए विश्वविद्यालय, मथुरा	126

शैक्षिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों से पेटेंट के लिए आवेदन करने वाल शीर्ष 10 भारतीय आवेदक

इस श्रेणी में संस्कृति विश्वविद्यालय और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (समेकित) व लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर रहे, जबकि चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजिस ने गत वर्ष की तुलना में फाइलिंग में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शा कर चौथा स्थान प्राप्त किया।

2. विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनः

(क) कन्वेंशन आवेदन :

गत वर्ष के **3382** की तुलना में वर्ष के दौरान पेरिस कन्वेंशन के तहत पूर्विक्ता दावा करते हुए दाखिल आवेदनों की कुल संख्या **3212** रही। यह वर्ष के दौरान दाखिल किए गए कन्वेन्शन आवेदनों की संख्या में लगभग **5.03%** की कमी दर्शाता है।

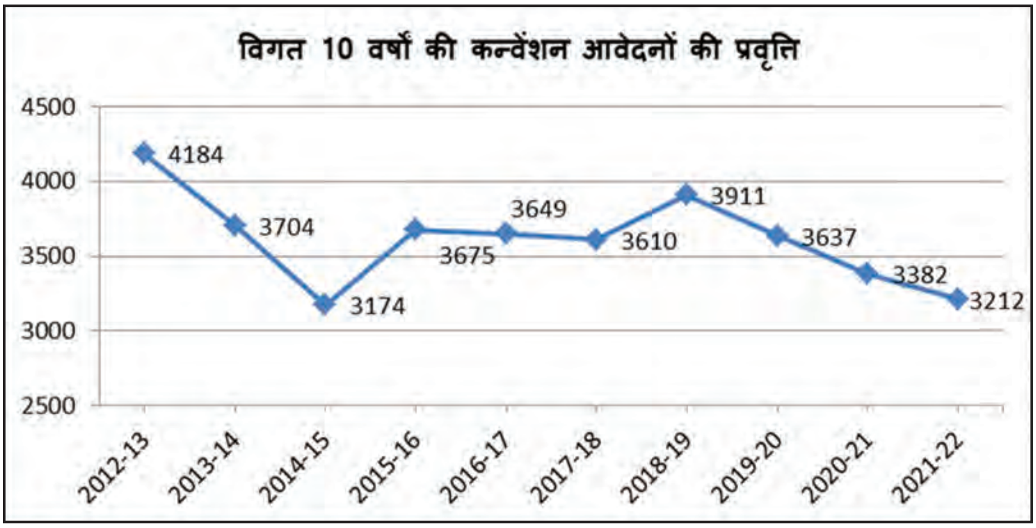

(ख) पी.सी.टी. राष्ट्रीय फेज आवेदनः

विदेश से प्राप्त आवेदनों में से अधिकांश पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) राष्ट्रीय फेज माध्यम से दाखिल किए गए। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान दाखिल ऐसे आवेदनों की संख्या **29765** रही जो विगत वर्ष की संख्या **27230** की तुलना में लगभग **9.31%** की वृद्धि दर्शाता है। आवेदन दाखिल करने वाला शीर्ष देश संयुक्त राज्य अमरीका (9612) रहा। देशानुसार विवरण **परिशिष्ट ख1** में प्रदर्शित किया गया है।

पी.सी.टी. राष्ट्रीय फेज हेतु शीर्ष आवेदक (देशानुसार)

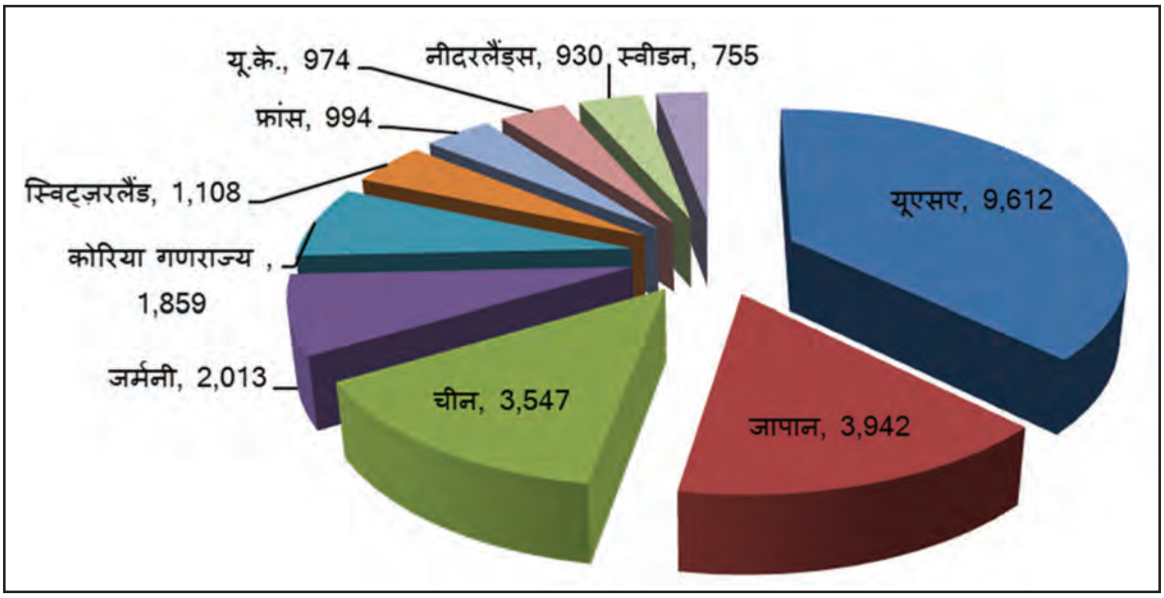

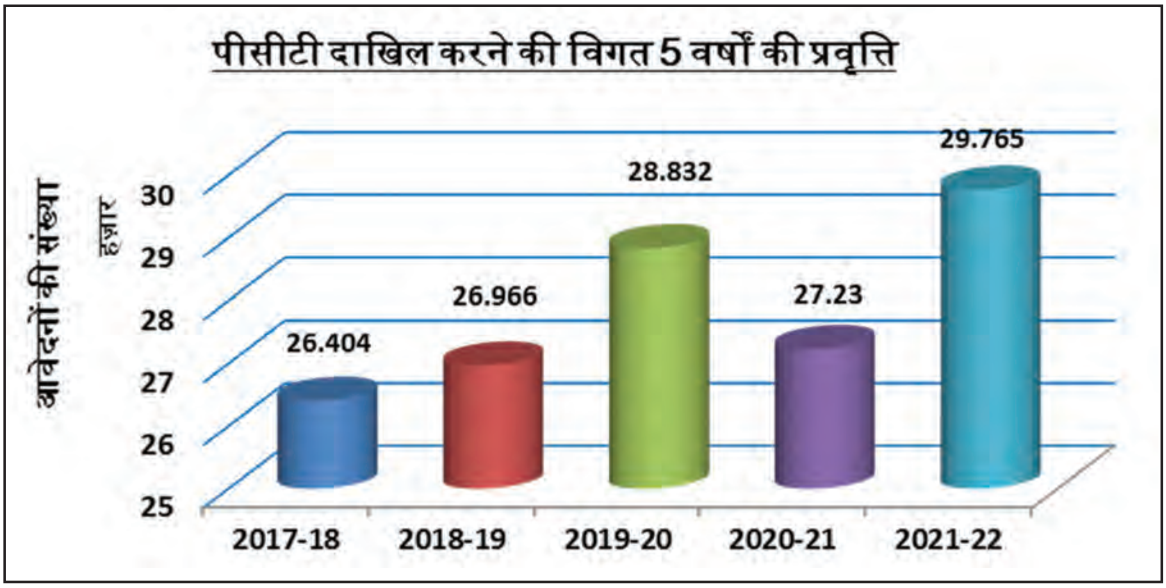

गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2021–22 के दौरान विभिन्न माध्यमों से प्राप्त पेटेंट आवेदनों का विवरण **परिशिष्ट–ख** (भारत में उद्गम राज्य के अनुसार वर्गीकृत) व **परिशिष्ट–ख1** (उद्गम देश के अनुसार वर्गीकृत) में दर्शाया गया है।

ग) शीर्ष 10 विदेशी प्रवासी आवेदक:

निम्नलिखित तालिका उन शीर्ष 10 विदेशी प्रवासी आवेदकों की सूची प्रदान करती है जिन्होंने 2021–22 के दौरान भारत में पेटेंट आवेदन दाखिल किए हैं। यह देखा गया है कि क्वालकम इंकॉरपोरेटेड इस वर्ष एक हजार छः सौ से अधिक आवेदनों के साथ इस सूची में अग्रणी रहा।

शीर्ष 10 विदेशी प्रवासी आवेदक

क्र.सं.	संगठन का नाम	आवेदनों की संख्या
1	क्वालकम इंकॉरपोरेटेड	1622
2	सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड	1294
3	हुआवि टेक्नोलॉजी क. लि	849
4	माइक्रोसॉफ्ट टेक्नॉलॉजी लाइसेंसिंग, एलएलसी	645
5	टेलेफोनाक्टिबोलागेट एलएम एरिक्सन (पीयूबीएल)	437
6	एप्पल इंक.	365
7	गुयांगोंग ओप्पो मोबाइल टेलिकम्यूनिकेशंस कॉर्प. लिमिटेड	344
8	गूगल एलएलसी	341
9	विवो मोबाइल कम्यूनिकेशन कं. लिमिटेड	293
10	एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंक.	289

शीर्ष 10 विदेशी प्रवासी आवेदक

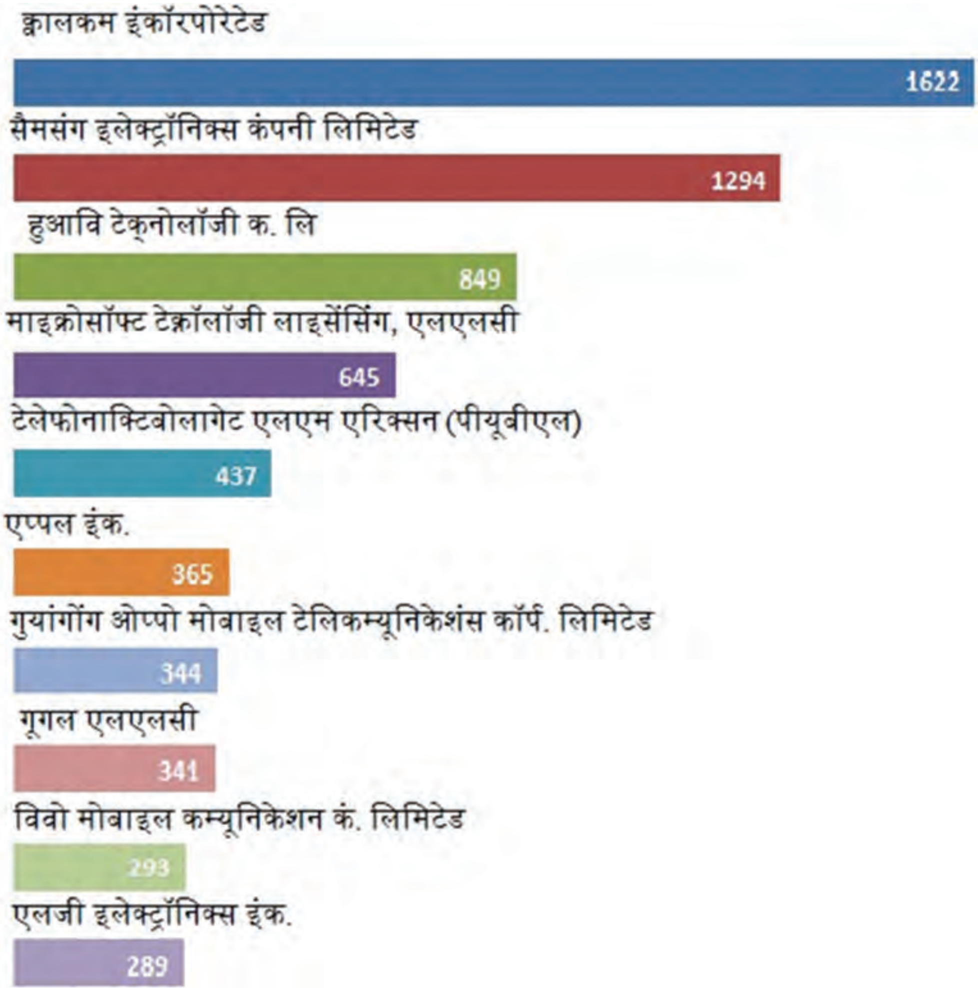

गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2021–22 के दौरान विभिन्न माध्यमों से प्राप्त पेटेंट आवेदनों का वितरण **परिशिष्ट–ख** (भारत में उद्गम राज्य के अनुसार वर्गीकृत) व **परिशिष्ट–ख1** (उद्गम देश के अनुसार वर्गीकृत) में दर्शाया गया है।

2012–13 से 2021–22 की अवधि के दौरान विभिन्न माध्यमों से भारतीय प्रवासियों एवं अप्रवासियों से प्राप्त पेटेंट आवेदनों की संख्या **परिशिष्ट–ग** में दर्शायी गई है।

विगत पाँच के दौरान रसायन, विद्युत, यांत्रिक, जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य, कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स, आदि पर विषयवार दाखिल आवेदनों का विवरण **परिशिष्ट–ङ** तथा **ङ1** में प्रदत्त सारणी द्वारा दिखाया गया है।

3. परीक्षित आवेदनों की कुल संख्या:

कार्यालय ने गत वर्ष के **73165** परीक्षित आवेदनों की तुलना में, वर्ष के दौरान **66571** आवेदनों का परीक्षण किया। यह लगभग 9% की कमी है जो मुख्य रूप से कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति और उसके लिए अपनाए गए प्रोटोकॉल के कारण थी।

4. परीक्षण हेतु अनुरोध (आरक्यू) का कुल निपटान:

गत वर्ष के **52755** की तुलना में वर्ष के दौरान **35990** परीक्षण हेतु अनुरोध (आरक्यू) का निपटान किया गया, जो 31.78% की गिरावट को दर्शाता है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समयसीमा की निर्धारित अवधि के विस्तार के कारण, धारा 21(1) के अंतर्गत **15991** आवेदनों का परित्याग आस्थगित किया गया। निपटान में अनुदानित, अस्वीकृत, धारा **21(1)** के तहत परित्यक्त व आहरित आवेदन शामिल हैं।

5. अनुदानित तथा प्रवृत्त पेटेंट:

वर्ष के दौरान अनुदानित पेटेंट की कुल संख्या **30073** रही, जिनमें से **6397** भारतीय आवेदकों को अनुदानित किए गए। वर्ष के दौरान अनुदानित पेटेंट 2020–21 के दौरान अनुदानित पेटेंट (28385) से 6% अधिक रहे।

31 मार्च 2022 तक प्रवृत्त पेटेंट की संख्या **115916** रही जिनमें से **19700** पेटेंट भारतीयों के नाम थे।

वर्ष 2012–13 से वर्ष 2021–22 की अवधि के दौरान दाखिल आवेदनों की संख्या, परीक्षण हेतु प्राप्त अनुरोधों की संख्या, परित्यक्त हुआ सा मान लिए गए आवेदन तथा पेटेंट अनुदान प्राप्त करने वाले आवेदन एवं प्रवृत्त पेटेंट की संख्या **परिशिष्ट–घ** में प्रदर्शित की गई है।

वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक के विगत पाँच वर्षों के दौरान आविष्कार के विभिन्न क्षेत्रों के तहत अनुदानित पेटेंट की संख्या **परिशिष्ट–च** व **च1** में प्रदर्शित की गई है।

6. शीघ्र परीक्षण स्थिति:

शीघ्र परीक्षण की सुविधा प्रारम्भ में स्टार्टअप और उन पेटेंट आवेदनों के लिए प्रदान की गई थी, जहां आवेदकों ने अपने संबंधित पीसीटी अंतरराष्ट्रीय आवेदनों के लिए आईएसए / आईपीईए के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय का चयन किया है। 17 सितंबर, 2019 से पेटेंट नियमों में संशोधन करके आवेदकों की 8 और श्रेणियों को इसमें शामिल कर लिया गया है। आवेदकों की नई श्रेणियों में लघु, मध्यम उद्यम, महिला आवेदक, सरकारी विभाग, केंद्रीय, प्रांतीय अथवा राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित संस्थान है, जो सरकार के स्वामित्व में है अथवा उसके द्वारा नियंत्रित है, सरकारी कंपनी, सरकार द्वारा पूर्णतः अथवा सारवान रूप से वित्तपोषित संस्थान तथा पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाइवे (पीपीएच) के अधीन दाखिल आवेदन शामिल हैं।

शीघ्र परीक्षण हेतु अनुरोधों की फाइलिंग में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है, जिसका कारण है कि इस श्रेणी के तहत आवेदनों का परीक्षण और संसाधन अतिशीघ्र किया जाता है जिससे अधिकांश मामलों में अनुदान/अंतिम निपटान, सामान्य परीक्षण मार्ग में अपेक्षित कुछ वर्षों की अवधि की तुलना में शीघ्र परीक्षण हेतु अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष के औसत समय के भीतर हो जाता है।

शीघ्र परीक्षण हेतु प्राप्त अनुरोध, परीक्षित व निपटान का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है जिसमें नई श्रेणियों को संचित रूप से "अन्य" के रूप में नामित किया गया है।

वर्ष	शीघ्र परीक्षण हेतु दाखिल अनुरोध				अनुदानित पेटेंट				अस्वीकृत			
	स्टार्ट अप	आईएसआर हेतु आवेदक	अन्य	कुल	स्टार्ट अप	आईएसआर हेतु आवेदक	अन्य	कुल	स्टार्ट अप	आईएसआर हेतु आवेदक	अन्य	कुल
2017–18	136	162	लागू नहीं	298	17	39	लागू नहीं	56	8	1	लागू नहीं	9
2018–19	294	318	लागू नहीं	612	102	187	लागू नहीं	289	34	23	लागू नहीं	57
2019–20	408	311	304	1023	189	235	5	429	53	57	0	110
2020–21	433	331	802	1566	252	212	283	747	57	48	24	129
2021–22	548	411	1554	2513	49	65	143	257	4	3	14	21
कुल	**1819**	**1533**	**2660**	**6012**	**609**	**738**	**431**	**1778**	**156**	**132**	**38**	**326**

7. भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल पीसीटी अंतर्राष्ट्रीय आवेदन:

विगत पाँच वर्षों के दौरान प्राप्तकर्ता कार्यालय (आरओ/आईएन) के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय में भारतीय आवेदकों द्वारा पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) के तहत दाखिल अंतरराष्ट्रीय आवेदनों की कुल संख्या निम्नवत है (इस संख्या में वे अंतरराष्ट्रीय आवेदन शामिल नहीं है जो भारतीय आवेदकों द्वारा सीधे वायपो के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो में प्राप्तकर्ता कार्यालय के रूप में दाखिल किए गए हैं):

वर्ष	वैयक्तिक	विधिक सत्ताधारी	कुल
2017–18	274	490	**764**
2018–19	336	630	**966**
2019–20	351	668	**1019**
2020–21	332	722	**1054**
2021–22	**331**	**866**	**1197**

2021–22 के दौरान पीसीटी अंतरराष्ट्रीय आवेदन दाखिल करने वाले प्रमुख भारतीय योगदानकर्ता थे: टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (समेकित)।

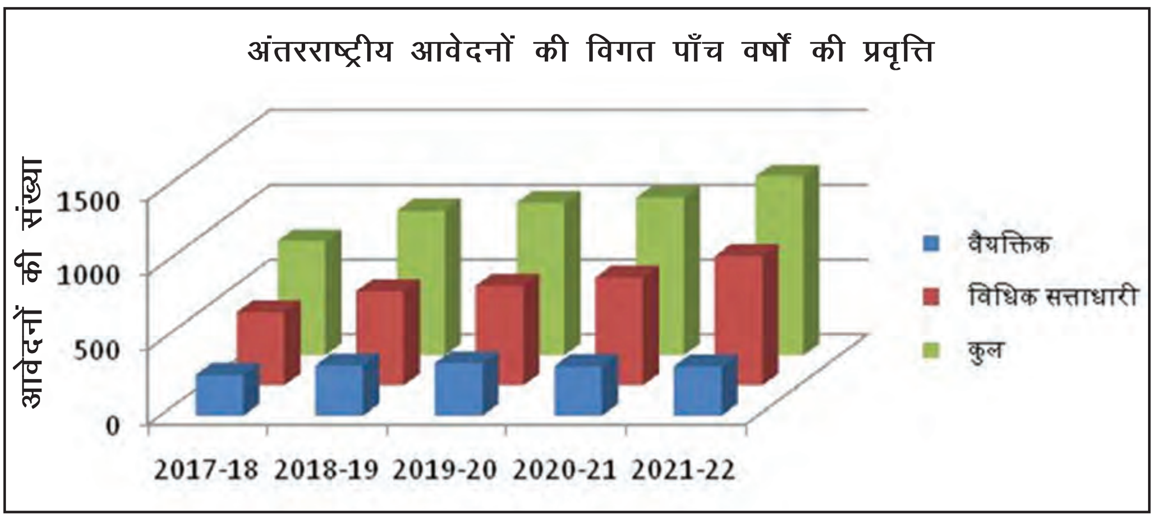

8. पेटेंट अधिनियम व नियमों के तहत विविध कार्यवाहियाँ:

(क) परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आविष्कार: वर्ष के दौरान, पेटेंट अधिनियम की धारा 4 के तहत **846** आवेदन परमाणु ऊर्जा विभाग को प्रेषित किए गए जिनमें से **10** आवेदन परमाणु ऊर्जा से संबद्ध पाए गए, जबकि **88** आवेदन सामान्य शासकीय कार्यवाही के तहत प्रक्रियागत करने के लिए अनुमत्त हुए तथा वर्ष के अंत तक शेष आवेदन परमाणु ऊर्जा विभाग के समक्ष विचारार्थ लंबित रहे।

(ख) धारा 11(क) के तहत पेटेंट आवेदनों का प्रकाशन: वर्ष 2021–22 के दौरान, पेटेंट अधिनियम की धारा 11(क) के तहत **69613** आवेदन प्रकाशित किए गए, जिनमें **14251** ऐसे आवेदन शामिल हैं जिनके लिए शीघ्र प्रकाशन हेतु अनुरोध प्राप्त किए गए थे। विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रकाशित पेटेंट आवेदनों की संख्या संबंधी वर्षानुसार विवरण निम्नवत है:

वर्ष	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
धारा 11 क के तहत प्रकाशन	43402	42281	44297	42462	55362
शीघ्र प्रकाशन	3497	4064	6526	10302	14251
कुल	**46899**	**46345**	**50823**	**52764**	**69613**

(ग) अनुदानपूर्व आपत्ति (धारा 25(1) के तहत): वर्ष के दौरान अनुदानपूर्व आपत्ति के रूप में **481** आवेदन प्राप्त हुए व **275** अनुदानपूर्व आपत्तियों का निष्पादन वर्ष के दौरान कर दिया गया।

(घ) अनुदानोत्तर आपत्ति (धारा 25(2) के तहत): वर्ष के दौरान, **37** अनुदानोत्तर आपत्तियाँ दाखिल की गईं। **8** अनुदानोत्तर आपत्तियों का निष्पादन वर्ष के दौरान कर दिया गया।

(ङ) गोपनीयता निदेश (धारा 35 के तहत): वर्ष के दौरान, **1149** पेटेंट आवेदन भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) को उन आविष्कारों के रक्षा उद्देश्य से संबद्ध होने विषयक विचार देने हेतु प्रेषित किए गए। वर्ष के दौरान, **710** आवेदनों को सामान्य कार्यवाही हेतु अनुमत्त किया गया। जहां **209** आवेदन को डीआरडीओ द्वारा आगे बढ़ने के लिए अस्वीकृत कर दिया गया, वहीं शेष आवेदन वर्ष के अंत तक डीआरडीओ के विचारार्थ प्रक्रियाधीन थे।

(च) देश से बाहर आवेदन करने की अनुमति (धारा 39 के तहत): वर्ष के दौरान, **8421** ऐसे आवेदन प्राप्त हुए जिनमें फॉर्म **25** पर भारत के बाहर पेंटेट दाखिल करने की अनुमति मांगी गई थी, जबकि **8265** आवेदनों के संबंध में अनुमति प्रदान की गई।

(छ) व्यपगत पेटेंट का प्रत्यावर्तन (धारा 60 के तहत): 2021–22 के दौरान पेटेंट के प्रत्यावर्तन के लिए **66** आवेदन प्राप्त हुए व **58** पेटेंट प्रत्यावर्तित किए गए।

(ज) समनुदेशन, मोर्गेज, लाइसेंस आदि (धारा 68 तथा 69 के तहत): इस धारा के तहत दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए **2348** मामले प्राप्त हुए व वर्ष के दौरान **2059** आवेदनों का निपटान किया गया।

(झ) जारी पेटेंट (धारा 146 के तहत): प्रतिवेदन वर्ष के दौरान फॉर्म–27 पर जारी पेटेंट के **55014** कथन प्राप्त किए गए जिनमें से **9616** पेटेंट को जारी रहने के रूप में दर्शाया गया था। विगत पाँच वर्षों के दौरान प्राप्त सूचना का विवरण निम्न सारणी में दिया गया है:

	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
प्रवृत्त पेटेंट	56764	64686	81279	98839	**115916**
प्राप्त फॉर्म–27	46618	51104	57192	58633	**55014**
जारी रहने के रूप में दर्शाया गया	12246	14277	16181	13924	**9616**

(ञ) अनिवार्य लाइसेंस (धारा 84, 92 तथा 92–क के तहत): वर्ष 2021–22 के दौरान अनिवार्य लाइसेंस के अनुदान हेतु **02** आवेदन प्राप्त हुए।

(ट) सूचना (धारा 153 के तहत): वर्ष के दौरान, पेटेंट नियम, 2003 (यथा संशोधित) के नियम 134 में यथा प्रदत्त इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत पेटेंट संबंधी सूचना की आपूर्ति के लिए पेटेंट कार्यालय को **71** अनुरोध प्राप्त हुए।

ठ) पेटेंट अभिकर्त्ताओं का पंजीकरण: वर्ष के दौरान **10** नए पेटेंट अभिकर्ताओं का पंजीकरण किया गया। 31 मार्च 2022 तक पंजीकृत पेटेंट अभिकर्त्ताओं की कुल संख्या **3347** रही।

9. राजस्वः

पेटेंट कार्यालय ने अधिनियम और नियमों के तहत विभिन्न कार्यवाहियों के लिए शुल्क के माध्यम से लगभग **रु. 667 करोड़** का राजस्व अर्जित किया। पेटेंट पर एकत्रित शुल्क का विवरण **परिशिष्ठ–छ** में दिया गया है।

10. सामान्य सूचनाः

पेटेंट कार्यालय, कोलकाता, मुम्बई, दिल्ली एवं चेन्नई के वैज्ञानिक तथा तकनीकी पुस्तकालय जनता को परामर्श तथा संदर्भ कार्य के लिए सुविधा प्रदान करते रहे। इन सुविधाओं का विभिन्न अनुसंधान व औद्योगिक संस्थानों के आविष्कारक तथा अन्य जनता के साथ–साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनुसंधानरत विद्वानों ने उपयोग किया।

वर्तमान में पेटेंट कार्यालय, सीडी–रोम्स, पुस्तकों और जर्नल के अतिरिक्त वैज्ञानिक और तकनीकी ई–जर्नल प्राप्त करता है। भारत और विदेश के पेटेंट कार्यालयों के पेटेंट विनिर्देश और अन्य प्रकाशनों के माध्यम से खोज संचालित करने हेतु हजारों लोग पेटेंट कार्यालय के पुस्तकालयों में आते हैं।

पेटेंट कार्यालय द्वारा अपनी वेबसाइट www.ipindia.nic.in पर प्रदत्त निःशुल्क ऑनलाइन इंटरनेट खोज सुविधा का हितधारकों और सर्वसाधारण ने भी व्यापक लाभ उठाया।

11. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचनाः

वर्ष के दौरान, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध कराने के लिए **2392** अनुरोध प्राप्त किए गए। अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार समय सीमा के भीतर 2229 अनुरोधों का निपटान किया गया और **23** को सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को स्थानांतरित कर दिया गया।

परिशिष्ट–क

परीक्षक एकस्व का विषयवार वितरण

क्र.सं.	विषय	परीक्षकों की संख्या
1	जैव रसायन	8
2	जैव प्रौद्योगिकी	22
3	जैव चिकित्सा अभियंत्रणा	20
4	रसायन	111
5	सिविल अभियंत्रणा	9
6	कम्प्यूटर एवं आई टी अभियंत्रणा	59
7	वैद्युतिक व इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रणा	165
8	खाद्य प्रौद्योगिकी	5
9	यांत्रिकी अभियंत्रणा	125
10	धातुकर्म अभियंत्रणा	12
11	भौतिकी	43
12	पॉलीमर	18
13	वस्त्र	6
	कुल	**603**

परिशिष्ट ख

उद्गम राज्य के अनुसार वर्ष 2020–21 की तुलना में 2021–22 में दाखिल किए गए पेटेंट आवेदन

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	साधारण आवेदन		कन्वेंशन आवेदन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2021–22	2020–21	2021–22	2020–21	2021–22	2020–21
अंडमान–निकोबार	1	3	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	934	708	0	0	0	1
अरुणाचल प्रदेश	23	18	0	0	0	0
असम	150	96	0	0	0	0
बिहार	80	62	0	0	0	0
चंडीगढ़	347	311	0	0	1	0
छत्तीसगढ़	120	80	0	0	0	0
दादरा और नागर हवेली	1	2	0	0	0	0
दादरा और नागर हवेली और दमन–दीव	1	3	0	0	0	0
दमन–दीव	5	1	0	0	0	0
दिल्ली	1657	1585	2	11	14	12
गोवा	46	37	1	0	0	0
गुजरात	1045	906	1	3	21	12
हरियाणा	996	744	0	14	2	7
हिमाचल प्रदेश	268	144	0	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	93	87	0	0	0	0
झारखंड	225	196	0	3	0	0
कर्नाटक	3171	2744	18	2	33	38
केरल	453	426	0	0	1	0
लक्षद्वीप	0	1	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	488	395	0	1	0	2
महाराष्ट्र	4508	4136	10	9	48	69
मणिपुर	11	6	0	0	1	0
मेघालय	26	9	0	0	0	0
मिजोरम	8	12	0	0	0	0
नागालैंड	6	4	0	0	0	0
उड़ीसा	327	377	1	0	0	0
पुडुचेरी	61	139	0	0	0	0
पंजाब	2197	1649	0	0	0	1
राजस्थान	452	434	0	1	13	14
सिक्किम	9	11	0	0	0	0

तमिलनाडु	5206	3926	49	9	7	10
तेलगांना	1724	1643	3	4	23	15
त्रिपुरा	12	13	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	3613	2310	1	2	8	5
उत्तराखंड	533	355	0	0	0	1
पश्चिम बंगाल	449	505	1	0	3	0
लागू नहीं	0	1	0	0	0	1
कुल	**29246**	**24079**	**87**	**59**	**175**	**188**

परिशिष्ट–ख 1

वर्ष 2020–21 की तुलना में 2021–22 में दाखिल उद्गम देश के अनुसार वर्गीकृत पेटेंट आवेदन

राष्ट्रमंडल देश	साधारण आवेदन		कन्वेंशन आवेदन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2021–22	2020–21	2021–22	2020–21	2021–22	2020–21
यू.के.	60	69	38	55	974	841
ऑस्ट्रेलिया	8	8	13	9	296	256
कनाडा	40	28	35	22	378	300
श्रीलंका	0	2	0	0	1	3
आयरलैंड	109	120	66	48	110	80
न्यूजीलैंड	1	4	0	2	62	37
समोआ	0	1	0	0	0	0
फ़िजी	0	0	0	0	1	0
पापुआ न्यू ग्युना	3	0	0	0	0	0
कुल	**221**	**232**	**152**	**136**	**1822**	**1517**

उत्तर व दक्षिण अमेरिका

देश	साधारण आवेदन		कन्वेंशन आवेदन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2021–22	2020–21	2021–22	2020–21	2021–22	2020–21
यू.एस.ए.	1770	1708	705	548	9612	8231
मैक्सिको	0	0	0	0	25	36
ब्राजील	3	0	5	2	67	47
बरमूडा	0	0	0	0	7	4
केमन आइलैंड	11	5	22	1	20	81
वर्जिन आइलैंड्स	0	0	0	0	2	2
क्यूबा	0	0	0	0	3	4
कोलंबिया	0	0	0	0	4	3
अर्जेन्टीना	1	0	0	0	5	1

चिली	1	8	0	2	11	11
बहामास	0	0	0	0	5	1
बारबाडोस	7	1	1	1	7	5
पेरु	6	0	0	0	2	2
उरुग्वे	0	0	0	0	3	2
कोस्टा रीका	0	0	0	0	0	1
पनामा	0	0	0	0	1	1
सेंट किट्स एंड नेविस	0	0	0	0	1	5
उत्तर और दक्षिण अमरीका के अन्य देश	3	0	0	0	47	37
कुल	**1802**	**1722**	**733**	**554**	**9822**	**8474**

परिशिष्ट–ख1 (जारी)

यूरोप

देश	साधारण आवेदन		कन्वेंशन आवेदन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2021–22	2020–21	2021–22	2020–21	2021–22	2020–21
ऑस्ट्रीया	4	0	18	8	241	230
बेलारूस	0	0	0	0	2	1
बेल्जियम	7	1	6	4	253	254
ब्रिटिश आइल्स	0	0	0	0	0	1
बुल्गारिया	4	2	1	1	3	6
चैनल आइलेंड	3	3	0	0	0	1
साइप्रस	0	0	0	0	7	8
चेक गणराज्य	5	3	2	3	27	15
डेनमार्क	18	21	11	23	339	327
इस्टोनिया	0	0	0	0	5	2
फ़िनलैंड	125	103	48	56	293	297
फ़्रांस	56	69	136	119	994	857
जर्मनी	339	316	329	326	2013	1947
गिबरालतार	0	0	0	0	0	1
ग्रीस	0	0	0	1	19	14
हॉलैंड	2	6	0	0	0	0
हंगरी	0	0	0	2	17	18
आइस लैंड	0	0	0	0	5	2
इटली	9	8	54	80	493	468
लातविया	0	0	0	0	1	0

लिक्टन्स्टाइन	0	0	0	3	10	10
लग्जमबर्ग	0	2	12	11	96	98
माल्टा	0	0	0	0	5	4
मोनाको	0	0	0	0	4	5
नीदरलैंड्स	78	73	7	14	930	907
नार्वे	5	2	0	2	89	92
पोलैंड	1	0	5	2	40	39
पुर्तगाल	0	0	0	1	18	22
रोमानिया	0	0	0	0	8	2
रूस	0	1	10	4	91	51
स्लोवाकिया	0	0	0	1	5	3
स्लोवेनिया	0	0	2	0	3	5
स्पेन	3	3	49	33	161	123
स्वीडन	40	20	18	21	755	696
स्विट्जरलैंड	138	138	88	114	1108	832
तुर्की	0	0	0	3	40	30
यूक्रेन	0	0	0	0	8	6
अन्य यूरोपीय देश और यूरोपीय संघ	11	3	0	1	17	18
कुल	**848**	**774**	**796**	**833**	**8100**	**7392**

परिशिष्ट–ख1 जारी

अफ्रीका

देश	**साधारण आवेदन**		**कन्वेंशन आवेदन**		**राष्ट्रीय फेज आवेदन**	
	2021–22	**2020–21**	**2021–22**	**2020–21**	**2021–22**	**2020–21**
दक्षिण अफ्रीका	1	2	0	1	28	30
मॉरिशस	14	9	0	2	2	0
सेशल्स	0	0	0	0	1	0
स्वाजीलैंड	0	0	0	0	2	0
कीनिया	0	0	0	0	0	2
इजिप्ट	1	0	0	0	4	8
मोरक्को	1	1	2	0	4	3
अन्य अफ्रीकी देश	15	10	0	0	4	5
कुल	**32**	**22**	**2**	**3**	**45**	**48**

एशिया

देश	साधारण आवेदन		कन्वेंशन आवेदन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2021–22	2020–21	2021–22	2020–21	2021–22	2020–21
बाहरीन	2	1	0	0	0	0
चीन	73	36	240	345	3547	3727
हाँग–काँग(चीन)	3	4	9	3	14	21
इंडोनेशिया	1	0	1	0	1	0
ईरान	0	0	0	0	7	3
इजराइल	17	8	8	13	344	335
जापान	100	72	791	948	3942	3762
जॉर्डन	2	0	0	0	1	1
कुवैत	1	0	0	0	1	0
कजाखिस्तान	0	0	0	0	0	3
मलेशिया	4	4	9	9	18	19
नेपाल	0	1	0	0	0	0
ओमान	16	6	0	0	1	2
फिलीपींस	0	1	0	0	4	2
कोरिया गणराज्य	733	608	236	304	1859	1664
सउदी अरब	24	6	1	1	4	28
सिंगापुर	25	35	12	14	178	156
ताइवान	22	23	221	216	20	28
थाइलैंड	5	5	1	2	12	18
यू.ए.ई	9	5	0	0	15	23
उज्बेकिस्तान	1	0	0	0	0	0
वियतनाम	0	0	0	0	5	2
अन्य एशियाई देश	14	0	0	0	3	5
कुल	**1052**	**815**	**1529**	**1855**	**9976**	**9799**
कुल योग	**33201**	**27644**	**3299**	**3441**	**29940**	**27418**

पिछले 10 वर्षों में प्रवासी और भारत में रहने वाले द्वारा विभिन्न माध्यमों से दाखिल आवेदन

आवेदक	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
भारत में रहने वाले	9911	10941	12071	13066	13219	15550	17005	20843	24326	**29508**
प्रवासी										
साधारण	1144	1228	1461	1915	2084	2290	2777	3156	3565	**3955**
कन्वेंशन	4184	3704	3174	3675	3649	3610	3911	3637	3382	**3212**
पीसीटी के तहत राष्ट्रीय फेज आवेदन	28435	27078	26057	28248	26492	26404	26966	28832	27230	**29765**
कुल योग	**43674**	**42951**	**42763**	**46904**	**45444**	**47854**	**50659**	**56468**	**58503**	**66440**

वर्ष 2012–13 से 2021–22 तक की अवधि के दौरान पेटेंट संबंधी विविध सूचना

वर्ष	दाखिल आवेदनों की संख्या	परीक्षण हेतु अनुरोधों की नहीं संख्या	पूर्ण विनिर्देश दाखिल करने के कारण परित्यक्त मान लिए गए आवेदनों की संख्या धारा 9 (1)	धारा 21 (1) के तहत अननुपालन के कारण परित्यक्त समझे गए आवेदनों की कुल संख्या	अनुदत्त पेटेंट की संख्या		प्रवृत्त पेटेंट की संख्या	
					भारतीय पेटेंटी	विदेशी पेटेंटी	भारतीय पेटेंटी	विदेशी पेटेंटी
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
2012–13	43674	36247	361	4559	716	3410	8308	35612
2013–14	42951	37474	224	6418	634	3592	7464	35168
2014–15	42763	34958	12	6970	684	5294	7561	35695
2015–16	46904	35960	1226	12782	918	5408	7306	37218
2016–17	45444	38578	4357	10408	1315	8532	7660	41105
2017–18	47854	37208	184	24992	1937	11108	8830	47934
2018–19	50659	38665	3779	30458	2511	12772	9787	54899
2019–20	56267	42007	3761	23291	4003	20933	12181	69098
2020–21	58503	42196	295	17944	5629	22756	15687	83211
2021–22	**66440**	**46230**	**0**	**1**	**6397**	**23676**	**19700**	**96216**

परिशिष्ट–ङ

आविष्कार के प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत 2017–18 से 2021–22 तक दाखिल पेटेंट आवेदनों की संख्या

आविष्कार का क्षेत्र / वर्ष	रसायन	औषध	पॉलीमर व विज्ञान प्रौद्योगिकी	कंप्यूटर विज्ञान व इलेक्ट्रॉनिक्स	संचार	वैद्युतिक	भौतिकी	जैव चिकित्सा	यांत्रिकी अभियंत्रणा	अन्य क्षेत्र (परिशिष्ट–ङ1 देखें)	कुल
2017–18	6343	2741	1116	6089	5486	4278	2996	1095	11573	6137	47854
2018–19	6560	2683	1100	5540	6308	4703	3659	812	12414	6880	50659
2019–20	5198	5622	1309	11126	6862	4587	2646	3508	10359	5050	56267
2020–21	8809	80	1508	11930	6660	3743	2842	4911	10540	7480	58503
2021–22	**5173**	**5179**	**858**	**15575**	**7314**	**4286**	**3007**	**5288**	**11969**	**7791**	**66440**

परिशिष्ट–ङ 1

आविष्कार के अन्य विविध क्षेत्रों के अंतर्गत 2017–18 से 2021–22 तक दाखिल पेटेंट आवेदनों की संख्या

आविष्कार का क्षेत्र / वर्ष	जैव–प्रौद्योगिकी	जैव–रसायन	खाद्य	माइक्रो–बायोलॉजी	धातुकर्म व सामग्री	वस्त्र	सिविल	सामान्य अभियंत्रणा	एग्रो–केमिकल्स	कृषि विज्ञान अभियंत्रणा	पारंपरिक ज्ञान
2017–18	992	331	344	297	713	795	779	1032	429	338	87
2018–19	882	282	430	301	734	881	956	1537	392	411	74
2019–20	1065	442	1111	17	836	693	816	27	19	13	11
2020–21	3368	820	617	0	870	900	827	31	3	11	6
2021–22	**3530**	**906**	**690**	**1**	**1004**	**793**	**866**	**0**	**1**	**0**	**0**

परिशिष्ट–च

आविष्कार के प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक अनुदानित पेटेंट की संख्या

आविष्कार का क्षेत्र / वर्ष	रसायन	औषध	पॉलीमर व विज्ञान प्रौद्योगिकी	कंप्यूटर विज्ञान व इलेक्ट्रॉनिक्स	संचार	वैद्युतिक	भौतिकी	जैव चिकित्सा	यांत्रिकी अभियंत्रणा	अन्य क्षेत्र (परिशिष्ट–च1 देखें)	कुल
2017–18	3376	733	747	1028	1031	818	568	150	2514	2080	13045
2018–19	4242	761	701	1074	1414	1253	703	290	2857	1988	15283
2019–20	4848	1930	923	2141	2692	2451	1349	565	5301	2736	24936
2020–21	6074	1264	1745	2049	2857	2637	1396	703	6348	3312	28385
2021–22	**4279**	**3317**	**893**	**2459**	**3238**	**3084**	**1609**	**982**	**6832**	**3380**	**30073**

परिशिष्ट–च 1

आविष्कार के अन्य विविध क्षेत्रों के अंतर्गत 2017–18 से 2021–22 तक अनुदानित पेटेंट की संख्या

आविष्कार का क्षेत्र / वर्ष	जैव–प्रौद्योगिकी	जैव–रसायन	खाद्य	माइक्रो–बायोलॉजी	धातुकर्म व सामग्री	वस्त्र	सिविल	सामान्य अभियंत्रणा	एग्रो–केमिकल्स	कृषि विज्ञान अभियंत्रणा
2017–18	546	142	106	108	429	179	124	297	125	24
2018–19	457	161	76	104	272	212	155	303	215	33
2019–20	357	188	114	152	363	493	280	446	289	54
2020–21	574	236	169	151	634	443	412	378	236	79
2021–22	**611**	**232**	**234**	**140**	**571**	**430**	**464**	**420**	**170**	**108**

अधिनियम व नियम के तहत विभिन्न कार्यवाहियों के संदर्भ में वर्ष 2021–22 के दौरान प्राप्त शुल्क

क्र. सं.	एकत्रित शुल्क का संदर्भ	प्राप्त कुल राशि (रु.)
1	1–अनंतिम/पूर्ण विनिर्देश के साथ पेटेंट के लिए नया आवेदन पृष्ठों व दावों की संख्या का निरीक्षण	2,14,58,29,160.00
2	2–अनंतिम विनिर्देश के बाद पूर्ण–फॉर्म 2 पृष्ठों व दावों की संख्या का निरीक्षण	3,20,01,500.00
3	4(i)–धारा 53(2) व 142(4), नियम 13(6), 80(1क) व 130 के अंतर्गत समय विस्तार हेतु अनुरोध पर–फॉर्म 4	65,63,820.00
4	4(ii)–नियम 24 ख के उपनियम (5) के अंतर्गत समय विस्तार हेतु अनुरोध पर–फॉर्म 4	5,35,52,000.00
5	6–उत्तर दिनांकन के लिए आवेदन	13,78,400.00
6	8(i)–आवेदक का प्रतिस्थापन/ परिवर्तन–फॉर्म 6	1,40,64,640.00
7	8(ii)–उत्तरजीवी / अन्य पक्ष के नाम पर कार्यवाही करने का अनुरोध	26,400.00
8	9–विरोध की सूचना–फॉर्म 7 (अनुदानोत्तर)	3,19,400.00
9	10–सुनवाई में उपस्थिति हेतु सूचना–कोई फॉर्म नहीं	1,44,000.00
10	11–किसी पेटेंट में आविष्कारक के रूप में उल्लेख–फॉर्म 8	53,31,840.00
11	12–शीघ्र प्रकाशन हेतु अनुरोध–फॉर्म 9	5,24,67,100.00
12	पेटेंट का नवीकरण	3,19,59,10,980.00
13	18(i)–अनुदान पूर्व आवेदन का संशोधन–फॉर्म 13	3,89,07,840.00
14	18(ii)–अनुदानोत्तर आवेदन का संशोधन–फॉर्म 13	6,75,350.00
15	18(iii)–नाम/पता/राष्ट्रीयता/सेवार्थ पते में संशोधन–फॉर्म 13	1,75,98,880.00
16	19–संशोधन/प्रत्यावर्तन/परित्याग का विरोध–फॉर्म 14	14,400.00
17	20–पेटेंट का प्रत्यावर्तन–फॉर्म 15	6,40,850.00
18	21–प्रत्यावर्तन हेतु अतिरिक्त शुल्क	10,88,700.00
19	22–पेटेंट परित्याग का प्रस्ताव	5,000.00
20	24–पेटेंट रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए–फॉर्म 16	1,82,61,250.00
21	25–पेटेंट रजिस्टर में प्रविष्टि के बदलाव के लिए	51,12,960.00
22	26–अतिरिक्त सेवार्थ पते की प्रविष्टि हेतु	69,600.00
23	27–अनिवार्य लाइसेन्स हेतु आवेदन–फॉर्म 17	24,000.00
24	28(i)–18 महीने के प्रकाशन के उपरांत परीक्षण हेतु अनुरोध–फॉर्म 18	72,71,34,400.00
25	28(ii)–त्वरित परीक्षण हेतु अनुरोध–फॉर्म 18	2,42,36,800.00

26	32—पेटेंट अभिकर्ता के रूप में पंजीकरण—फॉर्म 22	30,300.00
27	33—अभिकर्ता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अनुरोध	52,11,200.00
28	34(i)—रजिस्टर में अभिकर्ता नाम जारी रखना—प्रथम वर्ष	7,600.00
29	34(ii)—रजिस्टर में अभिकर्ता नाम जारी रखना—द्वितीय वर्ष से	27,19,600.00
30	35—पेटेंट अभिकर्ता के लिए अनुलिपि प्रमाण पत्र	4,950.00
31	36—रजिस्टर में अभिकर्ता के नाम का प्रत्यावर्तन—फॉर्म 23	1,38,750.00
32	37—लिपिकीय त्रुटियों का सुधार	24,16,800.00
33	38—नियंत्रक के निर्णय की समीक्षा हेतु आवेदन—फॉर्म 24	13,52,750.00
34	39—भारत के बाहर पेटेंट आवेदन करने हेतु अनुमति—फॉर्म 25	3,13,28,250.00
35	40—प्रतिलिपि पेटेंट हेतु आवेदन (एलपी)	24,000.00
36	41—धारा 72 के अधीन सत्यापित प्रति अथवा धारा 147 व नियम 133(1) के अधीन प्रमाण पत्र	1,55,59,070.00
37	42—कार्यालय प्रतियों के प्रमाणन हेतु, प्रत्येक मुद्रण	22,400.00
38	43—रजिस्टर की जांच हेतु अनुरोध	14,400.00
39	44—सूचना हेतु अनुरोध	1,49,280.00
40	45—पेटेंट अभिकर्ता के प्राधिकरण का फॉर्म—फॉर्म 26	800.00
41	46—पूर्विक्ता दस्तावेज़ दाखिल करने में देरी/अनियमितता ठीक करने/देरी ठीक करने हेतु याचिका—फॉर्म 26	16,85,12,250.00
42	47—दस्तावेज़ की छायाप्रति की आपूर्ती	16,376.00
43	48—अंतरराष्ट्रीय आवेदन हेतु पारेषण शुल्क	12,46,700.00
44	49—पूर्विक्ता दस्तावेज़ की सत्यापित प्रति तैयार करना	79,800.00
45	विविध—फॉर्म 30	89,645.00
46	गैर राजस्व	6,00,402.00
47	सूचना का अधिकार	400.00
48	4(iii) नियम 24(ग) के उप नियम 11 के अंतर्गत समय के विस्तार हेतु अनुरोध—फॉर्म 4	2,14,000.00
49	नियम 24 ख के अधीन परीक्षण हेतु अनुरोध का शीघ्र परीक्षण में परिवर्तन—फॉर्म 18 क	3,02,76,000.00
50	नियम 129 क के अंतर्गत सुनवाई के स्थगन हेतु अनुरोध	2,23,37,400.00
51	धारा 72 के अधीन सत्यापित प्रतियाँ अथवा धारा 147 व नियम 133 (2) के अंतर्गत प्रमाण पत्र	62,48,730.00
52	आवेदक के प्रकार में परिवर्तन से संबन्धित बकाया शुल्क	1,12,77,172.00
53	दावे, पृष्ठ, संशोधन के उपरांत सीक्वेंस लिस्टिंग में वृद्धि से संबन्धित शुल्क	2,70,63,644.00

54	1. विरोधी का लिखित कथन एवं साक्ष्य (चौथी अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 6 में देय शुल्क)/2. हलफ़नामा (चौथी अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 6 में देय शुल्क)	8,000.00
55	1. पेटेंटी का लिखित कथन एवं साक्ष्य (चौथी अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 6 में देय शुल्क)/2. हलफ़नामा (चौथी अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 6 में देय शुल्क)	25,000.00
56	कार्यालय कार्रवाई का उत्तर (अनिवार्य)	10,97,502.00
57	गैर राजस्व (वेतन गैर–योजना)	1,27,249.00
58	गैर राजस्व (चिकित्सा)	1,51,029.00
59	गैर राजस्व (कार्यालय व्यय गैर–योजना)	4,599.00
60	अन्य प्राप्ति	54,094.00
61	विविध–फॉर्म 30 (नियम 6(6) के अधीन याचिका)	25,383.00
62	कार्यालय कार्रवाई का उत्तर (अनिवार्य)	10.00
63	गैर राजस्व (सामान्य भविष्य निधि)	2,80,000.00
	कुल	**6,67,00,74,805.00**

पेटेंट सहयोग संधि

परिचय

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रशासित पेटेंट सहयोग संधि सदस्य देशों के आवेदकों को 153 देशों में पेटेंट अनुदान हेतु एकल अंतरराष्ट्रीय आवेदन दाखिल करने की सुविधा प्रदान करता है। इसका एक और लाभ यह है कि यह प्रत्येक देश में राष्ट्रीय चरण में प्रवेश करने से पूर्व अंतरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट (आईएसआर) और वैकल्पिक रूप से अंतरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण रिपोर्ट (आईपीईआर) प्रदान करता है। आईएसआर और आईपीईआर को विश्व के पेटेंट कार्यालयों में से एक द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विनियमित मानकों के अनुसार स्थापित किया जाता है, जो पेटेंट आवेदनों की जांच करने में अत्यधिक अनुभवी है और जिसे विशेष रूप से वाइपो द्वारा अंतरराष्ट्रीय खोज और प्रारंभिक परीक्षण के लिए नियुक्त किया गया है। भारतीय पेटेंट कार्यालय को पीसीटी के तहत अंतरराष्ट्रीय खोज प्राधिकारी (आईएसए) और अंतरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकारी (आईपीईए) नियुक्त किया गया है।

1. पीसीटी के तहत प्राप्तकर्ता कार्यालय के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय :

प्रवासी या भारत का नागरिक पीसीटी के तहत भारतीय पेटेंट कार्यालय के माध्यम से प्राप्तकर्ता कार्यालय (आरओ/आईएन) अथवा वाइपो के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो के माध्यम से प्राप्तकर्ता कार्यालय (आरओ/आईबी) के रूप में अंतरराष्ट्रीय आवेदन दाखिल कर सकता है।

(क) आरओ/आईएन और आरओ/आईबी के माध्यम से भारत के नागरिकों / प्रवासियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय आवेदन दाखिल करने की प्रवृत्तिः

वर्ष	आरओ/आईएन		कुल	आरओ/आईबी		कुल	कुल योग (आरओ/आईएन व आरओ/आईबी)
	आवेदक का प्रकार			आवेदक का प्रकार			
	वैयक्तिक	विधिक सत्ताधारी		वैयक्तिक	विधिक सत्ताधारी		
2017–18	274	490	765	360	577	937	1701
2018–19	336	630	966	503	558	1061	2027
2019–20	351	668	1019	325	540	865	1884
2020–21	312	652	964	339	512	851	1815
2021–22	**295**	**680**	**975**	**378**	**580**	**958**	**1933**

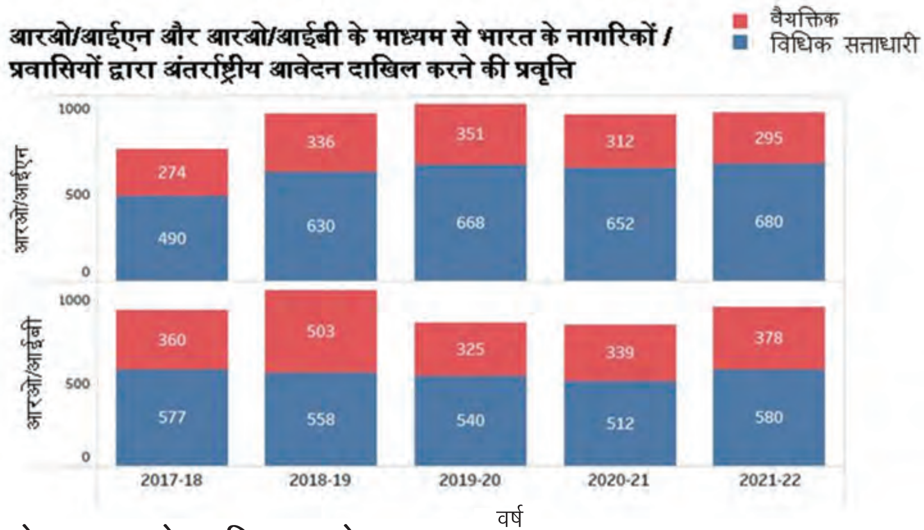

ख)   ईपीसीटी के माध्यम से दाखिल आवेदनः

आरओ/आईएन, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता के पेटेंट कार्यालयों के काउंटर पर अथवा वायपो द्वारा प्रस्तुत ईपीसीटी फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है। आरओ/आईबी के माध्यम से भी कागज पर या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईपीसीटी का उपयोग करके आवेदन दाखिल किया जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईपीसीटी के माध्यम से आरओ/आईएन में दाखिल अंतर्राष्ट्रीय आवेदनः

वर्ष	संख्या	आरओ/आईएन में कुल दाखिल का प्रतिशत
2017—2018	669	88%
2018—2019	916	95%
2019—2020	976	98%
2020—2021	951	98.6%
2021—2022	**971**	**99.58%**

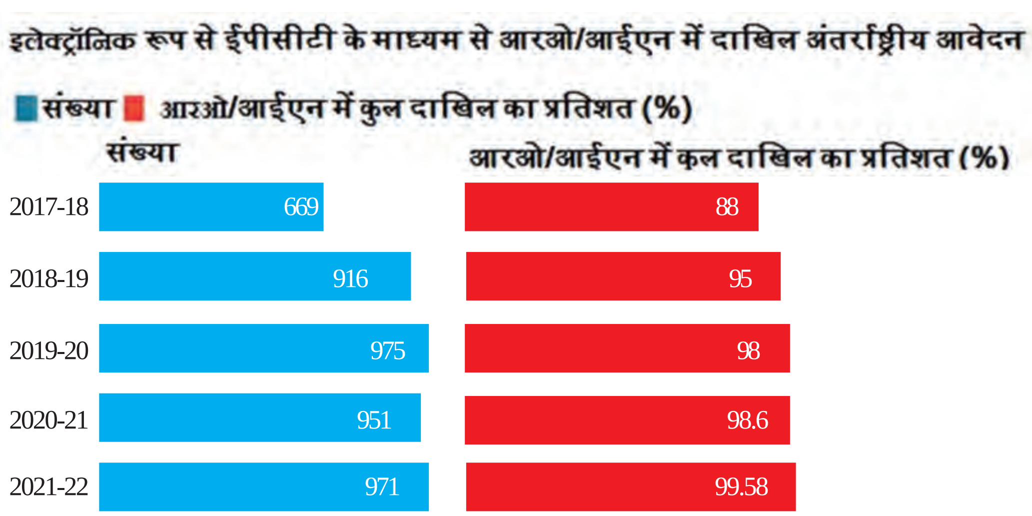

ग) इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही व समयबद्धता:

आरओ/आईएन अंतरराष्ट्रीय आवेदनों पर आगे की कार्यवाही के लिए ईपीसीटी का उपयोग करता है और ईपीसीटी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड प्रतियां और खोज प्रतियां प्रेषित करता है। अप्रैल 2017 से इन कार्यों को आईपीओ दिल्ली में केंद्रीकृत किया गया है। ईसर्च प्रतियां आरओ/आईएन द्वारा 8 में से 7 आईएसए को प्रेषित की जाती हैं जिन्हें भारतीय आवेदकों के लिए सक्षम घोषित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय फाइलिंग तिथि से 4 सप्ताह की निर्धारित समय सीमा के भीतर वायपो के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो में रिकॉर्ड प्रतियां भेजने में समयबद्धता को 2019–20, 2020–21 और 2021–22 में 100% कायम रखा गया।

2021–22 में भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल 10 शीर्ष पीसीटी (आरओ/आईएन)

क्र. सं.	आवेदक का नाम	कुल फाइलिंग
1	टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड	80
2	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शोध संस्थान	43
3	भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान	40
4	टेलीफोनैक्टीबोलगेट एलएम एरिक्सन (च्न्ठस्)	21
5	डॉ रेड्डीस लेबोरेटरिस लिमिटेड	13
6	सिप्ला लिमिटेड	10
7	सेंट–गोबेन फ्रांस	9
8	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8
9	एमएसएन लेबोरेटरिस प्राइवेट लिमिटेड, आर & डी सेंटर	8
10	राजधानी पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड	7

2021–22 में भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल 10 शीर्ष पीसीटी (आरओ/आईएन)

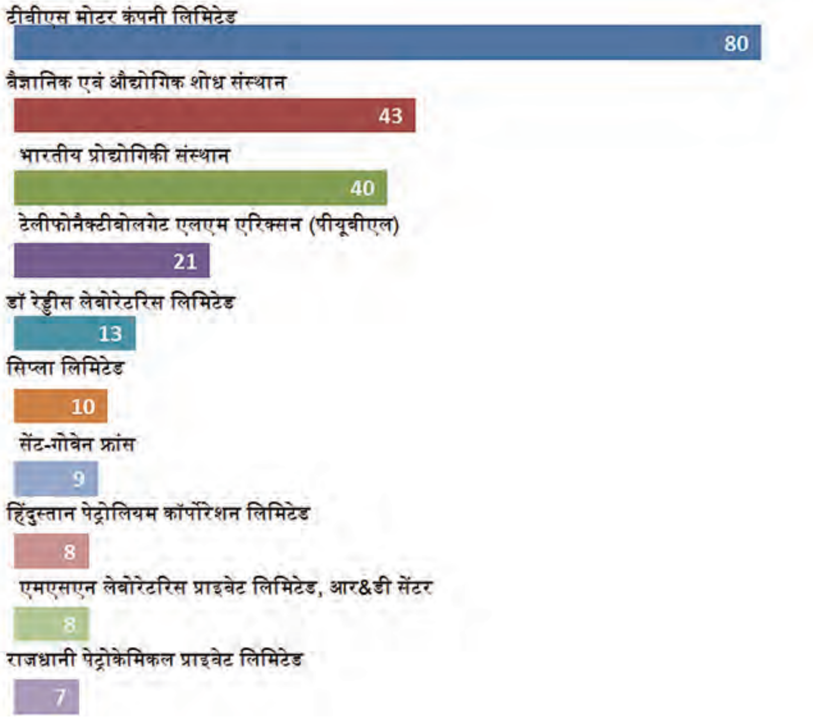

2. पीसीटी के तहत अंतरराष्ट्रीय खोज प्राधिकरण (आईएसए) व अंतरराष्ट्रीय प्रारम्भिक परीक्षण प्राधिकरण (आईपीईए) के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालयः

भारतीय पेटेंट कार्यालय को वायपो द्वारा पीसीटी के तहत अंतरराष्ट्रीय खोज और प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण के रूप में कार्य करने हेतु मान्यता प्रदान की गई है और इसने 15 अक्टूबर 2013 से कार्य करना प्रारम्भ किया है। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, भारत, ईरान और जापान के नागरिकों / निवासियों द्वारा दाखिल अंतरराष्ट्रीय आवेदनों के लिए आईपीओ सक्षम आईएसए/आईपीईए था।

क) आईएसए /आईएन में दाखिल, निपटान, आहरित व वर्ष के दौरान के दौरान लंबित खोज प्रतियों संबंधी वर्ष–वार विवरणः

वर्ष	दाखिल	निष्पादित	आहरित	वर्ष के दौरान लंबित
2014–15	519	502	4	129
2015–16	711	621	1	218
2016–17	940	983	0	175
2017–18	1213	1156	1	231
2018–19	1738	1639	3	327
2019–20	1654	1640	2	339
2020–21	1780	1793	1	325
2021–22	**2016**	**1959**	**1**	**381**

ख) आईपीईए/आईएन में (दाखिल, निष्पादित, आहरित व वर्ष के दौरान लंबित) प्राप्त मांगों संबंधी वर्ष–वार विवरण :–

वर्ष	दाखिल	निष्पादित	आहरित	वर्ष के दौरान लंबित
2014–15	11	0	1	10
2015–16	24	14	1	19
2016–17	30	28	1	20
2017–18	49	29	0	40
2018–19	61	54	1	46
2019–20	65	87	1	23
2020–21	79	69	5	28
2021–22	**58**	**58**	**4**	**24**

ग) आईएसए/आईपीईए में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालीः–

भारतीय पेटेंट कार्यालय (आईपीओ) ने पीसीटी के तहत अंतरराष्ट्रीय खोज और प्रारंभिक परीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार आईएसए/आईपीईए के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की है। आईएसए/आईपीईए का गुणवत्ता सेल, जिसमें विभिन्न विषय के विशेषज्ञ परीक्षक व नियंत्रक शामिल होते हैं, रिपोर्ट की गुणवत्ता की जाँच इसकी स्थापना व आवेदक तथा वायपो को इसकी रिपोर्ट प्रेषित करने से पूर्व करते हैं।

घ) समयबद्धताः–

यदि आवेदकों द्वारा ईमेल उपलब्ध कराया गया है तो आईपीओ ईमेल द्वारा अंतरराष्ट्रीय खोज और प्रारम्भिक परीक्षण रिपोर्ट प्रेषित करता है और वायपो के साथ स्थापित सुरक्षित ट्रांसमिशन चैनल पीसीटी के ई–आईडी माध्यम से वायपो को रिपोर्ट प्रसारित करता है। आवेदकों को रिपोर्ट की सूचना इसकी स्थापना की तारीख पर ही तुरंत प्रेषित की जाती है। सभी रिपोर्ट आईएसए में विहित समय के भीतर ही स्थापित की जाती हैं।

ङ) खोज रणनीतियों का प्रकाशन :–

आईपीओ ने अंतरराष्ट्रीय आवेदनों के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के पेटेंट्सस्कोप सर्च पोर्टल पर प्रकाशन हेतु खोज रणनीतियों को साझा करना प्रारम्भ किया है जिनके लिए 1 जनवरी, 2018 से रिपोर्ट स्थापित की गई है। भारत इस सेवा को प्रारम्भ करने वाले 23 प्राधिकरणों में सातवां अंतरराष्ट्रीय प्राधिकरण है। पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में यह आईपीओ द्वारा महत्वपूर्ण कदम है जो आईपीओ द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रति आवेदकों में विश्वास भरता है। पूर्ण खोज रणनीतियाँ आवेदक के साथ–साथ अन्य कार्यालयों के परीक्षकों के लिए भी उपयोगी हैं ताकि उद्धरणों को खोजने के लिए आईएसए के परीक्षक द्वारा किए गए प्रयास के स्तर का मूल्यांकन किया जा सके।

च) आईपीओ को आईएसए /आईपीईए के रूप में चयन करने वाले आवेदकः–

पीसीटी अंतरराष्ट्रीय आवेदनों के आवेदक जो भारत, ईरान और जापान के नागरिक/प्रवासी हैं, भारतीय पेटेंट कार्यालय को आईएसए/आईपीईए के रूप में चुन सकते हैं। आईएसए/ आईपीईए के रूप में आईपीओ का चयन करने वाले भारतीय आवेदकों में वैयक्तिक आविष्कारक, स्टार्ट अप, प्रमुख अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय, भारतीय बहु–राष्ट्रीय समूह, विदेशी बहु–राष्ट्रीय फर्मों की भारतीय इकाइयाँ और भारतीय आविष्कारक या भारतीय कंपनियों के साथ सह आवेदक के रूप में विदेशी कंपनियाँ शामिल हैं।

2021–22 के दौरान आईएसए के रूप में आईपीओ का चयन करने वाली शीर्ष आवेदकः

क्र. सं.	आवेदक का नाम	कुल आवेदन
1	भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, मुंबई	64
2	टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड	54
3	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद	49
4	टेलीफोनैक्टीबोलगेट एलएम एरिक्सन (पीयूबीएल)	27
5	कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड	21
6	भारतीय विज्ञान संस्थान	20
6	डॉ रेड्डीस लेबोरेटरिस लिमिटेड	20
7	सेंट–गोबेन ग्लास फ्रांस	19
8	लोहिया कॉर्प लिमिटेड	13
9	पद्मिनी वीएनए मेकाट्रोनिक्स प्रा. लि.	12
10	रिलायंस इंडस्ट्रिस लिमिटेड	11
10	भारतीय चिकित्सा शोध परिषद	11
10	सेलिक्स बायो प्राइवेट लिमिटेड	11

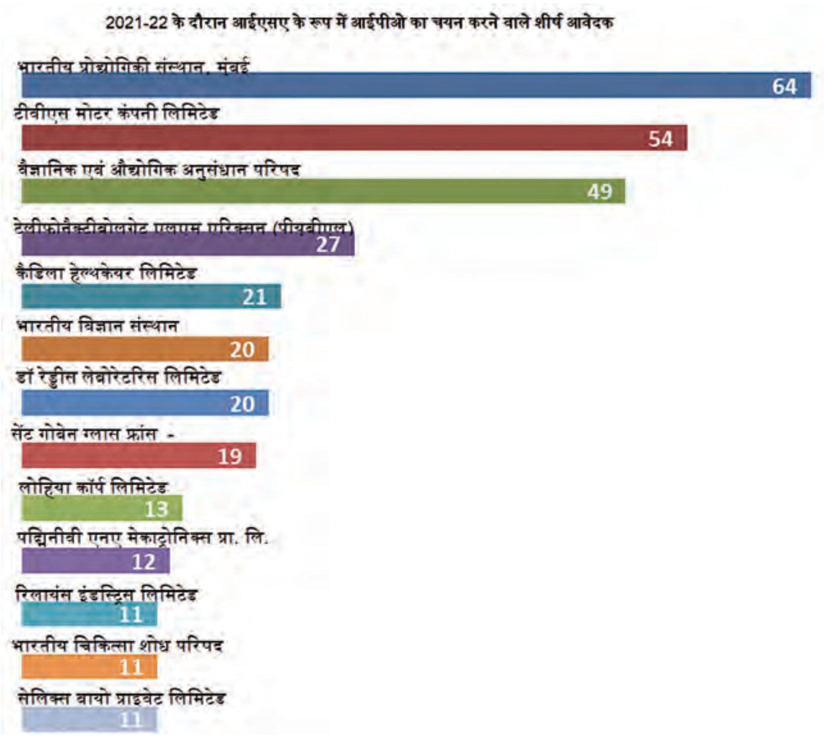
2021-22 के दौरान आईएसए के रूप में आईपीओ का चयन करने वाले शीर्ष आवेदक
भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, मुंबई
64
टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड
54
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद
49
टेलीफोनैक्टीबोलगेट एलएम एरिक्सन (पीयूबीएल)
27
कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड
21
भारतीय विज्ञान संस्थान
20
डॉ रेड्डीस लेबोरेटरिस लिमिटेड
20
सेंट गोबेन ग्लास फ्रांस -
19
लोहिया कॉर्प लिमिटेड
13
पद्मिनीवी एनए मेकाट्रोनिक्स प्रा. लि.
12
रिलायंस इंडस्ट्रिस लिमिटेड
11
भारतीय चिकित्सा शोध परिषद
11
सेलिक्स बायो प्राइवेट लिमिटेड
11

डिजाइन

भारत में औद्योगिक डिजाइन का पंजीकरण और संरक्षण डिजाइन अधिनियम 2000 तथा तत्संबंधी डिजाइन नियम 2001 द्वारा प्रशासित होता है जो 11 मई 2001 से लागू हुआ। डिजाइन नियम, 2001 को डिजाइन नियम 2008, डिजाइन नियम 2014 एवं डिजाइन नियम 2021 द्वारा संशोधित किया गया है। औद्योगिक डिजाइन नए आकार की नई मूल विशेषताओं के निर्माण, आकृति, सतह विन्यास, सतह अलंकरण, किसी वस्तु पर पंक्तियों अथवा रंगों की संरचना जो निर्मित होने के उपरांत केवल आँखों से परखी जा सके उसे मान्यता प्रदान करता है।

डिजाइन नियमों में नवीनतम संशोधन 25 जनवरी, 2021 से लागू हुआ, जिसमें 'स्टार्टअप' के रूप में मान्यता प्राप्त एक नई श्रेणी सम्मिलित की गई है, जो भारतीय इकाई के मामले में स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त हो एवं विदेशी आवेदक के मामले में, आवेदक को स्टार्टअप इंडिया पहल के अनुसार टर्नोवर और निगमन या पंजीकरण की अवधि के मानदंडों को पूरा करने के साथ–साथ इस आशय का घोषणा भी प्रस्तुत करनी होगी। यह नवीनतम श्रेणी 'प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों), लघु इकाई (इकाइयों) एवं 'अन्य', अकेले या प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) और / या स्टार्टअप और या लघु इकाई के साथ पहले से मौजूद श्रेणियों के अतिरिक्त है। लघु इकाई या स्टार्टअप के लिए शुल्क को भी संशोधित कर प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के शुल्क के समान कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, नियम 10 के उपनियम (1) को भी प्रतिस्थापित किया गया है तथा डिजाइन के पंजीकरण और नियमों के प्रयोजन के लिए वस्तुओं को 'विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (वायपो) द्वारा प्रकाशित औद्योगिक डिजाइन हेतु अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण प्रणाली (लोकार्नो प्रणाली) के वर्तमान संस्करण' के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा।

1. दाखिल एवं पंजीकृत डिजाइन आवेदनः

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, डिजाइन पंजीकरण हेतु दाखिल किए गए आवेदनों की संख्या **22699** रही एवं **15262** डिजाइन पंजीकृत किए गए। डिजाइन आवेदन दाखिल करने एवं उनके पंजीकरण की प्रवृत्ति नीचे प्रदर्शित की गयी है:

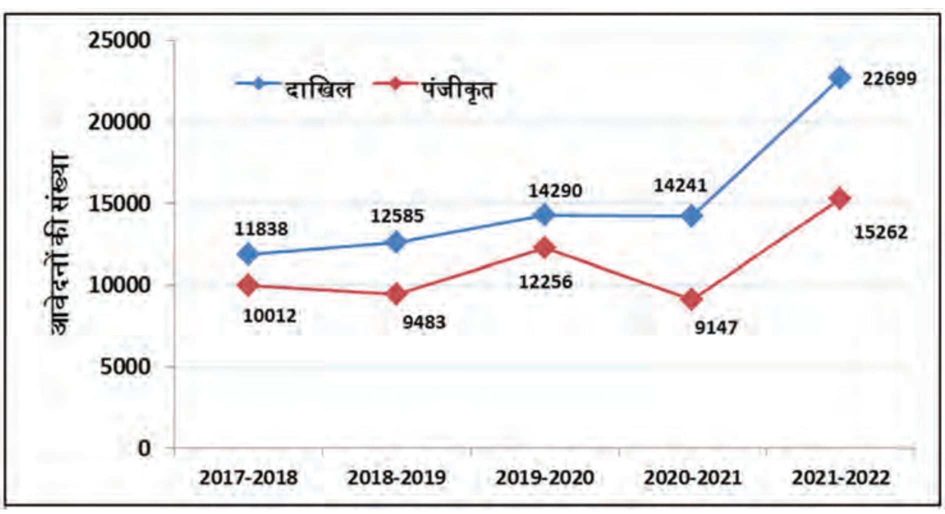

1.1 भारत एवं विदेशों से उद्गमित आवेदन:

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान भारत से उद्गमित आवेदनों की संख्या **18851** थी, जबकि **3848** डिजाइन आवेदन विदेशों से प्राप्त हुए। कुल दाखिल आवेदनों में से भारत से उद्गमित आवेदन लगभग 83% रहे। डिजाइन आवेदनों को दाखिल करने एवं आवेदन के उद्गम के आधार पर इसके पंजीकरण की प्रवृत्ति को ग्राफ द्वारा नीचे दर्शाया गया है:

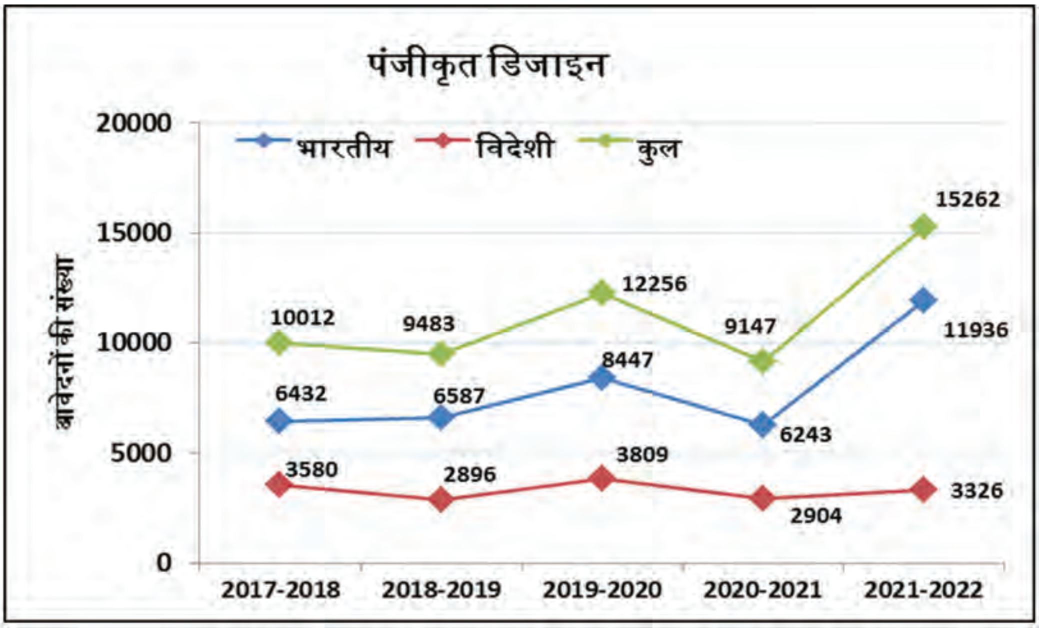

1.2. भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन:

वर्ष के दौरान भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की कुल संख्या **18851** रही, जिनमें से 4520 आवेदनों के साथ गुजरात प्रथम स्थान पर बना रहा। महाराष्ट्र 3546 आवेदनों के साथ द्वितीय स्थान पर एवं 2143 आवेदनों के साथ दिल्ली तीसरे स्थान पर रहा। दाखिल करने वाले दाखिल करने वाले राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों का ग्राफीय वर्णन नीचे दिया गया है:

दाखिल डिजाइन आवेदन (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अनुसार)

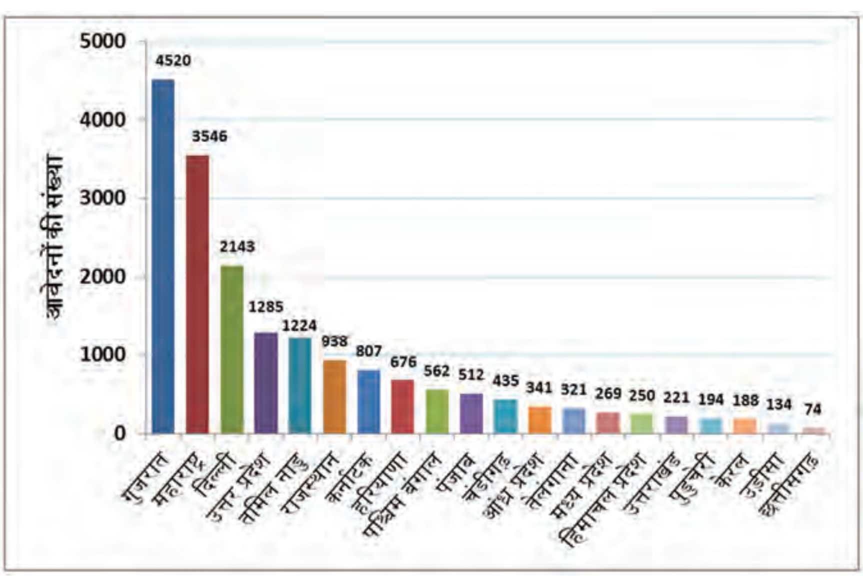

अग्रणी भारतीय आवेदक रहे–चितकारा इनोवेशन इनक्यूबेटर फाउंडेशन (367), सब्यसाची कलकत्ता एलएलपी (269), माइकल आराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (267), शूलीनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी एंड मेनेजमेंट साइंसेज़ (203), हैवेल्स इंडिया लिमिटेड (173), रिलेक्सो फुटवियर्स लिमिटेड (160), शारदा यूनिवर्सिटी (160), मसरूर कुत्बुल्लाह खान (135), औलीरा डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड (91), हरप्रीत नरूला (89) व फैबइंडिया ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड (89), आदि।

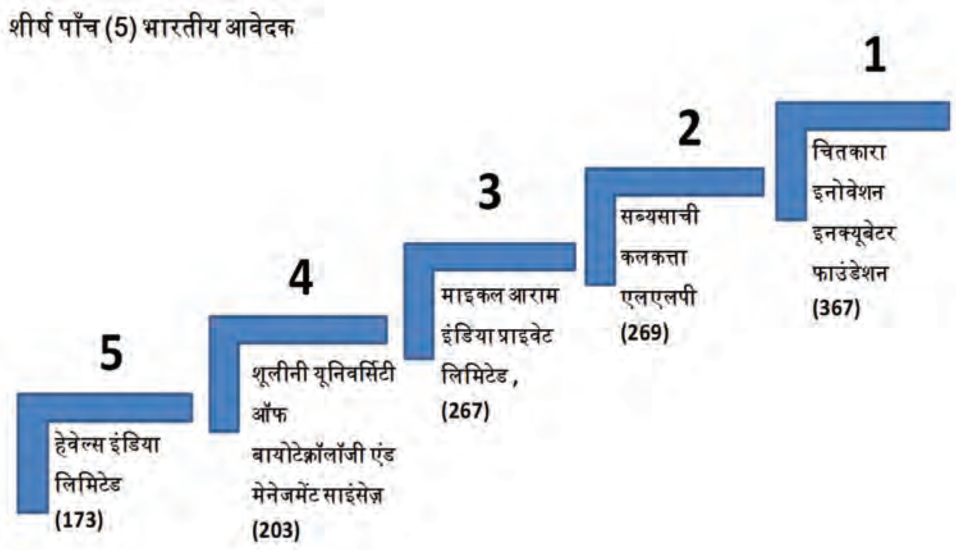

1.3. विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनः

विदेशों से उद्गमित **3848** आवेदनों के संदर्भ में, यू.एस.ए. अधिकतम आवेदनों की संख्या (893) के साथ अग्रणी रहा जिसके बाद क्रमशः चीन (671), जापान (329), जर्मनी (273), नीदरलैंड्स (264), कोरिया गणराज्य (237), यूनाइटिड किंगडम (234), स्विट्जरलैंड (167), फ्रांस (105), इटली (105) और स्वीडन (89) का स्थान रहा। डिजाइन अधिनियम, 2000 की धारा 44 के अंतर्गत पारस्परिक व्यवस्था के तहत 2823 आवेदनों ने पूर्विक्ता का दावा किया। विभिन्न देशों/क्षेत्रों द्वारा विदेशों से उद्गमित आवेदनों का ग्राफीय वर्णन नीचे दिया गया है।

दाखिल विदेशी डिजाइन आवेदन (देश/क्षेत्र अनुसार)

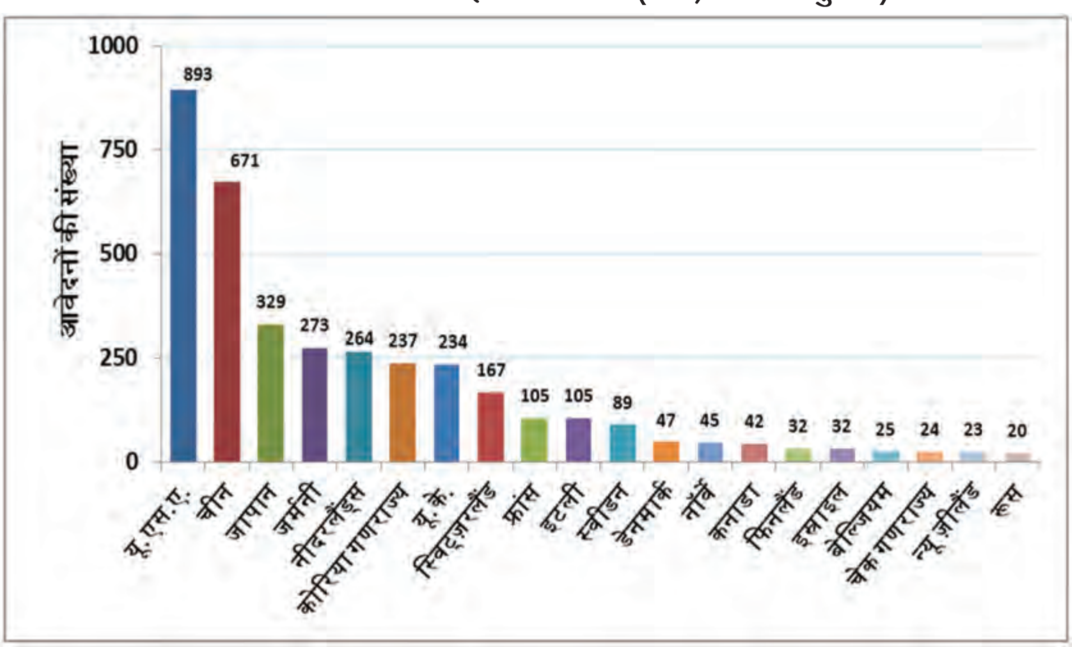

अग्रणी विदेशी आवेदक जिन्होंने डिजाइन आवेदन किए वे थे–कोनिङ्क्लिके फिलिप्स एन.वी. (218), एचटीएल फर्नीचर (चीन) कंपनी लिमिटेड (192), सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड (104), कोहलर कंपनी (97), बीजिंग शाओमि मोबाइल सॉफ्टवेयर कंपनी लिमिटेड (71), शै ज़्हेंगाओ (69), पैरी मर्रे एंड कंपनी लिमिटेड (59), द जिलेट कंपनी एलएलएलसी. (50), युनिलीवर ग्लोबल आईपी लिमिटेड (44), गुआंग्डोंग ओप्पो मोबाइल टेलिकम्युनिकेशंस कार्पोरेशन लिमिटेड (38) आदि।

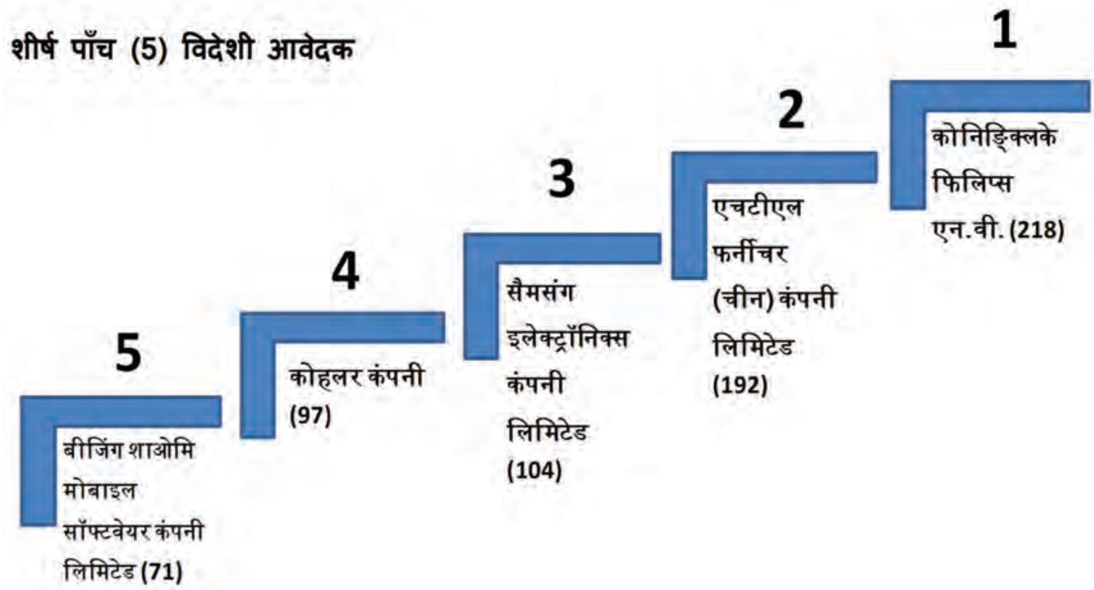

1.4. वर्गीकरण के अनुसार दाखिल डिजाइन आवेदनः

भारत से उद्‌गमित आवेदनों में से, 3570 आवेदन वर्ग 02 (वस्त्र वस्तु व बिसाती वस्तु के अंतर्गत) दाखिल किए गए, जिसके बाद वर्ग 12 (यातायात या उत्तोलन के साधन) के अंतर्गत 1376, वर्ग 06 (फर्निशिंग) के अंतर्गत 1232, वर्ग 09 (माल के परिवहन या हैंडलिंग के लिए पैकेजिंग और कंटेनर) के अंतर्गत 1200, वर्ग 07 (घरेलू समान अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं) के अंतर्गत 1175, वर्ग 23 (द्रव वितरण उपकरण, स्वच्छता, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग उपकरण, ठोस ईंधन) के अंतर्गत 1103 व वर्ग 15 (मशीनें, अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं) के अंतर्गत 998 आदि थे। दूसरी तरफ, प्रतिवेदन वर्ष के दौरान विदेशों से उद्‌गमित आवेदनों की वर्गानुसार प्रवृत्ति ये हैः वर्ग 14 (रिकॉर्डिंग, संचार या संचार प्राप्ति उपकरण) के अंतर्गत 503 आवेदन, वर्ग 12 (यातायात या उत्तोलन के साधन) के अंतर्गत 368, वर्ग 23 (द्रव वितरण उपकरण आदि) के अंतर्गत 347, वर्ग 09 (माल के परिवहन या हैंडलिंग के लिए पैकेजिंग और कंटेनर) के अंतर्गत 327, वर्ग 24 (चिकित्सा और प्रयोगशाला उपकरण) के अंतर्गत 289 तथा वर्ग 28 (फार्मास्युटिकल और कॉस्मेटिक उत्पाद, शौचालय के सामान और उपकरण) के अंतर्गत 277। शेष आवेदन अन्य वर्गों में दाखिल किए गए। भारतीय और विदेशी आवेदकों की ओर से दाखिल आवेदनों की वर्गानुसार प्रवृत्ति नीचे प्रदर्शित की गई हैः

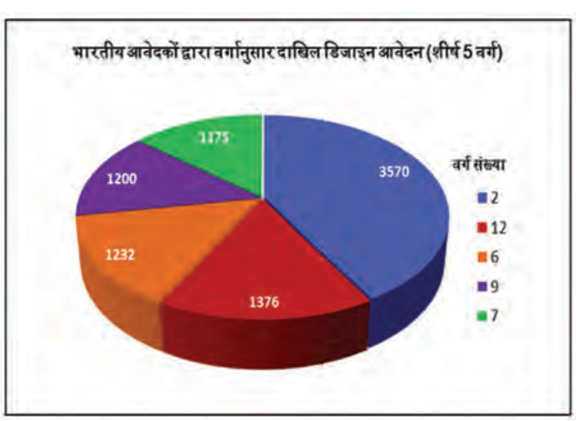

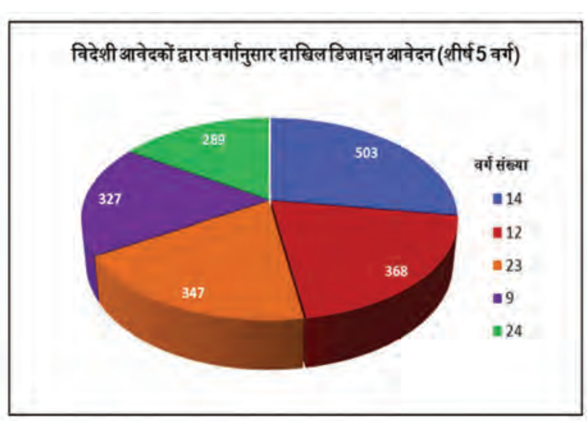

भारतीय और विदेशी आवेदकों की ओर से दाखिल आवेदनों की वर्गानुसार प्रवृत्ति नीचे प्रदर्शित की गई है:

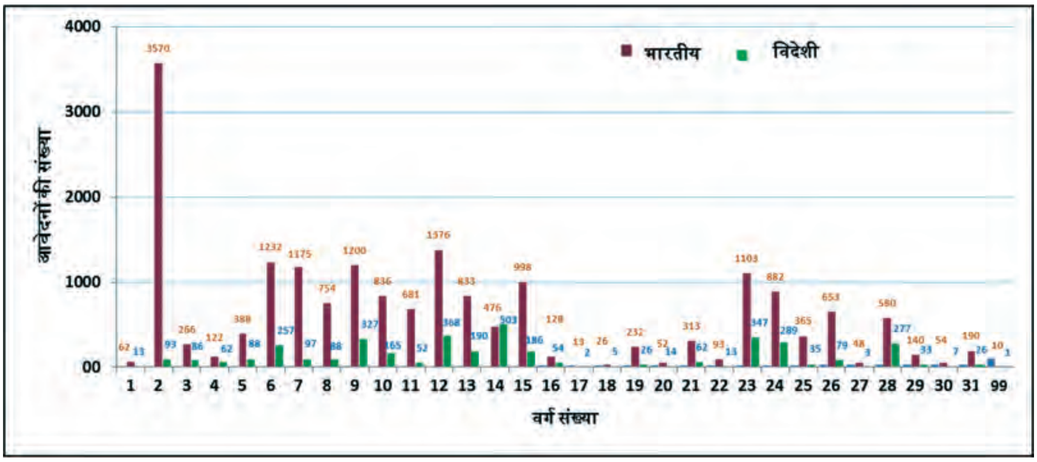

2. पंजीकृत डिजाइन आवेदन:

2.1. भारत व विदेशी उद्‌गम द्वारा डिजाइन पंजीकरण:

कुल पंजीकृत **15262** डिजाइन में से, **11936** पंजीकृत डिजाइन भारत से उद्‌गमित थे तथा **3326** विदेशों से उद्‌गमित थे। भारत व विदेशों से उद्‌गमित पंजीकरणों की प्रवृत्ति नीचे दर्शाई गयी है:

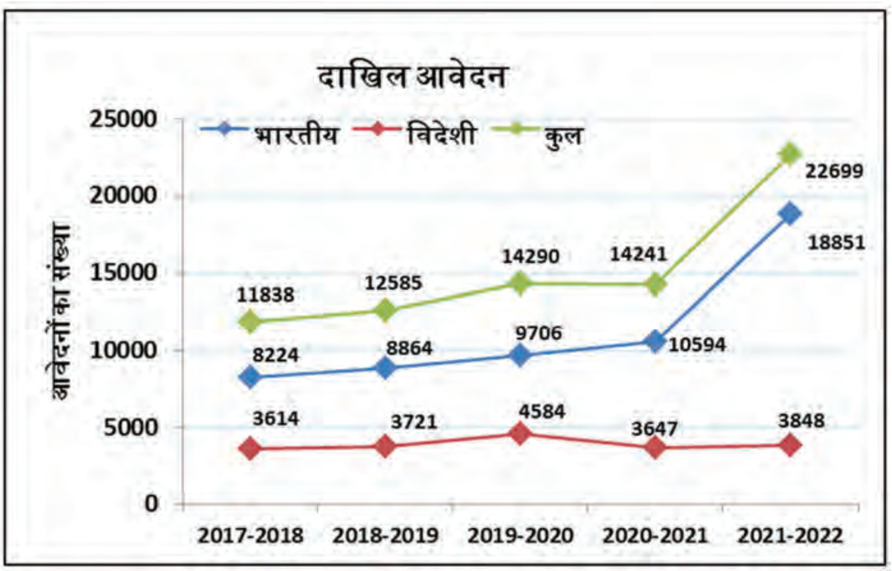

2.2. भारतीय उद्‌गम द्वारा डिजाइन पंजीकरण:

वर्ष के दौरान, भारतीय आवेदकों द्वारा पंजीकृत आवेदनों की कुल संख्या **11936** में से, 2604 पंजीकरणों के साथ गुजरात प्रथम स्थान पर रहा। महाराष्ट्र 2277 पंजीकरणों के साथ द्वितीय स्थान पर रहा जबकि दिल्ली 1439 पंजीकरणों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों का ग्राफीय वर्णन नीचे दिया गया है।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार–पंजीकृत डिजाइन

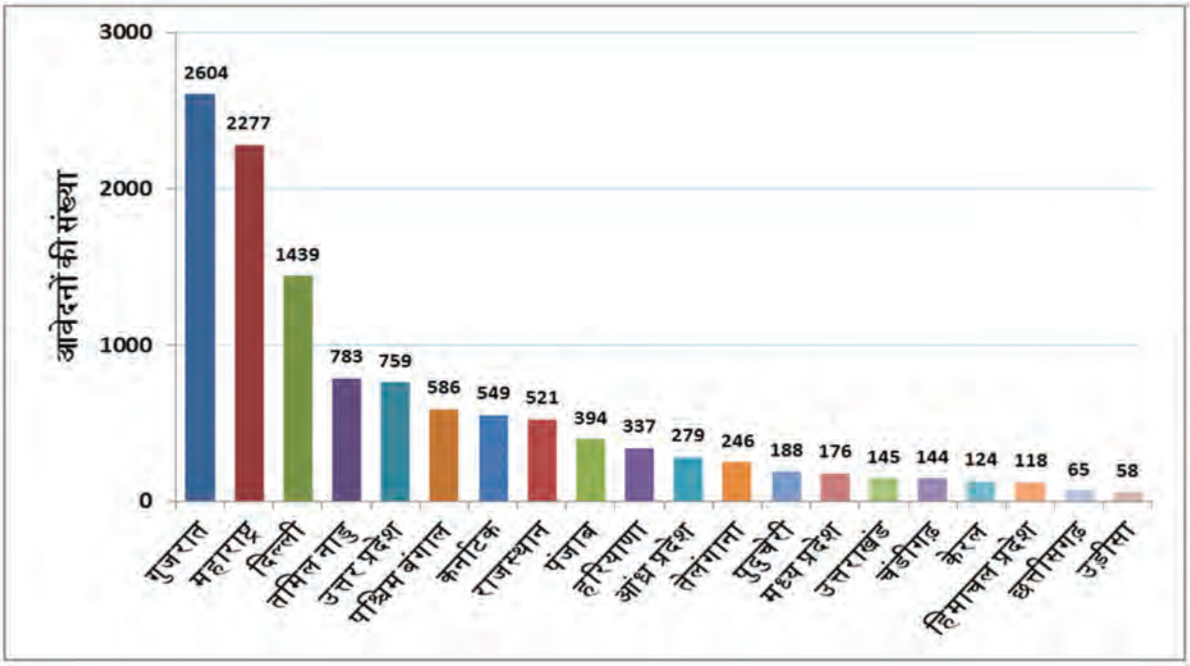

साथ ही, डिजाइन पंजीकरण वाले प्रमुख भारतीय आवेदक के नाम हैं–रिलैक्सो फुटवियर लिमिटेड (212), माइकल अराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (191), साब्यसाची कोट्यूर (181), सब्यसाची कलकत्ता एलएलपी (170), शारदा विश्वविद्यालय (124), एक्वालाइट इंडस्ट्रीज प्रा. (111), चितकारा इनोवेशन इनक्यूबेटर फाउंडेशन (107), हैवेल्स इंडिया लिमिटेड (93), इटालिया जेमिश शांतिभाई (89) व गोदरेज एंड बॉयस मेन्यूफ़ेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (85), आदि।

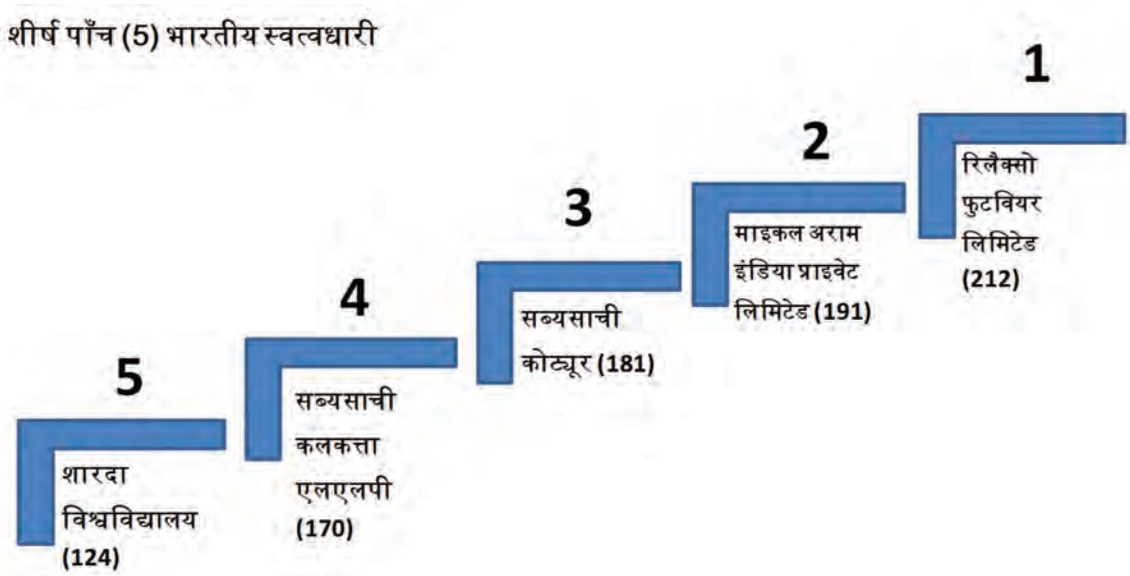

2.3. विदेशी उद्‌गम द्वारा डिजाइन पंजीकरण:

विदेशों से उद्‌गमित **3326** आवेदनों में से यू.एस.ए. अधिकतम आवेदनों की संख्या (750) के साथ अग्रणी रहा जिसके बाद क्रमशः चीन (601), जापान (334), कोरिया गणराज्य (309), जर्मनी (217), यूनाइटेड किंगडम (179) तथा नीदरलैंड (162) का स्थान रहा। विभिन्न देशों/ क्षेत्रों के पंजीकृत डिजाइन का ग्राफीय वर्णन नीचे दर्शाया गया है:

पंजीकृत डिजाइन–देश/क्षेत्र अनुसार

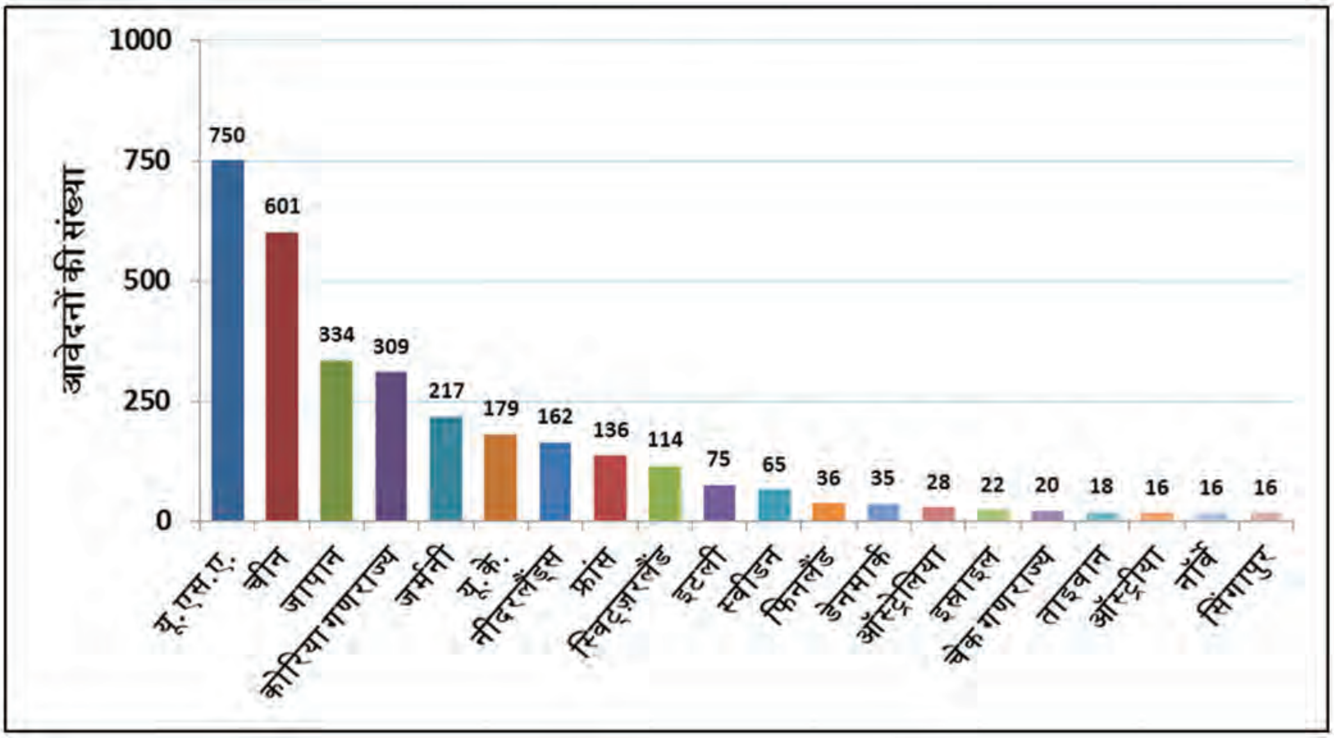

अग्रणी विदेशी आवेदक जिन्होंने डिजाइन आवेदन पंजीकृत किए वे थे–सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड (165), एचटीएल फर्नीचर (चीन) कंपनी लिमिटेड (137), कोनिङ्क्लिके फिलिप्स एन.वी. (128), बीजिंग शाओमि मोबाइल सॉफ्टवेयर कंपनी लिमिटेड (82), रेनौ एस.ए.एस. (74), कोहलर कंपनी (73), पैरी मर्रे एंड कंपनी लिमिटेड (57), ग्वांगडोंग ओप्पो मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस कार्पोरेशन लिमिटेड (53), होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड (51), गूगल एलएलसी, (48) और एप्पल इंक. (38), आदि।

शीर्ष पाँच (5) पंजीकृत विदेशी स्वत्वधारी

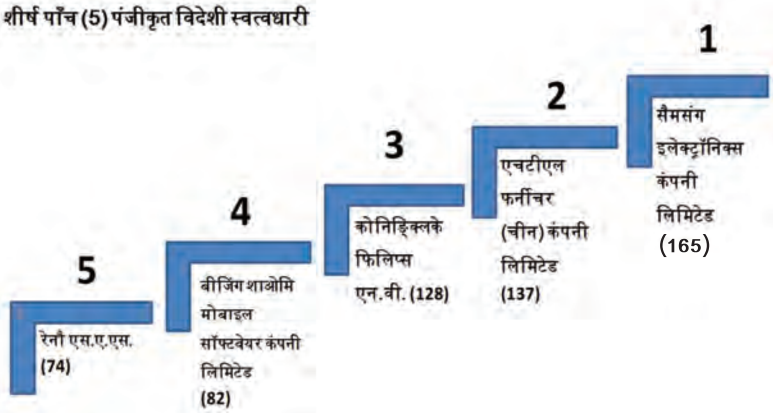

2.4. वर्गीकरण के अनुसार पंजीकृत डिजाइन आवेदन:

भारतीय उद्‌गम के पंजीकृत डिजाइन के वर्गानुसार वितरण में वर्ग 02 (वस्त्र व बिसाती वस्तु) के अंतर्गत 2407, वर्ग 12 (यातायात या उत्तोलन के साधन) के अंतर्गत 941, वर्ग 6 (फर्निशिंग) के तहत 819, वर्ग 09 (माल के परिवहन और उसकी उठाई–धराई के लिए पैकेज और आधान) के अंतर्गत 776, वर्ग 23 (द्रव वितरण उपकरण) के अंतर्गत 706, वर्ग 07 (घरेलू सामान) के अंतर्गत 698, वर्ग 15 (मशीनें, अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं) के अंतर्गत 668, वर्ग 08 (उपकरण और हार्डवेयर) के अंतर्गत 589, वर्ग 24 (डॉक्टरों, अस्पतालों और प्रयोगशालाओं के लिए उपकरण और यंत्र) के अंतर्गत 567 शामिल हैं। जबकि, विदेशी उद्‌गम के संदर्भ में पंजीकृत डिजाइन के वर्गानुसार वितरण में वर्ग 14 (रिकॉर्डिंग, संचार या संचार प्राप्ति उपकरण) के अंतर्गत 481, वर्ग 12 (यातायात या उत्तोलन के साधन) के अंतर्गत 362, वर्ग 09 (माल के परिवहन और उसकी

उठाई–धराई के लिए पैकेज और आधान) के अंतर्गत 271, वर्ग 23 (तरल वितरण उपकरण) के अंतर्गत 265, वर्ग 24 (डॉक्टरों, अस्पतालों और प्रयोगशालाओं के लिए उपकरण और यंत्र) के अंतर्गत 240, वर्ग 6 (फर्निशिंग) के अंतर्गत 194 आदि रहे। शेष आवेदन अन्य वर्गों में पंजीकृत किए गए।

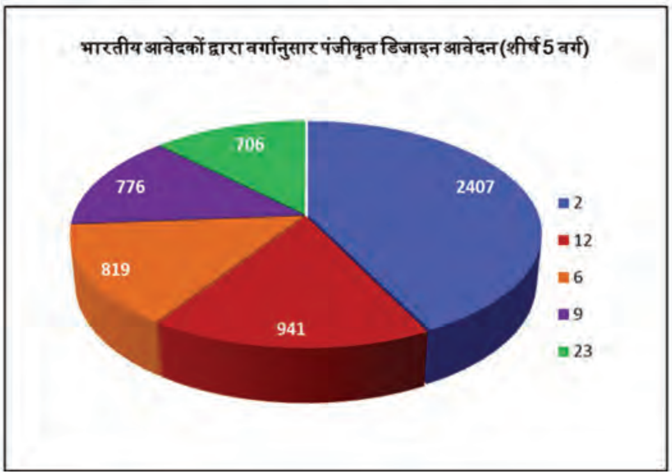

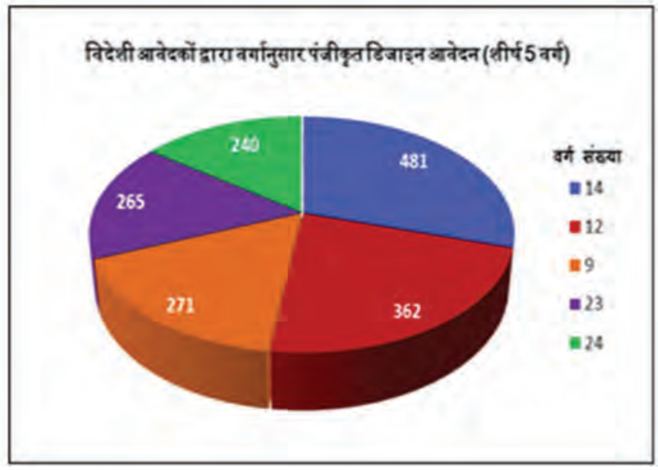

भारतीय उद्गम के साथ साथ विदेशी आवेदनों के पंजीकरण का वर्गानुसार वितरण नीचे प्रदर्शित किया गया है:

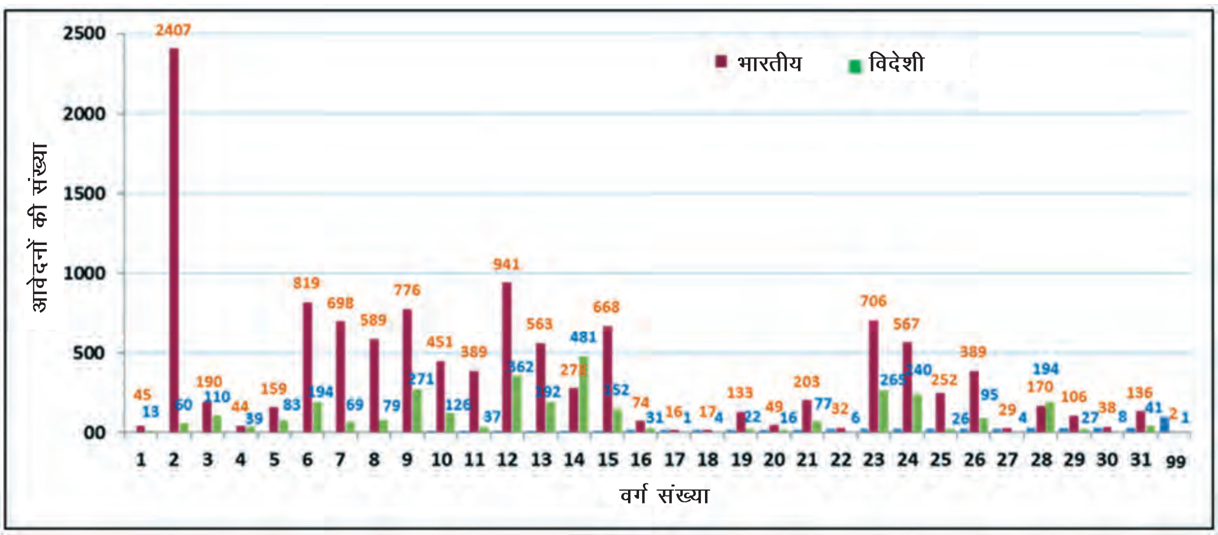

3. डिजाइन आवेदनों का परीक्षण:

प्रतिवेदन अवधि के दौरान, डिजाइन के पंजीकरण हेतु कुल **22120** आवेदनों का परीक्षण किया गया जिनमें से **15117** आवेदनों की प्रथम परीक्षण रिपोर्ट (एफ़ईआर) भेजने की आवश्यकता थी। वर्ष के दौरान पंजीकृत डिजाइन की संख्या **15262** रही। पंजीकरण के अलावा, **174** आवेदनों को अस्वीकृत किया गया तथा **219** आवेदन परित्यक्त किए गए।

4. प्रतिलिप्यधिकार विस्तार (धारा 11(2) के तहत):

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, पंजीकृत डिजाइन में प्रतिलिप्यधिकार विस्तार के लिए **2295** आवेदन प्राप्त किए गए। प्रतिवेदन वर्ष **1787** पंजीकृत डिजाइन का आगामी 5 वर्षों के लिए नवीकरण किया गया। हालांकि, शेष मामलों पर कार्यवाही प्रारंभ की गई है। वर्ष के दौरान, डिजाइन के प्रत्यावर्तन के लिए **106** आवेदन दाखिल किए गए जिनमें से **09** आवेदनों का प्रत्यावर्तन कर दिया गया। शेष आवेदनों पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

5. विविध कार्यवाहियाँ:

क. डिजाइन का निरस्तीकरण (धारा 19 के तहत): प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, पंजीकृत डिजाइन के निरस्तीकरण के लिए 122 आवेदन दाखिल हुए। 86 निर्णय जारी किए गए जिनमें से 16 मामलों पर, याचिका अनुमत की गई और 70 मामलों पर, याचिका खारिज की गईं।

ख. पंजीकृत डिजाइन का निरीक्षण (धारा 17(1) के तहत): पंजीकृत डिजाइन आवेदनों के निरीक्षण हेतु 10 याचिका प्राप्त हुईं।

ग. नाम और पते आदि में परिवर्तन (नियम 31 के तहत): वर्ष के दौरान नाम, पते एवं सेवार्थ पते में परिवर्तन हेतु **1298** अनुरोध प्राप्त हुए, जिनमें से **919** मामलों का निपटान कर आदेश जारी किया गया। शेष मामलों पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

घ. डिजाइन रजिस्टर में सेवा के लिए दो पतों की प्रविष्टि हेतु अनुरोध (धारा 10 के तहत): वर्ष के दौरान डिजाइन रजिस्टर में सेवार्थ पते के लिए दो पतों की प्रविष्टि हेतु 384 अनुरोध प्राप्त हुए, जिनमें से 343 मामलों का निपटान किया गया। शेष मामलों में कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है।

ङ. धारा 30 व धारा 31 के तहत समनुदेशन: प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, 1533 समनुदेशन के आवेदन दाखिल हुए, जिनमें से 496 का निपटान किया गया व आदेश जारी किए गए। शेष मामलों पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

च. खोज सूचना (धारा 18 के तहत): प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, धारा 18 के तहत 142 मामले दाखिल हुए व सभी का निपटान कर दिया गया।

छ. लिपिकीय त्रुटि का परिमार्जन (नियम 29 के तहत): प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, लिपिकीय त्रुटि के परिमार्जन हेतु 18 अनुरोध प्राप्त हुए और सभी का निपटान कर दिया गया।

ज. नियम 41 तथा धारा 17 (2) के तहत सत्यापित प्रतियां: वर्ष के दौरान, 528 अनुरोध दाखिल किए हुए व सभी का निपटान कर दिया गया।

झ. स्टार्ट–अप इंटलेक्चुयल प्रॉपर्टि प्रोटेक्शन (एसआईपीपी)–सुविधाप्रदाता (फेसीलीटेटर): प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, डिजाइन आवेदनों को दाखिल करने और/या पंजीकरण के लिए सुविधाप्रदाता शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए सुविधाकर्ताओं द्वारा 153 दावे किए गए; जिनमें से 132 दावों का निपटान किया गया जबकि 03 अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया। शेष आवेदनों पर कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है।

6. प्रवृत्त डिजाइन:

प्रतिवेदन वर्ष के अंत तक प्रवृत्त पंजीकृत डिजाइन की संख्या 99807 रही।

7. राजस्व:

वर्ष के दौरान, डिजाइन अधिनियम 2000 तथा उसके अधीन बने नियमों के तहत डिजाइन आवेदनों तथा अन्य कार्यवाहियों के संबंध में **रू. 7,69,12,200/**–(सात करोड़ उनहत्तर लाख बारह हजार दो सौ रुपये मात्र) का कुल राजस्व पेटेंट कार्यालय (कोलकाता, दिल्ली, मुंबई एवं चेन्नई कार्यालयों) से अर्जित हुआ। विवरण इस प्रकार है:

पेटेंट कार्यालय	राजस्व (रु. में)
कोलकाता	7,46,53,200
दिल्ली	12,04,000
मुंबई	7,72,000
चेन्नई	2,83,000
कुल	**7,69,12,200**

वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान अर्जित राजस्व की प्रवृत्ति

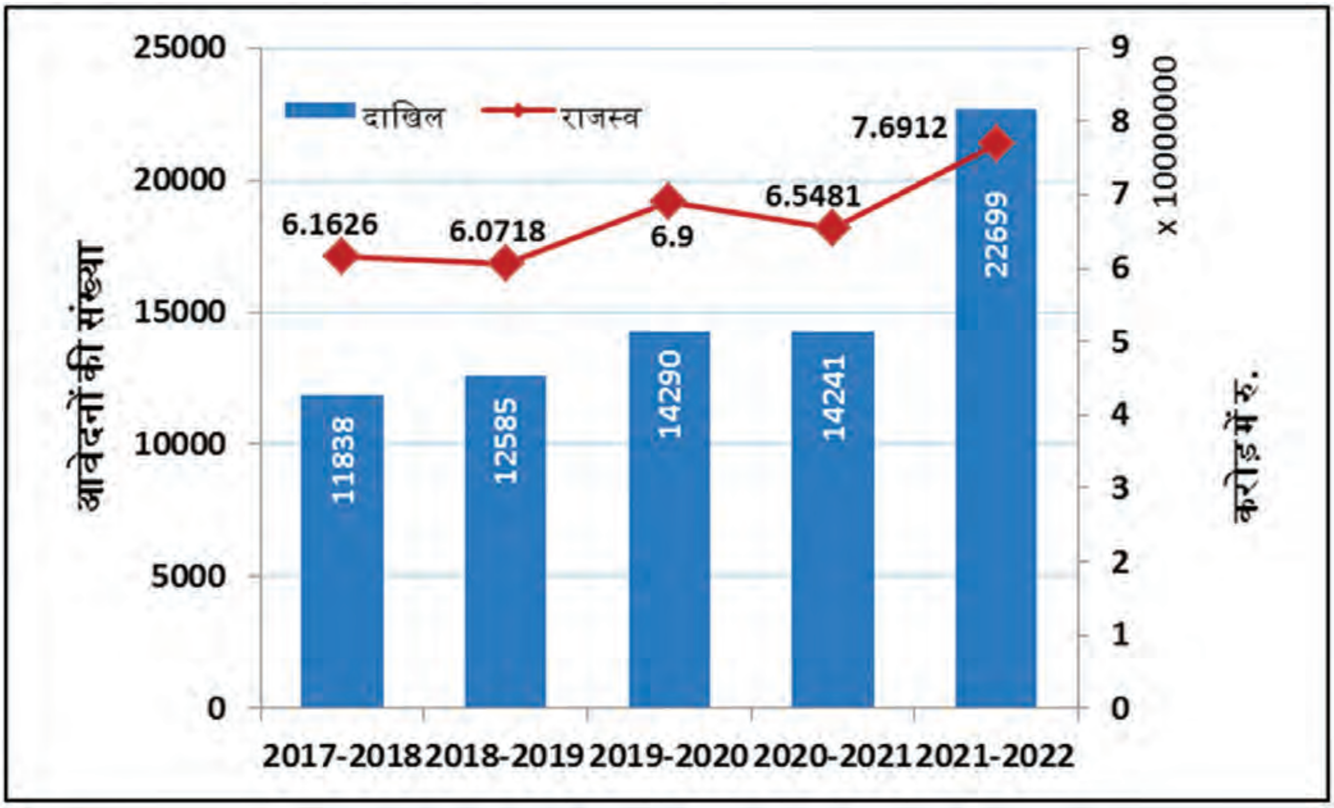

2021–22 के दौरान अर्जित राजस्व

प्रलेखों का विवरण	संख्या	शुल्क (रु.)	राशि (रु.)
डिजाइन अधिनियम, 2000 धारा 5 एवं 44 के तहत डिजाइन पंजीकरण हेतु आवेदन (दिल्ली, मुंबई एवं चेन्नई पेटेंट कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों सहित)	22699	1000, 4000	4,94,69,000
धारा 11(2) के तहत प्रतिलिप्यधिकार के विस्तार हेतु आवेदन	2295	2000, 8000	1,74,00,000
धारा 12(2) के तहत व्यपगत डिजाइन का प्रत्यावर्तन	106	1000, 4000	4,86,000
धारा 30 व 31 के तहत समनुदेशन	1533	500, 200, 2000, 800	16,88,700
धारा 19 के तहत डिजाइन का निरस्तीकरण	122	1500, 6000	3,09,000
धारा 26 और 17(2) के तहत सत्यापित प्रति	528	500, 2000	13,08,500
डिजाइन अधिनियम, 2000 व डिजाइन नियम 2001 के तहत अन्य विविध शुल्क; दिल्ली, मुंबई एवं चेन्नई पेटेंट कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों सहित)		प्रथम अनुसूची के अनुसार	62,51,000
कुल योग			**7,69,12,200**

अध्याय–VI

व्यापार चिह्न

यह अध्याय व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 149 के तहत व्यापार चिह्न रजिस्ट्री द्वारा निष्पादित गतिविधियों से संबंधित 63वाँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

व्यापार चिह्न अधिनियम लागू होने का उद्देश्य देश में वाणिज्य वस्तु पर नकली व्यापार चिह्न के उपयोग को रोकने के लिए वस्तुओं व सेवाओं के व्यापार चिह्न का पंजीकरण व उन्हें संरक्षण प्रदान करना है। व्यापार चिह्न का पंजीकरण पंजीकृत स्वत्वधारी को कतिपय सांविधिक अधिकार प्रदान करता है, जो उसे व्यापार चिह्न के अतिलंघन करने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हेतु सक्षम बनाता है। यह उन सामान्य विधिक अधिकार के अतिरिक्त है जहां पासिंग ऑफ के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है।

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 तथा व्यापार चिह्न नियम, 2002, 15 सितंबर, 2003 से प्रभावी हुए। व्यापार चिह्न नियम, 2002 को 6 मार्च 2017 से व्यापार चिह्न नियम 2017 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय का मुख्यालय मुंबई में है तथा इसकी शाखाएं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में स्थित हैं।

देश में बौद्धिक संपदा अधिकार के विषय में सामान्य रूप से तथा व्यापार चिह्न के संबंध में विशेष रूप से बढ़ती जागरुकता के कारण व्यापार चिह्न रजिस्ट्री (टीएमआर) की गतिविधि तथा उत्तरदायित्व में लगातार वृद्धि हो रही है। व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अधीन और व्यापार चिह्न के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के लिए मैड्रिड प्रोटोकॉल से भारत के संबद्ध होने के बाद सेवा चिह्न, सुविख्यात चिह्न, सामूहिक चिह्न की संरक्षा तथा बहुवर्ग (मल्टी–क्लास) आवेदनों हेतु प्रावधान इत्यादि को शामिल किए जाने से इस भूमिका में और बढ़ोतरी हुई है।

1. 2021–22 के दौरान गतिविधियों की प्रवृत्तिः

वर्ष 2021–22 के दौरान व्यापार चिह्न रजिस्ट्री द्वारा की गई विविध गतिविधियों संबंधी जानकारी निम्नलिखित सारणी में प्रदान की गई है। आवेदन दाखिल करने की प्रवृत्ति यह इंगित करती है कि दाखिल आवेदनों की संख्या वर्ष 2020–21 के 431213 से बढ़ कर **447805** हो गयी, एवं व्यापार चिह्न का पंजीकरण 255976 से बढ़ कर **261408** हो गया। दाखिल, परीक्षित एवं पंजीकृत आवेदनों की संख्या के संबंध मे गतिविधियों का विवरण परिशिष्ट–I में दिया गया है।

क्र. सं.	गतिविधियाँ	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
1.	पंजीकरण के लिए दाखिल किए गए आवेदन	272974	323798	334805	431213	**447805**
2.	व्यापार चिह्न जर्नल में विज्ञापित आवेदनों की संख्या	423030	396063	378147	339356	**310196**
3.	पंजीकृत व्यापार चिह्न की संख्या	300913	316798	294172	255976	**261408**
4.	पंजीकरण के अतिरिक्त अन्यथा रूप में (अर्थात अस्वीकृति, परित्याग और आहरण द्वारा) निष्पादित पोस्ट–परीक्षित आवेदनों की संख्या	254864	202387	125394	38978	**57470**
5.	पंजीकरण का नवीकरण किए जाने वाले व्यापार चिह्नों की संख्या	64661	62497	70583	73100	**69968**
6.	पंजीकृत व्यापार चिह्न (समनुदेशन सहित) में पंजीकरण के बाद किए गए परिवर्तनों की प्रविष्टि हेतु निष्पादित अनुरोधों की संख्या	73764	47251	32596	29214	**22957**
7.	प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम,1957 की धारा 45(1) के तहत जारी प्रमाण पत्र	1605	2760	7362	9032	**5437**

2. व्यापार चिह्न आवेदन दाखिल करने की प्रवृत्तिः

2021—22 के दौरान, भारत में व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए दाखिल किए जा रहे आवेदनों की प्रवृत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 2021—22 में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में दाखिल आवेदनों की संख्या 2020—21 के 431213 से बढ़ कर **447805** हो गयी है परंतु विदेशियों द्वारा दाखिल आवेदनों की संख्या 2020—21 के 12619 से बढ़ कर 2021—22 में **13721** हो गयी है।

साथ ही, वर्ष 2021—22 के दौरान, मैड्रिड प्रणाली के तहत विदेशी आवेदकों के **15109** अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण व्यापार चिह्न के संरक्षण हेतु भारत में नामित किए गए। इन अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों का परीक्षण किया गया और इन पर राष्ट्रीय आवेदनों के रूप में आगे की कार्यवाही की गयी।

i. 2017—18 से 2021—22 के दौरान दाखिल आवेदनों का प्रवृत्तिः

वर्ष	भारतीय आवेदक	विदेशी आवेदक	कुल
2017—18	247734	25240	272974
2018—19	310116	13682	323798
2019—20	320940	13865	334805
2020—21	418594	12619	431213
2021—22	**434084**	**13721**	**447805**

ii. भारतीयों द्वारा दाखिल व्यापार चिह्न आवेदन—राज्यानुसारः

वर्ष के दौरान भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की कुल संख्या **434084** में से 83147 आवेदनों के साथ महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा। दिल्ली 64661 आवेदनों के साथ द्वितीय स्थान पर रही जबकि 45685 आवेदनों के साथ गुजरात तीसरे स्थान पर रहा। विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से आवेदकों से प्राप्त आवेदनों की संख्या के साथ ग्राफीय वर्णन नीचे प्रदर्शित किया गया हैः

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	आवेदनों की संख्या
अंडमान व निकोबार	45
आंध्र प्रदेश	5511
अरुणाचल प्रदेश	27
असम	1913
बिहार	6003

चंडीगढ़	2687
छत्तीसगढ़	2850
दादरा व नागर हवेली	171
दमन व दीव	72
दिल्ली	64661
गोवा	1044
गुजरात	45685
हरियाणा	26526
हिमाचल प्रदेश	2450
जम्मू व कश्मीर	2033
झारखंड	2238
कर्नाटक	24373
केरल	15878
लक्षद्वीप	5
मध्य प्रदेश	11960
महाराष्ट्र	83148
मणिपुर	152
मेघालय	59
मिज़ोरम	21
नागालैंड	51
उड़ीसा	2755
पुदुचेरी	367
पंजाब	14529
राजस्थान	20691
सिक्किम	45
तमिल नाडु	24382
तेलंगाना	16702
त्रिपुरा	144
उत्तर प्रदेश	36475
उत्तराखंड	3728
पश्चिम बंगाल	14703
कुल	**434084**

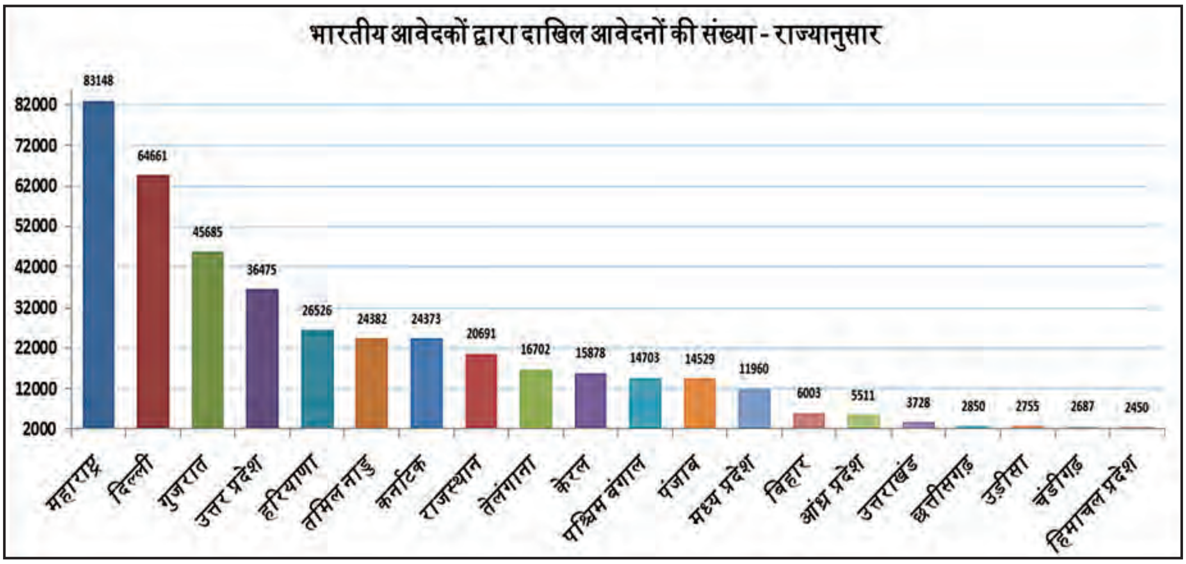

iii. विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनः

वर्ष 2021–22 के दौरान विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की संख्या **13721** रही। शीर्ष 20 विदेशी देशों द्वारा दाखिल किए गए आवेदनों की संख्या निम्न तालिका में प्रदान की गई है और साथ ही ग्राफीय वर्णन भी नीचे दियाः

आवेदन दाखिल करने वाले शीर्ष 20 विदेशी देश

देश का नाम	दाखिल आवेदनों की संख्या
संयुक्त राज्य अमेरिका	4599
चीन	1993
सिंगापुर	1224
यूनाइटेड किंगडम	697
संयुक्त अरब अमीरात	528
कोरिया गणराज्य	414
जापान	386
हांगकांग	340
स्विट्ज़रलैंड	336
कनाडा	270
जर्मनी	258
ऑस्ट्रेलिया	199
ताइवान, चीन का प्रांत	158
केमन द्वीप समूह	152
मलेशिया	125
फ्रांस	124
नीदरलैंड	110
बेल्जियम	100
ब्रिटिश वर्जिन आईलैन्ड्स	98
इटली	96
अन्य	1514
कुल	**13721**

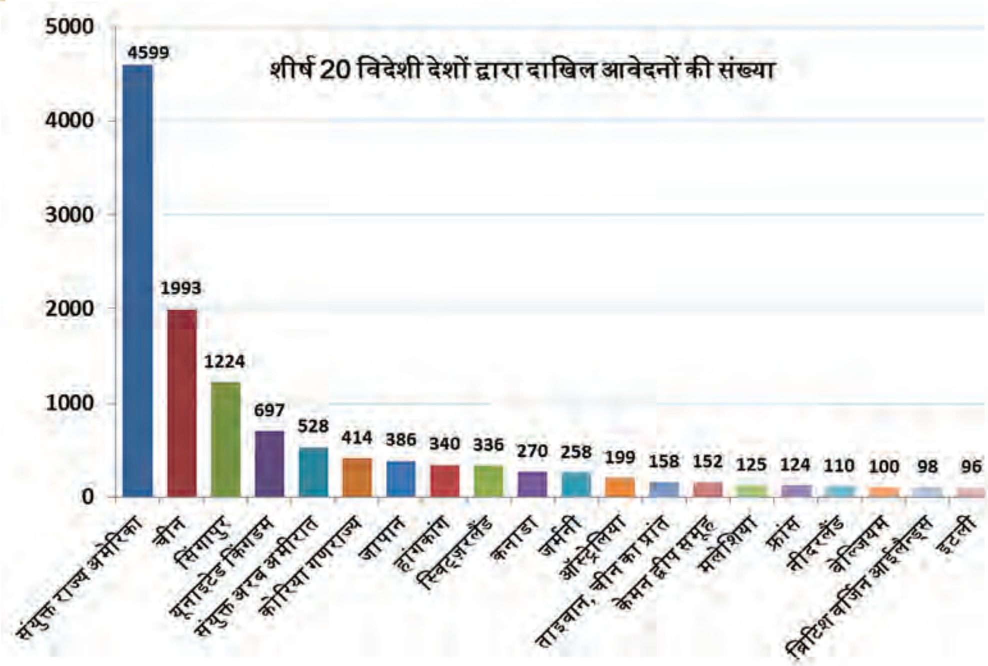

iv. वर्गानुसार दाखिल किए गए आवेदनों की प्रवृत्तिः

वर्ष 2021–22 के दौरान दाखिल किए गए व्यापार चिह्न आवेदनों की वर्गानुसार प्रवृत्ति निम्न प्रदत्त सारणी में दर्शायी गई है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी सर्वाधिक आवेदन वर्ग 5 के अंतर्गत की वस्तुओं (औषधीय, पशु चिकित्सीय तथा आरोग्यकारक पदार्थों आदि) के लिए प्राप्त हुए हैं।

वे वर्ग जिनमें आवेदन दाखिल किए गए थे उनके % भाग के साथ उनका विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ग	वस्तुओं / सेवाओं का विवरण	आवेदनों की संख्या	% भाग
1	उद्योग, विज्ञान, फोटोग्राफी, कृषि, उद्यान–कृषि, वानिकी, खाद आदि में उपयोग में लाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ	6814	1.52
2	पेंट और वार्निश	2234	0.50
3	सुगंधित पदार्थ, अंगराग आदि	20476	4.57
4	औद्योगिक तेल और चिकनाइयाँ (खाद्य तेल के अलावा) आदि	2198	0.49
5	औषधीय, भेषजीय, पशु चिकित्सीय और आरोग्यकारक पदार्थ आदि	71856	16.05
6	अन–रॉट और अंशतः रॉट सामान्य धातु एवं उनके मिश्र धातु आदि	5392	1.20
7	मशीन और मशीनी औजार, मोटरें, आदि	7783	1.74
8	हाथ से काम करने के औजार और उपकरण आदि	1831	0.41
9	वैज्ञानिक, समुद्री, सर्वेक्षण और विद्युत उपकरण, आदि।	23480	5.24
10	शाल्यिक, औषधीय, दंत और पशुचिकित्सा उपकरण और यंत्र आदि	6441	1.44
11	प्रकाशन साधित्र, तापक वाष्पजनक आदि	9599	2.14
12	वाहन और उनके पूर्जे, यंत्र, भूमि पर, व्योम में अथवा जल पर चलने के लिए यंत्र आदि	5218	1.17
13	अग्न्यास्त्र, गोला बारूद और क्षेपित्र आदि	296	0.07
14	बहुमूल्य वस्तुएं और उनका मिश्र धातु आदि	5649	1.26
15	संगीत के यंत्र (बोलने वाली मशीन और वायरलेस उपकरण के अतिरिक्त)	344	0.08

16	कागज और कागज की वस्तुएं, लेखन सामग्री, छपी सामग्री आदि	7081	1.58
17	गट्टा पर्चा, भारतीय रबर आदि	3344	0.75
18	चमड़े और कृत्रिम चमड़े आदि	4312	0.96
19	भवन निर्माण सामग्रियां आदि	6285	1.40
20	फर्नीचर, आईने आदि	6882	1.54
21	छोटे घरेलू बर्तन आदि	8700	1.94
22	रस्सी, सुतली आदि	978	0.22
23	सूत और धागे	678	0.15
24	टिशू (खंडित वस्तुएं) आदि	6047	1.35
25	बूट, जूते और स्लीपर सहित पहनने की वस्तुएं	33645	7.51
26	गोटा और कसीदा, फीता और चोटी आदि	1280	0.29
27	गलीचे, लोई, चटाइयां आदि	1064	0.24
28	खेल और खेलने की चीजें आदि	5468	1.22
29	मांस, मछली, मुर्गी पालन आदि	13760	3.07
30	कॉफी, चाय, कोको आदि	25657	5.73
31	कृषि, बागवानी और वन्य उत्पाद और अनाज जो अन्य वर्गों के अंतर्गत नहीं है	7784	1.74
32	बीयर, एल और पोर्ट, खनिज और वाति जल और अन्य अमद्यसारिक पेय जो अन्य वर्गों के अंतर्गत नहीं है	5676	1.27
33	वाइन स्प्रिट और मद्य पेय	2622	0.59
34	तम्बाकू, कच्चा या निर्मित, धूम्रपान करने वालों के लिए चीजें, दियासलाइयाँ	2855	0.64
35	विज्ञापन, कारोबार प्रबन्ध, कारोबार प्रशासन, कार्यालय कृत्य	42743	9.55
36	बीमा वित्तीय कार्य, आर्थिक कार्य, संपदा कार्य	7675	1.71
37	भवन निर्माण मरम्मत संस्थापन सेवाएं	5914	1.32
38	दूरसंचार	4156	0.93
39	यातायात, माल की पैकिंग और भंडारण, यात्रा इंतजाम	4694	1.05
40	सामग्री का बहिस्त्राव	1667	0.37
41	शिक्षा, प्रशिक्षण प्रदान करना, मनोरंजन, क्रीडा और सांस्कृतिक क्रियाकलाप	19991	4.46
42	वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाओं तथा उससे संबंधित शोध और अभिकल्प, औद्योगिक विश्लेषण और शोध सेवाएं, कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का डिजाइन और विकास	13875	3.10
43	खाद्य और पेय हेतु सेवाएं; अस्थायी निवास	13847	3.09
44	चिकित्सा सेवाएं; पशुचिकित्सा सेवाएं; मानव या पशुओं के लिए स्वच्छता और सौन्दर्य देखभाल; कृषि, बागवानी तथा वन्य सेवाएं,	8850	1.98
45	विधिक सेवाएं; सम्पत्ति और व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा सेवाएं; व्यक्तियों की आवश्यकता पूर्ति के लिए अन्य लोगों द्वारा प्रदान की जाने वाली व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाएं	4635	1.04

टिप्पणी: *बहुवर्ग आवेदन दाखिल करने का प्रावधान है क्योंकि एक से अधिक वर्ग की वस्तु तथा सेवाओं को एक ही आवेदन में उल्लिखित किया जा सकता है। उपरोक्त जानकारी के उद्देश्य से, वर्गानुसार आवेदनों के संबंध में, बहु–वर्गीय आवेदनों में प्रत्येक वर्ग पर पृथक रूप से विचार किया जाता है।*

v. **शाखानुसार दाखिल किए गए आवेदनों की प्रवृत्तिः**

वर्ष 2021–22 के दौरान, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की दिल्ली शाखा में अधिकतम संख्या में आवेदन **(163228)** दाखिल किए गए जिसके बाद क्रमशः मुंबई **(100637)**, चेन्नई **(88559)**, अहमदाबाद **(66875)** एवं कोलकाता **(28506)** का स्थान आता है।

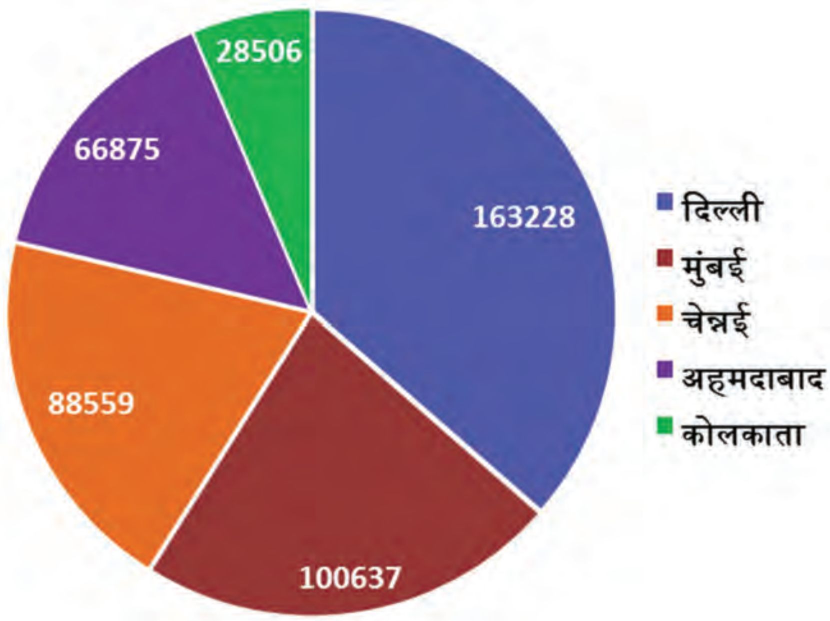

3. व्यापार चिह्न का पंजीकरण एवं अन्य गतिविधियाँः

वर्ष 2021–22 के दौरान, पंजीकृत व्यापार चिह्न की संख्या **261408** रही। दिनांक 31 मार्च, 2022 तक पंजीकृत व्यापार चिह्न की कुल संख्या **2628180** थी।

वर्ष के दौरान अन्य गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

- **69968** पंजीकृत व्यापार चिह्नों का नवीकरण किया गया,
- पंजीकृत व्यापार चिह्न (अन्य व्यक्तियों को उनके समनुदेशन सहित) के संदर्भ में पंजीकरण के उपरांत परिवर्तन हेतु **37045** अनुरोध प्राप्त हुए व **22957** अनुरोध निष्पादित कर दिए गए,
- कानूनी कार्यवाहियों में उपयोग के लिए अथवा विदेशों में पंजीकरण प्राप्त करने हेतु **21999** प्रमाणपत्र जारी किए गए,
- प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 45(1) के तहत **5437** प्रमाण पत्र प्रतिलिप्यधिकार के रूप में कलात्मक कार्य के पंजीकरण हेतु जारी किए गए।

रजिस्ट्री ने व्यापार चिह्न पंजीकरण के लिए विगत वर्ष के **339356** विज्ञापनों की तुलना में इस वर्ष के दौरान **310196** आवेदन व्यापार चिह्न जर्नल में विज्ञापित किए। पिछले पाँच वर्षों में व्यापार चिह्न जर्नल में प्रकाशित व्यापार चिह्न की प्रवृत्ति **परिशिष्ट II** में दिखाई गई है।

रजिस्ट्री ने व्यापार चिह्न अधिनियम और नियम के अधीन अर्ध न्यायिक कार्यवाहियाँ भी संचालित की जिनमें मुख्यतः विरोध और परिशोधन की कार्यवाहियाँ थी। वर्ष 2021–22 के दौरान **54990** विरोध की सूचना एवं **4071** परिशोधन हेतु आवेदन व्यापार चिह्न के पंजीकरण को रद्द करने अथवा व्यापार चिह्न के पंजीकरण को भिन्न करके व्यापार चिह्न के रजिस्टर में परिशोधन हेतु दाखिल किए गए तथा ऐसे **7233** मामलों का पूर्णतया निष्पादन कर दिया गया। ऐसे दाखिल और निष्पादित मामलों का विवरण **परिशिष्ट III** में दिया गया है।

4. पंजीकृत व्यापार चिह्न की संख्या का वर्गानुसार विवरण:

निम्न प्रदत्त सारणी वर्ष 2021–22 के दौरान पंजीकृत व्यापार चिह्न का वर्गानुसार विवरण प्रस्तुत करती है। यह देखा गया है कि वर्ग–5 के अंतर्गत सर्वाधिक **33857** व्यापार चिह्न पंजीकृत किए गए, जो कुल पंजीकरण का 12.95% है, जिसके बाद वर्ग–35 आता है जो 8.41% है।

वर्ग	वस्तुओं / सेवाओं का विवरण	आवेदनों की संख्या	% भाग
1	उद्योग, विज्ञान, फोटोग्राफी, कृषि, उद्यान–कृषि, वानिकी, खाद आदि में उपयोग में लाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ	4438	1.70
2	पेंट और वार्निश	1438	0.55
3	सुगंधित पदार्थ, अंगराग आदि	11269	4.31
4	औद्योगिक तेल और चिकनाइयाँ (खाद्य तेल के अलावा) आदि	1559	0.60
5	औषधीय, भेषजीय, पशु चिकित्सीय और आरोग्यकारक पदार्थ आदि	33857	12.95
6	अन–रॉट और अंशतः रॉट सामान्य धातु एवं उनके मिश्र धातु आदि	3644	1.39
7	मशीन और मशीनी औजार, मोटरें, आदि	5174	1.98
8	हाथ से काम करने के औजार और उपकरण आदि	1647	0.63
9	वैज्ञानिक, नाविक, सर्वे, वैद्युत उपकरण आदि	15606	5.97
10	शाल्यिक, औषधीय, दंत और पशुचिकित्सा उपकरण और यंत्र आदि	4335	1.66
11	प्रकाशन साधित्र, तापक वाष्पजनक आदि	6230	2.38
12	वाहन और उनके पूर्जे, यंत्र, भूमि पर, व्योम में अथवा जल पर चलने के लिए यंत्र आदि	3070	1.17
13	अग्न्यास्त्र, गोला बारूद और क्षेपित्र आदि	222	0.08
14	बहुमूल्य वस्तुएं और उनका मिश्र धातु आदि	3608	1.38
15	संगीत के यंत्र (बोलने वाली मशीन और वायरलेस उपकरण के अतिरिक्त)	295	0.11
16	कागज और कागज की वस्तुएं, लेखन सामग्री, छपी सामग्री आदि	4988	1.91
17	गट्टा पर्चा, भारतीय रबर आदि	2132	0.82
18	चमड़े और कृत्रिम चमड़े आदि	3097	1.18
19	भवन निर्माण सामग्रियां आदि	4068	1.56
20	फर्नीचर, आईने आदि	4474	1.71
21	छोटे घरेलू बर्तन आदि	6849	2.62
22	रस्सी, सुतली आदि	805	0.31
23	सूत और धागे	523	0.20
24	टिशू (खंडित वस्तुएं) आदि	4338	1.66
25	बूट, जूते और स्लीपर सहित पहनने की वस्तुएं	20408	7.81
26	गोटा और कसीदा, फीता और चोटी आदि	942	0.36
27	गलीचे, लोई, चटाइयां आदि	853	0.33
28	खेल और खेलने की चीजें आदि	3837	1.47
29	मांस, मछली, मुर्गी पालन आदि	7694	2.94

30	कॉफी, चाय, कोको आदि	12871	4.92
31	कृषि, बागवानी और वन्य उत्पाद और अनाज जो अन्य वर्गों के अंतर्गत नहीं है	4733	1.81
32	बीयर, एल और पोर्ट, खनिज और वाति जल और अन्य अमद्यसारिक पेय जो अन्य वर्गों के अंतर्गत नहीं है	3625	1.39
33	वाइन स्प्रिट और मद्य पेय	1555	0.59
34	तम्बाकू, कच्चा या निर्मित, धूम्रपान करने वालों के लिए चीजें, दियासलाइयाँ	1550	0.59
35	विज्ञापन, कारोबार प्रबन्ध, कारोबार प्रशासन, कार्यालय कृत्य	21977	8.41
36	बीमा वित्तीय कार्य, आर्थिक कार्य, संपदा कार्य	4550	1.74
37	भवन निर्माण मरम्मत संस्थापन सेवाएं	4045	1.55
38	दूरसंचार	2904	1.11
39	यातायात, माल की पैकिंग और भंडारण, यात्रा इंतजाम	3047	1.17
40	सामग्री का बहिस्त्राव	1332	0.51
41	शिक्षा; प्रशिक्षण प्रदान करना, मनोरंजन, क्रीडा और सांस्कृतिक क्रियाकलाप	12883	4.93
42	वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाओं तथा उससे संबंधित शोध और अभिकल्प, औद्योगिक विश्लेषण और शोध सेवाएं, कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का डिजाइन और विकास	9520	3.64
43	खाद्य और पेय हेतु सेवाएं; अस्थायी निवास	7507	2.87
44	चिकित्सा सेवाएं ; पशुचिकित्सा सेवाएं; मानव या पशुओं के लिए स्वच्छता और सौन्दर्य देखभाल; कृषि, बागवानी तथा वन्य सेवाएं,	4862	1.86
45	विधिक सेवाएं; सम्पत्ति और व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा सेवाएं; व्यक्तियों की आवश्यकता पूर्ति के लिए अन्य लोगों द्वारा प्रदान की जाने वाली व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाएं	3047	1.17

टिप्पणी: बहुवर्ग आवेदन दाखिल करने का प्रावधान है (अर्थात एक से अधिक वर्ग की वस्तु तथा सेवाओं के लिए एकल आवेदन) व तदनुसार,सभी वर्गों की वस्तुओं व सेवाओं के लिए एकल पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। उपरोक्त जानकारी के उद्देश्य से, वर्गानुसार आवेदनों के संबंध में, बहु–वर्गीय आवेदनों में प्रत्येक वर्ग पर पृथक रूप से विचार किया जाता है।

5. राजस्वः

वर्ष 2021–22 के दौरान, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री ने रू. 417.765 करोड़ (इसमें मेड्रिड प्रणाली के तहत अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के शुल्क के रूप में आईबी से प्राप्त रू. 31.35 करोड़ रू. शामिल हैं) का राजस्व अर्जित किया जबकि गत वर्ष के दौरान यह रू. 361.13 करोड़ रहा।

परिशिष्ट I

पिछले पाँच वर्षों में व्यापार चिह्न आवेदनों की प्रवृत्ति

	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
दाखिल	272974	323978	334805	431213	**447805**
परीक्षित	306259	337541	338551	463912	**431520**
पंजीकृत	300913	316798	294172	255976	**261408**

पिछले पाँच वर्षों में व्यापार चिह्न आवेदनों की चित्रमय प्रतिनिधित्व

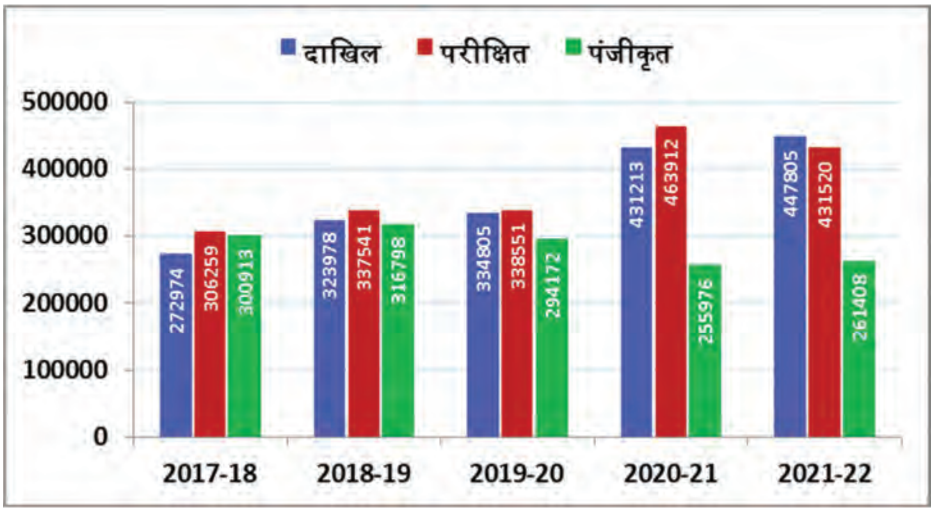

परिशिष्ठ II

पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रकाशित व्यापार चिह्नों की संख्या

क्र. सं.	वर्ष	जर्नल में प्रकाशित व्यापार चिह्न की संख्या
1	2017–18	423030
2	2018–19	396063
3	2019–20	378147
4	2020–21	339356
5	**2021–22**	**310196**

परिशिष्ट III

1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक विभिन्न कार्यालयों में दाखिल विरोध/परिशोधन आवेदन और उनके निष्पादन का विवरण

व्यापार चिह्न कार्यालय	दाखिल विरोध/परिशोधन	निष्पादित मामले
अहमदाबाद	9754	946
चेन्नई	10258	2537
दिल्ली	22361	548
कोलकाता	5135	628
मुंबई	11553	2574
आईआर डिविजन	700	53

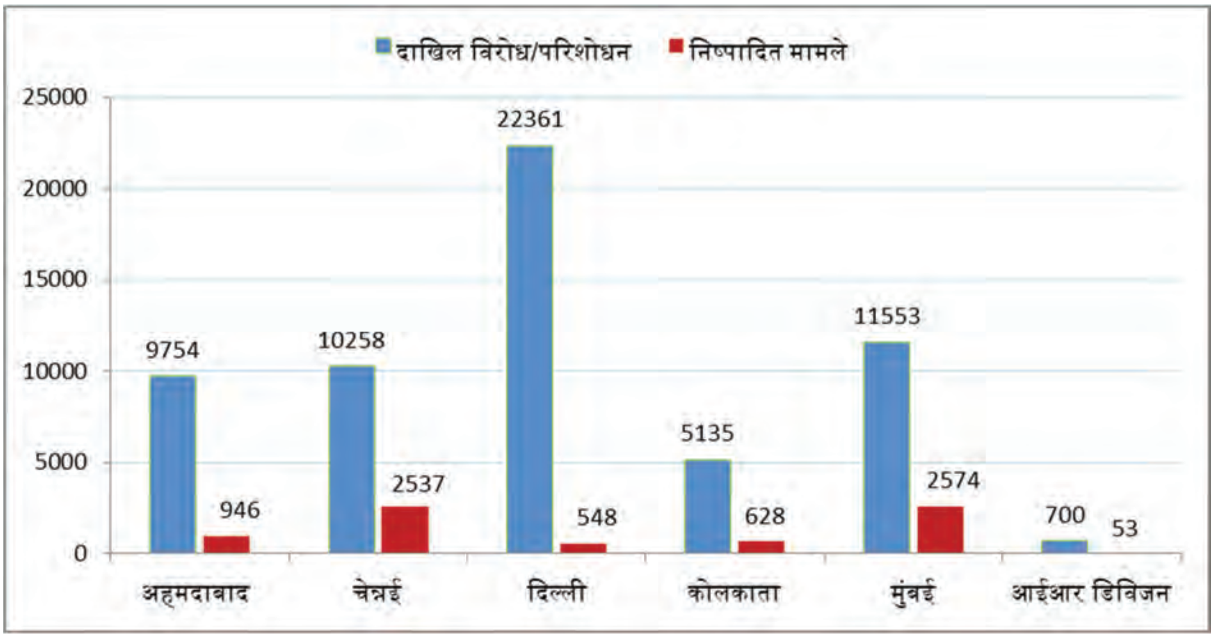

पिछले पाँच वर्षों के दौरान पंजीकृत व्यापार चिह्न

क्रम संख्या	वर्ष	पंजीकृत व्यापार चिह्नों की संख्या
1	2017–18	300913
2	2018–19	316798
3	2019–20	294172
4	2020–21	255976
5	**2021–22**	**261408**

पिछले 5 वर्षों के दौरान पंजीकृत व्यापार चिह्न की ग्राफ़ीय प्रस्तुति

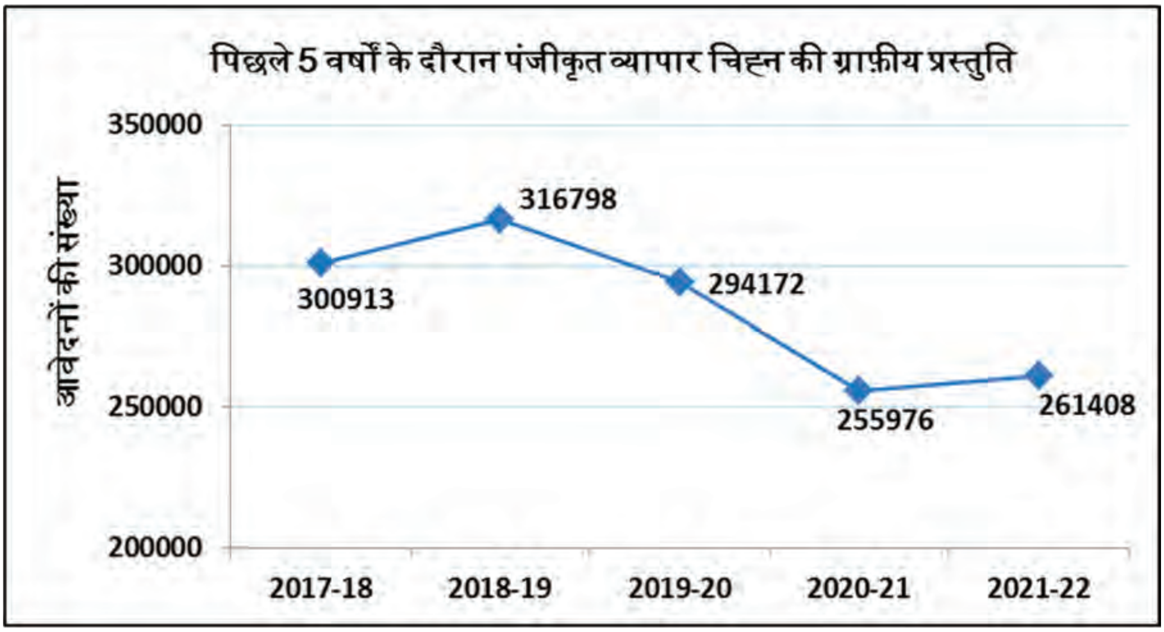

अध्याय–VII

चिह्नों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण हेतु मैड्रिड प्रणाली

परिचय

मैड्रिड प्रणाली कई देशों में व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए एकल प्रक्रिया प्रदान करती है। यह दो संधियों द्वारा शासित होती है नामतः, 'द मैड्रिड एग्रीमेंट कंसर्निंग द इन्टरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स' (संक्षेप में मैड्रिड एग्रीमेंट के रूप में जाना जाता है) और 'प्रोटोकॉल रिलेटिंग टू द मैड्रिड एग्रीमेंट' (संक्षेप में मैड्रिड प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है)।

ये संधियाँ स्विट्जरलैंड के जेनेवा में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (वायपो) के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो (आईबी) द्वारा प्रशासित होती हैं।

1. भारत के मैड्रिड प्रोटोकॉल में शामिल होने की पृष्ठभूमिः

- 8 फरवरी 2007 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिह्नों के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के संबंध में भारत के मैड्रिड प्रोटोकॉल में शामिल होने के लिए अपनी स्वीकृति दी।
- 21 सितंबर 2010 को व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 को संशोधित किया गया, जिसमें 'मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के माध्यम से व्यापार चिह्न के संरक्षण से संबंधित विशेष प्रावधान' को अधिनियम में अंतःस्थापित किया गया।
- व्यापार चिह्न (संशोधन) नियम, 2013 को प्रभाव में लाने के लिए 14 जनवरी 2013 के राजपत्र में व्यापार चिह्न (संशोधन) नियम, 2013 प्रकाशित किए गए।
- 8 जुलाई, 2013 से भारत में मैड्रिड प्रोटोकॉल के प्रावधान लागू हो गए।

मैड्रिड सिस्टम के तहत चिह्नों के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण की प्रक्रिया (विशेष रूप से मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत) निम्नानुसार वर्णित हैः

मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत पंजीकरण

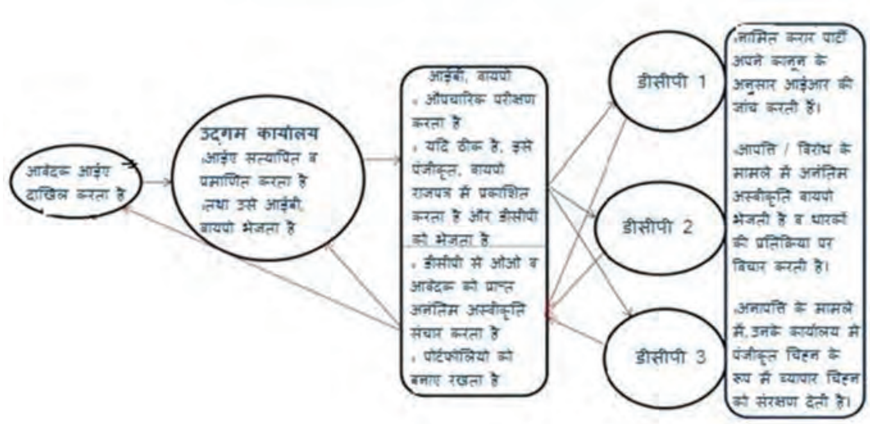

2. भारत में मैड्रिड प्रणाली का कार्यान्वयनः

2.1 अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण विंगः

मुंबई में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के प्रधान कार्यालय में अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण विंग की स्थापना की गई है। यह विंग मुख्य

रूप से भारतीय उद्यमियों से प्राप्त अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के लिए आवेदनों के संबंध में मैड्रिड प्रणाली के तहत "उद्गम कार्यालय" (ऑफिस ऑफ ऑरिजिन) के रूप में तथा मैड्रिड प्रणाली के तहत "नामित करार पार्टी कार्यालय" (ऑफिस ऑफ द डेज़ीग्नेटिंग कोंट्रेक्टिंग पार्टी) के रूप में, विदेशी आवेदक के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के संबंध में, जहां भारत को चिह्न के संरक्षण के लिए नामित किया गया है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है।

उद्गम कार्यालय के रूप में अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण विंग इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करता है:

- भारतीय उद्यमियों से फॉर्म एमएम 2 पर अंतर्राष्ट्रीय आवेदन प्राप्त करना, उनके साथ ऐसे आवेदनों के विषय में ऑन–लाइन संवाद करना और व्यापार चिह्न रजिस्ट्री (टीएमआर) की व्यापक ई–फाइलिंग सेवाओं के माध्यम से आवेदकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करना,
- ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों को सत्यापित करना और प्रमाणित करना और उन्हें वायपो को प्रेषित करना,
- यदि भारतीय कार्यालय द्वारा अग्रेषित अंतरराष्ट्रीय आवेदनों के संबंध में, वायपो द्वारा अनियमितताओं के विषय में सूचित किया जाता है, तो संबंधित आवेदकों से संपर्क करना और अनियमितताओं के विषय में वायपो को उत्तर देना,
- उन मामलों में जहां भारत में व्यापार चिह्न आवेदन या पंजीकरण जिसके आधार पर अंतरराष्ट्रीय आवेदन दाखिल किया गया था वह खत्म हो जाता है, वायपो को अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के प्रभाव को रोकने के लिए संचार करना,
- साप्ताहिक आधार पर एफ़टीपी सर्वर के माध्यम से भारत को नामित करने वाले अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों के साथ–साथ भारत से उद्गम होने वाले अंतरराष्ट्रीय आवेदनों के संबंध में वायपो के साथ सभी पत्राचार करना।

2.2. मैड्रिड प्रणाली के तहत व्यापार चिह्नों का अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण–भारतीय आवेदक:

वर्ष 2021–22 के अंत तक, भारतीय व्यापार चिह्न कार्यालय ने मैड्रिड प्रणाली के तहत व्यापार चिह्न के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण हेतु **2398** आवेदन प्राप्त किए हैं, जिसमें से **2223** आवेदन सत्यापित, प्रमाणित किए गए एवं वायपो को अग्रेषित किए गए तथा इन आवेदनों में से **1799** चिह्न वायपो के स्तर पर पंजीकृत किए गए हैं।

पिछले 5 वर्षों के दौरान भारतीय कार्यालय द्वारा प्राप्त व वायपो को प्रेषित भारतीय उद्यमियों के अंतरराष्ट्रीय आवेदनों और मैड्रिड प्रणाली के तहत वायपो के साथ उनके पंजीकरण की संख्या निम्नानुसार हैं:

वर्ष	प्राप्त अंतरराष्ट्रीय आवेदन	वायपो द्वारा किए गए अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण
2017–18	222	205
2018–19	414	238
2019–20	445	418
2020–21	338	309
2021–22	**396**	**340**

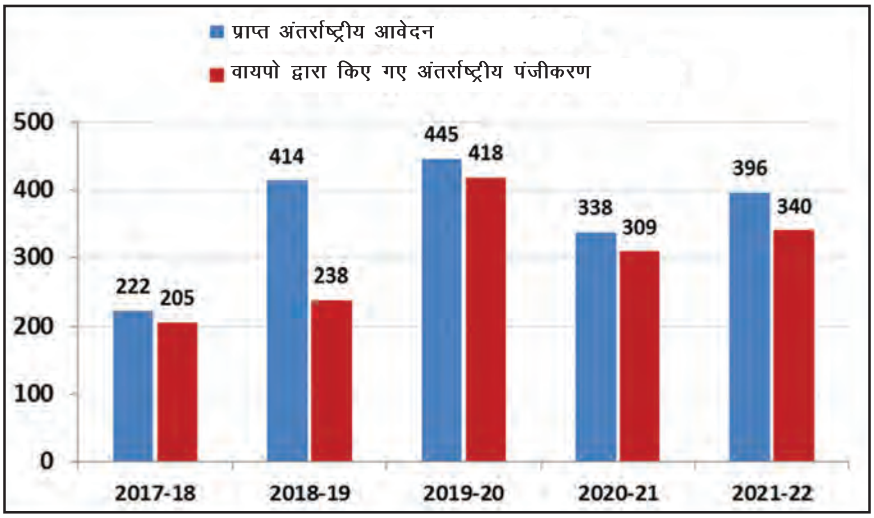

2.3. नामित करार पार्टी कार्यालय के रूप में, अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण विंग इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करता है:

- वायपो द्वारा भारतीय कार्यालय को अधिसूचित अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण का विवरण व्यापार चिह्न रजिस्ट्री डाटाबेस में स्थानांतरित करना, और राष्ट्रीय आवेदन के समान आईआरडीआई के रूप में प्रतिरूप रिकॉर्ड बनाना,
- इस तरह के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के विषय में वायपो की सूचनाओं के अनुसार व्यापार चिह्न रजिस्ट्री (टीएमआर) रिकॉर्ड को अद्यतन करना, जैसे कि धारक के नाम या पते में परिवर्तन, अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के तहत माल/सेवाओं को प्रतिबंधित करना, त्याग, आदि,
- व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 व उसके तहत बने नियमों के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों का परीक्षण करना व यदि अधिनियम के अनुसार भारत में चिह्न को संरक्षण नहीं प्रदान किया जा सकता है तो वायपो को अनंतिम असम्मति प्रेषित करना,
- हमारी राष्ट्रीय विधि के अनुसार ऐसे अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के धारकों की ओर से प्रस्तुत अनंतिम असम्मति के विरुद्ध प्रतिक्रिया पर ध्यान देना और यदि आवश्यकता हो, तो कारण बताओ सुनवाई की समय सारणी तय करना,
- हमारे राष्ट्रीय व्यापार चिह्न जर्नल में स्वीकृत मामलों को प्रकाशित करना,
- ऐसे प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय पदों के विरुद्ध, यदि कोई हो, विरोध को प्राप्त करना, और विरोध के आधार पर वायपो को अनंतिम असम्मति भेजना, अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण धारक की ओर से जवाबी कथन प्राप्त करना और विधि के अनुसार विपक्षी कार्यवाही आयोजित करना,
- ऐसे अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के संबंध में पंजीकार के आदेशों के खिलाफ दाखिल अपील/रिट याचिका के मामले में कार्यालय का प्रतिनिधित्व करना,
- वायपो को ऐसे अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के संबंध में अंतिम (साथ ही आगे के निर्णय, यदि कोई हों) का संचार करना।

2.4. वर्ष 2021–22 के दौरान गतिविधियाँ–अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण :

- वायपो ने भारत में व्यापार चिह्न के संरक्षण के लिए **15109** अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों को भारतीय कार्यालय को अधिसूचित किया,
- इन सभी अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों का प्रतिरूप रिकॉर्ड आईआरडीआई के रूप में बनाया गया एवं **14406** आईआरडीआई का परीक्षण किया गया,
- परीक्षण के आधार पर **9193** चिह्नों के संबंध में अनंतिम अस्वीकृति को वायपो को सूचित किया गया,

- व्यापार चिह्न जर्नल में प्रकाशन के अनुसरण में प्राप्त तीसरे पक्ष के विरोध के आधार पर, **700** अनंतिम अस्वीकृति वायपो को सूचित की गईं,
- **53** विरोधों का अंतिम निष्पादन किया गया,
- व्यापार चिह्न अधिनियम के तहत सभी प्रक्रियाएँ पूर्ण करने के उपरांत संरक्षण प्रदान करने के लिए **6971** अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के मामले वायपो प्रेषित किए गए; **6971** में से **4437** अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों के संबंध में, आवेदकों को इस कार्यालय से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं हुई और भारत में इस तरह के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों के तहत चिह्न अनुदानित किए गए,
- **575** अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों को भारत में चिह्न के संरक्षण के लिए अस्वीकृत किया गया।

वायपो द्वारा अधिसूचित अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों की संख्या और सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद गत 5 वर्षों के भीतर वायपो को भेजे गए ऐसे अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों के तहत चिह्नों के संरक्षण का अनुदान इस प्रकार है:

वर्ष	वायपो से प्राप्त अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण की अधिसूचना	भारतीय कार्यालय द्वारा अनुदानित अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण की संरक्षा
2017–18	13475	12642
2018–19	14778	18038
2019–20	14001	14699
2020–21	12913	9943
2021–22	**15109**	**6971**

विगत 5 वर्षों के दौरान प्राप्त वायपो द्वारा अधिसूचित अंतरराष्ट्रीय आवेदनों की प्रवृत्ति

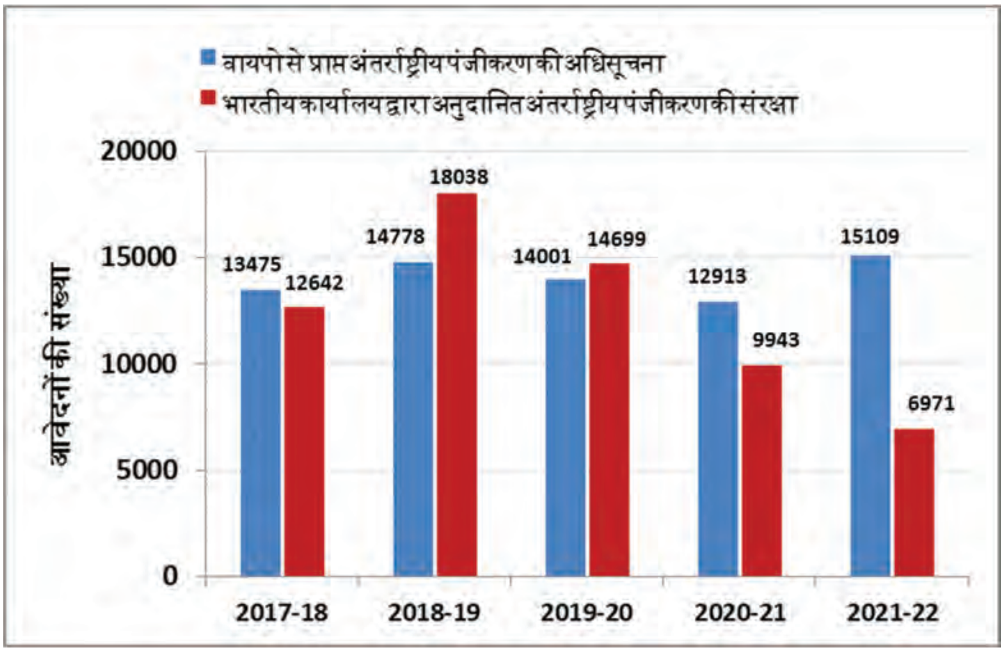

3. राजस्व

भारतीय कार्यालय को वायपो से मैड्रिड प्रणाली के तहत अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों के संबंध में राजस्व प्राप्त होता है, जहाँ ऐसे अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों के नवीकरण के साथ–साथ भारत में चिह्न का संरक्षण मांगा गया है। वर्ष 2021–22 के दौरान, भारतीय कार्यालय ने चिह्नों के संरक्षण के लिए भारत को नामित करने वाले अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों के शुल्क के रूप में रू. 31.349 करोड़ प्राप्त किए।

अध्याय–VIII

भौगोलिक उपदर्शन

परिचय

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री (जीआईआर) एक वैधानिक संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य भौगोलिक उपदर्शन से संबंधित वस्तुओं के पंजीकरण और उन्हें बेहतर संरक्षण प्रदान करना और भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 का प्रशासन करना है, जिसे 15 सितंबर 2003 को लागू किया गया था। भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री कार्यालय चेन्नई में स्थित है।

रजिस्ट्री भारतीय भौगोलिक उपदर्शन के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न भागों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन तथा ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेता रहा है। चाय, कॉफी, मसाले, कृषि और बागवानी उत्पाद, हस्तकरघा उत्पाद, हस्तशिल्प, वस्त्र, प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुएँ, दुग्धउत्पाद, प्राकृतिक वस्तुएँ, स्पिरिट एवं मद्य के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

1. कार्य निष्पादन की प्रमुख विशेषताएँ:–

रजिस्ट्री ने 15 सितंबर, 2003 से पंजीकरण हेतु भौगोलिक उपदर्शन आवेदन प्राप्त करना प्रारम्भ किया है। 31 मार्च, 2022 तक रजिस्ट्री ने कुल 861 (आठ सौ इकसठ) जीआई आवेदन प्राप्त किए हैं।

रजिस्ट्री को मई 2009 से भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन भी प्राप्त करने प्रारम्भ किया हैं तथा रजिस्ट्री ने 31 मार्च, 2022 तक 13569 (तेरह हजार पांच सौ उनहत्तर) भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन प्राप्त किए हैं।

15 सितम्बर, 2003 से अब तक कुल 420 (चार सौ बीस) भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) पंजीकृत किए गए हैं। कुल 7086 (सात हजार छियासी) भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक कार्यालय ने **116** भौगोलिक उपदर्शन आवेदन एवं **5745** भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन प्राप्त किए हैं, **50** भौगोलिक उपदर्शन एवं **2201** भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ताओं का पंजीकरण किया गया है।

2. भौगोलिक उपदर्शन आवेदन:–

31 मार्च, 2022 तक भौगोलिक उपदर्शन आवेदन की स्थिति

दायर भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की कुल संख्या	861
पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की कुल संख्या	**420**

31 मार्च, 2022 तक प्राप्त भौगोलिक उपदर्शन आवेदन का स्थितिवार ब्यौरा

भौगोलिक उपदर्शन आवेदन पंजीकृत	420
भौगोलिक उपदर्शन आवेदन प्रक्रिया में हैं	310
विरोध के तहत भौगोलिक उपदर्शन आवेदन	02
भौगोलिक उपदर्शन आवेदन एवं अन्य निपटान	129
कुल भौगोलिक उपदर्शन आवेदन प्राप्त हुए	**861**

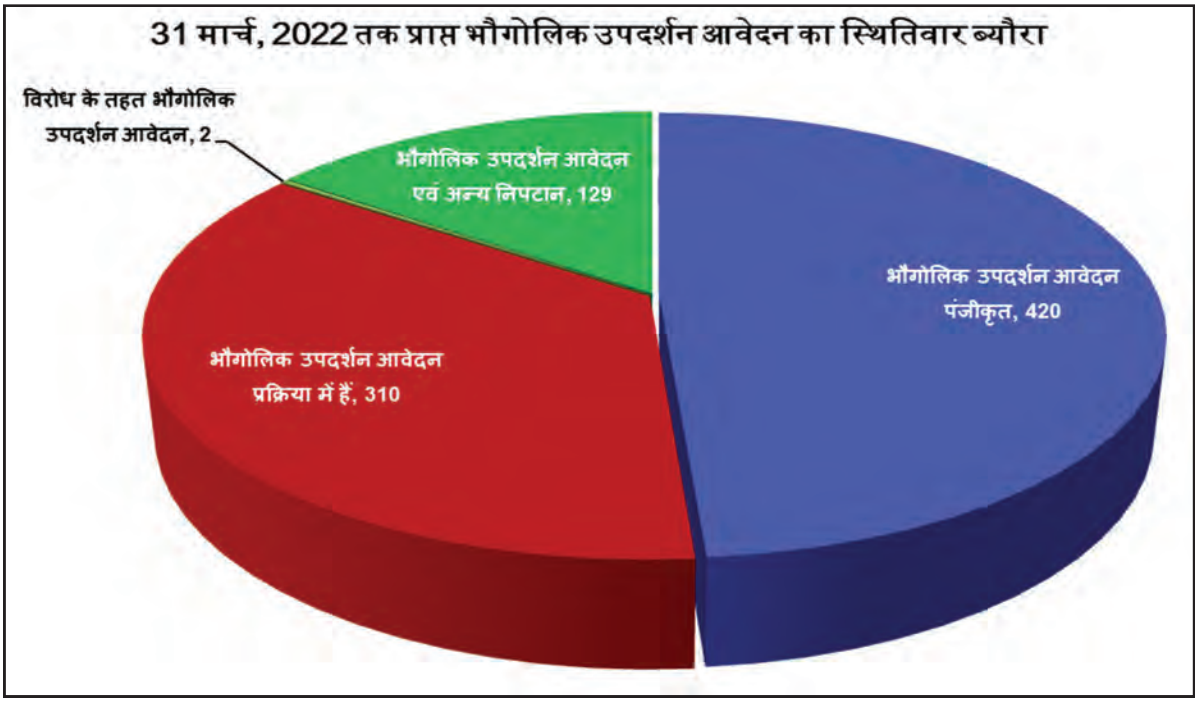

31 मार्च, 2022 तक दाखिल किए गए भौगोलिक उपदर्श नआवेदन का वर्ष वार विवरण

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2003—04	6
2004—05	29
2005—06	16
2006—07	33
2007—08	37
2008—09	44
2009—10	40
2010—11	27
2011—12	148
2012—13	24
2013—14	75
2014—15	47
2015—16	17
2016—17	32
2017—18	38
2018—19	32
2019—20	42
2020—21	58
2021—22	**116**
कुल	**861**

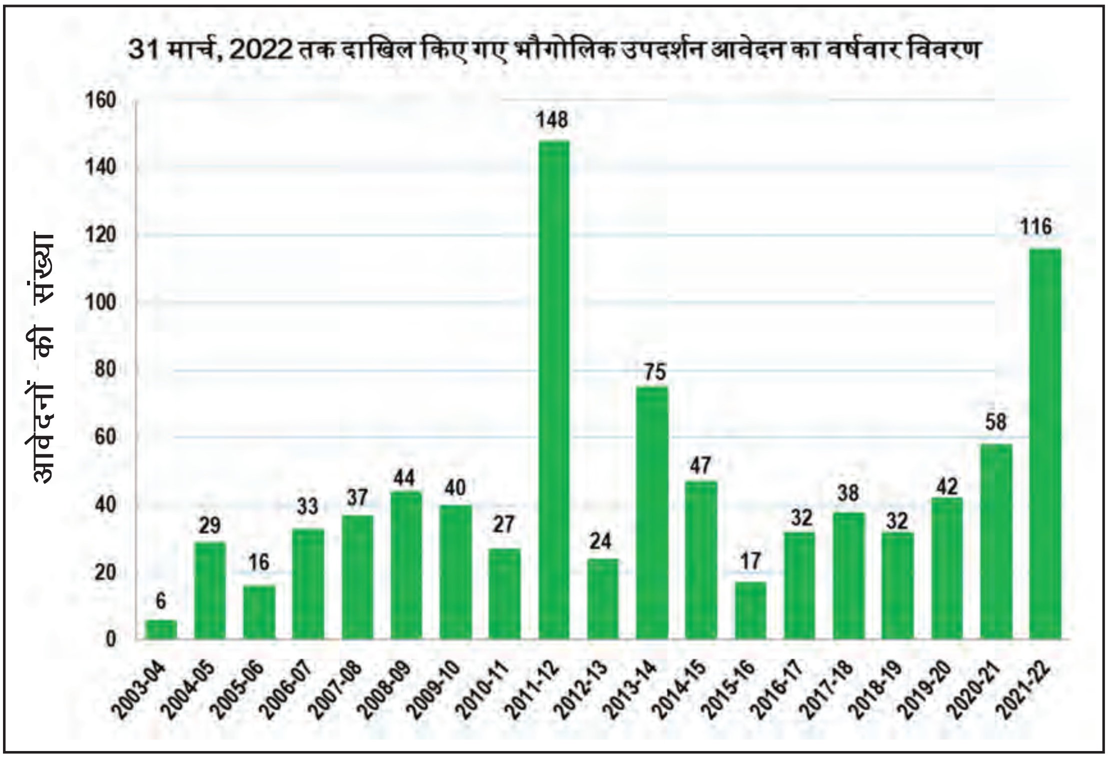

भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम, 1999 की धारा 2 (च) के अनुसार 31 मार्च, 2022 तक पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन का वस्तुओं के अनुसार विवरण

भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम, 1999 की धारा 2 (च) के अनुसार	वस्तु भौगोलिक उपदर्शन के लिए प्राप्त हुए आवेदन	पंजीकृत उपदर्शन की संख्या
हस्तकला (कपड़ा सहित)	389	232
कृषि	252	125
निर्मित	149	36
खाद्य सामग्री	61	25
प्राकृतिक	10	2
कुल	**861**	**420**

भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम, 1999 की धारा 2(च) के अनुसार 31 मार्च, 2022 तक पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन का वस्तुओं के अनुसार विवरण

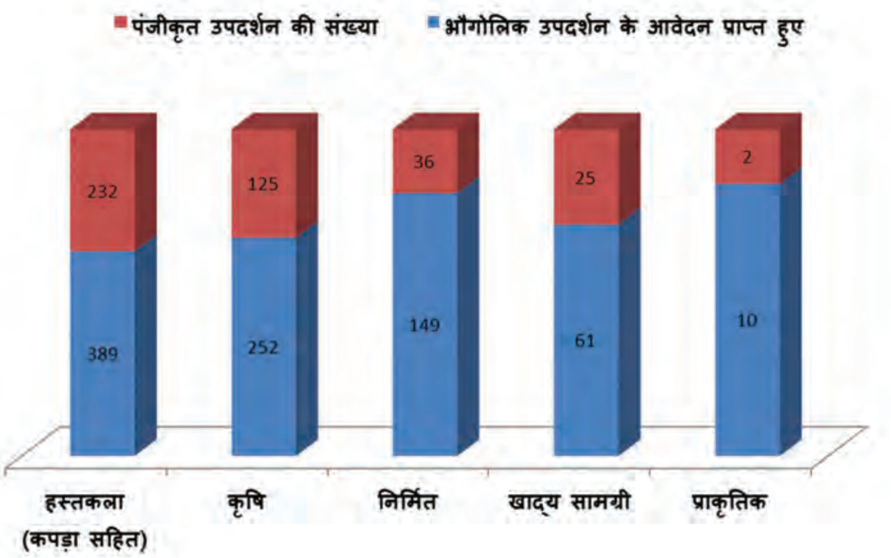

31 मार्च, 2021 तक राज्यवार पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन

राज्य / अस्तित्व	पंजीकृत भौ. उ. की संख्या
आंध्र प्रदेश	17
अरुणाचल प्रदेश	2
असम	10
बिहार	14
छत्तीसगढ	6
गोवा	5
गुजरात	16
हिमाचल प्रदेश	10
भारत (बहु राज्य)–(कर्नाटक और महाराष्ट्र)	1
भारत (केरल और तमिलनाडु)	1
भारत (केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु)	1
भारत–(महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश)	1
भारत (उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश)	1
भारत (मणिपुर और नागालैंड)	1
भारत–(महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमन दीव)	1
भारत (पंजाब / हरियाणा / हिमाचल प्रदेश / दिल्ली / उत्तराखंड / उत्तर प्रदेश / जम्मू और कश्मीर)	1
भारत (पंजाब, हरियाणा और राजस्थान)	1
भारत (आंध्र प्रदेश और ओडिशा)	1
भारत (कर्नाटक और केरल)	2
भारत (तेलंगाना और आंध्र प्रदेश	1
भारत (सिक्किम और पश्चिम बंगाल)	1

जम्मू और कश्मीर	8
झारखंड	1
कर्नाटक	42
केरल	30
मध्य प्रदेश	11
महाराष्ट्र	30
मणिपुर	6
मेघालय	2
मिजोरम	7
नागालैंड	4
उड़ीसा	17
पुदुचेरी	2
राजस्थान	15
सिक्किम	1
तमिलनाडु	42
तेलंगाना	15
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	34
उत्तराखंड	8
पश्चिम बंगाल	21
विदेशी	29
कुल	**420**

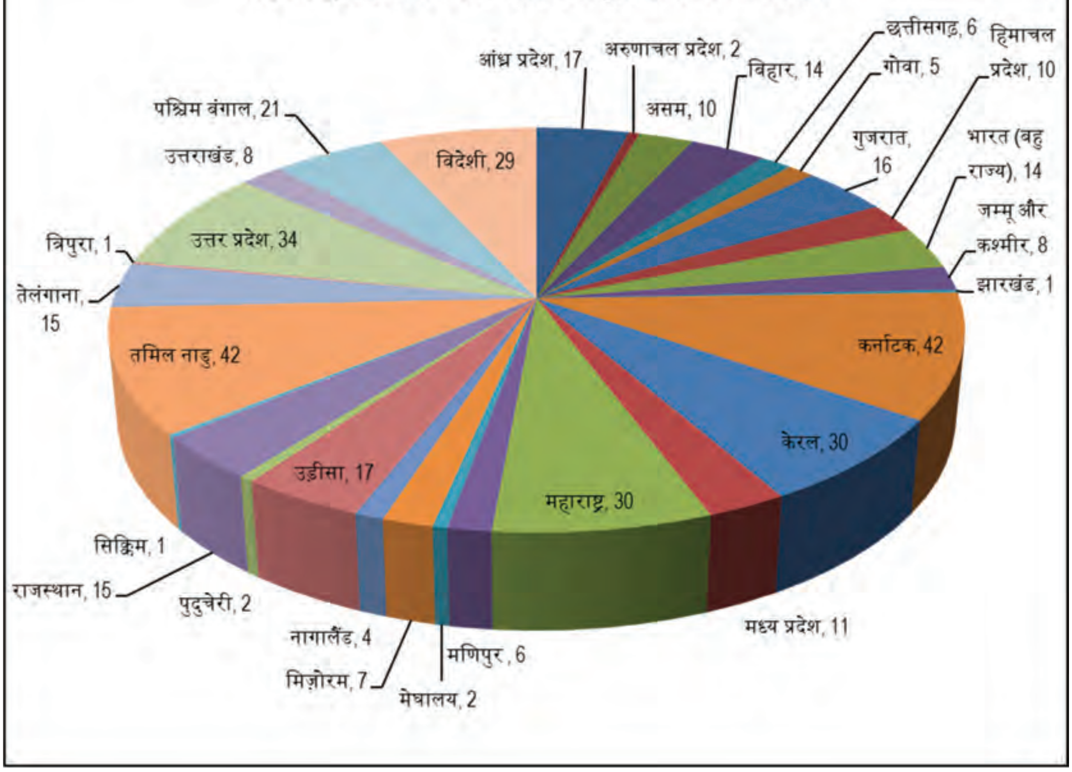

31 मार्च, 2022 तक राज्यवार पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन

3. प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन

भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन प्राप्त करने का प्रावधान 2003 से उपलब्ध था किन्तु मई 2009 से रजिस्ट्री ने भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन प्राप्त करना प्रारम्भ किया तथा रजिस्ट्री ने 31 मार्च, 2022 तक 13569 (तेरह हजार पांच सौ उनहत्तर) भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन प्राप्त किए हैं।

31 मार्च, 2022 तक दाखिल भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों का वर्षवार विवरण

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2003—04	0
2004—05	0
2005—06	0
2006—07	0
2007—08	0
2008—09	0
2009—10	101
2010—11	124
2011—12	145
2012—13	1070
2013—14	471
2014—15	262
2015—16	176
2016—17	1548
2017—18	823
2018—19	662
2019—20	1476
2020—21	966
2021—22	**5745**
कुल	**13569**

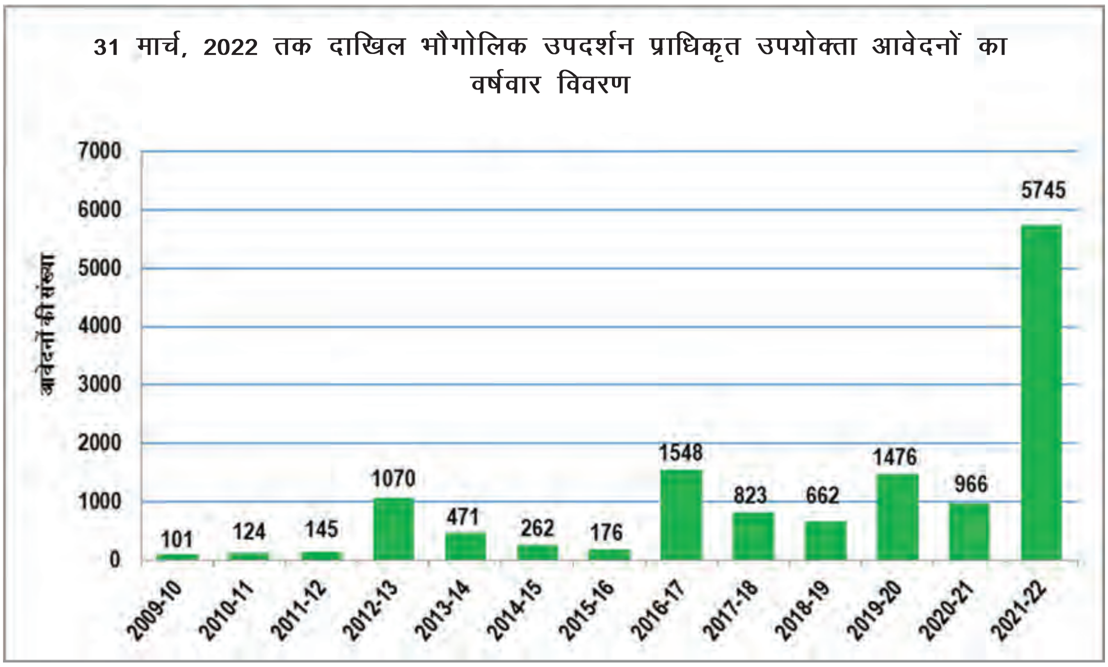

31 मार्च, 2022 तक भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन की स्थिति

पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या	7086
परीक्षित भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या	1695
पूर्व–परीक्षित भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या	2170
विज्ञापित भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या	2612
विरोध के अधीन भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या	1
विलय किए गए भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या	5
भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की कुल संख्या	**13569**

31 मार्च, 2022 तक भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों का वस्तुओं के अनुसार विवरण

भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम, 1999 की धारा 2(च) के अनुसार वस्तुएँ	प्राप्त भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या	पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या
हस्तकला (वस्त्र सहित)	6592	3083
कृषि	6529	3653
विनिर्मित	178	175
खाद्य पदार्थ	262	171
प्राकृतिक	8	4
कुल	**13569**	**7086**

31 मार्च, 2022 तक भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों का वस्तुओं के अनुसार विवरण

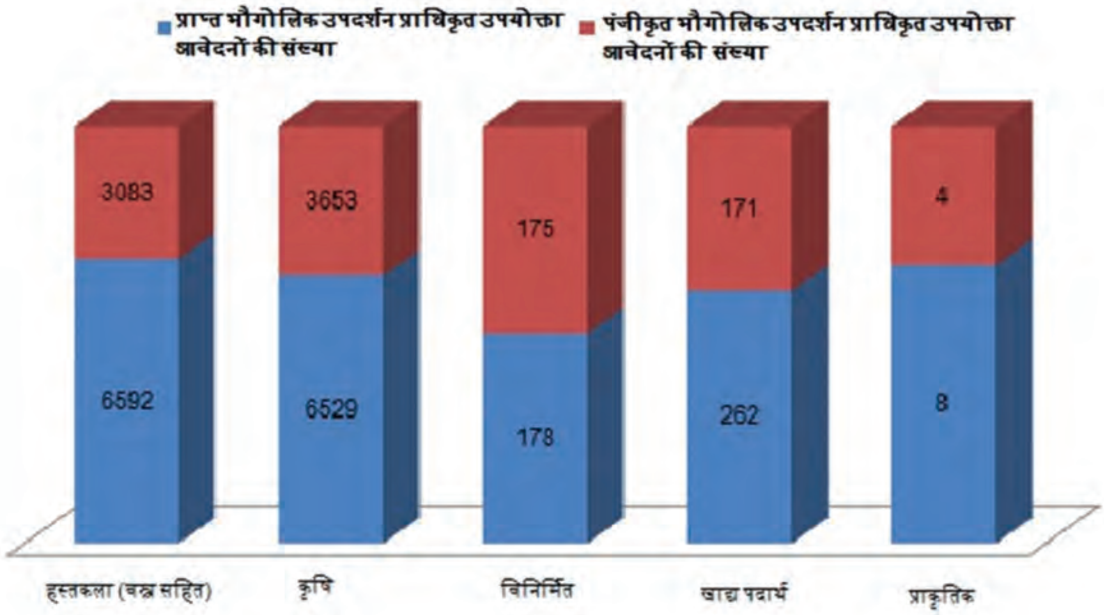

कॉपीराइट

परिचय

कॉपीराइट किसी कलात्मक कार्य के स्वामी को प्रदत्त वह अधिकार है जिससे उसे उस कार्य के सीमित उपयोग और उसके वित्तीय लाभ का अवसर प्राप्त होता है। मानव मेधा से सृजित ऐसे कार्य साहित्य (संकलन और सॉफ्टवेयर सहित), अभिनय, संगीत, कलात्मक, सिनेमेटोग्राफ फिल्म और ध्वनि रिकॉर्डिंग के रूप में उपलब्ध होते हैं।

कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत कॉपीराइट का प्रशासन किया जाता है, जिसमें समय–समय पर संशोधन करके विधि को तीव्र विकास के अनुरूप बनाया गया है।

1. कॉपीराइट कार्यालयः

कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 9 (1) के अधीन कॉपीराइट कार्यालय की स्थापना 1958 में की गई थी। कॉपीराइट कार्यालय का मुख्य कार्य कॉपीराइट का पंजीकरण करना है। कॉपीराइट कार्यालय द्वारा कॉपीराइट के रजिस्टर का रख–रखाव किया जाता है जिससे आम जनता को कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के अधीन पंजीकृत कार्य के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, रजिस्टर का निरीक्षण करने, विवरण में परिवर्तन, उसका सार लेने, कॉपीराइट सोसाइटी का प्रशासन इत्यादि जैसी सुविधाएं भी कॉपीराइट कार्यालय के प्रक्षेत्र (डोमेन) में आती है।

जैसा कि कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 13 के तहत प्रावधान किए गए हैं, कॉपीराइट निम्नलिखित वर्ग अथवा कार्यों का निर्वाह करता हैः

(i) मूल साहित्यिक, अभिनय, संगीत व कलात्मक कार्य;
(ii) सिनेमेटोग्राफिक फिल्में; और
(iii) ध्वनि रिकॉर्डिंग

किसी कार्य का निर्माण होते ही कॉपीराइट अस्तित्व में आ जाता है और कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए कोई औपचारिकता पूर्ण करने की आवश्यकता नहीं होती है। हालाँकि, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 48 के अनुसार, कॉपीराइट के पंजीकरण का प्रमाण पत्र और उसमें दर्ज प्रविष्टियाँ विधिक न्यायालय में कॉपीराइट के स्वामित्व से संबंधित विवाद के संदर्भ में प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में कार्य करती हैं।

आवेदन पत्र, शुल्क संरचना, कॉपीराइट नियम, 2013 के संबंधित उद्धरण सहित पंजीकरण प्रक्रिया का विवरण कॉपीराइट की वेबसाइट अर्थात http://copyright.gov.in पर उपलब्ध हैं।

2. कॉपीराइट का स्वामित्वः

कॉपीराइट विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार विशिष्ट हैं यद्यपि ये सीमित अवधि के लिए हैं। ऐसे किसी भी कार्य का कार्य के स्वामी की प्राधिकृति/अनुमति के बिना उपयोग विधि का उल्लंघन अथवा कॉपीराइट का अतिलंघन हो सकता है (कॉपीराइट विधि के तहत कुछ सीमाएं व अपवाद प्रदान किए गए हैं)। विधि यह भी सुनिश्चित करती है कि एक बार इस विशिष्ट अधिकार की अवधि समाप्त होने के उपरांत, आम जनता की उस कार्य तक सहज पहुँच हो।

3. कॉपीराइट सोसाइटीः

भारत में पंजीकृत कॉपीराइट सोसाइटी निम्नलिखित हैंः

- इंडियन पर्फ़ोर्मिंग राइट्स सोसाइटी (आईपीआरएस)–संगीत कार्य व ऐसे संगीत कार्य से जुड़े साहित्यिक कार्यों के लिए।

- इंडियन रेप्रोग्राफिक राइट्स ऑर्गनाइज़ेशन (आईआरआरओ)–फोटोग्राफी कार्यों के लिए
- इंडियन सिंगर्स राइट्स असोशिएशन (आईएसआरए)–गायकों के अदाकारी के अधिकार तथा उनसे जुडी अन्य सहायक गतिविधियां
- रेकॉर्डेड म्यूज़िक परफ़ोर्मेंस लि. (आरएमपीएल)–ध्वनि रोकॉर्डिंग कार्य के लिए.

4. अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन / समझौते / संधि :

विदेशों में भारतीय कार्य को संरक्षण प्रदान करने के लिए, भारत कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों पर निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का सदस्य बना हुआ है:

- बर्न कन्वेन्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटररी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स
- यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेन्शन
- ट्रेड रिलेटिड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटलेक्चुयल प्रॉपर्टी राइट्स (ट्रिप्स) समझौता
- मरक्केश ट्रीटी टू फेसिलिटेट एक्सेस टू पब्लिश्ड वर्क्स बाय विजुयली इंपेयर्ड पर्सन्स (वीआईपीस) एंड पर्सन्स विद प्रिंट डिसेबिलिटीज़
- वायपो कॉपीराइट ट्रीटी (डबल्यूसीटी)
- वायपो परफोरमेनसिस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी (डबल्यूपीपीटी)

5. अभिनव विकास:

भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर.225 (ई) दिनांक 30 मार्च 2021 के संदर्भ के तहत कॉपीराइट (संशोधन) नियम 2021 को अधिसूचित किया है। संशोधन निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया है:

- कॉपीराइट कार्यालय की वेबसाइट पर कॉपीराइट जर्नल के प्रकाशन के संबंध में एक नया प्रावधान लाया गया है, जिससे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की आवश्यकता समाप्त हो गई है।
- सॉफ्टवेयर कार्यों के पंजीकरण के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को काफी हद तक कम कर दिया गया है, जिसमें आवेदक स्रोत कोड के पहले 10 और अंतिम 10 पृष्ठ, या संपूर्ण स्रोत कोड, यदि 20 पृष्ठों से कम है, बिना किसी अवरुद्ध या संशोधित भागों के फाइल कर सकते हैं।
- कॉपीराइट सोसायटियों को प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट तैयार करने और उसे सार्वजनिक करने की आवश्यकता होगी।
- जवाबदेही और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने के लिए, रॉयल्टी की अविभाजित राशि से निपटने के प्रावधान और रॉयल्टी के संग्रह और वितरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक और ट्रेस करने योग्य भुगतान विधियों के उपयोग की शुरुआत की गई है।

6. कॉपीराइट की प्रवृत्ति:

कॉपीराइट कार्यालय ने उपयोगकर्ताओं की पारदर्शिता और डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ाने के अपने प्रयास में "कॉपीराइट सोसाइटी के पंजीकरण/नवीनीकरण फॉर्म VIII) और फॉर्म (IX) और "कलाकार सोसायटी के पंजीकरण/नवीकरण" (फॉर्म XI) और फॉर्म (XII)।" के लिए ई–फाइलिंग सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है।

2021–22 के दौरान, कुल **30988** आवेदन प्राप्त हुए एवं **29106** आवेदन परीक्षित किए गए। परीक्षण के दौरान, प्रेक्षित विसंगतियों को सुधार के लिए आवेदकों को सूचित किया गया। 2021–22 में उत्पन्न रजिस्टर ऑफ सर्टिफिकेट की (आरओसी) संख्या **20673** रही। 2017–18 से 2021–22 तक के सांख्यिकीय आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

वर्ष	कुल प्राप्त आवेदन	कुल परीक्षित आवेदन	उत्पन्न रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट (आरओसी)	कुल निपटान
2017–18	17841	34388	19997	39799
2018–19	18250	22658	14625	25943
2019–20	21905	29670	16029	22516
2020–21	24451	21523	16399	19477
2021–22	**30988**	**29106**	**20673**	**20820**

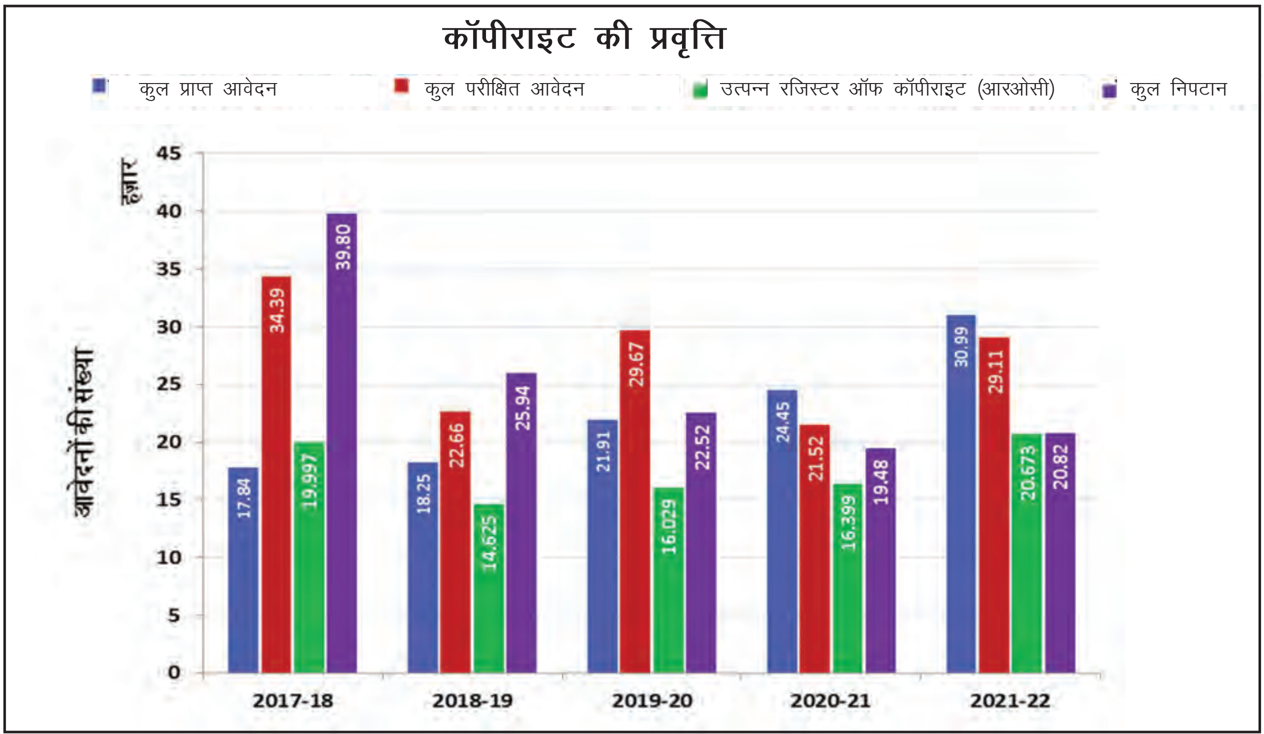

वर्ष 2021–22 के दौरान उत्पन्न कॉपीराइट के पंजीकरण (आरओसी) का वर्गवार विवरण

क्र. सं.	वर्ग	आरओसी
1	कलात्मक	4227
2	चलचित्र फिल्म	233
3	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	974
4	साहित्यिक / नाटकीय	12867
5	संगीत	40
6	ध्वनि रिकॉर्डिंग	2332
	कुल आरओसी:	**20673**

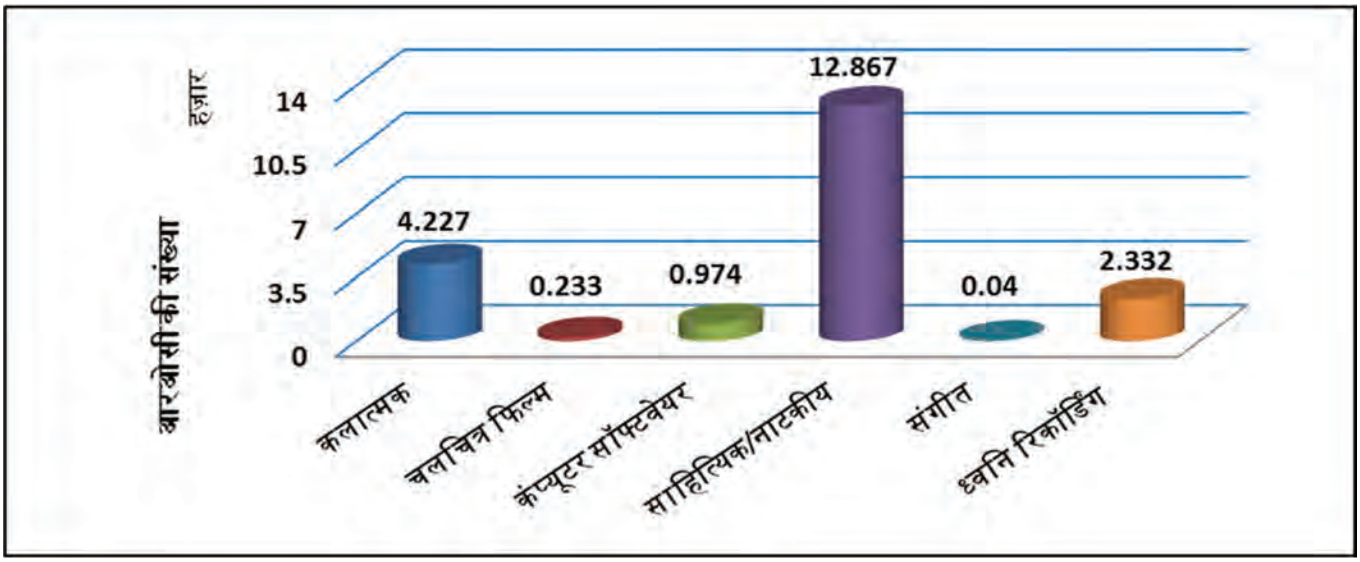

7. कॉपीराइट कार्यालय की प्रमुख उपलब्धियांः

- पिछले वित्त वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान प्राप्त आवेदनों में लगभग 26.5% की वृद्धि हुई हैं।
- ऑनलाइन आवेदन की फाइलिंग कुल आवेदनों के 94% के स्तर तक पहुंच गई है।
- कॉपीराइट रजिस्टर (फॉर्म XV) में दर्ज "कॉपीराइट के विवरण में परिवर्तन के पंजीकरण" के लिए ई–फाइलिंग सुविधा प्रारम्भ की गई है।
- "कॉपीराइट सोसायटी का पंजीकरण/नवीकरण (फॉर्म VIII) और (फॉर्म IX)" और "परफोरमर्स सोसायटी का पंजीकरण/नवीकरण (फॉर्म XI) और (फॉर्म XII)" के लिए ई–फाइलिंग सुविधा।
- कॉपीराइट कार्यालय के ई–फाइलिंग पोर्टल में गैर–कर रसीद पोर्टल प्रारम्भ किया जा रहा है।
- कार्यालय ने कॉपीराइट के शासकीय वेबसाइट पर एक विंडो उपलब्ध कराकर कॉपीराइट के लिए दाखिल प्रस्तावित कार्य के विरुद्ध तीसरे पक्ष की आपत्तियों से संबंधित एक नए प्रावधान की शुरुआत की है जिसके तहत प्रस्तावित आवेदक के विरुद्ध ऐसी आपत्तियाँ दाखिल की जा सकती हैं। यह शुरुआत कागज बचाने के हरित प्रयास और डिजिटल इंडिया की संकल्पना को बढ़ावा देने की एक पहल है।
- अवितरित रॉयल्टी से संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यालय शासकीय वेबसाइट पर एक रेडियो बटन उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है जिसकी सहायता से शिकायतकर्ता सदस्य पंजीकृत सोसायटीज़ की अनियमितताओं के विरुद्ध अपनी आपत्तियाँ/ शिकायत दाखिल कर सकेंगे।

अध्याय–X

अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री

परिचयः

यह अध्याय अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम 2000 की धारा 88 के तहत अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री (एसआईसीएलडीआर) द्वारा की गई गतिविधियों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 (एसआईसीएलडी अधिनियम) अर्धचालक एकीकृत परिपथ (आईसी) डिजाइनों को संरक्षण प्रदान करता है। अर्धचालक एकीकृत परिपथ अर्धचालकों, धातुओं, डाईइलेक्ट्रिक (इंसुलेटर) व अन्य सामग्री की कई परतों को मिलाकर सब–स्ट्रेट पर बनाए (फेब्रीकेट किए) जाते हैं। एसआईसीएलडी अधिनियम और नियम एकीकृत परिपथ अभिन्यास के रूप में इन परतों के त्रिआयामी विन्यास को संदर्भित करते हैं।

एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन के पंजीकरण के लिए मानदंड यह है कि वह होना चाहिएः–

- मूल
- विशिष्ट
- किसी भी अन्य अभिन्यास डिजाइन से अलग होने में सक्षम
- भारत में अथवा किसी भी कन्वेंशन देश में कहीं भी व्यावसायिक रूप से उपयोग नहीं किया गया हो।

1. अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री (एसआईसीएलडीआर):

एकीकृत परिपथों के विन्यास डिजाइन संबंधी आवेदन बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्री में दाखिल किए जाते हैं। इस रजिस्ट्री का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण भारत है। अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन (एसआईसीएलडी) अधिनियम, 2000 तथा एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन (एसआईसीएलडी) नियम, 2001 में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार रजिस्ट्री एकीकृत परिपथ के विन्यास डिजाइन का परीक्षण करती है व अर्धचालक एकीकृत परिपथ के मूल विन्यास डिजाइन को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करती है।

अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम और अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री का प्रशासन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के नियंत्रण में था, लेकिन 17 मार्च, 2016 की अधिसूचना द्वारा अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 और अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री के प्रशासन को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) में स्थानांतरित कर दिया गया तथा कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न के नियंत्रण में लाया गया। अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री अब बौद्धिक संपदा भवन, द्वारका नई दिल्ली से कार्य कर रही है।

2. उपलब्धियां:

प्रतिवेदन वर्ष 2021–22 के दौरान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से 'एयर–कॉर्ड ट्रांसफ़ोर्मर की डिजाइन और पावर कंवर्टर में इसके क्रियान्वयन' विषय पर **एक (1)** अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन आवेदन पंजीकरण हेतु

प्राप्त हुए हैं और इस आवेदन की प्रारंभिक जांच पूर्ण कर ली गई है।

अब तक, अभिन्यास डिजाइन के लिए दो (2) पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं: (i) डिजाइन संख्या 1(I)/2013 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के नाम से दिनांक 20 जनवरी, 2015, शीर्षक–"8 पोर्ट माइक्रो–कंट्रोलर (बीई.80501)"; तथा (ii) डिजाइन संख्या 2(I)/2016 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के नाम से दिनांक 24 मई, 2016, शीर्षक–"50–60 गीगाहर्ट्ज सब हार्मोनिक आईक्यू मिक्सर"।

प्रतिवेदन वर्ष 2021–22 तक चौदह (14) अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन आवेदन पंजीकरण हेतु दाखिल किए गए हैं।

3. एसआईसीएलडी रजिस्ट्री की जनशक्ति संरचना

एसआईसीएलडी रजिस्ट्री में निम्नलिखित पद अनुमोदित हुए हैं:

क्र. सं.	पदनाम	पद (पदों) की संख्या	ग्रेड पे के साथ पूर्व संशोधित वेतनमान
1.	पंजीकार	एक	पीबी4 + जीपी रु.8700
2.	तकनीकी अधिकारी	एक	पीबी2 + जीपी रु.5400
3.	निजी सचिव	एक	पीबी2 + जीपी रु.4600

अध्याय–XI

राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) व पेटेंट सूचना पद्धति (पीआईएस)

परिचय

बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) संबंधी गतिविधियाँ पिछले कई वर्षों से देश में निरंतर बढ़ रही हैं। आईपीआर के सृजन, उपयोग व सार्थक समुपयोजन में कई जटिलताएँ शामिल हैं। देश में आईपीआर के ज्ञान में सुधार लाने और आईपीआर में हितधारकों के कौशल को उन्नत करने के लिए राष्ट्रीय केंद्र की आवश्यकता को महसूस करते हुए भारत सरकार ने बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में प्रशिक्षण, प्रबंधन, शोध और शिक्षण हेतु उच्च कोटि के राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में नागपुर में राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) की स्थापना की है। आरजीएनआईआईपीएम–परीक्षक एकस्व एवं अभिकल्प हेतु प्रशिक्षण, बौद्धिक संपदा कार्यालय (आईपीओ) के अधिकारियों हेतु न्यायिक प्रशिक्षण, परीक्षक–व्यापार चिह्न एवं भौगोलिक उपदर्शन व अन्य आईपीओ अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा यह विभिन्न उपयोक्ता समुदायों हेतु बौद्धिक संपदा प्रशिक्षण/शिक्षण व आईपीआर प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

उद्देश्य

आरजीएनआईआईपीएम को देश में बौद्धिक संपदा (आईपी) व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ–साथ राष्ट्रीय हितों की रक्षा हेतु निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ स्थापित किया गया है। वर्तमान में, आरजीएनआईआईपीएम का प्राथमिक उद्देश्य आईपी अधिकारियों व विभिन्न प्रकार के हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करना एवं आईपीआर विषय में जागरूकता पैदा करना है। समग्र उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- बौद्धिक संपदा कार्यालयों की आंतरिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करना व उन्हें पूर्ण करना तथा बौद्धिक संपदा कार्यालय के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना,
- राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के उद्देश्यों को लागू करने हेतु विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों आदि में बौद्धिक संपदा जागरूकता पैदा करने व प्रशिक्षित आईपी जनशक्ति के सृजन हेतु सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना
- आईपी व्यावसायिकों, आईपी प्रबंधकों, अनुसंधान एवं विकास वैज्ञानिकों, सरकारी संस्थान व अन्य व्यक्तियों आदि जैसे आईपी उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना,
- आईपीआर पर अल्पकालिक अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना,
- आईपी उपयोगकर्ताओं जिनमें विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्थान और विभिन्न संगठन शामिल हैं उनके आईपी प्रणाली की सामान्य जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना,
- बौद्धिक संपदा अधिकार के सृजन, वाणिज्यिकरण और प्रबंधन में शामिल हितधारकों–उपयोक्ता समुदायों, सरकारी कर्मियों आदि को आधारभूत शिक्षा प्रदान करना,
- देश में सभी प्रकार के बौद्धिक संपदा हितधारकों के लिए व प्रमुख संस्थानों के साथ मिलकर आईपीआर के प्रशिक्षण और शिक्षण की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

आरजीएनआईआईपीएम बौद्धिक संपदा अधिकारों अर्थात पेटेंट, डिजाइन, व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन, कॉपीराइट एवं एसआईसीएलडी आदि के वास्तविक और संभावित उपयोगकर्ताओं की पेटेंट व अन्य आईपी प्रणाली की आवश्यकताओं को

ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इनसे व्यावसायिक, स्टार्ट–अप, विधि व्यवसाय, भावी पेटेंट आईपीआर अभिकर्ता (एजेंट), अनुसंधान एवं विकास संगठन, उद्योग, लघु व मध्यम उद्यमी, विद्याविद, केन्द्रीय /राज्य सरकारी /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, वैयक्तिक आविष्कारकगण लाभान्वित होते हैं।

आरजीएनआईआईपीएम निम्नलिखित के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है:

- नवनियुक्त आईपीओ के अधिकारी,
- आईपीओ के अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम,
- आईपीओ के अधिकारियों के लिए न्यायिक प्रशिक्षण,
- आईपी पर अल्पकालिक सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम,
- संस्थानों, संगठनों, आईपीआर से संबंधित संगठनों के लिए बौद्धिक संपदा विषय पर कार्यशालाएँ/ संगोष्ठियाँ/ जागरूकता कार्यक्रम,
- वायपो व अन्य संगठनों के साथ संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।

2021–22 के दौरान उपलब्धियां

वर्ष 2021–22, में कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण, आरजीएनआईआईपीएम ने विभागीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम सहित सभी प्रशिक्षण को दूरस्थ रूप से ऑनलाइन प्रारूप में संचालित करना जारी रखा। उपर्युक्त संदर्भ में आरजीएनआईआईपीएम ने प्रतिवेदन अवधि के दौरान कुल **413** कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आयोजित सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक दिवसीय 12 शुल्क सहित वेबिनार, 2 दिवसीय 19 शुल्क सहित वेबिनार, 3 दिवसीय 08 शुल्क सहित वेबिनार, 5 दिवसीय 09 शुल्क सहित वेबिनार और 01 दो सप्ताह के शुल्क सहित वेबिनार सम्मिलित था। इच्छुक जनता के लिए कुल 189 निपम (राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा मिशन) कार्यक्रम और **169** आईपीआर जागरूकता कार्यशालाएं ऑनलाइन प्रारूप में आयोजित की गईं। 04 विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं 02 अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी ऑनलाइन प्रारूप में सफलतापूर्वक संचालित किये गये। विवरण इस प्रकार हैं:

साल	सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम						विभागीय प्रशिक्षण			सेमिनार/ सार्वजनिक संस्थान के लिए कार्यशाला/ जागरूकता कार्यक्रम	अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम	प्रतिभागियों की संख्या	कुल
	प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि												
	1 दिन	2दिन	3 दिन	5 दिन	6 दिन	2 सप्ताह	6 सप्ताह	1–21 दिन	(ऑन-जॉब) प्रशिक्षण				
2017–2018	24	12	8	9	10	—	1	1	—	27	2	3021	94
2018–2019	16	14	3	4	6	2	—	6	—	39	2	5763	92
2019–2020	14	14	10	3	6	2	1	1	—	41	3	5655	95
2020–2021 (केवल ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम कोविड–19 महामारी को देखते हुए आयोजित किए गए)	17	1	1	3	—	–	1	3	1	128	1	21077	156
2021–2022 (कोविड–19 महामारी को देखते हुए कई ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए)	12	19	8	9	—	1	1	3	—	358	2	79136	413
कुल	**83**	**60**	**30**	**28**	**22**	**5**	**4**	**14**	**1**	**593**	**10**	**114652**	**850**

वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक आयोजित कार्यक्रमों का विवरण

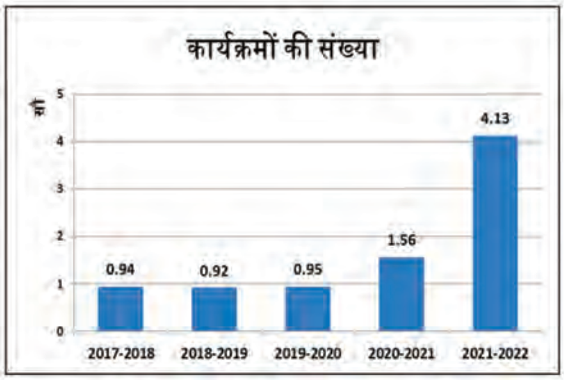

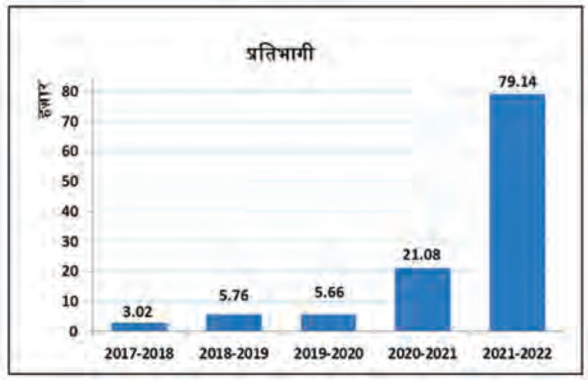

प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संकाय सदस्यः

प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संकाय सदस्य के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय के बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधित विषय के विशेषज्ञ थे तथा देश के जाने–माने विभिन्न प्रसिद्ध संगठनों जिसमें आईपी न्यायवादी (अटर्नी), आईपी विशेषज्ञ आदि भी शामिल थे।

2021–22 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों का विवरणः

क. विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमः

दिनांक	विवरण
11 जून, 2021 से 23 अगस्त, 2021	पेटेंट और डिजाइन के 01 नवनियुक्त परीक्षक के लिए छह सप्ताह का फाउंडेशन(बुनियादी) प्रशिक्षण कार्यक्रम
02 अगस्त, 2021 से 13 अगस्त, 2021	पेटेंट और डिजाइन के सहायक नियंत्रक के लिए दो सप्ताह का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम। फैकल्टी–श्री मनीष शुक्ला, डॉ. केएस कर्दम, श्री डी.के.स्वामी, डॉ. डब्ल्यू.एम धूमाने, श्री एस. चंद्रशेखरन, श्री अनिल धवास, श्री अविनाश प्रभु, श्री डी.पी.एस परमार, श्री सतीश अदके, डॉ. एसके मित्रा
09 दिसंबर, 2021	सीजीपीडीटीएम कार्यालय के सभी अधिकारियों के लिए लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम। फैकल्टी–सुश्री माधुरी साकुलकर, डॉ. मनीष कोठेकर, डॉ. वसंती देशपांडे
03–14 जनवरी, 2022	ट्रेड मार्क एवं जीआई के नवनियुक्त उप रजिस्ट्रार का उन्मुखीकरण कार्यक्रम–श्री एस.के. पाण्डेय, श्री शक्ति धर ओझा, श्री सी. एस. उचिल, सुश्री शलाखा वी. पोद्दार, सुश्री सोनल वैनगांवकर, सुश्री दीपमाला पी. माथापाथी , डॉ. सचिन शर्मा, डॉ. पवन कुमार पाण्डेय

लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम की छायाचित्र :

Appriciation of Evidence In
Patent Act

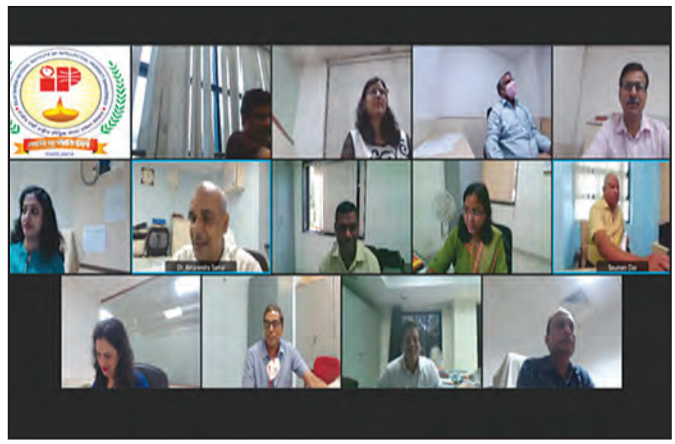

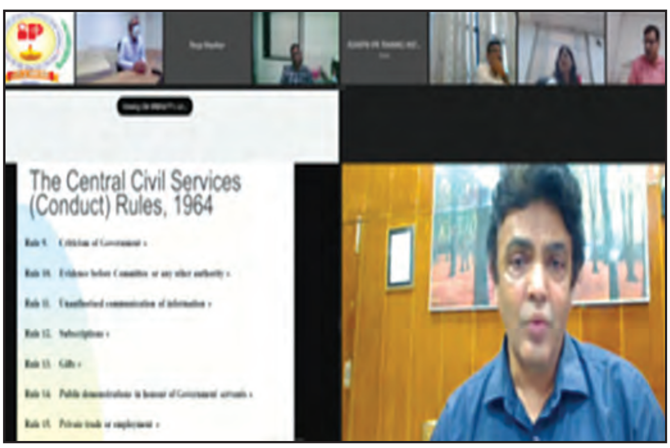
The Central Civil Services
(Conduct) Rules, 1964

Patent Agent

ख. वायपो–भारत प्रशिक्षण कार्यक्रमः

आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर ने वायपो अकादमी के सहयोग से 15 से 26 नवंबर, 2021 के दौरान आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर में दो सप्ताह के लिए पेटेंट और डिजाइन के परीक्षक के लिए उन्नत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया।

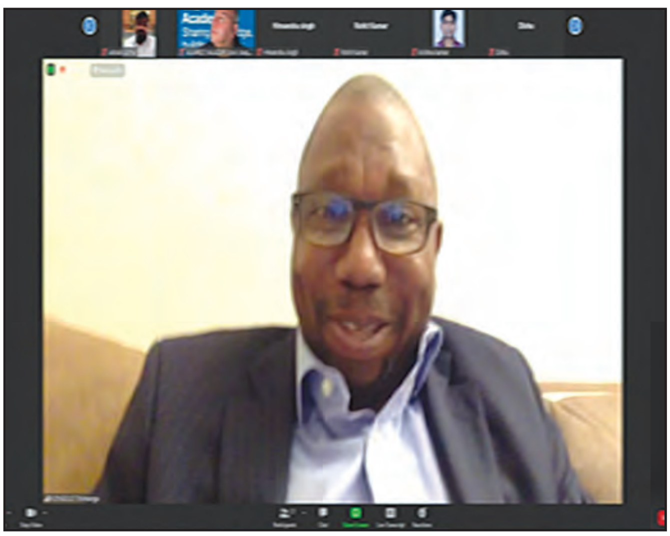

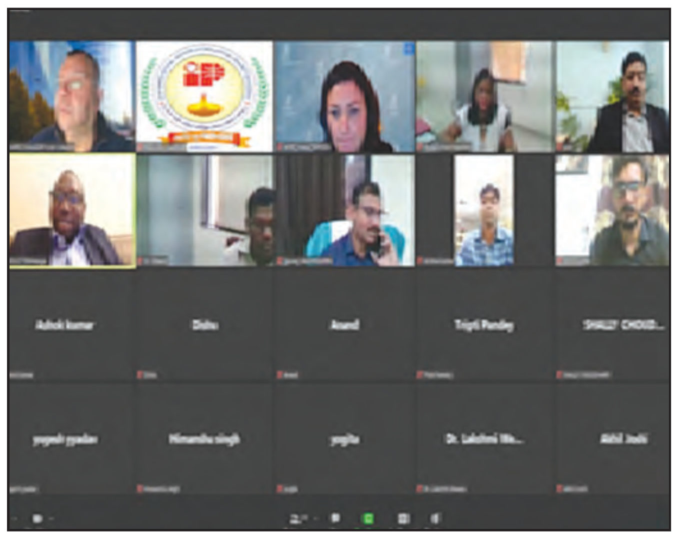

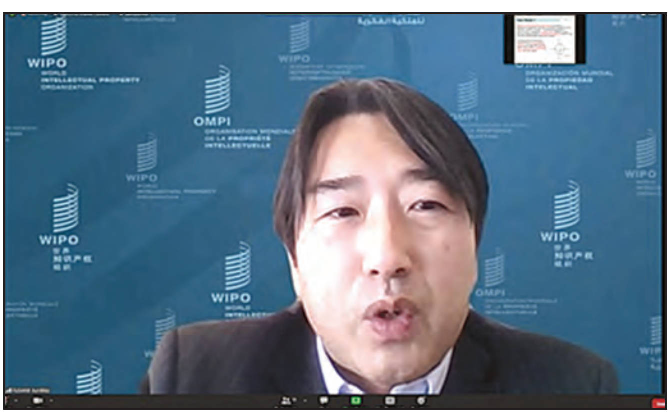

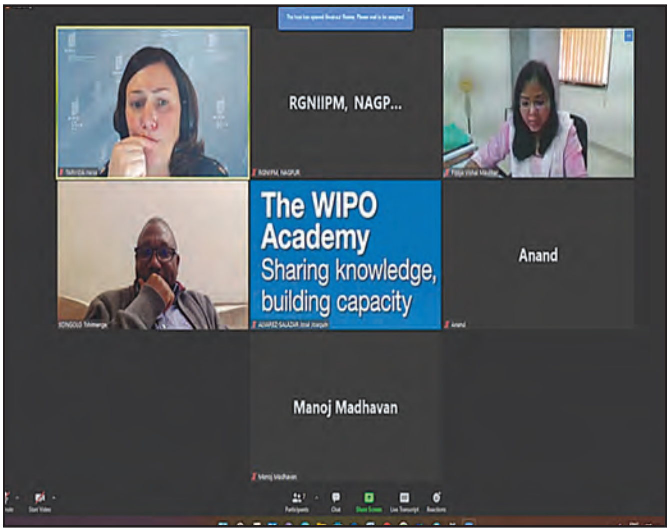

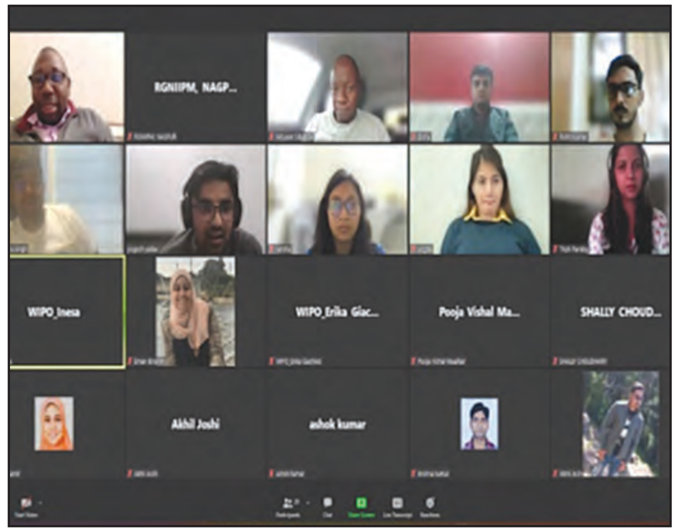

ग. अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमः

सीजीपीडीटीएम–भारत, सी.एन.आई.पी.ए–चीन, एस.ए–सी.आई.पी.सी–दक्षिण अफ्रीका, आई.एन.पी.आई–ब्राजील एवं रोस्पेटेंट–रूस के अधिकारियों के लिए 6 से 10 दिसंबर, 2021 तक ऑनलाइन मोड के माध्यम से एक ब्रिक्स ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था।

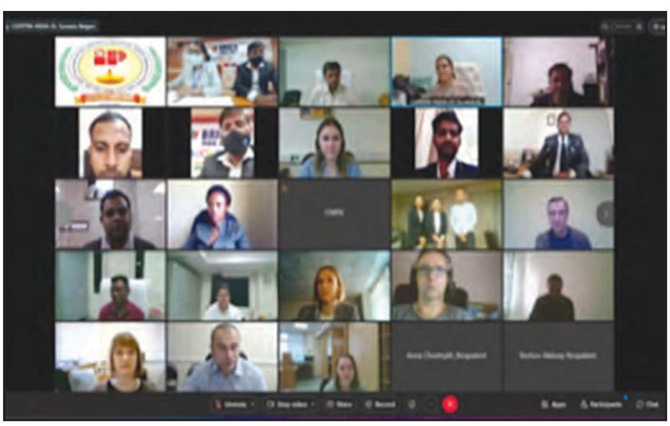

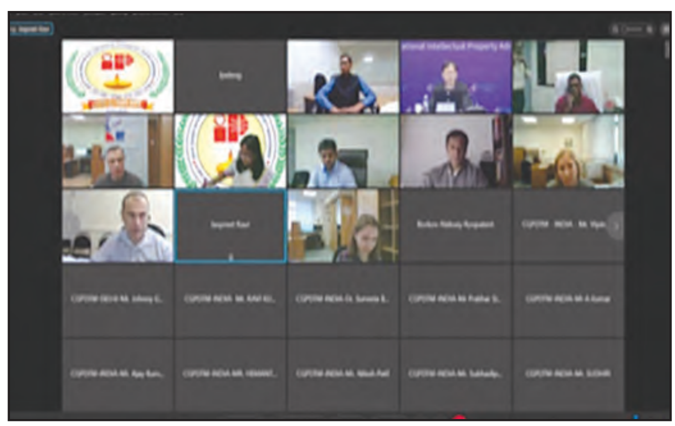

घ. सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रमः

आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर ने आम जनता के लिए बौद्धिक संपदा के विभिन्न पहलुओं जिनमें ये विषय शामिल हैं–आईपीआर का परिचय, पेटेंट योग्य होने के मापदंड, पेटेंट कार्यवाही, पेटेंट खोज सूचना और पेटेंट विनिर्देश का परिचय, अनंतिम एवं पूर्ण विनिर्देश, आईपी लाइसेंसिंग की प्राथमिक जानकारी, समनुदेशन, मुक़दमेबाज़ी, फॉर्म व फीस, ई–फाइलिंग, पीसीटी प्रक्रिया,डिजाइन, व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन, एसआईसीएलडीआर और कॉपीराइट प्रक्रिया आदि पर 1 दिवसीय, 2 दिवसीय, 3 दिवसीय, 5 दिवसीय और 2 सप्ताह के ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किए हैं।

PHOTOS

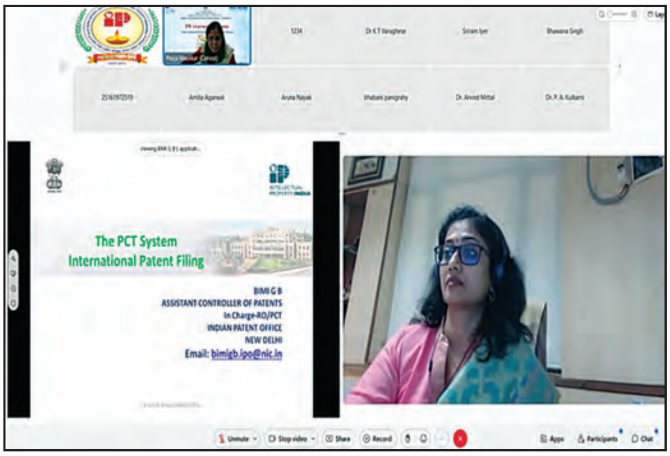
The PCT System
International Patent Filing
BIMI G B
ASSISTANT CONTROLLER OF PATENTS
In Charge-RO/PCT
INDIAN PATENT OFFICE
NEW DELHI
Email: bimigb.ipo@nic.in

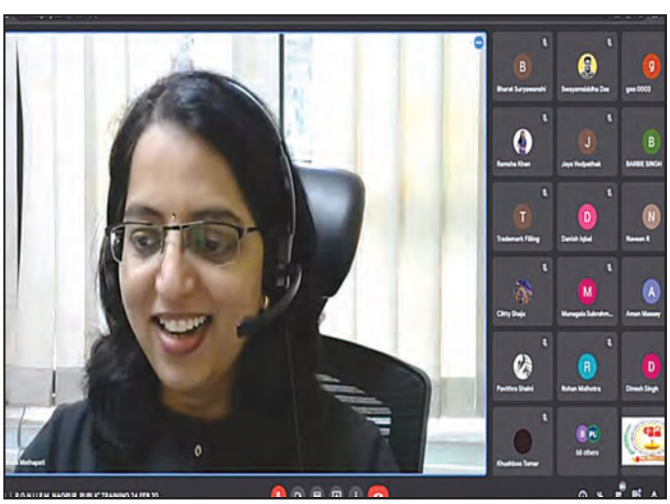

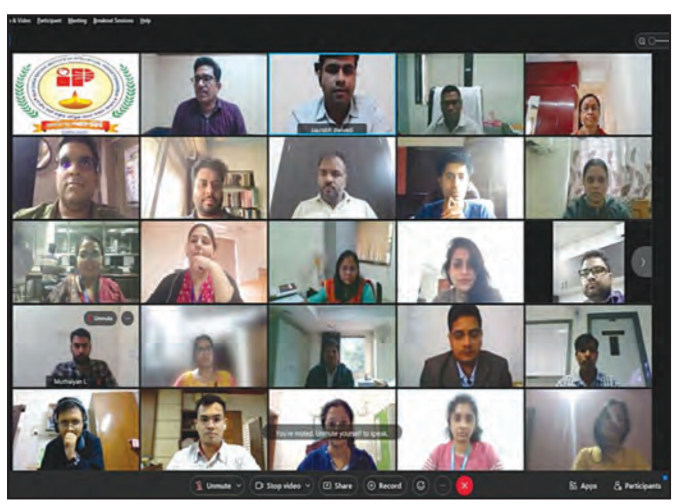

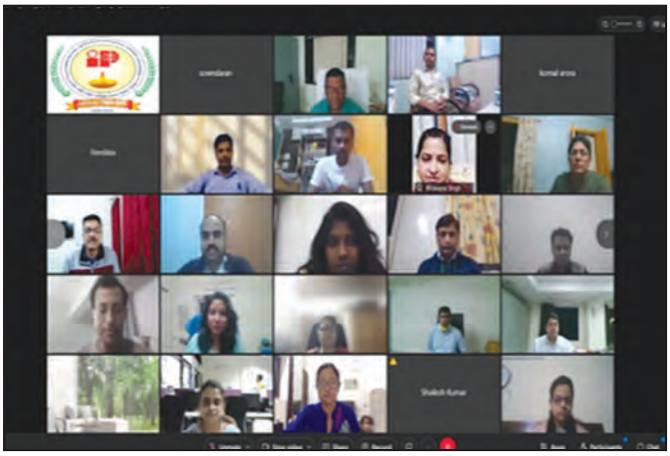

INTELLECTUAL PROPERTY INDIA
The Trade Marks Act, 1999
An Introduction and Processing of TM Applications
Office of Controller General of Patents, Designs and Trademarks

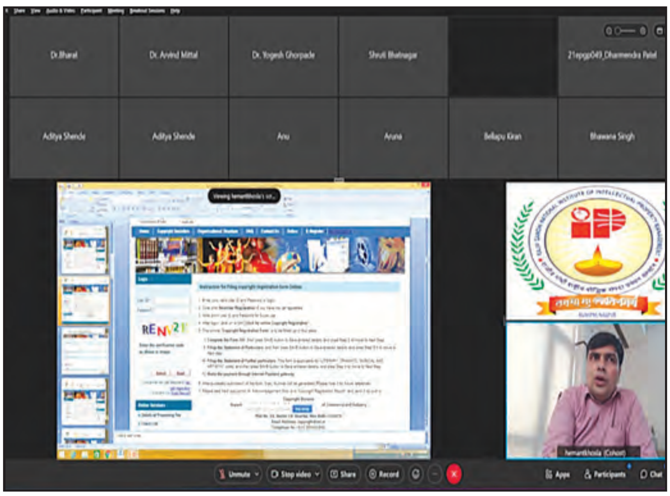

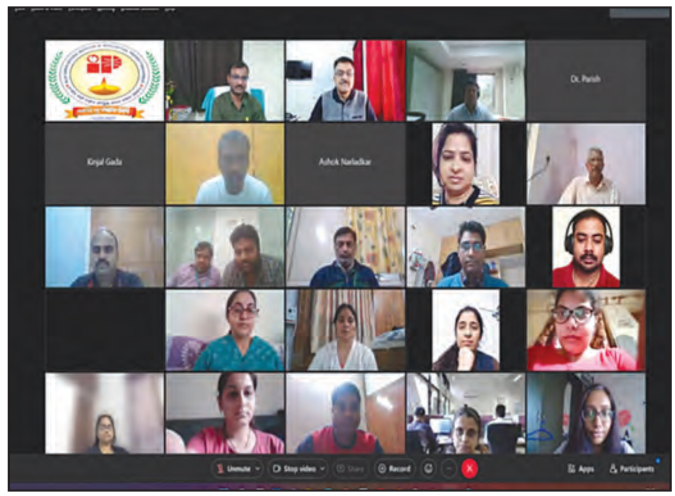

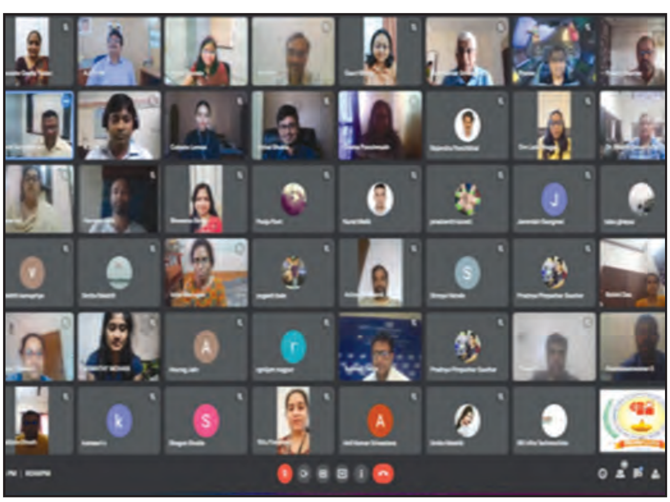

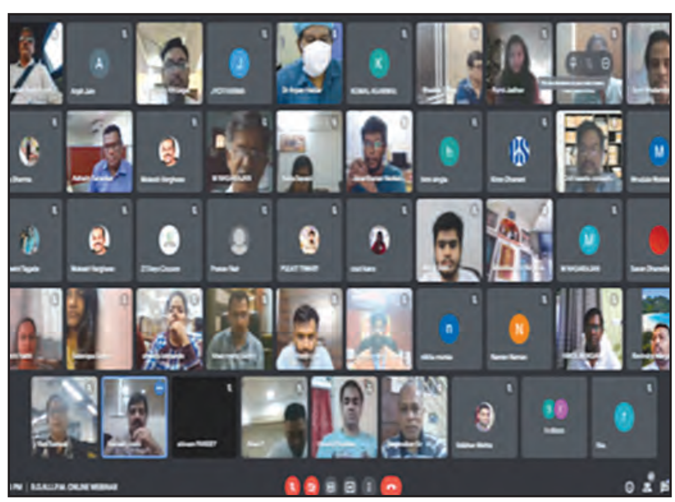

i) एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमः

1–दिवसीय कार्यक्रम में आईपीआर का संक्षिप्त परिचय, पेटेंट योग्य होने के मापदंड, पेटेंट कार्यवाही, पेटेंट खोज सूचना और पेटेंट विनिर्देश का मसौदा तैयार करने पर संक्षिप्त परिचय तथा आईपी लाइसेंसिंग, समनुदेशन, मुकदमेबाजी, प्रवर्तन आदि विषयों पर प्राथमिक जानकारी शामिल है।

ii) दो/तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमः

2/3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान, बौद्धिक संपदा अधिकार का महत्व, पेटेंट योग्य होने के मापदंड, पेटेंट आवेदनों के प्रकार, पेटेंट आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया, अनंतिम एवं पूर्ण विनिर्देश, पेटेंट विनिर्देश का लेख, फॉर्म व फीस, ई–फाइलिंग, पीसीटी प्रक्रिया आदि विषय होते हैं। तीन दिन के प्रशिक्षण में, पेटेंट विनिर्देश व्यवहार, दावा मसौदा तैयार करने और उनकी व्याख्या, पेटेंट आवेदन दाखिल करने के व्यवहार और अन्य दस्तावेज भी शामिल किए गए हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

iii) पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमः

यह कार्यक्रम पेटेंट प्रणाली के सभी पहलुओं पर विस्तार से ध्यान केंद्रित करने के लिए आयोजित किया जाता है। यह कार्यक्रम इच्छानुसार 1/2/3/5 दिवसीय कार्यक्रमों में विभाजित करके भी आयोजित किया जाता है; ताकि यदि कोई अपनी रुचि के विषय के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना चाहे, तो वह दिनों का चयन कर सकता है। पेटेंट प्रणाली के सभी प्रमुख पहलू, अर्थात बौद्धिक संपदा अधिकार का परिचय, आईपी प्रबंधन, पेटेंट योग्य होने के मापदंड, पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया, प्रकाशन, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य व आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया, पेटेंट विनिर्देश का लेख व दावे, पेटेंट विनिर्देश का प्रारूपन, विरोध, उल्लंघन, लाइसेंस, पेटेंट खोज आदि विषय इस कार्यक्रम में सम्मिलित किए जाते हैं।

iv) 2–सप्ताह का उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमः

यह विशेष रूप से तैयार किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम उन व्यावसायिकों के लिए है जो आईपी के क्षेत्र में अपनी जीविका चुनने के इच्छुक हैं। यह विशेषज्ञ संकाय की मदद से आईपीआर के सभी पहलुओं पर उनकी धारणा को स्पष्ट करने में उनकी मदद करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम में सभी बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) जैसे पेटेंट, डिज़ाइन, व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन व कॉपीराइट आदि शामिल हैं, जिसमें भारत और विदेश में आवेदन दाखिल करना, पीसीटी अंतरराष्ट्रीय आवेदनों का प्रसंस्करण, पेटेंट विनिर्देश और दावे, विरोध, उल्लंघन, लाइसेंस, आईपीआर का वाणिज्यीकरण, आईपी प्रबंधन, आईपी खोज अभ्यास आदि शामिल हैं।

2021–22 में आयोजित जन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण :

क्र.सं.	दिनांक	प्रतिभागी	संगठन
1	18 जून, 2021	100	जी.एच रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर के साथ आधे दिन का वेबिनार
2	15 जुलाई, 2021	50	आरएस मुंडले धर्मपेठ आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, नागपुर के साथ आधे दिन का वेबिनार
3	28 जुलाई, 2021	50	चेट्टीनाड हॉस्पिटल एंड रिसर्च, चेन्नई के साथ वेबिनार
4	30 जुलाई, 2021	50	एच.ए.एल, बैंगलोर के साथ एक दिवसीय वेबिनार
5	23–27 अगस्त, 2021	18	आईपीआर पर एक सप्ताह का व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
6	23–24 अगस्त, 2021	4	दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम–'आईपीआर का परिचय, पेटेंट योग्यता, भारत में पेटेंट फाइलिंग प्रक्रिया'
7	23–25 अगस्त, 2021	5	3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम–'आईपीआर का परिचय, पेटेंट योग्यता, भारत में पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया, पेटेंट विशिष्टता, एवं केस स्टडीज'
8	26–27 अगस्त, 2021	8	'पेटेंट खोज, मामला अध्ययन, पेटेंट अधिनियम/नियमों के अनुसार अन्य महत्वपूर्ण पेटेंट कार्यवाही' विषयों पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

9	6–7 सितंबर, 2021	50	प्रतिरक्षा कर्मियों के साथ 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
10	8 सितंबर, 2021	50	मुफखम शाह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 'प्रायर आर्ट सर्च' (पूर्व खोज विषय) पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
11	20 सितंबर, 2021– 1 अक्टूबर, 2021	30	दो सप्ताह का ऑनलाइन एडवांस प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम
12	20–24 सितंबर, 2021	36	एक सप्ताह का ऑनलाइन व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
13	27 सितंबर, 2021– 1 अक्टूबर, 2021	27	एक सप्ताह का ऑनलाइन व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
14	20–21 सितंबर, 2021	4	दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम–'आईपीआर का परिचय, पेटेंट योग्यता' एवं भारत में पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया आदि विषयों पर
15	20–22 सितंबर, 2021	2	3 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम–'आईपीआर का परिचय, पेटेंट योग्यता' पर भारत में पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया, पेटेंट विशिष्टता–केस स्टडी'
16	23–24 सितंबर, 2021	5	दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम–'पेटेंट खोज, केस स्टडी, पेटेंट अधिनियम/नियमों के अनुसार अन्य महत्वपूर्ण पेटेंट कार्यवाही'
17	27–28 सितंबर, 2021	4	दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम–'भारत में पेटेंट फाइलिंग प्रक्रिया, केस स्टडीज, लिटिगेशन' आदि विषयों पर
18	27–29 सितंबर, 2021	6	3 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम–'भारत में पेटेंट फाइलिंग प्रक्रिया, केस स्टडीज, मुकदमेबाजी, ट्रेडमार्क–मैड्रिड प्रोटोकॉल फाइलिंग प्रक्रिया, एवं भारत में भौगोलिक उपदर्शन फाइलिंग' आदि विषयों पर
19	29 सितंबर, 2021– 1 अक्टूबर, 2021	2	3 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम–'ट्रेडमार्क–मैड्रिड प्रोटोकॉल फाइलिंग प्रक्रिया, भारत में भौगोलिक संकेत फाइलिंग, भारत में कॉपीराइट फाइलिंग प्रक्रिया, लिटिगेशन, भारत में डिजाइन फाइलिंग प्रक्रिया, आदि विषयों पर
20	30 सितंबर, 2021– 1 अक्टूबर, 2021	20	दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम–'कॉपीराइट फाइलिंग प्रोसेस इन इंडिया, लिटिगेशन्स, डिजाइन फाइलिंग प्रोसेस इन इंडिया, लिटिगेशन' आदि विषयों पर
21	25–26 अक्टूबर, 2021	3	दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम–'आईपीआर का परिचय, पेटेंट योग्यता'; भारत में पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया आदि विषयों पर
22	25–27 अक्टूबर, 2021	4	3 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम;–'आईपीआर का परिचय, पेटेंट योग्यता' पर भारत में पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया; पेटेंट विशिष्टता एवं अन्य मामले के अध्ययन' आदि विषयों पर
23	25–29 अक्टूबर, 2021	47	एक सप्ताह का व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
24	26–28 अक्टूबर, 2021	1	3 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम–'भारत में पेटेंट फाइलिंग प्रक्रिया'; पेटेंट विशिष्टता एवं मामले का अध्ययन; पेटेंट खोज, आदि विषयों पर
25	28–29 अक्टूबर, 2021	3	दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम–'पेटेंट खोज, मामला अध्ययन, पेटेंट अधिनियम/नियमों के अनुसार अन्य महत्वपूर्ण पेटेंट कार्यवाही' आदि विषयों पर
26	22–23 नवंबर, 2021	7	दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम–'भारत में पेटेंट फाइलिंग प्रक्रिया, पीसीटी–अंतरराष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग प्रक्रिया' एवं पेटेंट विशिष्टता (विवरण और दावा लेखन)' आदि विषयों पर
27	22–24 नवंबर, 2021	16	3–दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम–'भारत में पेटेंट फाइलिंग प्रक्रिया, पीसीटी–अंतरराष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग प्रक्रिया' ; पेटेंट विशिष्टता (विवरण और दावा लेखन); पेटेंट खोज, आईपीसी वर्गीकरण आदि विषयों पर
28	22–26 नवंबर, 2021	64	आईपीआर पर एक सप्ताह का ऑनलाइन व्यवसाय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

29	23–24 नवंबर, 2021	6	दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम; 'पेटेंट विशिष्टता (विवरण और दावा लेखन);' पर पेटेंट खोज, आईपीसी वर्गीकरण, आदि विषयों पर
30	25–26 नवंबर, 2021	25	दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम–'भारत में ट्रेडमार्क फाइलिंग प्रक्रिया, मैड्रिड–अंतरराष्ट्रीय ट्रेडमार्क फाइलिंग प्रक्रिया, भारत में कॉपीराइट फाइलिंग, भारत में डिजाइन फाइलिंग' आदि विषयों पर
31	13–17 दिसंबर, 2021	56	एक सप्ताह का ऑनलाइन व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
32	13–14 दिसंबर, 2021	6	2 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 'भारत में पेटेंट फाइलिंग प्रक्रिया, पेटेंट विशिष्टता (विवरण और दावे)' आदि विषयों पर
33	14–15 दिसंबर, 2021	3	2 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम–'पेटेंट विशिष्टता (विवरण एवं उदाहरण के साथ दावा लेखन)' आदि विषयों पर
34	15–16 दिसंबर, 2021	1	दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम–'पेटेंट विशिष्टता (विवरण और दावे), पेटेंट खोज' आदि विषयों पर
35	16–17 दिसंबर, 2021	3	दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम–'पेटेंट खोज, उदाहरण, आईपीसी वर्गीकरण, आदि विषयों पर
36	15 और 17 दिसंबर, 2021	1	2–दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम–'पेटेंट विशिष्टता (विवरण और दावा लेखन; पेटेंट खोज, आईपीसी वर्गीकरण, आदि) आदि विषयों पर
37	17–21 जनवरी, 2022	96	एक सप्ताह का ऑनलाइन व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
38	21–22 फरवरी, 2022	18	दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम–'भारत में पेटेंट फाइलिंग प्रक्रिया' ऑनलाइन पेटेंट विशिष्टता (विवरण और दावे), आदि विषयों पर
39	21–23 फरवरी, 2022	22	तीन दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम–'भारत में पेटेंट फाइलिंग प्रक्रिया', पेटेंट विशिष्टता (विवरण और दावे), पेटेंट खोज, आईपीसी वर्गीकरण, आदि विषयों पर
40	21–25 फरवरी, 2022	49	आईपीआर पर एक सप्ताह का व्यावसायिक कौशल विकास कार्यक्रम
41	24–25 फरवरी, 2022	41	दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम–भारत में 'टीएम फाइलिंग प्रक्रिया, मैड्रिड इंटरनेशनल टीएम फाइलिंग प्रक्रिया' ; भारत में कॉपीराइट फाइलिंग, भारत में डिजाइन फाइलिंग' आदि विषयों पर
42	21–25 मार्च, 2022	49	एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम–'पेटेंट अधिनियम और नियमों के महत्वपूर्ण प्रावधान' आदि विषयों पर

ङ. एन.एल.यू, नागपुर व एन.एल.यू, मुंबई के सहयोग से आयोजित संयुक्त कार्यक्रम:

क्र.सं.	दिनांक	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रम का नाम
1	27 अप्रैल, 2021	55	एक दिवसीय पेड वेबिनार–आईपीआर, पेटेंट विशिष्टता, फाइलिंग, प्रोसेसिंग और पेटेंट खोज पर एम.एन.एल. यू. मुंबई के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। संकाय–डॉ. डब्ल्यू एम धूमाने, डॉ. भरत सूर्यवंशी, श्रीमती पूजा माऊलिकर
2	24 मई, 2021	74	एक दिवसीय ऑनलाइन संयुक्त कार्यशाला–आईपीआर का परिचय, भारतीय पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया, प्रपत्र, शुल्क व कार्यवाही, एम. एन. एल. यू. मुंबई के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। संकाय–डॉ. डब्ल्यू.एम. धूमाने और डॉ. पंकज बोरकर
3	25 मई, 2021	74	एक दिवसीय ऑनलाइन संयुक्त कार्यशाला–पेटेंट विशिष्टता और दावों के प्रारूपण आदि विषयों पर एम. एन. एल. यू. मुंबई के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। संकाय–डॉ. डब्ल्यू एम धूमाने, डॉ . पंकज बोरकर, श्री चिराग तन्ना

4	17 जून, 2021	106	एक दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला–भारत में ट्रेडमार्क फाइलिंग प्रक्रिया, मैड्रिड अंतरराष्ट्रीय ट्रेडमार्क फाइलिंग प्रक्रिया पर एम. एन. एल. यू. मुंबई के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया गया।। संकाय–श्री एसडी ओझा एवं डॉ. पवन कुमार पाण्डेय
5	18 जून, 2021	73	एक दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला–भारत में डिजाइन और कॉपीराइट फाइलिंग प्रक्रिया पर एम. एन. एल. यू. मुंबई के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया गया संकाय–डॉ. डब्ल्यूएम धूमाने, श्री जेके प्रधान, सुश्री किरण शर्मा
6	8 जुलाई, 2021	103	एक दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला–भारतीय पेटेंट फाइलिंग प्रक्रिया, फार्म, शुल्क और पीसीटी इंटरनेशनल पेटेंट फाइलिंग पर एम. एन. एल. यू. मुंबई के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया–संकाय–डॉ. डब्ल्यूएम धूमाने, डॉ. पंकज बोरकर, सुश्री जीबी बिमी
7	9 जुलाई, 2021	81	एक दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला–पेटेंट विवरण, दावों और पेटेंट खोज पर एनएलयू, नागपुर और एनएलयू, मुंबई के सहयोग से संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। संकाय–डॉ. पंकज बोरकर, डॉ. भरत सूर्यवंशी, श्रीमती पूजा मौलिककर
8	1 सितंबर, 2021	38	एक दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला–आरजीएनआईआईपीएम और एनएलयू, मुंबई द्वारा संयुक्त रूप से भारत में भौगोलिक संकेत, पौधों की किस्मों की सुरक्षा, इंटीग्रेटेड सर्किट के सेमीकंडक्टर लेआउट डिजाइन आदि विषयों पर आयोजित की गई। संकाय–श्री साजिद शेख, श्री सचिन शर्मा, श्री एपी श्रीवास्तव, श्रीमती दिपल रॉय चौधरी, डॉ. टी . के. नागरत्ना, डॉ. डब्ल्यू. एम . धूमाने
9	16 नवंबर, 2021	75	एक दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला–आई पी आर आई पी लाइसेंसिंग और व्यावसायीकरण पर आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर और एनएलयू, मुंबई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई। संकाय–डॉ. डब्ल्यू एम धूमाने, डॉ. योगेश पई, श्री सुभाजीत साहा, सुश्री पद्मा सतीश, डॉ. बिजय कुमार साहू

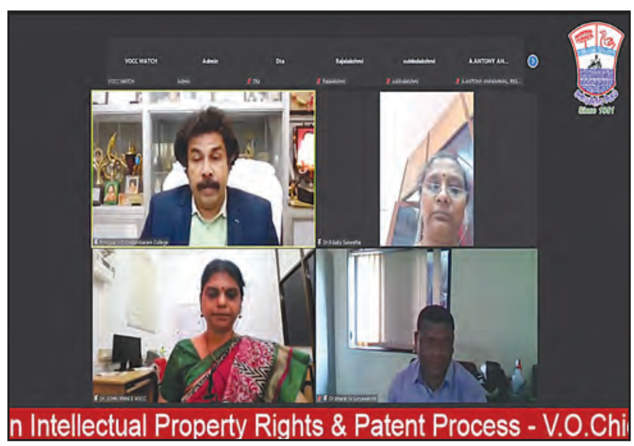

च. आरजीएनआईआईपीएम द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (निपम) और आईपीआर विषय पर कार्यशालाः

वर्ष 2021–22 के दौरान, आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर ने **169** आईपीआर कार्यशालाओं का आयोजन किया, जिसमें 27310 प्रतिभागियों ने पेटेंट, डिजाइन और आईपीआर के अन्य पहलुओं के महत्व को समझा। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (निपम) कार्यक्रम के तहत 31 मार्च, 2022 तक **189** शैक्षणिक संस्थानों के लिए ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किए गए, जिसमें 51704 छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया। उक्त कार्यक्रम/कार्यशालाएं पूरे वर्ष आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में विभिन्न संगठनों, संस्थाओं एवं अन्य शैक्षणिक विभागों के प्रतिभागी लाभान्वित हुए, जिनका विवरण इस प्रकार हैः

दिनांक	संगठन के सहयोग से
5 अप्रैल, 2021	संत मुक्ताबाई आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, जलगाँव
6 अप्रैल, 2021	राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी, अंबाझरी, नागपुर
9 अप्रैल, 2021	सुब्बालक्ष्मी लक्ष्मीपति कॉलेज ऑफ साइंस, मदुरै
9 अप्रैल, 2021	पैट्रीशियन कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, अडयार, चेन्नई
20 अप्रैल, 2021	जनता शिक्षण मंडल कॉलेज, अलीबाग
22 अप्रैल, 2021	सिंहगड इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल साइंस, लोनावाला
22 अप्रैल, 2021	जय श्रीराम इंजीनियरिंग कॉलेज, तमिलनाडु
22 अप्रैल, 2021	तुलसीरामजी गायकवाड़–पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, नागपुर
22 अप्रैल, 2021	इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एंड एजुकेशन रिसर्च, बोरगांव, वर्धा
23 अप्रैल, 2021	टीआईई, नागपुर
26 अप्रैल, 2021	डॉ.अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च, नागपुर
28 अप्रैल, 2021	यशवंतराव चव्हाण इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सतारा
18 मई, 2021	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर
27 मई, 2021	केडीके कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नागपुर
28 मई, 2021	गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गांधीनगर, गुजरात
31 मई, 2021	एसएम मोहोता कॉलेज ऑफ साइंस, नागपुर
2 जून, 2021	महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नागपुर
3 जून, 2021	एनएडीपी, नागपुर
5 जून, 2021	झूलेलाल प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर
14 जून, 2021	एसबी महिला महाविद्यालय, नागपुर
15 जून, 2021	सीएसआईआर–खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएमएमटी) सचिवालय मार्ग, भुवनेश्वर
16 जून, 2021	सदाबाई रायसोनी महिला कॉलेज, नागपुर
17 जून, 2021	जीएच रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नागपुर
18 जून, 2021	जीएच रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नागपुर
23 जून, 2021	कर्मवीर भाऊराव पाटिल कॉलेज, वाशी
23 जून, 2021	श्री बिंजनी सिटी कॉलेज, नागपुर
26 जून, 2021	यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज (न्स्सै), दिल्ली
28 जून, 2021	डॉ. बीए टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, लोनेरे, रायगढ़
2 जुलाई, 2021	सेंट क्लैरट कॉलेज, बैंगलोर
15 जुलाई, 2021	आरएस मुंडले धरमपेठ आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, नागपुर
14 जुलाई, 2021	दावणगेरे विश्वविद्यालय, दावणगेरे
19 जुलाई, 2021	जीएच रायसोनी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जलगाँव
22 जुलाई, 2021	डॉ. एपी जे, अब्दुल कलाम गवर्नमेंट कॉलेज, सिलवासा
27 जुलाई, 2021	एचएएल, बैंगलोर
27 जुलाई, 2021	बीएसएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, प्रयागराज
28 जुलाई, 2021	केसी लॉ कॉलेज, मुंबई
29 जुलाई, 2021	बीएमएस महिला कॉलेज, बेंगलुरु
29 जुलाई, 2012	केआईआईटी स्कूल ऑफ लॉ, भुवनेश्वर
3 अगस्त, 2021	गीतारतन इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल, नई दिल्ली
3 अगस्त, 2021	नीलकंठराव शिंदे साइंस एंड आर्ट्स कॉलेज, भद्रावती, चंद्रपुर

28 अगस्त, 2021	एमएनएलयू, नागपुर
1 सितंबर, 2021	जीएच रायसोनी विश्वविद्यालय, साईखेड़ा
2 सितंबर, 2021	आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बेंगलुरु
3 सितंबर, 2021	मुफ्फखम जाह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद
6 सितंबर, 2021	नागपुर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), नागपुर
7 सितंबर, 2021	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
9 सितंबर, 2021	एन एम ए एम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, निट्टे, कर्नाटक
9 सितंबर, 2021	एटीएसएस कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, चिंचवाड़, पुणे
13 सितंबर, 2021	वीओ चिदंबरम कॉलेज, थूथुकुडी
13 सितंबर, 2021	डॉ बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, रत्नागिरी
14 सितंबर, 2021	डीडी भोयार कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, मौदा, नागपुर
14 सितंबर, 2021	न्यू होराइजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बेंगलुरु
14 सितंबर, 2021	सेंट फ्रांसिस डी सेल्स कॉलेज, नागपुर
15 सितंबर, 2021	जीएच रायसोनी विश्वविद्यालय, साईखेड़ा
15 सितंबर, 2021	एसए जैन कॉलेज, अंबाला सिटी
16 सितंबर, 2021	राघवेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (त्प्च्म्), अनंतपुर
16 सितंबर, 2021	ईस्ट वेस्ट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बेंगलुरु
16 सितंबर, 2021	जी आई एम एस इंजीनियरिंग मैनेजमेंट टेक्निकल कैंपस, नोएडा
16 सितंबर, 2021	गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज, सिद्दकट्टे, कर्नाटक
17 सितंबर, 2021	संजय घोडावत पॉलिटेक्निक, कोल्हापुर
17 सितंबर, 2021	श्री गुरु सिंह जी गवर्नमेंट कॉलेज, पांवटा साहिब, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
17 सितंबर, 2021	गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, भरूच
18 सितंबर, 2021	यूजीसी, डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर
20 सितंबर, 2021	न्यू लॉ कॉलेज, पुणे
20 सितंबर, 2021	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पंजाब
21 सितंबर, 2021	यूजीसी–मानव संसाधन विकास केंद्र, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर
21 सितंबर, 2021	श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, भिलाई
21 सितंबर, 2021	श्री संत सावता माली ग्रामीण महाविद्यालय, फूलंबरी
21 सितंबर, 2021	कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन, गुंटूर
21 सितंबर, 2021	आरवीएस कॉलेज ऑफ फार्मास्युटिकल साइंसेज, सुलूर, कोयम्बटूर
22 सितंबर, 2021	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा
22 सितंबर, 2021	अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराईकुडी, तमिलनाडु
22 सितंबर, 2021	ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, अंबाझारी
22 सितंबर, 2021	मूलजी जैता कॉलेज, जलगाँव
22 सितंबर, 2021	सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (ब्डज्), बेंगलुरु
23 सितंबर, 2021	कलिंगा विश्वविद्यालय, नया रायपुर, छत्तीसगढ़
23 सितंबर, 2021	श्री महावीर फर्स्ट ग्रेड कॉलेज, कोडंगल्लू, कर्नाटक
24 सितंबर, 2021	लायलपुर खालसा कॉलेज, पंजाब
24 सितंबर, 2021	भिलाई प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्ग
25 सितंबर, 2021	पंडित दीनदयाल ऊर्जा विश्वविद्यालय, गांधीनगर

27 सितंबर, 2021	राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पंजाब
27 सितंबर, 2021	सीपी और बरार कॉलेज, नागपुर
28 सितंबर, 2021	गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, सकोली
28 सितंबर, 2021	ओरिएंटल यूनिवर्सिटी, इंदौर
28 सितंबर, 2021	दादा रामचंद बखरू सिंधु महाविद्यालय, नागपुर
28 सितंबर, 2021	सरस्वती विद्यालय–आठवीं कक्षा के लिए, नागपुर
28 सितंबर, 2021	बैंगलोर स्पीच एंड हियरिंग ट्रस्ट, बेंगलुरु
29 सितंबर, 2021	डॉ डी वाई पाटिल विद्यापीठ, पुणे
29 सितंबर, 2021	सरस्वती विद्यालय–9वीं कक्षा के लिए, नागपुर
29 सितंबर, 2021	अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेज, अमृतसर, पंजाब
29 सितंबर, 2021	लक्ष्मीनारायणदेव कॉलेज ऑफ फार्मेसी, भरूच
29 सितंबर, 2021	सुवीरा इंस्टीट्यूट फॉर रिहैबिलिटेशन एंड डिसएबिलिटीज, लखनऊ
30 सितंबर, 2021	सरस्वती विद्यालय 10वीं कक्षा के लिए, नागपुर
30 सितंबर, 2021	मल्ला रेड्डी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हैदराबाद
1 अक्टूबर, 2021	बांकुरा विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल
1 अक्टूबर, 2021	वी. वी. वन्नियापेरुमल कॉलेज फॉर वूमेन, विरुधुनगर
1 अक्टूबर, 2021	संजय घोडावत पॉलिटेक्निक, अतिग्रे
1 अक्टूबर, 2021	मल्ला रेड्डी फार्मेसी कॉलेज, मैसम्मागुडा, सिकंदराबाद
1 अक्टूबर, 2021	टीमलीज स्किल यूनिवर्सिटी, गुजरात
4 अक्टूबर, 2021	छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई
4 अक्टूबर, 2021	सोमलवार स्कूल माँ उमिया शाखा, नागपुर
5 अक्टूबर, 2021	आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, तिरुपति
5 अक्टूबर, 2021	जैव रसायन विभाग, सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली
5 अक्टूबर, 2021	धरमपेठ एमपी देव मेमोरियल साइंस कॉलेज, नागपुर
6 अक्टूबर, 2021	गुरु नानक प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर
7 अक्टूबर, 2021	सीएसआईआर–सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, पिलानी, राजस्थान
8 अक्टूबर, 2021	केडीके कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नागपुर
8 अक्टूबर, 2021	एमजीएम यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद
8 अक्टूबर, 2021	श्री चंद्रप्रभु जैन कॉलेज, एससीपीजेसी, मिंजुर
8 अक्टूबर, 2021	श्री मथुरादास मोहोता कॉलेज ऑफ साइंस, नागपुर
9 अक्टूबर, 2021	इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज, गाजियाबाद
9 अक्टूबर, 2021	नवरचना विश्वविद्यालय, वडोदरा, गुजरात
9 अक्टूबर, 2021	महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक
10 अक्टूबर, 2021	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नागपुर
11 अक्टूबर, 2021	सीएच चौधरी आर्ट्स, एसजी पटेल कॉमर्स और बाबाजी बीजे पटेल साइंस कॉलेज, नंदुरबार
11 अक्टूबर, 2021	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर
12 अक्टूबर, 2021	पिंपरी चिंचवाड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (पीसीसीओई), पुणे
12 अक्टूबर, 2021	सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, जवाहर लाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवम होम्योपैथी अनुसंधान भवन, नई दिल्ली
12 अक्टूबर, 2021	गुरुकुल कांगड़ी (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी), हरिद्वार

13 अक्टूबर, 2021	क्रिश्चियन एमिनेंट कॉलेज, इंदौर
13 अक्टूबर, 2021	जीएमसी, भावनगर
13 अक्टूबर, 2021	आचार्य बैंगलोर बी–स्कूल, बेंगलुरु
14 अक्टूबर, 2021	इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर
14 अक्टूबर, 2021	स्टेनली महिला इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कॉलेज के, हैदराबाद
16 अक्टूबर, 2021	श्री रामदेवबाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, नागपुर
20 अक्टूबर, 2021	गेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, अनंतपुर
21 अक्टूबर, 2021	गेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग, अनंतपुर
21 अक्टूबर, 2021	जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, नागपुर
21 अक्टूबर, 2021	गांधीनगर प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर
22 अक्टूबर, 2021	गेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, अनंतपुर
22 अक्टूबर, 2021	अल्फा आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, चेन्नई
22 अक्टूबर, 2021	जेडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, नागपुर
24 अक्टूबर, 2021	एमएनएलयू, नागपुर
25 अक्टूबर, 2021	गोवा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गोवा
25 अक्टूबर, 2021	डीबीएफ दयानंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, सोलापुर
25 अक्टूबर, 2021	एस.एस.एस.एस कॉलेज ऑफ कॉमर्स फॉर वूमेन, अमृतसर
26 अक्टूबर, 2021	श्री विठ्ठल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, फार्मेसी कॉलेज, पंढरपुर
27 अक्टूबर, 2021	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद
27 अक्टूबर, 2021	वैनगंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, नागपुर
27 अक्टूबर, 2021	आईपीएस अकादमी, इंजीनियरिंग और विज्ञान संस्थान, इंदौर
27 अक्टूबर, 2021	अनुसंधान निदेशालय, आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद
27 अक्टूबर, 2021	फल विज्ञान विभाग, ए एस पी ई ई बागवानी और वानिकी कॉलेज, नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी, गुजरात
28 अक्टूबर, 2021	गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज, इंदौर
28 अक्टूबर, 2021	महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर, मध्य प्रदेश
28 अक्टूबर, 2021	कवि कुलगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, रामटेक
28 अक्टूबर, 2021	सेंट अलॉयसियस कॉलेज, जबलपुर
28 अक्टूबर, 2021	गेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग, अनंतपुर
29 अक्टूबर, 2021	गेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अनंतपुर
29 अक्टूबर, 2021	गेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, अनंतपुर
29 अक्टूबर, 2021	धोटे बंधु साइंस कॉलेज, गोंदिया
30 अक्टूबर, 2021	कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर
9 नवंबर, 2021	सेंट थॉमस कॉलेज, भिलाई
10 नवंबर, 2021	कंप्यूटर विज्ञान और आईटी विभाग, लायलपुर खालसा कॉलेज, जालंधर
11 नवंबर, 2021	इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर
11 नवंबर, 2021	मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क, चेन्नई
12 नवंबर, 2021	वेल टेक हाई टेक, डॉ. रंगराजन डॉ शकुंतला इंजीनियरिंग कॉलेज, चेन्नई

15 नवंबर, 2021	विज्ञान संस्थान, नागपुर
16 नवंबर, 2021	श्रीनिवास रामानुजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अनंतपुर
17 नवंबर, 2021	श्रीनिवास रामानुजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अनंतपुर
18 नवंबर, 2021	बलभीम कला, विज्ञान और वाणिज्य, बीड
18 नवंबर, 2021	श्री शिवाजी एजुकेशन सोसाइटी, अमरावती साइंस कॉलेज, नागपुर
18 नवंबर, 2021	श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, चेन्नई
20 नवंबर, 2021	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग, जीएच रायसोनी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, नागपुर
23 नवंबर, 2021	रॉयल कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज, बेरहामपुर, ओडिशा
24 नवंबर, 2021	चलपति इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल साइंसेज, लाम, गुंटूर
25 नवंबर, 2021	फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, हैदराबाद
25 नवंबर, 2021	क्राइस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु
25 नवंबर, 2021	बिशप मूर कॉलेज, केरल
25 नवंबर, 2021	जी एन आई ओ टी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ग्रेटर नोएडा, यूपी
26 नवंबर, 2021	मंघनमल उधरम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, पिंपरी, पुणे
26 नवंबर, 2021	द न्यू कॉलेज, चेन्नई
2 दिसम्बर, 2021	इस्लामिया कॉलेज, तिरुपत्तूर, तमिलनाडु
3 दिसम्बर, 2021	ए.बी.एन सील कॉलेज, कूच बिहार, पश्चिम बंगाल
6 दिसम्बर, 2021	के.एल.ई. सोसायटी गुडलेप्पा हल्लीकेरी डिग्री कॉलेज, हावेरी, कर्नाटक
6 दिसम्बर, 2021	इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय (आईजीडीटीयूडब्ल्यू)–अन्वेषण फाउंडेशन, दिल्ली
6 दिसम्बर, 2021	जेडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, नागपुर
6 दिसम्बर, 2021	केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कोकराझार, असम
7 दिसम्बर, 2021	शिवाजीराव कदम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (एस के आई टी एम), भोपाल
7 दिसंबर, 2021	श्री विद्यानिकेतन इंजीनियरिंग कॉलेज, तिरुपति, आंध्र प्रदेश
8 दिसंबर, 2021	अनंत लक्ष्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, (ए एल टी एस), अनंतपुर
9 दिसंबर, 2021	उद्यमिता के लिए नवाचार और ऊष्मायन केंद्र आई. आई. सी. ई, भोपाल
9 दिसंबर, 2021	बी. के बिड़ला कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, कल्याण
10 दिसम्बर, 2021	जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर
10 दिसम्बर, 2021	तुलसीरामजी गायकवाड़–पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, नागपुर
13 दिसम्बर, 2021	महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एम एन एल यू), नागपुर
15 दिसंबर, 2021	गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस, मुंबई
18 दिसंबर, 2021	उत्तर कामरूप कॉलेज, असम
20 दिसम्बर, 2021	कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अकोला
21 दिसंबर, 2021	मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, (एमएएनयूयू), शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय–बीदर
22 दिसंबर, 2021	एस. के. एन सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पंढरपुर
22 दिसंबर, 2021	कृषि महाविद्यालय, नागपुर
23 दिसम्बर, 2021	पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल, गोंदिया
24 दिसंबर, 2021	नगर परिषद शिवाजी महाविद्यालय, मोवाड, नागपुर
27 दिसंबर, 2021	एमजी आर्ट्स, साइंस एंड लेट एनपी कॉमर्स कॉलेज, अरमोरी, गढ़चिरौली
28 दिसंबर, 2021	गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नागपुर

28 दिसंबर, 2021	सासी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, ताडेपल्लीगुडेम, आंध्र प्रदेश
29 दिसंबर, 2021	बाबा नानक सिंधी हिंदी हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज, नागपुर
29 दिसंबर., 2021	सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, नागपुर
30 दिसंबर, 2021	शैलदेवी महाविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़
30 दिसंबर, 2021	भवनस–भगवानदास पुरोहित विद्या मंदिर, त्रिमूर्ति नगर, नागपुर
3 जनवरी, 2022	मदर टेरेसा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, औरंगाबाद
4 जनवरी, 2022	लक्ष्मीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एलआईटी), नागपुर
4 जनवरी, 2022	मेथोडिस्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एबिड्स, हैदराबाद
4 जनवरी, 2022	पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, आरटीएमएनयू, नागपुर
4 जनवरी, 2022	महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, सेवाग्राम, वर्धा
5 जनवरी, 2022	मदर थेरेसा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, कुरनूल, आंध्र प्रदेश
5 जनवरी, 2022	एस. जे. बी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बेंगलुरु
5 जनवरी, 2022	दयानन्द आर्य कन्या महाविद्यालय, नागपुर
6 जनवरी, 2022	पी. बी. आर विश्वोदय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश
6 जनवरी, 2022	कॉलेज ऑफ फार्मेसी (सी. ई. एस. सी. ओ. पी), कुरनूल
7 जनवरी, 2022	जीएच रायसोनी लॉ कॉलेज, नागपुर
7 जनवरी, 2022	झूलेलाल प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर
7 जनवरी, 2022	कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पुणे
7 जनवरी, 2022	एम. आई. टी एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, आलंदी, पुणे
8 जनवरी, 2022	इंडस यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद
10 जनवरी, 2022	एच. वी. पी. एम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अमरावती
10 जनवरी, 2022	डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर महाविद्यालय, अमरावती; तक्षशिला महाविद्यालय, अमरावती; रामकृष्ण महाविद्यालय, दारापुर
10 जनवरी, 2022	राजर्षि शाहू कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बुलढाणा
10 जनवरी, 2022	कस्तूरबा नर्सिंग कॉलेज, सेवाग्राम
11 जनवरी, 2022	बौद्धिक संपदा सुविधा केंद्र, आईपीएफसी–आईआईटी–हैदराबाद
11 जनवरी, 2022	सोनेकर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नागपुर
11 जनवरी, 2022	विद्या भारती महाविद्यालय, अमरावती
11 जनवरी, 2022	के.जे सोमैया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, मुंबई
11 जनवरी, 2022	सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पुत्तूर, आंध्र प्रदेश
12 जनवरी, 2022	एसबी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एंड रिसर्च, नागपुर
12 जनवरी, 2022	विद्यालंकार प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई
13 जनवरी, 2022	हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर
13 जनवरी, 2022	पी. वाधवानी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, यवतमाल
13 जनवरी, 2022	स्त्री शिक्षण प्रसारक मंडल, महिला महाविद्यालय, नागपुर, राजकुमार केवलरमानी कन्या महाविद्यालय, नागपुर और यशोदा गर्ल्स आट्र्स एंड कॉमर्स कॉलेज, नागपुर
13 जनवरी, 2022	विद्या विकास कला वाणिज्य और विज्ञान महाविद्यालय, समुद्रपुर
13 जनवरी, 2022	श्री मुक्तानंद कॉलेज, औरंगाबाद
14 जनवरी, 2022	नीलकंठराव शिंदे साइंस एंड आट्र्स कॉलेज, चंद्रपुर
14 जनवरी, 2022	बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रौद्योगिकी प्रबंधन और व्यापार केंद्र कृषि महाविद्यालय, केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशूर, केरल

14 जनवरी, 2022	गवर्नमेंट विदर्भ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, अमरावती
17 जनवरी, 2022	झूलेलाल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर, नागपुर
17 जनवरी, 2022	ठाकुर शोभा सिंह सरकार कॉलेज, पत्थलगांव
18 जनवरी, 2022	ग्रेट ब्रिटेन हाई स्कूल, नागपुर
18 जनवरी, 2022	तिरपुड़े कॉलेज ऑफ सोशल वर्क, नागपुर
18 जनवरी, 2022	विद्याभारती कॉलेज, सेलू, वर्धा
18 जनवरी, 2022	गोविन्दराम सेकसरिया कॉलेज (जीएस) ऑफ कॉमर्स, वर्धा
18 जनवरी, 2022	गोंडवाना विश्वविद्यालय, गढ़चिरौली
19 जनवरी, 2022	अंजुमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, नागपुर
19 जनवरी, 2022	रूंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, भिलाई
20 जनवरी, 2022	भिवापुर महाविद्यालय, भिवापुर, नागपुर
20 जनवरी, 2022	महेंद्र कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सलेम
20 जनवरी, 2022	नागरिक शिक्षण संस्थान कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, ताड़देव, मुंबई
21 जनवरी, 2022	स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर
21 जनवरी, 2022	गुरु नानक कॉलेज, चेन्नई
21 जनवरी, 2022	गवर्नमेंट नवीन कॉलेज, बेरला
21 जनवरी, 2022	श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, रायपुर
24 जनवरी, 2022	मौली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, शेगांव
24 जनवरी, 2022	दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज, नागपुर
24 जनवरी, 2022	स्योरटेक कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नागपुर
24 जनवरी, 2022	स्कूल ऑफ लॉ, डीएवीवी, इंदौर
24 जनवरी, 2022	पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश
24 जनवरी, 2022	यशवंतराव शिंदे जूनियर कॉलेज, भद्रावती
25 जनवरी, 2022	राजर्षि शाहू महाविद्यालय, लातूर
25 जनवरी, 2022	जगदंभा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यवतमाल
27 जनवरी, 2022	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
27 जनवरी, 2022	डॉ. आरजी भोयार इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, वर्धा
27 जनवरी, 2022	इनोवेशन ऑनलाइन ट्रेनिंग एकेडमी (आई ओ टी ए), कोयम्बटूर
27 जनवरी, 2022	अनुराग कॉलेज ऑफ फार्मेसी, भंडारा
27 जनवरी, 2022	बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भोपाल
28 जनवरी, 2022	डोमिनियन फिलिप्स कंसल्टेंसी, नागपुर
28 जनवरी, 2022	पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड साइंसेज (पीआईएएस), वडोदरा, गुजरात
28 जनवरी, 2022	डॉ. ए.एस. मधुकरराव वासनिक पीडब्ल्यूएस कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, नागपुर
31 जनवरी, 2022	स्कूल ऑफ लाइफ एंड एलाइड साइंस, आईटीएम यूनिवर्सिटी, रायपुर
1 फरवरी, 2022	धोटे बंधु साइंस कॉलेज, गोंदिया
1 फरवरी, 2022	सेठ केसरीमल पोरवाल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, कामटी
2 फरवरी, 2022	यशवंतराव चव्हाण कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (वाईसीसीई), नागपुर
2 फरवरी, 2022	गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जगदलपुर
3 फरवरी, 2022	महात्मा फुले कला, वाणिज्य और सीतारामजी चौधरी विज्ञान महाविद्यालय, वरुद

3 फरवरी, 2022	श्री राजेंद्र हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज, नागपुर
4 फरवरी, 2022	स्कूल ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज, विनायक मिशन रिसर्च फाउंडेशन, सलेम, तमिलनाडु
5 फरवरी, 2022	श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय, इंदौर
7 फरवरी, 2022	गुरुनाक पब्लिक स्कूल, बल्लारपुर
7 फरवरी, 2022	शिरडी साईं रूरल इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, रहाता
7 फरवरी, 2022	बौद्धिक संपदा अधिकार केंद्र, आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम
8 फरवरी, 2022	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा
8 फरवरी, 2022	अशोकराव माने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वाथर वडगाँव, ताल–हाटकनंगले
8 फरवरी, 2022	डॉ. ए.एस. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च, नागपुर
8 फरवरी, 2022	आई.सी.एफ.ए.आई यूनिवर्सिटी, रायपुर
8 फरवरी, 2022	विद्याभारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अमरावती
9 फरवरी, 2022	स्कूल ऑफ स्टडीज इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर
10 फरवरी, 2022	केएमटी सरकार। कन्या महाविद्यालय, रायगढ़
9 फरवरी, 2022	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, छत्तीसगढ़
9 फरवरी, 2022	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भिलाई
9 फरवरी, 2022	सांदीपनी अकादमी, दुर्ग
10 फरवरी, 2022	अवधेश प्रदाप सिंह (एपीएस) विश्वविद्यालय, रीवा
10 फरवरी, 2022	गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, नागपुर
11 फरवरी, 2022	सेंट विंसेंट पल्लोटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, नागपुर
11 फरवरी, 2022	डी. के. टी. ई पद्मभूषण डॉ. वसंतरोदादा पाटिल प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इचलकरंजी
11 फरवरी, 2022	विधि विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, मध्य प्रदेश
14 फरवरी, 2022	डॉ अंबेडकर कॉलेज ऑफ सोशल वर्क, वर्धा
14 फरवरी, 2022	कृषि उद्योग एमयूएल शिक्षण संस्था, करहाटी, पुणे
15 फरवरी, 2022	जयपुर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जयपुर
15 फरवरी, 2022	साव। लीना किशोर ममिडवार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च, कोसरा, चंद्रपुर
15 फरवरी, 2022	ऋषि दयाराम और सेठ हसाराम नेशनल कॉलेज और सेठ वासियामुल एसोमूल साइंस कॉलेज, बांद्रा वेस्ट, मुंबई
15 फरवरी, 2022	आदर्श आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, देसाईगंज, गढ़चिरौली
16 फरवरी, 2022	राजेंद्र गोदे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, अमरावती
16 फरवरी, 2022	श्री विले पार्ले केलवानी मंडल की नरसी मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, मुंबई
16 फरवरी, 2022	जीएच रायसोनी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, नागपुर
16 फरवरी, 2022	राही सेंट्रल स्कूल और राही पब्लिक स्कूल, नागपुर
16 फरवरी, 2022	स्वामी सहजानंद कॉलेज, जहानाबाद
17 फरवरी, 2022	इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, वर्धा
17 फरवरी, 2022	केडीके कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नागपुर (कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग), नागपुर
17 फरवरी, 2022	इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन, धुले
17 फरवरी, 2022	लक्ष्मी–शालिनी कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस महिला कॉलेज, पेजारी, रायगढ़
17 फरवरी, 2022	महारानी लक्ष्मी अम्मन्नी महिला कॉलेज, बेंगलुरु
18 फरवरी, 2022	क्रिस्तु जयंती कॉलेज, बेंगलुरु
18 फरवरी, 2022	अन्नासाहेब गुंडेवार कॉलेज, नागपुर

19 फरवरी, 2022	डॉ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर
21 फरवरी, 2022	डॉ राजेंद्र गोड कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मलकापुर
21 फरवरी, 2022	गवर्नमेंट कॉलेज लॉन, जिला–बलौदा बाजार भाटापारा, छत्तीसगढ़
22 फरवरी, 2022	वीएसपीएम माधुरीबाई देशमुख इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, नागपुर
22 फरवरी, 2022	मातृ सेवा संघ सामाजिक कार्य संस्थान, नागपुर
22 फरवरी., 2022	महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, रायपुर, छत्तीसगढ़
23 फरवरी., 2022	श्री शंकराचार्य तकनीकी परिसर, भिलाई
24 फरवरी., 2022	प्रेरणा कॉलेज ऑफ कॉमर्स, नागपुर
24 फरवरी., 2022	महर्षि कर्वे सड़क शिक्षण संस्था, सीता बाई नरगुंडकर महिला नर्सिंग कॉलेज, नागपुर
24 फरवरी, 2022	दिशा कॉलेज, रायपुर
24 फरवरी, 2022	जीएच रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नागपुर
25 फरवरी, 2022	ओपी जिंदल विश्वविद्यालय, रायगढ़, छत्तीसगढ़
25 फरवरी, 2022	राजर्षि शाहू साइंस कॉलेज, चंदूर रेलवे, अमरावती
25 फरवरी, 2022	विश्वोदय इंजीनियरिंग कॉलेज, कावली, आंध्र प्रदेश
25 फरवरी, 2022	जीएच रायसोनी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, खापरखेड़ा, नागपुर
26 फरवरी, 2022	वालचंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, सोलापुर
28 फरवरी, 2022	श्रीमान भाऊसाहेब ज़डबुके महाविद्यालय, बार्शी, सोलापुर
1 मार्च, 2022	एम. वी. पी. एस कर्मवीर शांतारामबापू कोंडाजी वावरे आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज, सिडको, नासिक
2 मार्च, 2022	डीईएस विवेकानंद महाविद्यालय, रायपुर
मार्च 3, 2022	पीआर पोटे पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, अमरावती
मार्च 3, 2022	श्री शिवाजी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, अमरावती
4 मार्च, 2022	अन्नासाहेब डांगे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आष्टा
4 मार्च, 2022	नागालैंड विश्वविद्यालय, नागालैंड
4 मार्च, 2022	कमला नेहरू महाविद्यालय, नागपुर
4 मार्च, 2022	प्रियदर्शिनी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन स्टडीज, नागपुर
7 मार्च, 2022	पी पी सवानी विश्वविद्यालय, सूरत
8 मार्च, 2022	राज कुमार गोयल प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ
8 मार्च, 2022	ग्रेट ब्रिटेन हाई स्कूल, नागपुर
9 मार्च, 2022	जनता हाई स्कूल, नरखेड, नागपुर
9 मार्च, 2022	सेज यूनिवर्सिटी, इंदौर
10 मार्च, 2022	महात्मा गांधी आयुर्वेद कॉलेज, हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, सालोद, वर्धा
10 मार्च, 2022	जेएसपीएम के राजर्षि शाहू कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च, पुणे
11 मार्च, 2022	सदाबाई रायसोनी महिला कॉलेज, नागपुर
16 मार्च, 2022	बॉम्बे हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इंदौर
16 मार्च, 2022	बालीराम पाटिल कला, वाणिज्य और विज्ञान महाविद्यालय, किनवट, नांदेड़
21 मार्च, 2022	देओला एजुकेशन सोसायटी कर्मवीर रामरावजी अहेर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज, देओला, नासिक
21 मार्च, 2022	एनआईटी, सिलचर, असम
22 मार्च, 2022	श्री नरेंद्र तिड़के कॉलेज, रामटेक; महात्मा गांधी कला और वाणिज्य महाविद्यालय, परसिवनी; नूतन आदर्श कला, वाणिज्य और श्रीमती एमएच वेगड साइंस कॉलेज, उमरेर

23 मार्च, 2022	गवर्नमेंट नागार्जुन पी.जी. ऑटोनॉमस कॉलेज ऑफ साइंस, रायपुर, छत्तीसगढ़
24 मार्च, 2022	विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़
24 मार्च, 2022	विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च (वीईएसआईएम), मुंबई
25 मार्च, 2022	विप्रा कला, वाणिज्य और शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़
25 मार्च, 2022	ए.के.एस यूनिवर्सिटी, सतना
25 मार्च, 2022	महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नागपुर
28 मार्च, 2022	स्कूल ऑफ स्कॉलर्स, बेलतरोड़ी, नागपुर
29 मार्च, 2022	चेट्टीनाड स्कूल ऑफ फार्मास्युटिकल साइंसेज, चेट्टीनाड एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन, केलमबक्कम, तमिलनाडु
29 मार्च, 2022	श्री शिवाजी लॉ कॉलेज, परभाणी

निपम कार्यक्रम की तस्वीरें

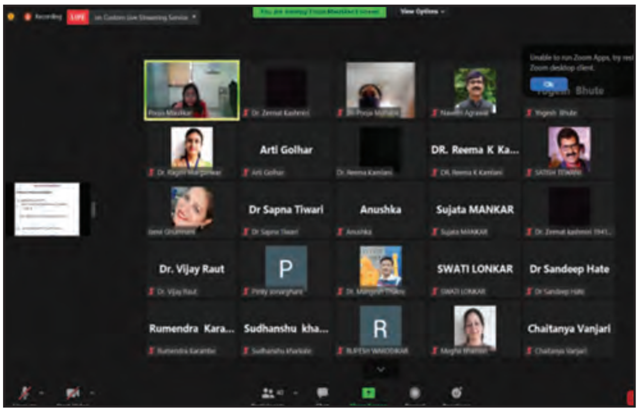

छ. आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम

विश्व आईपी दिवस समारोहः

26 अप्रैल, 2020 को यानी विश्व आईपी दिवस के अवसर पर, संकाय सदस्यों, छात्रों आदि के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए वेबिनार के माध्यम से आरजीएनआईआईपीएम द्वारा की गई पहल अत्यधिक सफल एवं सराहनीय रही। तकनीकी सत्र विश्व आईपी दिवस पर लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग के माध्यम से प्रतिभागियों के बीच आईपी को बढ़ावा देने के लिए विचारों के आदान–प्रदान एवं अन्य रणनीतियों पर परिचर्चा की गई।

पेटेंट सूचना पद्धति

1980 में भारत सरकार ने नागपुर में, पेटेंट सूचना पद्धति (पीआईएस) कार्यालय की स्थापना विश्व स्तर पर पेटेंट विनिर्देशों और पेटेंट से संबंधित साहित्य का विशद् संकलन बनाए रखने ताकि अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, उद्योगों, व्यवसायी उद्यमों, आविष्कारकों और भारत के अन्य उपयोक्ताओं की प्रौद्योगिकीय सूचना की आवश्यकता पूर्ण की जा सके व पेटेंट में निहित प्रौद्योगिकी सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। पेटेंट सूचना पद्धति उपयोगकर्ताओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यालय में उपलब्ध पेटेंट दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रदान करके पेटेंट आपूर्ति सेवा प्रदान करती है।

अध्याय–XII

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

परिचय

वर्ष 2021–22 के दौरान, कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न ने कई पहल कीं, जो अन्य आईपी कार्यालयों के साथ बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में निर्देशित थीं। कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न ने विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण आईपी से संबंधित मुद्दों पर डब्ल्यूआईपीओ और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आयोजित चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, अन्य देशों के आईपी कार्यालयों के साथ आईपी के क्षेत्र में नए समझौता ज्ञापन (एमओयू) और कार्य योजनाओं पर द्विपक्षीय स्तर पर हस्ताक्षर किए गए। विदेशी बौद्धिक संपदा कार्यालयों के सहयोग से कार्य योजनाओं के अंतर्गत कई पारस्परिक रूप से लाभकारी गतिविधियों का संचालन किया गया। यह अध्याय प्रतिवेदन वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में हुई प्रगति से संबंधित है।

I. द्विपक्षीय सहयोग:

1. डेनिश पेटेंट व व्यापार चिह्न कार्यालय:

कार्य योजना के तहत, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के संबंध में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में कई बैठकें आयोजित की गईं। कोविड–19 महामारी द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों के बावजूद, जिसमें यात्रा प्रतिबंध शामिल थे, दोनों पक्ष क्यूएमएस से संबंधित कार्य में प्रगति करने में सक्षम रहे।

2. जापान पेटेंट कार्यालय:

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न और जापान पेटेंट कार्यालय ने एक–दूसरे के अंतरराष्ट्रीय खोज प्राधिकरण और अंतरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण (आईएसए/आईपीईए) को मान्यता दी और इस बात पर सहमति व्यक्त की कि दोनों कार्यालय 1 जुलाई 2021 से आईएसए/आईपीईए के रूप में कार्य करना प्रारम्भ कर देंगे। दोनों कार्यालयों को एक–दूसरे की आईटी प्रणालियों की अपनी समझ में सुधार करने की अनुमति देने के लिए आईपीओ और जेपीओ (आईटी विशेषज्ञ एमटीजी) के बीच बैठक भी आयोजित की गई। आईटी विशेषज्ञों ने भी टेलीवर्किंग के कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा की।

3. संयुक्त राज्य पेटेंट और व्यापार चिह्न कार्यालय (यूएसपीटीओ):

दिसंबर 2020 में डीपीआईआईटी और यूएसपीटीओ के बीच हस्ताक्षरित सहमति ज्ञापन के अनुसार डीपीआईआईटी और यूएसपीटीओ के बीच पारस्परिक रूप से सहमत कार्य योजना दिसंबर 2021 में लागू हुई।

4. फेडरल सर्विस फॉर इंटलेक्चुयल प्रॉपर्टी (रोसपेटेंट):

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और फेडरल सर्विस फॉर इंटलेक्चुयल प्रॉपर्टी (रोसपेटेंट) के बीच बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर 03 दिसंबर, 2021 को हस्ताक्षर किए गए।

II. वायपो के सदस्य देशों की सभाएं – बैठकों की 62वीं श्रृंखला:

1. 2021–22 के दौरान, वायपो महासभा और वायपो के सदस्य देशों की सभाओं में निम्नलिखित भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लियाः

- क) श्री इन्द्र मणि पांडे, राजदूत, स्थायी प्रतिनिधि, स्थायी मिशन, जेनेवा
- ख) श्री पुनीत अग्रवाल, राजदूत, उप स्थायी प्रतिनिधि, स्थायी मिशन, जेनेवा
- ग) सुश्री श्रुति सिंह, संयुक्त सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), नई दिल्ली
- घ) श्री राजेंद्र रत्नू, महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली
- ङ) श्री करण थापर, उप सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली
- च) श्री समीर कुमार स्वरूप, उप नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प, कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली
- छ) श्री शक्ति धर ओझा, उप पंजीकार व्यापार चिह्न एवं भौगोलिक उपदर्शन, कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली
- ज) श्री सुखदीप सिंह, सहायक नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प, कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली
- झ) सुश्री गरिमा पॉल, प्रथम सचिव, स्थायी मिशन, जेनेवा

2. भारत की ओर से उद्घाटन वक्तव्य भारत के स्थायी प्रतिनिधि श्री इंद्र मणि पांडे ने दिया। यह कहा गया कि कोविड–19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के कारण सदस्य देश वायपो में नियामक मुद्दों पर सीमित प्रगति करने में सक्षम रहे हैं। अतः भारत यह आशा करता है कि सदस्य देशों के रचनात्मक योगदान से ठोस मुद्दों पर प्रगति होगी। भारत के प्रतिनिधिमंडल ने आईपी अधिकारों और विकास के बीच सही संतुलन बनाने की दिशा में कार्य करने के लिए वायपो की प्रतिबद्धता में विश्वास व्यक्त किया और विश्व व्यापार संगठन में ट्रिप्स छूट पर भारत–दक्षिण अफ्रीका संयुक्त प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेने का आह्वान किया।

3. आईजीसी की रिपोर्ट पर, *(बौद्धिक संपदा और आनुवंशिक संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान और लोकगीत पर अंतर सरकारी समिति की रिपोर्ट* (*आईजीसी*) भारत के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि चल रही चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए अगले द्विवार्षिक के लिए आईजीसी के जनादेश का विस्तार महत्वपूर्ण था। ऐसे संसाधनों तक उचित पहुंच के साथ–साथ जीआर के उपयोग से होने वाले लाभों के उचित और समान बंटवारे को बढ़ावा देना स्वयं एसडीजी का हिस्सा था। सदियों पुराने पारंपरिक ज्ञान व तकनीकों को अपनाकर संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए आईजीसी का जीआर, टीके, टीसीई और एसडीजी के बीच अंतर्निहित संबंध रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने जीआर, टीके और टीसीई के संरक्षण के लिए उपकरणों के शीघ्र निष्कर्ष की प्रतीक्षा में है और सभी सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे महान उद्देश्य की शीघ्र पूर्ति के लिए अधिक रचनात्मक तरीके से संलग्न होने की अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाएं जो आईजीसी का उद्देश्य है।

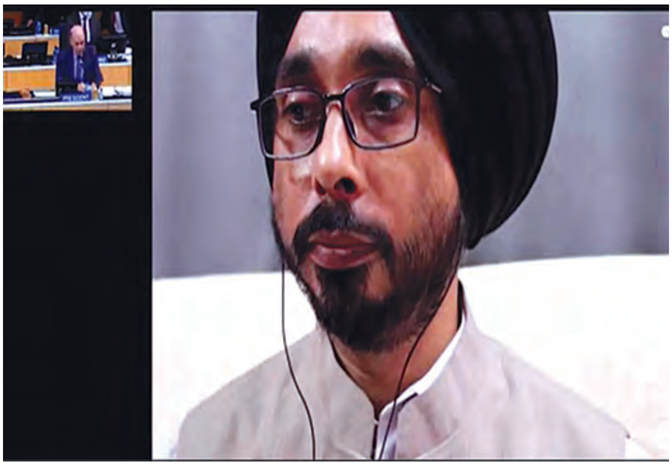

4. आईओडी रिपोर्ट (*आंतरिक निरीक्षण प्रभाग के निदेशक द्वारा वार्षिक रिपोर्ट*) पर, भारत के प्रतिनिधिमंडल ने कोविड–19 महामारी के मद्देनजर कार्य को कारगर बनाने के लिए अपनी कार्य योजना को संशोधित करने के लिए आईओडी द्वारा किए गए उपायों की सराहना की और अन्य निरीक्षण निकायों के साथ आईओडी के सहयोग का स्वागत किया। प्रतिनिधिमंडल ने वायपो कार्यक्रमों की अधिक पूर्ण और गहन समीक्षा प्रदान करने के लिए लेखा परीक्षकों और परीक्षकों और मूल्यांकन व्यावसायिकों के साथ आईओडी के निरंतर प्रति–अनुभागीय सहयोग की सराहना की। प्रतिनिधिमंडल ने जोर देकर कहा कि निदेशक, आईओडी की रिपोर्ट ने कुछ बहुमूल्य सिफारिशें की हैं और उन्हें विश्वास है कि संगठन रिपोर्ट के कार्यान्वयन और इसके समापन की दिशा में कार्य करेगा।

5. *'डिजाइन कानून संधि को अपनाने के लिए राजनयिक सम्मेलन के आयोजन से संबंधित मामले'* (डीएलटी)' पर, भारत के प्रतिनिधिमंडल ने तकनीकी सहायता और प्रकटीकरण आवश्यकताओं पर प्रावधानों के राजनीतिक प्रकृति के होने पर विचार करते हुए कहा कि उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रभाव को हल करने के लिए समाधान खोजना अत्यावश्यक था। प्रतिनिधिमंडल ने सदस्य देशों से समाधान की दिशा में सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया, जो उन मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करेगा और डीएलटी के लिए राजनयिक सम्मेलन के शीघ्र आयोजन के लिए अपने समर्थन को दोहराया।

6. एससीपी रिपोर्ट (*पेटेंट के कानून पर स्थायी समिति पर रिपोर्ट*) पर, भारत के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पेटेंट प्रणाली संतुलित होनी चाहिए, न कि एक तरफ अथवा दूसरी तरफ झुकी हुई। प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पेटेंट प्रणाली में अपवाद और सीमाएं महत्वपूर्ण हैं और उन्होने संतुलन प्राप्त करने में मदद की। और, प्रतिनिधिमंडल ने प्रस्तावित किया कि, भविष्य के कार्य के भाग के रूप में, उन अपवादों और सीमाओं के बारे में अध्ययन किया जाए जो चल रही महामारी के लिए प्रासंगिक थे, क्योंकि इससे सदस्य राज्य दूसरे राज्यों से सीख पाएंगें। प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न अधिकार क्षेत्रों द्वारा सामना की जा रही सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं को दूर करने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार–संबंधित पहलुओं (ट्रिप्स समझौते) पर समझौते में लचीलेपन को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि विपक्षी प्रणाली ने पेटेंट की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अत्यधिक योगदान दिया है और इसने पेटेंट प्रणाली में सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा

दिया है। प्रतिनिधिमंडल ने इस तथ्य पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण एक चुनौती बना हुआ है, जबकि यह पेटेंट प्रणाली का उद्देश्य था। इस संबंध में, प्रतिनिधिमंडल ने अन्य सदस्य राज्यों के साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की।

7. एससीसीआर रिपोर्ट (*कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों पर स्थायी समिति की रिपोर्ट*) पर, भारत के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि प्रसारण संगठनों की सुरक्षा पर संधि के मसौदे के संबंध में, वह ऐसी संधि को अंतिम रूप देने का समर्थन करता है जो प्रसारण संगठनों के हितों की रक्षा करती है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करती है। प्रतिनिधिमंडल का मानना था कि पुस्तकालयों और अभिलेखागार, शैक्षिक अनुसंधान संस्थानों और अन्य विकलांग व्यक्तियों के लिए सीमाओं और अपवादों ने समाज के अधिक समग्र और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रतिनिधिमंडल इस संबंध में एक संतुलित और दीर्घकालिक पाठ पर सदस्य देशों के साथ कार्य करने के लिए उत्सुक था।

III. **पीसीटी कार्यकारी समूहः** 14 जून से 18 जून, 2021 तक जेनेवा में आयोजित पीसीटी कार्यकारी समूह के चौदहवें सत्र में, भारत के प्रतिनिधिमंडल ने व्याख्यात्मक बयान के कार्यान्वयन पर अध्ययन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को धन्यवाद दिया, जिसका भारतीय पेटेंट कार्यालय ने पिछली कार्य समूह की बैठक में अनुरोध किया था। यह कहा गया कि अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि नियम 82 *quater*.1 जब व्याख्यात्मक बयान को प्रभावी बनाने के लिए संशोधित किया गया तो सामान्य व्यवधान की स्थितियों को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सकता है। समय सीमा को पूरा करने में देरी का बहाना करने के लिए कार्यालयों द्वारा प्राप्त अनुरोधों की संख्या कम थी और कार्यालयों को इन अनुरोधों को संसाधित करने का चरण संसाधन–गहन या समय लेने वाला नहीं लगा। प्रतिनिधिमंडल ने नियम 82 *quater*.1 में प्रस्तावित संशोधनों का समर्थन किया और प्रस्तावित नियम 82 *quater*.1(d) के संबंध में एक सुझाव भी दिया। यह कहा गया कि छूट अधिसूचना में छूट का कारण और अवधि बताई जानी चाहिए और इसे और विस्तारित करने का प्रावधान हो सकता है। प्रस्तावित नियम 82 *quater*.3 के तहत, यह देखा गया कि नियम तब लागू होता है जब व्यवधान कार्यालय, प्राधिकरण या अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो के संचालन को प्रभावित करता है, जिससे पक्षों की समय सीमा को पूरा करने की क्षमता प्रभावित होती है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि प्रभावित पक्षों को नियम 82 *quater*.1(a) में संशोधन करके "या जहां कार्यालय, प्राधिकरण या अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो स्थित है" पाठ के बाद "क्षेत्र में जहां इच्छुक पार्टी निवास करती है, उसका निवास स्थान है या रह रही है" पाठ शामिल करके समान उपाय प्रदान किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करेगा कि केवल प्रभावित पक्ष उपचार का लाभ उठाएं जबकि अन्य समय–सीमा को पूरा करें और इससे समय–सीमा को पार करने वाली स्थितियों में कमी होगी और पीसीटी प्रणाली को अनुमानित रूप से कार्य करने में सक्षम होगी।

IV. कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों पर स्थायी समिति (एससीसीआर): 28 जून से 1 जुलाई, 2021 तक जेनेवा में आयोजित एससीसीआर के इकतालीसवें सत्र में, भारत के प्रतिनिधिमंडल ने प्रसारण संगठनों की सुरक्षा के लिए संधि का समर्थन किया और विश्वास व्यक्त किया कि समिति विषयों पर कार्य करेगी और प्रसारण संगठनों की सुरक्षा की परिभाषा पर सभी प्रमुख मुद्दों को संबोधित करेगी। सीमाओं और अपवादों के संबंध में, यह कहा गया कि कॉपीराइट कानून में अधिकारों की कुछ सीमाएं हैं, जिनमें अधिकार धारकों के बीच संतुलन कायम करने के लिए, अधिकार धारकों के प्राधिकरण के बिना संरक्षित कार्यों का उपयोग किया जा सकता है। प्रतिनिधिमंडल ने प्रस्तावित की जा रही सीमाओं और अपवादों का भी समर्थन किया और बाद के सत्रों में अधिक विवरण के साथ जुड़ने की आशा व्यक्त की।

V. बौद्धिक संपदा और आनुवंशिक संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान और लोककथाओं पर अंतर–सरकारी समितिः 28 फरवरी से 4 मार्च, 2022 तक जेनेवा में आयोजित आईजीसी के बयालिसवें सत्र में, भारत के प्रतिनिधिमंडल ने बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधनों और आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान से संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानूनी साधन के मसौदे के अध्यक्षीय पाठ पर कुछ चिंताएं व्यक्त कीं। यह कहा गया कि प्रस्तावना और उद्देश्य उपकरण को वर्तमान में पेटेंट प्रणाली तक सीमित किया जाए जबकि अनुच्छेद 9 अनुच्छेद 3 और प्रकटीकरण आवश्यकताओं को अन्य आईपी तक विस्तारित करने के लिए समीक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 3. 1 और 3.2 के संदर्भ में, यह कहा गया कि भौतिक रूप से और प्रत्यक्ष रूप से शब्द के उपयोग के संबंध में अस्पष्टता थी और शब्द 'भौतिक रूप से' व्यापक सुरक्षा प्रदान करेगा क्योंकि इसमें व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल ने अनुच्छेद 3.1ख और 3.2 की गैर–बाध्यकारी प्रकृति पर भी चिंता व्यक्त की क्योंकि यह माना जाता है कि यह संभावना नहीं थी कि किसी शोधकर्ता को स्रोत का ज्ञान नहीं होगा।

VI. वायपो मानकों पर समितिः 1 नवंबर से 5 नवंबर 2021 तक जेनेवा में आयोजित सीडबल्यूएस के नौवें सत्र में भारत के प्रतिनिधिमंडल ने ऑस्ट्रेलिया और रूसी संघ के नेतृत्व वाली ब्लॉकचेन टास्क फोर्स को धन्यवाद दिया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि भारतीय पेटेंट कार्यालय वर्तमान में आईपी पारिस्थितिकी तंत्र में ब्लॉकचेन का उपयोग करने की संभावनाएं खोज रहा है और आईपी प्रणाली में ब्लॉकचेन के संबंध में विभिन्न संबंधित मुद्दों को देख रहा है। संशोधित वायपो एसटी.26 को अपनाने के संबंध में, प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि आईपीओ अनुक्रम सूचीकरण मानकों के लिए वायपो एसटी.26 को अपनाने पर विचार कर रहा है और विकास परीक्षण, सत्यापन और सॉफ्टवेयर टूल के कार्यान्वयन और एसटी.26 में सुचारू संक्रमण के लिए वायपो के साथ सहयोग कर सकता है। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि आईपीओ इस संबंध में वायपो द्वारा संभावित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रतीक्षा कर रहा है।

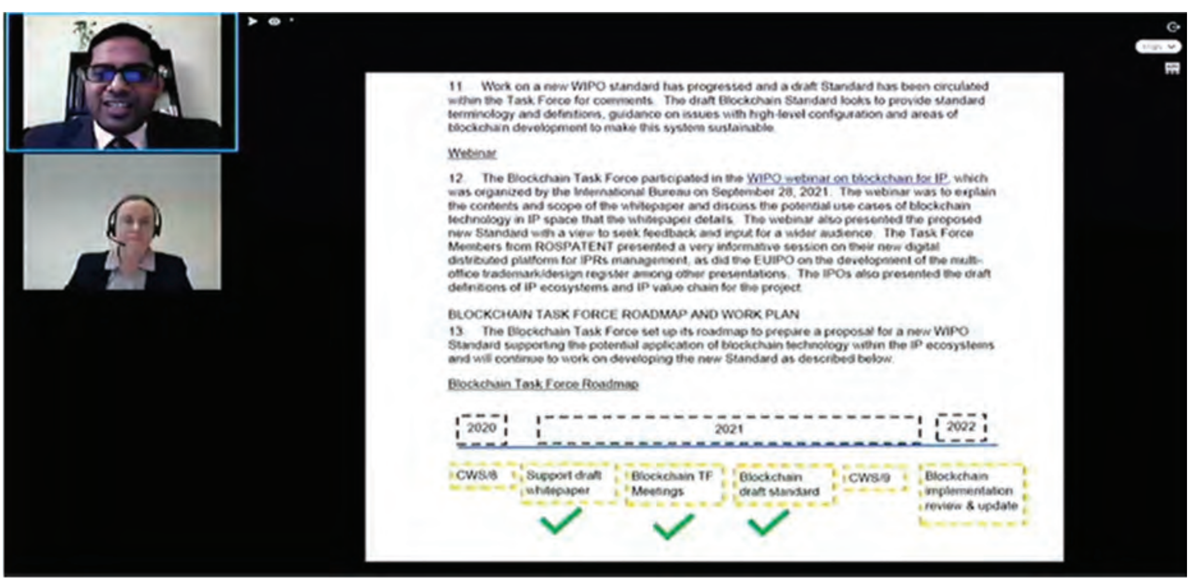

VII. ब्रिक्स–आईपीआर सहयोगः

25 अगस्त, 2021 को भारत की अध्यक्षता में 'ब्रिक्स आईपीआर सहयोग रोडमैप कार्यक्रम' के बौद्धिक संपदा कार्यालयों प्रमुखों की (एचआईपीओ) की 13वीं ब्रिक्स बैठक आभासी रूप से आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्री राजेंद्र रत्नू, महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न (भारत) ने की। सीएनआईपीए (चीन) के आयुक्त डॉ. शेन चंग्यू; सीआईपीसी (दक्षिण अफ्रीका) के आयुक्त, अधि.रोरी वोलर; आईएनपीआई (ब्राजील) के अध्यक्ष श्री क्लॉडियो विल्लर फर्टाडो; और रोस्पेटेंट (रूस) के महानिदेशक श्री ग्रिगोरी इव्लिव ने अपने संबंधित प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठक में भाग लिया।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल में निम्नलिखित अधिकारी थेः डॉ. दिनेश पी. पाटिल, उप नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प और तकनीकी प्रमुख, डॉ. अमरेंद्र सामल, उप नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प, कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न, मुंबई, श्री एन.के. मोहंती, संयुक्त नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प, कार्यालय प्रमुख, पेटेंट कार्यालय, मुंबई, श्री कल्याण रवेला, आईआरएस और उप सचिव, कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न, मुंबई, श्री सागर बाबूराव पोल, सहायक नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प, पेटेंट कार्यालय, मुंबई, श्री प्रखर सिंह, परीक्षक एकस्व एवं अभिकल्प, पेटेंट कार्यालय, मुंबई, श्री नीलेश एस पाटिल, परीक्षक एकस्व एवं अभिकल्प, पेटेंट कार्यालय, मुंबई, श्री रवि कुमार, परीक्षक एकस्व एवं अभिकल्प, पेटेंट कार्यालय, दिल्ली और श्रीमती शीला अंकुश वानखेड़े, परीक्षक व्यापार चिह्न एवं भौगोलिक उपदर्शन।

बैठक के दौरान, प्रतिनिधिमंडलों ने आईपी आवेदनों के प्रसंस्करण में डिजिटल प्रौद्योगिकियों और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग के महत्व और ब्रिक्स आईपी कार्यालयों की कार्यप्रणाली में ऐसी प्रौद्योगिकियों को अपनाने, ग्रामीण विकास में भौगोलिक उपदर्शनों की भूमिका और सदस्य देश द्वारा सफल आईपी अभ्यास सहित कई मुद्दों पर विचारों का आदान–प्रदान किया। यह स्वीकार किया गया कि भविष्य में एआई–आधारित नवाचारों का उदय अपरिहार्य है और इसके द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में आए अंतर को पाटने के लिए और विचार–विमर्श की आवश्यकता है।

सीजीपीडीटीएम–इंडिया द्वारा 6 दिसंबर से 10 दिसंबर, 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से 5 दिवसीय **'आईपी ब्रिक्स परीक्षक प्रशिक्षण–2021'** भी आयोजित किया गया। आईपी–ब्रिक्स समन्वय टीम के समन्वय में राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम–नागपुर) द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

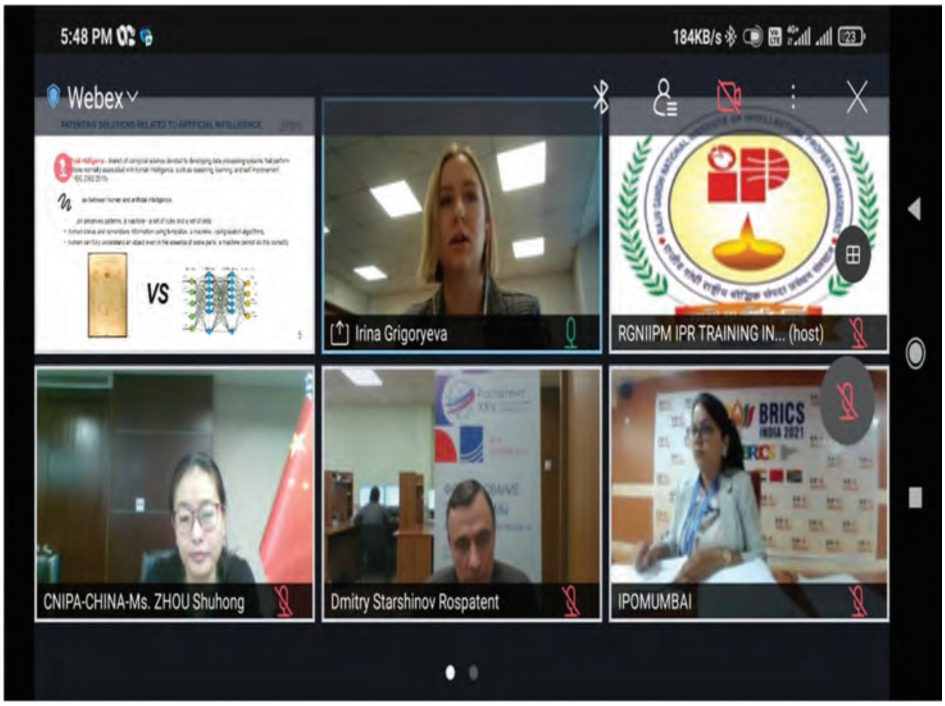

प्रशिक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई उभरती प्रौद्योगिकियों (एनईटी) पर विशेष ध्यान देने के साथ परीक्षा के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया और नामित अधिकारी इस प्रकार थे:

- समावेशी आईपी शासन (एसएमई, मितव्ययी आविष्कारक, लिंग–समावेशी आदि) को बढ़ावा देने की दिशा में कदम और चुनौतियां: श्री श्रीकांत के.एस., सहायक नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प
- केस स्टडी के माध्यम से एआई और एनईटी (न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी) संबंधित पेटेंट आवेदनों के लिए पूर्व कला खोज के विभिन्न दृष्टिकोण: श्री अक्षय कुमार, सहायक नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प
- एआई और एनईटी संबंधित पेटेंट आवेदनों के लिए केस स्टडी के माध्यम से नवीनता और आविष्कारशील कदम विश्लेषण: श्री विशाल शुक्ला, सहायक नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प
- एआई और एनईटी संबंधित पेटेंट आवेदनों के मामले के अध्ययन के माध्यम से संबंधित काउंटी के पात्रता बहिष्करण लेख (गैर–पेटेंट योग्य) का विश्लेषण: श्री राकेश कुमार कुशवाहा, सहायक नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प
- पेटेंट परीक्षण में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना: श्री संतोष कुमार गुप्ता, सहायक नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प

प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। सीजीपीडीटीएम–इंडिया द्वारा पत्र के माध्यम से 01 जनवरी, 2022 से आईपी–ब्रिक्स की अध्यक्षता सीएनआईपीए–चीन को स्थानांतरित कर दी गई।

अध्याय–XIII

प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा बर्हि–क्रियाकलाप

परिचय

नवाचार और रचनात्मकता का पोषण और प्रोत्साहन करते हुए बौद्धिक संपदा (आईपी) समाज की सांस्कृतिक और आर्थिक उन्नयन में सहभागी बनता है। आईपी एक बहु–आयामी विधा है, जो, उदाहरणस्वरूप,

(i) आविष्कारक, लेखक एवं कलाकारों को प्रोत्साहित करता है;

(ii) शोध औए विकास चक्र में निरंतरता लाता है;

(iii) उनकी साख के अप्राधिकृत प्रयोग के विरुद्ध संरक्षा अनुदानित करता है; और

(iv) उन शिल्पकारों के गरीबी उन्मूलन के लिए योगदान देता है जो भौगोलिक उपदर्शन के सबसे निचले स्तर के प्रयोगकर्ता हैं।

उपर्युक्त के मद्देनज़र, कार्यालय महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न विगत कई वर्षों से जन साधारण के लिए जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम संचालित करने की पहल करता रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से उद्देश्य है कि आईपी से संबंधित प्रमुख मुद्दों और समस्याओं की व्यापक समझ पैदा हो, आईपीआर सुरक्षा और प्रवर्तन के बारे में ज्ञान प्रदान किया जाय और जागरूकता बढ़ाने के साथ–साथ आईपीआर का लाभ उठाने के लिए व्यवसायों को सशक्त बनाया जाय। आईपी कार्यालयों के अधिकारी इन जागरूकता कार्यक्रमों में नियमित संसाधन व्यक्ति रहे हैं।

1. आईपीओ अधिकारियों का प्रशिक्षणः

आईपी अधिकारियों के कौशल और विशेषज्ञता के विकास के उद्देश्य और आईपी कार्यालयों के क्षमता निर्माण के लिए कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न द्वारा नए परीक्षक एकस्व एवं अभिकल्प के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पेटेंट नियंत्रकों के लिए पुनश्चर्या/विधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिससे मानव संसाधन का मजबूत आधार तैयार हो सके।

2. सीजीपीडीटीएम कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम :

स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ के स्मारकीय अवसर पर, भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के बाद से भारत की यात्रा का जश्न मनाने के लिए एक विशेष पहल *'आजादी का अमृत महोत्सव'* की शुरुआत की गई। इस संदर्भ में, माननीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने एक निश्चित समयावधि में देश में दस लाख छात्रों के बीच आईपी जागरूकता पैदा करने के लिए महानियंत्रक कार्यालय को एक दायित्व सौंपा था।

इसके मद्देनजर, महानियंत्रक कार्यालय ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (निपम) नामक एक अभियान की संकल्पना की, जिसका शुभारंभ माननीय सचिव, डीपीआईआईटी, श्री अनुराग जैन के कर कमलों द्वारा 8 दिसंबर, 2021 को किया गया था, इस अभियान का उद्देश्य 15 अगस्त, 2022 से पहले देश भर में 01 मिलियन छात्रों को आईपी जागरूकता प्रदान करना था।

हिंदी और अँग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार बैनर शासकीय वेबसाइट www.ipindia.gov.in पर उपलब्ध है।

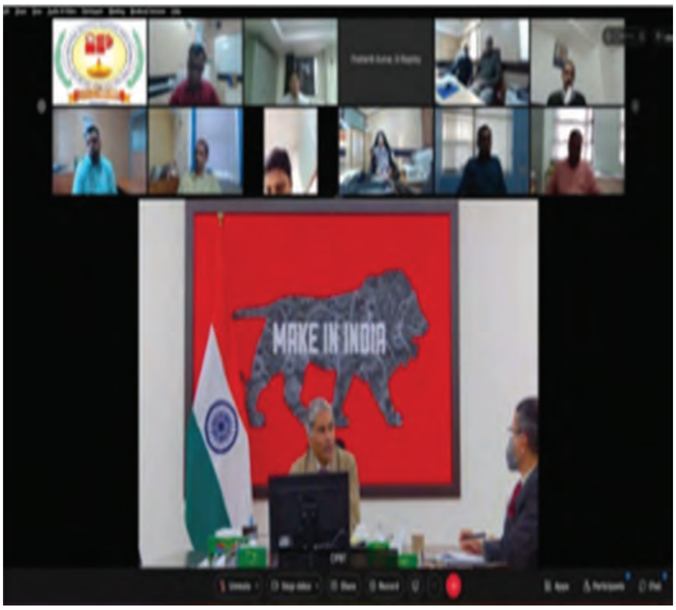

देश भर में दस लाख छात्रों के बीच आईपी जागरूकता पैदा करने के इस अभियान के माध्यम से, भारत सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण की पहल के लिए एक छोटा सा योगदान दिया गया था। यह सर्वविदित है कि आईपी जागरूकता यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि देश में उत्पन्न होने वाली बौद्धिक पूंजी को उचित मान्यता और सुरक्षा मिले, ताकि आईपी निर्माता उससे निकलने वाले लाभों का आनंद प्राप्त कर सकें।

लक्ष्य समूह

इस अभियान ने छात्रों को दो स्तरों पर लक्षित किया था, जो इस प्रकार हैः

स्तर A–विद्यालय (कक्षा 9 से 12)

स्तर B–विश्वविद्यालय / महाविद्यालय

इच्छुक स्कूलों/कॉलेजों के साथ–साथ व्यक्तिगत छात्रों के लिए वेबसाइट https://ipindiaservices-gov-in/events-ipr/home/home-aspx या https://ipindiaservices.gov.in/events-ipr/OnlineUser/OnlineRegistration.aspx पर एक समर्पित लिंक ने इस जागरूकता कार्यक्रम तक पहुंच बनाई और पंजीकरण को सरल बनाया।

आगामी कार्यक्रमों के सभी विवरण इस लिंक पर देखे जा सकते हैं

आउटरीच का तरीका:

भारत के विशाल भौगोलिक विस्तार और चल रही कोविड–19 महामारी के दौरान उत्पन्न चुनौतियों को देखते हुए, कोविड प्रोटोकॉल की व्यापकता और लक्षित दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण का ऑफलाइन और हाइब्रिड मोड प्रदान किया गया था।

समयावधि

इस अभियान का उद्देश्य 15 अगस्त 2022 तक दस लाख छात्रों में जागरूकता फैलाने का लक्ष्य हासिल करना था। इसके बाद, अभियान जारी रह सकता है और यह महानियंत्रक कार्यालय का एक प्रमुख कार्यक्रम बन सकता है।

अधिकारियों की समर्पित टीम ने परियोजना के एक कार्यक्रम समन्वयक के अधीक्षण में काम किया और विवरण निम्नानुसार है:

स्थान	वरिष्ठ टीम लीडर	टीम लीडर	निपम अधिकारी
दिल्ली	1	5	43
चेन्नई	1	4	17
कोलकाता	1	5	19
मुंबई	1	5	11
आरजीएन आईआईपीएम, नागपुर	1	1	4
कुल	**5**	**20**	**94**

उपर्युक्त अधिकारियों द्वारा संगठन/संस्था से प्राप्त ऑनलाइन अनुरोध निम्नानुसार हैं:

स्थान	वरिष्ठ टीम लीडर	टीम लीडर	निपम अधिकारी
दिल्ली	237	230	219
चेन्नई	106	101	71
कोलकाता	69	66	66
मुंबई	83	77	73
आरजीएन आईआईपीएम, नागपुर	6	6	6
कुल	**501**	**480**	**435**

उपरोक्त अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त ऑनलाइन अनुरोध निम्नानुसार हैं:

स्थान	वरिष्ठ टीम लीडर	टीम लीडर	निपम अधिकारी
दिल्ली	217	212	177
चेन्नई	102	98	65
कोलकाता	48	48	48
मुंबई	128	34	27
आरजीएन आईआईपीएम, नागपुर	2	2	0
कुल	**497**	**394**	**317**

01 नवंबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान कुल **2311** कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें कुल **609819** लोगों की उपस्थित रही।

महीना	कुल आयोजित कार्यक्रम	कुल सहभागी
दिसंबर, 2021	264	60390
जनवरी, 2022	557	149848
फरवरी, 2022	845	216151
मार्च, 2022	645	183430
कुल	**2311**	**609819**

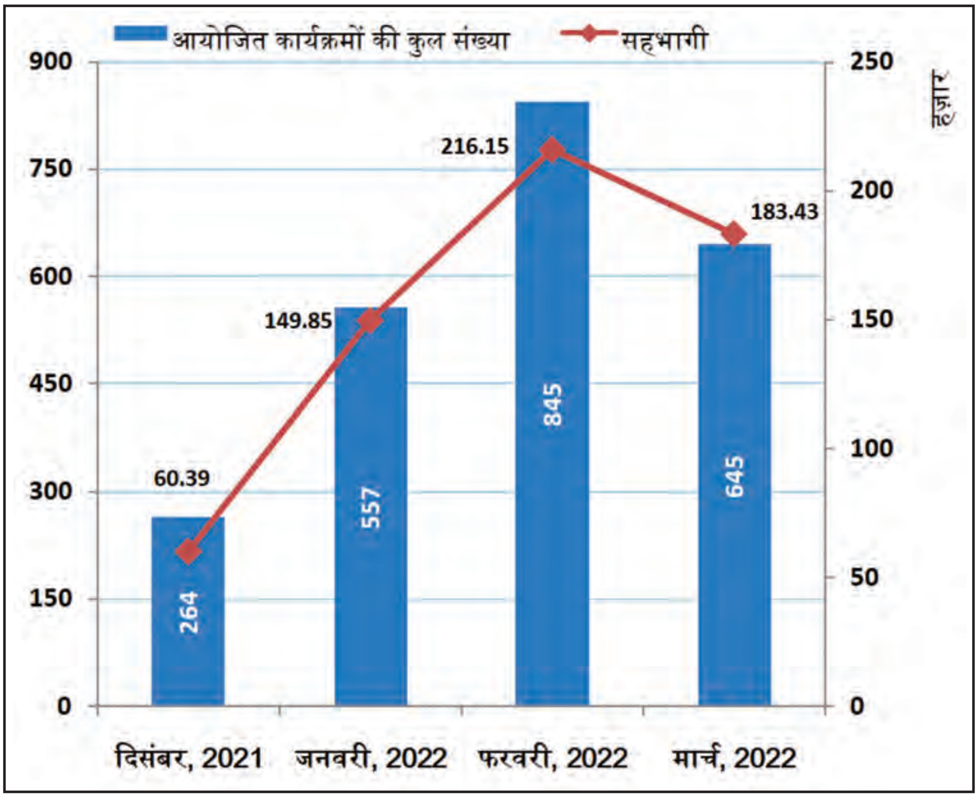

विभिन्न प्रकार के संगठनों के साथ उपस्थित लोगों के साथ आयोजित कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है;

संगठन के प्रकार	कुल कार्यक्रम	कुल प्रतिभागी	प्रमाण पत्र की	प्रमाण पत्र लंबित मंजूरी
कॉलेज	1024	376387	376358	29
संस्थान	183	56215	56214	1
एनए	481	—	—	—
विद्यालय	372	102131	102131	0
विश्व विद्यालय	251	75086	75085	1
कुल	**2311**	**609819**	**609788**	**31**

विभिन्न स्थानों से विभिन्न पेटेंट कार्यालयों द्वारा संचालित कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

द्वारा आयोजित	कुल कार्यक्रम	कुल प्रतिभागी
बौद्धिक संपदा कार्यालय, चेन्नई	520	147077
बौद्धिक संपदा कार्यालय, दिल्ली	889	215930
बौद्धिक संपदा कार्यालय, कोलकाता	289	91719
बौद्धिक संपदा कार्यालय, मुंबई	424	103389
आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर	189	51704

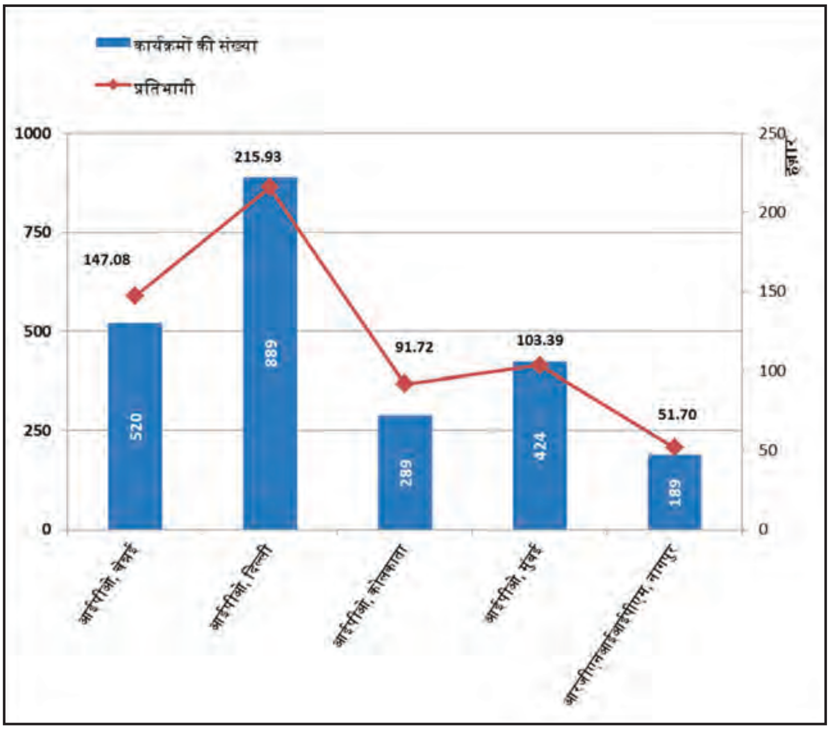

उपस्थित लोगों का लिंग वितरण इस प्रकार है:

सहभागी की श्रेणी	पुरुष	स्त्री	सूचना उपलब्ध नहीं
संकाय	28021	22242	–
विधार्थी	290020	269295	209

उपस्थित लोगों के साथ आयोजित कुल कार्यक्रमों का राज्यवार विवरण इस प्रकार है:

राज्य	कुल कार्यक्रम	कुल प्रतिभागी
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (संघशासित क्षेत्र)	1	291
आंध्र प्रदेश	140	45859
अरुणाचल प्रदेश	13	1587
असम	26	6053
बिहार	26	6656
चंडीगढ़ (संघशासित क्षेत्र)	4	911
छत्तीसगढ़	37	8834
दादरा और नगर हवेली (संघशासित क्षेत्र) दमन और डीयू (संघशासित क्षेत्र)	2	1120
दिल्ली–एनसीआर (संघशासित क्षेत्र)	112	19646
गोआ	23	1823
गुजरात	35	8413
हरियाणा	108	26774
हिमाचल प्रदेश	19	5922
जम्मू और काश्मीर (संघशासित क्षेत्र)	8	1042
झारखंड	29	10137
कर्नाटक	46	13983
केरल	124	20825
लद्दाख (संघशासित क्षेत्र)	2	267
मध्य प्रदेश	107	33140
महाराष्ट्र	399	100868
मणिपुर	6	701
मेघालय	7	3915
मिज़ोरम	5	1229
नागालैंड	7	4327
ओडिशा	31	6614
पुडुचेरी (संघशासित क्षेत्र)	10	3327
पंजाब	28	11891
राजस्थान	338	88943
सिक्किम	3	1528
तमिलनाडु	194	63454
तेलंगाना	38	11008
त्रिपुरा	3	383
उत्तर प्रदेश	142	34500
उत्तराखंड	40	9606
पश्चिम बंगाल	169	54242
लागू नहीं	29	–

कार्यालय महानियंत्रक ने सभी संभावित स्थानों तक पहुंचने का प्रयास किया है जो आसानी से और साथ ही हवाई/रेल/सड़क द्वारा पहुंचना मुश्किल हो सकता है। रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान शामिल किए गए कुछ कम ज्ञात जिले इस प्रकार हैं:

राज्य संगठन	निहित जिला /कुल जिला	निहित जिला
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (संघशासित क्षेत्र)	1/3	दक्षिण अंडमान
आंध्र प्रदेश	12/26	अनंतपुर, चित्तोर, गुंटूर, कृष्णा, कुर्नूल, एसपीएसआर नेल्लोरे, श्रीकाकुलम, विसाखपटनम, विजीयनगरम, पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, वाईएसआर (कड़पा)
अरुणाचल प्रदेश	4/15	चंगलांग, लोहित, पापुम परे, सियांग
असम	12/35	बारपेटा, काचर, दाररंग, धेमजी, डिब्रूगढ़, जोरहट, कामरूप मेट्रोपॉलिटन, कोकराझार, नागोन, सोनीपुर, तिनसुकिया
बिहार	13/38	अरारिया, औरंगाबाद, भोजपुर, पूर्व चंपारण, गया, मधेपुरा, मधुबनी, पटना, पुर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, शिवहर, वैशाली
चंडीगढ़ (संघशासित क्षेत्र)	1/1	चंडीगढ़
छत्तीसगढ़	5/27	बेमेतरा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, राजनन्दगाँव
दादरा और नगर हवेली (संघशासित क्षेत्र) दमन और डीयू (संघशासित क्षेत्र)	1/3	दादरा और नगर हवेली
दिल्ली–एनसीआर (संघशासित क्षेत्र)	8/11	पूर्व दिल्ली, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, उत्तर पूर्व दिल्ली, उत्तर पश्चिम, दक्षिण दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, पश्चिम दिल्ली
गोआ	2/2	उत्तर गोआ, दक्षिण गोआ
गुजरात	7/33	अहमदाबाद, आनंद, भावनगर, गांधीनगर, मेहसाना, सूरत, वडोदरा
हरियाणा	20/22	अम्बाला, भिवानी, चरखी, दादरी, फ़रीदाबाद, गुगूग्राम, हिसार, झज्जर, जिंद, कैथल, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, नूह, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रेवारी रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनागर
हिमाचल प्रदेश	3/12	कंगरा, मंडी, सोलन
जम्मू और काश्मीर (संघशासित क्षेत्र)	4/22	गंडेरबल, कठुआ, सम्बा, श्रीनगर
झारखंड	8/24	बोकारो, धनबाद, पूर्व सिंघभूम, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, पश्चिम सिंघभूम
कर्नाटक	15/31	कोलार, बगल्कोटे, बंगलोर, बेलगावी, बेल्लारी, बीजापुर, दक्षिण कन्नड़, दावणगेरे, धारवाड़, कालबुरगी, रायचूर, रमंगारा, शिमोगा, तुमकुर
केरल	13/14	अलप्पुजा, एर्णाकुलम, इडुक्की, कन्नूर, कोल्लम कोट्टायम, कोझिकोड, मलप्पुरम, पलक्कड, पथनंथीट्टा, थिरुवंथपुरम, थ्रिस्सूर, वयानन्द
लद्दाख (संघशासित क्षेत्र)	1/2	लेह जिला

मध्य प्रदेश	23 / 55	अनुप्पूर, अशोकनागर, बेतुल, भोपाल, छतरपुर, छिन्दवाडा, देवास, धार, दिंदोरी, गुणा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, मंदसौर, नीमुच, रीवा, शाजापुर, शिवपुरी, सिंगरौली, उज्जैन, विदिशा
महाराष्ट्र	28 / 36	अहमदनगर, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, बुलढाना, धुले, गडचिरोली, गोंदिया, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई सिटी, नागपुर, नांदेड़, नाशिक, उस्मानाबाद, पालघर, पुणे, राइगड़, रतनागिरी, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, सोलापुर, ठाणे, वर्धा, यावतमल
मणिपुर	2 / 16	इम्फ़ाल पशिचम, सेनापति
मेघालय	4 / 12	ईस्ट ख़ासी हिल्स, रिभोइ, वेस्ट गारो हिल्स, वेस्ट जाईंतिया हिल्स
मिज़ोरम	1 / 11	आइजवल
नागालैंड	3 / 16	किफिरे, कोहिमा, दिमापुर
ओडिशा	8 / 30	बालेश्वर, बोलंगीर, बौद्ध, गंजम, कालाहंडी, खोरदा, रायगड्डा
पुडुचेरी (संघशासित क्षेत्र)	2 / 4	पांडेचरी, काराईकाल
पंजाब	9 / 23	भटिंडा, फतेहगढ़, साहिब, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मोगा, मोहाली, पटियाला, रूपनगर
राजस्थान	25 / 33	अजमेर, अलवर, बरन, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तोडगढ़, चुरू, दौसा, ढोलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, झालावार, झुनझुन्नु, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, श्री गंगानगर, टोंक, उदयपुर
सिक्किम	1 / 6	ईस्ट सिक्किम
तमिलनाडु	23 / 38	चेन्नई, कोयम्बटूर, डिंडुगुल, इरोड, कल्लाकुरीची, कांचीपुरम, कन्नीयाकुमारी, करूर, मदुरै, नागपट्टिनम, नामक्कल, पेरंबलूर, रामनाथपुरम, सलेम, सिवागंगा, थंजावूर, थूथूकुडी, तिरुचिरपपल्ली, तिरुनेल्वेलि, तिरुप्पूर, तिरुवल्लूर, वेल्लोर, विरुधुनगार
तेलंगाना	6 / 33	हैदराबाद, मेदचल–मलकाजगीरी, नलगोंडा, निजामाबाद, रंगा रेड्डी, वारंगल
त्रिपुरा	2 / 8	नॉर्थ त्रिपुरा, वेस्ट त्रिपुरा
उत्तर प्रदेश	30 / 75	आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर, नागर, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बंडरा, बाराबंकी, बरेली, बिजनोर, देओरिया, गौतम बुद्ध नागर, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, हापुर, हातरस, झाँसी, कानपुर, लखनऊ, महाराजगंज, मथुरा, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मोरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, राई बरेली, सीतापुर, सुलतानपुर, वाराणसी
उत्तराखंड	9 / 13	वागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहारादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौरी, गढ़वाल, रुद्रपुर, उत्तरकाशी
पश्चिम बंगाल	17 / 23	अलीपुर, बांकुरा, दक्षिण दिनाजपुर, दार्जिलिंग, हूघली, हावड़ा, कलिमपोंग, कोलकाता, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, नॉर्थ 24 परगना, पश्चिम बर्धमान, पश्चिम मिदिनीपुर, पूर्व बर्धमान, पूर्व मेदिनीपुर, उत्तर दिनाजपुर

निपम का प्रभावः निपम के तहत आयोजित आईपी जागरूकता कार्यक्रमों ने प्रभावशाली परिणाम दिए हैं। आईपी फाइलिंग में वृद्धि देखी गई है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, भारत से आने वाले आवेदनों की संख्या में वृद्धि हुई है। पेटेंट के तहत दाखिल कुल घरेलू आवेदन 44.41% है; डिजाइन 83.05% है जबकि व्यापार चिह्न में कुल फाइलिंग का 96.94% है।

आईपी आवेदन दाखिल करने में वृद्धि विशेष रूप से भारतीय मूल के आवेदन

आईपी का प्रकार	कुल दाखिल आवेदन			भारतीय मूल के आवेदन			कुल आवेदन का %
	2020–21	2021–22	% वृद्धि	2020–21	2021–22	% वृद्धि	
पेटेंट	58503	66440	13.57	24326	29508	21.3	44.41
डिजाइन	14241	22699	59.39	10594	18851	77.94	83.05
व्यापार चिह्न	431213	447805	3.85	418594	434084	3.7	96.94

4. भारत और विदेश में अंतरराष्ट्रीय मंच और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की बैठक में अधिकारियों की भागीदारीः

कोविड–19 महामारी की व्यापकता और भारत और विदेशों में लगातार लॉकडाउन के कारण, केवल कुछ ही बैठकें आयोजित की गईं और एक कार्यक्रम को छोड़कर जिसमें व्यक्तिगत रूप से भाग लिया गया था, भागीदारी मुख्य रूप से ऑनलाइन थी।

क्र. सं.	प्रशिक्षण / संगोष्ठी / कार्यशाला / कार्यक्रम में भाग लिया	देश का दौरा किया	भाग लेने वाले अधिकारियों की संख्या
1	पीसीटी मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन टास्क फोर्स ("टास्क फोर्स") की तीसरी बैठक 17 से 21 मई, 2021 तक वायपो मुख्यालय, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई	दूरस्थ भागीदारी	3
2	व्यापार चिह्न, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक उपदर्शन (एससीटी) के कानून पर स्थायी समिति का 44वां सत्र 17 से 19 मई, 2021 तक जेनेवा, स्विट्जरलैंड में वायपो मुख्यालय में आयोजित हुआ।	दूरस्थ भागीदारी	3
3	वायपो मुख्यालय, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में 14 से 17 जून, 2021 तक आयोजित पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) वर्किंग ग्रुप का चौदहवां सत्र	दूरस्थ भागीदारी	6
4	जेनेवा में वायपो मुख्यालय में हाइब्रिड प्रारूप में और 28 जून से 01 जुलाई, 2021 तक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों (एससीसीआर) पर स्थायी समिति का चालीसवां सत्र आयोजित किया गया।	दूरस्थ भागीदारी	2
5	26 से 30 जुलाई, 2021 तक वायपो के मुख्यालय में जेनेवा में हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित विकास और बौद्धिक संपदा समिति (CDIP) का छब्बीसवां सत्र	दूरस्थ भागीदारी	1
6	30 अगस्त से 03 सितंबर, 2021 तक जेनेवा में वायपो मुख्यालय में आयोजित बौद्धिक संपदा और आनुवंशिक संसाधन, पारंपरिक ज्ञान और लोकगीत (IGC) पर अंतर सरकारी समिति का 41वां सत्र।	दूरस्थ भागीदारी	3

7	प्रवर्तन पर सलाहकार समिति (एसीई) ऑनलाइन संवाद, 21 सितंबर, 2021 को जेनेवा में वायपो मुख्यालय में आयोजित किया गया	दूरस्थ भागीदारी	3
8	वायपो, पीसीटी यूनियन और मैड्रिड यूनियन के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं की बैठकों की साठवीं श्रृंखला जेनेवा, स्विट्जरलैंड में 04 से 09 अक्टूबर, 2021 तक आयोजित की गई	दूरस्थ भागीदारी	4
9	22 नवंबर से 26 नवंबर, 2021 तक जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित विकास और बौद्धिक संपदा समिति (सीडीआईपी) का सत्ताईसवाँ सत्र	दूरस्थ भागीदारी	1
10	15 नवंबर से 19 नवंबर, 2021 तक जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित अंकों के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के लिए मैड्रिड प्रणाली के कानूनी विकास पर कार्य समूह का उन्नीसवां सत्र	दूरस्थ भागीदारी	1
11	वायपो मानकों (CWS) पर समिति का नौवां सत्र 01 से 05 नवंबर, 2021 तक वायपो मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया	दूरस्थ भागीदारी	2
12	अंतरराष्ट्रीय पेटेंट वर्गीकरण (IPC संघ) IPC संशोधन कार्य समूह के लिए विशेष संघ का चालीसवां सत्र 08 से 10 नवंबर, 2021 तक जेनेवा, स्विट्जरलैंड में वायपो मुख्यालय में आयोजित किया गया	दूरस्थ भागीदारी	2
13	24 जनवरी से 28 जनवरी, 2021 तक जेनेवा, स्विट्जरलैंड में वायपो मुख्यालय में आयोजित औद्योगिक डिजाइनों के अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण के लिए लोकार्नो यूनियन के विशेषज्ञों की समिति का पंद्रहवां सत्र	दूरस्थ भागीदारी	1
14	28 फरवरी से 04 मार्च, 2022 तक जेनेवा, स्विट्जरलैंड में वायपो मुख्यालय में आयोजित बौद्धिक संपदा और आनुवंशिक संसाधन, पारंपरिक ज्ञान और लोकगीत (IPO) पर अंतर सरकारी समिति का 42वां सत्र	दूरस्थ भागीदारी	3
15	28 से 30 मार्च, 2022 (तीन दिन) तक जेनेवा, स्विट्जरलैंड में वायपो मुख्यालय में आयोजित व्यापार चिह्न, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेत (एससीटी) के कानून पर स्थायी समिति का पैंतालीसवां सत्र	दूरस्थ भागीदारी	3
16	कोपेनहेगन, डेनमार्क में 08 नवंबर से 26 नवंबर तक आयोजित डीएफसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2021 के तहत "फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड व्यावसायीकरण ऑफ आईपीआर"	व्यक्तिगत भागीदारी	6
17	24 जनवरी से 07 फरवरी, 2022 तक टोक्यो, जापान में डिजाइन मूल परीक्षा और हेग समझौते में शामिल होने पर जेपीओ/आईपीआर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	दूरस्थ भागीदारी	1

मानव संसाधन

परिचयः

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न के अधीक्षण एवं प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत पेटेंट कार्यालय, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री, पेटेंट सूचना पद्धति (पीआईएस)/ राजीव गाँधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) अपनी गतिविधियाँ निष्पादित करते हैं।

वर्ष 2021–22 के दौरान संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के माध्यम से वरिष्ठ परीक्षक, व्यापार चिह्न एवं भौगोलिक उपदर्शन के नौ पद तथा उप पंजीकार, व्यापार चिह्न एवं भौगोलिक उपदर्शन के तीन पदों को भरने की कार्रवाई की गई। साथ–ही–साथ संदर्भ वर्ष के दौरान पेटेंट कार्यालय और व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में रिक्त 14 पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए भी कार्यवाही की गई है।

विभिन्न बौद्धिक संपदा कार्यालयों में मानव संसाधनः

1. कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प व व्यापार चिह्न, मुंबईः

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) में निम्नलिखित सहायक कर्मचारी हैं:

31 मार्च, 2022 तक कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न के तहत अनुमोदित और नियोजित व कार्मिक शक्ति का विवरणः

क्र. सं.	पदनाम	संस्वीकृत कार्मिक संख्या	कार्यरत कार्मिक संख्या
1	महानियंत्रक	1	1
2	निजी सचिव	1	1
3	स्टाफ कार ड्राइवर	1	1
4	मल्टी–टास्किंग स्टाफ	1	0
	कुल	**4**	**3**

हालांकि, पेटेंट और व्यापार चिह्न कार्यालयों के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को सीजीपीडीटीएम के कार्यालय में स्थापना, प्रशासन, बजट और वित्त, नीतिगत मामलों आदि से संबंधित कार्यों को संभालने के लिए नियुक्त किया गया है।

ख. पेटेंट कार्यालयः

पेटेंट कार्यालयों की कार्मिक शक्ति **परिशिष्ट क** में दर्शायी गई है। उक्त परिशिष्ट चारों पेटेंट कार्यालयों में 31 मार्च, 2022 को संस्वीकृत कार्मिक संख्या के साथ–साथ कार्यरत कार्मिक संख्या की भी सूचना प्रदान करता है।

ग. व्यापार चिह्न रजिस्ट्रीः

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की कार्मिक शक्ति **परिशिष्ट ख** में दर्शाई गई है। उक्त परिशिष्ट पांचों व्यापार चिह्न कार्यालयों में 31 मार्च, 2022 को संस्वीकृत कार्मिक संख्या के साथ–साथ कार्यरत कार्मिक संख्या की भी सूचना प्रदान करता है।

घ. भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीः

मानव संसाधन के संदर्भ में भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री के पास अलग से स्वीकृत संख्या है। **परिशिष्ट ग** भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री की 31 मार्च, 2022 को संस्वीकृत कार्मिक संख्या के साथ–साथ कार्यरत कार्मिक संख्या की भी सूचना प्रदान करता है।

ङ. पीआईएस / आरजीएनआईआईपीएमः

31 मार्च, 2022 को पीआईएस / आरजीएनआईआईपीएम में संस्वीकृत कार्मिक संख्या के साथ–साथ कार्यरत कार्मिक संख्या का विवरण **परिशिष्ट घ** में दिया गया है।

परिशिष्ट क

31 मार्च, 2022 तक पेटेंट कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारियों की कार्मिक शक्ति का विवरण

क्र. सं.	पदनाम	वर्ग	संस्वीकृत कार्मिक संख्या					कार्यरत कार्मिक संख्या				
			कोलकाता	मुंबई	चेन्नई	दिल्ली	कुल	कोलकाता	मुंबई	चेन्नई	दिल्ली	कुल
1	वरिष्ठ संयुक्त नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प	समूह क	1	1	1	2	5	0	0	0	1	1@
2	संयुक्त नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प	समूह क	3	2	3	3	11	1	2	1	2	6+1*
3	निदेशक	समूह क	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
4	उप सचिव	समूह क	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
5	उप नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प	समूह क	16	6	15	14	51	15	4#	14	10	43+1*
6	प्रधान व्यवस्था विश्लेषक	समूह क	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
7	सहायक नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प	समूह क	35	28	51	82	196	35	28	51	81#	195+1*
8	वरिष्ठ व्यवस्था विश्लेषक	समूह क	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
9	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	समूह क	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
10	परीक्षक एकस्व एवं अभिकल्प	समूह क	150	39	127	285	673^	150	39	127	285	601+1* +1$
11	सहायक निदेशक (राभा)	समूह क	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
12	वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी	समूह क	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
13	प्रशासनिक अधिकारी	समूह क	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0
14	व्यवस्था विश्लेषक सह कंप्यूटर प्रोग्रामर	समूह क	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0
	कुल		**207**	**81**	**198**	**395**	**953**	**202**	**75**	**193**	**379**	**854**

1	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	समूह ख (राजपत्रित)	1	2	1	2	6	1	2	1	2	6
2	सहायक पुस्तकाध्यक्ष व सूचना अधिकारी	समूह ख (राजपत्रित)	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2
3	निजी सचिव	समूह ख (राजपत्रित)	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1
4	वित्त अधिकारी	समूह ख (राजपत्रित)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
5	भंडार अधिकारी	समूह ख (राजपत्रित)	1	1	1	2	5	0	0	0	0	0
	कुल		**4**	**6**	**3**	**5**	**18**	**2**	**3**	**2**	**2**	**9**
1	वरिष्ठ अनुवादक	समूह ख (अराजपत्रित)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
2	कार्यालय अधीक्षक	समूह ख (अराजपत्रित)	26	14	14	22	76	20	10	9	8	47
3	पुस्तकालय एवं सूचना सहायक	समूह ख (अराजपत्रित)	1	1	1	2	5	0	0	0	1	1
4	क. अनुवादक	समूह ख (अराजपत्रित)	0	1	1	1	3	0	0	1	1	2
5	आशुलिपिक वर्ग–1	समूह ख (अराजपत्रित)	1	1	1	1	4	1	1	1	0	3
6	लेखाकार (अराजपत्रित)	समूह ख	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
7	विधि सहायक	समूह ख (अराजपत्रित)	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0
	कुल		**29**	**19**	**18**	**28**	**94**	**21**	**11**	**11**	**10**	**53**

1	फोटोग्राफी सहायक	समूह ग	1	1	1	1	4	1	0	1	1	3
2	प्रवर श्रेणी लिपिक	समूह ग	20	14	14	19	67	19	0	10	13	42
3	आशुलिपिक–वर्ग II	समूह ग	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2
4	डाटा इंट्री ऑपरेटर	समूह ग	1	4	0	5	10	1	3	0	5	9
5	स्वागतकर्ता	समूह ग	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
6	निम्न श्रेणी लिपिक	समूह ग	9	13	10	12	44	6	7	4	9	26
7	मल्टी–टास्किंग स्टाफ	समूह ग	31	5	10	14	60	16	4	9	8	37
	कुल		**62**	**38**	**35**	**53**	**188**	**43**	**15**	**24**	**38**	**120**

@ 1 वरिष्ठ संयुक्त नियंत्रक, एकस्व एवं अभिकल्प बौद्धिक संपदा संग्रहालय, अहमदाबाद में पदस्थापित हैं।

* 1 संयुक्त नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प, 1 उप नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प, 1 सहायक नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प एवं 1 परीक्षक एकस्व एवं अभिकल्प आरजीएनआईआईपीएम, नागपूर में पदस्थापित हैं।

1 उप नियंत्रक, एकस्व एवं अभिकल्प एवं 1 सहायक नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प प्रतिनियुक्ति पर हैं।

$ 1 परीक्षक, एकस्व एवं अभिकल्प आरजीएनआईआईपीएम, नागपूर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

^ बाद में वितरण किया जाएगा।

31 मार्च, 2022 तक व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के अधिकारी व कर्मचारियों की कार्मिक शक्ति का विवरण

क्र.	पदनाम	वर्ग	संस्वीकृत कार्मिक संख्या						कार्यरत कार्मिक संख्या					
			मुम्बई	कोलकाता	चेन्नई	दिल्ली	अहमदाबाद	कुल	मुम्बई	कोलकाता	चेन्नई	दिल्ली	अहमदाबाद	कुल
1	वरिष्ठ संयुक्त पंजीकार व्यापार चिह्न व भौ. उ.	समूह क	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	संयुक्त पंजीकार व्यापार चिह्न व भौ.	समूह क	2	1	1	1	0	5	1	0	0	0	0	1
3	उप पंजीकार व्यापार चिह्न व भौ. उ.	समूह क	6	2	2	4	1	15	3	2	1	2	0	8
4	सहायक पंजीकार व्यापार चिह्न व भौ. उ.	समूह क	10	2	5	10	4	31	1	0	1	1	1	4
5	वरिष्ट परीक्षक व्यापार चिह्न व भौ. उ.	समूह क	39	3	9	20	3	74	9	3	9	17	4	42
6	सहायक निदेशक (राभा)	समूह क	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
7	लेखा अधिकारी	समूह क	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	कुल		**59**	**8**	**17**	**36**	**8**	**128**	**14**	**05**	**11**	**21**	**5**	**56**
1	परीक्षक व्यापार चिह्न व भौ.उ.	समूह ख (राजपत्रित)	98	8	13	29	12	160 100*	36	5	5	10	5	61 47*
2	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	समूह ख (राजपत्रित)	2	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0
3	सहायक पुस्तकालय व सूचना अधिकारी	समूह ख (राजपत्रित)	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
4	निजी सचिव	समूह ख (राजपत्रित)	2	0	1	0	0	3	1	0	1	0	0	2
5	भंडार अधिकारी	समूह ख (राजपत्रित)	1	1	1	1	1	5	0	0	0	0	0	0
	कुल		**104**	**9**	**15**	**31**	**13**	**172 100***	**38**	**5**	**6**	**10**	**5**	**64 47***

31 मार्च, 2022 तक व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के अधिकारी व कर्मचारियों की कार्मिक शक्ति का विवरण

क्र.	पदनाम	वर्ग	संस्वीकृत कार्मिक संख्या						कार्यरत कार्मिक संख्या					
			मुम्बई	कोलकाता	चेन्नई	दिल्ली	अहमदाबाद	कुल	मुम्बई	कोलकाता	चेन्नई	दिल्ली	अहमदाबाद	कुल
1	कार्यालय अधीक्षक	समूह ख (अराजपत्रित)	8	1	1	2	1	13	2	0	0	0	0	2
2	पुस्तकालय व सूचना सहायक	समूह ख (अराजपत्रित)	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
3	आशुलिपिक समूह I	समूह ख (अराजपत्रित)	3	2	2	2	1	10	1	0	2	2	1	6
4	सहा. परीक्षक व्या. चिह्न व भौ. उ.	समूह ख (अराजपत्रित)	14	2	3	7	6	32	1	0	1	2	0	4
5	कनिष्ठ अनुवादक	समूह ख (अराजपत्रित)	1	0	1	1	0	3	0	0	0	1	0	1
6	लेखाकार	समूह ख (अराजपत्रित)	1	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0
	कुल		**28**	**6**	**7**	**13**	**8**	**62**	**5**	**0**	**3**	**5**	**1**	**14**
1	सहायक अधीक्षक	समूह ग	7	1	1	1	1	11	7	1	1	0	1	10
2	रोकड़िया	समूह ग	1	1	1	1	0	4	0	0	0	0	0	0
3	प्रवर श्रेणी लिपिक	समूह ग	25	5	6	5	3	44	13	3	4	1	0	21
4	आशुलिपिक समूह II	समूह ग	2	2	0	7	0	11	2	1	0	4	0	7
5	अवर श्रेणी लिपिक	समूह ग	20	3	7	5	3	38	6	2	4	4	1	17
6	डाटा इंट्री ऑपरेटर	समूह ग	0	2	1	4	2	9	0	2	0	3	1	6
7	मल्टी–टास्किंग स्टाफ	समूह ग	25	4	7	9	4	49	8	2	5	3	3	21
	कुल		**80**	**18**	**23**	**32**	**13**	**166**	**36**	**11**	**14**	**15**	**6**	**82**

* परीक्षक व्यापार चिह्न संविदा के आधार पर

परिशिष्ट ग

31 मार्च, 2022 तक भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री में कार्मिक शक्ति का विवरण

क्र. सं.	पदनाम	वर्ग	संस्वीकृत कार्मिक संख्या	कार्यरत कार्मिक संख्या
1	वरिष्ठ संयुक्त पंजीकार व्यापार चिह्न व भौ.उपदर्शन	समूह क	1	0
2	सहायक पंजीकार व्यापार चिह्न व भौ.उपदर्शन	समूह क	1	0
3	वरिष्ठ परीक्षक व्यापार चिह्न व भौ.उपदर्शन	समूह क	1	1
4	आशुलिपिक वर्ग II	समूह ग	1	1
5	मल्टी–टास्किंग स्टाफ	समूह ग	1	1
	कुल		**5**	**3**

31 मार्च, 2022 तक पेटेंट सूचना पद्धति और आरजीएनआईआईपीएम के अधिकारियों और कार्मिक शक्ति का विवरण

क्र. सं.	पदनाम	वर्ग	संस्वीकृत कार्मिक संख्या	कार्यरत कार्मिक संख्या
1	वरिष्ठ प्रलेखन अधिकारी	समूह क	1	0
2	कार्यालय अधीक्षक	समूह ख (अराजपत्रित)	1	0
3	वरिष्ठ प्रलेखन सहायक	समूह ख (अराजपत्रित)	1	0
4	कनिष्ठ अनुवादक	समूह ख (अराजपत्रित)	1	1
5	आशुलिपिक वर्ग I	समूह ख (अराजपत्रित)	1	1
6	भंडार सहायक	समूह ख (अराजपत्रित)	1	1
7	कनिष्ठ रिप्रोग्राफी सहायक	समूह ग	3	1
8	सहायक अधीक्षक	समूह ग	1	1
9	शेल्फ सहायक	समूह ग	1	1
10	प्रवर श्रेणी लिपिक	समूह ग	3	1
11	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	समूह ग	2	2
12	अवर श्रेणी लिपिक	समूह ग	3	3
13	हिंदी टंकक	समूह ग	1	1
14	मल्टी–टास्किंग स्टाफ	समूह ग	4	3
	कुल		**24**	**16**

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प,
व्यापार चिन्ह एवं भौगोलिक उपदर्शन

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग